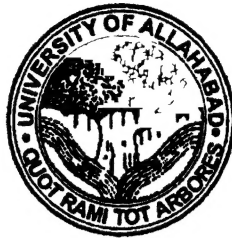


उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद् (1991-1997)

संरचनात्मक - संख्यात्मक - श्रिकाण



लाहाबाद विश्वविद्यालय, लाहाबाद के राजनीति विज्ञान विषय में
डाक्टर ऑफ़् फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध - प्रबन्ध

शोध निदेशक -
डॉ आलोक पंत
विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

शोधकर्त्री -
मनीषा सिंह
शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

कला संकाय
लाहाबाद विश्वविद्यालय, लाहाबाद
दिसम्बर २००२

डॉ० आलोक पंत

विभागाध्यक्ष,

राजनीति विज्ञान विभाग,

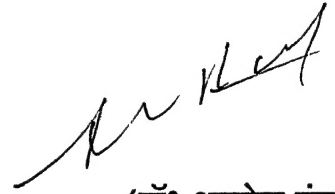
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मनीषा सिंह सुपुत्री (स्वर्गीय) डॉ० रामरूप सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पत्राक 3, दिनांक 4 जनवरी 1999 के अनुसार "उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद (1991-1997) संरचनात्मक-संख्यात्मक दृष्टिकोण" शीर्षक पर हमारे निर्देशन में अपना शोध-कार्य पूर्ण कर लिया है। इनका यह कार्य अत्यन्त मौलिक एवं शोध-मानको के अनुसार क्रमबद्ध तथा सुसंगत है।

अतः शोध-प्रबन्ध के मूल्यांकनार्थ अनुमत है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।



(डॉ० आलोक पंत)

शोध-निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद।

विश्व के जनतन्त्रात्मक राज्यों में जो स्थान (संख्या की दृष्टि से) भारत का है वही स्थान भारत के सदस्य में उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति को सर्वथा एक नई दिशा और दशा प्रदान की है, जिसके कारण यह राजनीतिक क्षितिज पर अत्यन्त आदरास्पद रहा है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय शासन की प्रकृति और प्रवृत्ति ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के ससदात्मक पद्धति पर अवलम्बित है ब्रिटेन में ससदीय प्रभुता का सिद्धान्त, यद्यपि की सिद्धान्त स्वीकृत एवं स्थापित माना जाता है, तथापि वस्तुतः वहाँ मन्त्रिमण्डल और प्रधानमंत्री की सम्प्रभुता ही विद्यमान है। यही कारण है कि मन्त्रिपरिषद् को 'राज्य-रूपी' जहाज का परिचालक चक्र' (रैम्नो म्योर), 'सरकार का केन्द्रीय निर्देशक' (ऐमरी) और ऐसा 'शक्ति-पुंज' जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यन्त्र घूमता है (जॉन मेरियट) लावेल ने इसे 'राजनीतिक भवन की आधारशिला (द-गवर्नमेण्ट ऑफ इंग्लैण्ड, खण्ड-1, पृष्ठ 57) कहा है।

मन्त्रिपरिषद् का निर्माण प्रधानमंत्री के लिए एक अत्यन्त दुष्कर एवं दुरुह कार्य होता है। उसे मन्त्रिपरिषद् के गठन में अनेक क्षेत्रीय, गुटीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्थितियों-परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। लावेल ने इस सन्दर्भ में ठीक ही लिखा है, "मन्त्रिमण्डल का निर्माण प्रधानमंत्री का ऐसा कार्य है, जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लाको की सहायता से, जो एक-दूसरे से मेल न खाते हो, एक चित्र तैयार करना है।"

ब्रिटेन के सन्दर्भों में ही भारतीय मन्त्रिपरिषद् की संरचना और उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका को समझना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के समान ही राज्य-सरकारों के अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् की संरचना और मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। वर्तमान में केन्द्र और उत्तर प्रदेश में जो मन्त्रिपरिषदीय संरचना है, वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की भूमिका को अधिक सश्लिष्ट व दुष्कर बनाती है, क्योंकि उक्त दोनों स्तरों पर अनेक प्रकार के दलों की मिली जुली सरकारें हैं।

उत्तर प्रदेश में आए दिन सरकारें बन-बिगड़ रही हैं। शोधकर्त्ता ने मन्त्रिपरिषद् की सत्ता और महत्ता की दृष्टि में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद् की संरचनात्मक-संख्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु प्रस्तुत विषय का चयन किया है।

शोध-विषय के अन्तर्गत सन् 1991 से 1997 तक का काल-विशेष निर्धारित है, क्योंकि इस कालखण्ड में प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता, परिवर्तन, मूल्यहीनता, अवसरवादिता आदि का नग्न प्रदर्शन हुआ। नेतागण अपनी सम्पूर्ण शक्ति और बौद्धिकता का प्रयोग सरकार बनाने और उसे बचाने में ही लगा रहे हैं, राष्ट्रीय हित या विकास का प्रश्न गौड़ हो गया है।

सन् 1991 से 1997 तक के काल में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की मन्त्रिपरिषद् बनी। 1991 में भाजपा, 1993 में सपा (बसपा समर्थित), 1995 में बसपा (भाजपा समर्थित), 1997 में पुनः छ-छ महीने के लिए भाजपा-बसपा की मिलीजुली, सरकार बनी। बसपा के कोटे के छ महीने व्यतीत होने के पश्चात् जब भाजपा का शेष छ महीने का कार्यकाल श्री कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री के रूप में प्रारम्भ हुआ, तो परस्पर विद्वेष और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण बसपा समर्थित भाजपा सरकार एक महीने भी नहीं चल पायी और अन्ततः अन्य दलों के जोड़-तोड़ से जेम्बोमन्त्रिमण्डल बना कर भाजपा ने सरकार बनायी।

यह शोध प्रबन्ध उपसंहार सहित नौ अध्यायों में विभक्त है तथा परिशिष्ट के रूप में 30 प्र० की मन्त्रियों की सूची, प्रश्नावली एवं सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची भी दी गई है।

भूमिका एवं शोध विधि प्रथम अध्याय से सम्बन्धित है। इसमें भूमिका के रूप में विषय-चयन का आधार बताते हुए विषय की महत्ता को रेखांकित किया गया है। शोध-विधि के अन्तर्गत ऐतिहासिक, वैधानिक एवं वर्णनात्मक दृष्टिकोण की समीक्षा करते हुए अधुनातन व्यवस्थित विश्लेषण (डेविड ईस्टन) तथा सरचनात्मक-प्रक्रियात्मक (आमण्ड-पॉवेल) दृष्टिकोणों को आधार मानकर शोध कार्य के सम्पादन का कारण बताया गया है। शोधकर्त्ता ने ईस्टन और पॉवेल के उक्त दोनों दृष्टिकोणों को समग्र रूप में न लेकर राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरणीय पृष्ठभूमि तथा 'सरचनात्मक' दृष्टि को ही मुख्य रूप से आधार माना है।

उत्तर प्रदेश - एक पार्श्वचित्र के रूप में द्वितीय अध्याय का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रदेश की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों सहित भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति-परिस्थिति का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया गया है।

तृतीय अध्याय में मन्त्रिपरिषद् की सरचनाओं उसके ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप में

व्याख्यायित करते हुए मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रिमण्डल में अन्तर स्पष्ट करते हुए मन्त्रिपरिषद् का विधानमण्डल तथा मुख्यमन्त्री से सम्बन्ध विवेचित है।

अध्याय चतुर्थ पचम् एव षष्ठम् में मन्त्रिपरिषद् की जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, शैक्षणिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के साथ ही स्त्री-पुरुष (लैंगिक विभिन्नता) का उल्लेख किया गया है। चूँकि नीति निर्माताओं के आचार-विचार एवं कार्य-व्यवहार को ये परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं, अतः इनको प्राप्त अभिलेखों प्रश्नों के माध्यम से मतदाताओं के उत्तरों आदि के आधार पर अलग-अलग तालिका द्वारा विवेचित-विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक परिवर्तनों की सरिणी के आधार पर विश्लेषणात्मक निष्कर्ष भी अत्यन्त संक्षेप में वही पर दिए गए हैं, यद्यपि उपसंहार सम्बन्धी अध्याय में समग्ररूप से निष्कर्ष विवेचित है।

सप्तम् अध्याय में मन्त्रिपरिषद् एवं विधान सभा-विधान परिषद् के मध्य सम्बन्ध को मुख्यतया इस आधार पर देखने का प्रयास किया गया है कि मन्त्रिपरिषद् में उक्त दोनों सदनों से कितनी संख्या में सदस्य लिए गए हैं। उनका आपस में अनुपात क्या है ?

मन्त्रिपरिषद् में दलीय स्थिति का ऑकलन/विवेचन को अष्टम् अध्याय का विषय बनाया गया है। इस अध्याय की प्रासंगिकता एवं महत्व इसलिए भी है कि निर्धारित कालखण्ड में निर्मित सरकारें बहुधा विभिन्न दलों के सहयोग से बनी थीं और उनके दल के विधायकगण मन्त्री बने थे।

उपसंहार के रूप में निर्धारित नवम् अध्याय में सम्पूर्ण शोध-प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायों में विवेचित परिवर्तनों का निष्कर्ष एवं विश्लेषण के पश्चात् वांछित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का प्रणयन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ० आलोक पन्त के कुशल, विद्वतापूर्ण निर्देशन में सम्पन्न हुआ है। यदि मुझे उन जैसा गुरु न मिला होता तो मैं यह कार्य पूरा नहीं कर पाती। विद्या के सभी क्षेत्रों में समान रुचि रखने वाले समादरणीय गुरुवर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ।

अनन्तर आभारी हूँ डॉ० लाल साहब सिंह (रीडर, आर आर पी जी कॉलेज, अमेठी) जिनके प्रेरणा, सहयोग एवं प्रोत्साहन के बिना इस महायज्ञ की पूर्णाहूति असम्भव थी।

श्रद्धावन्त हूँ डॉ० पंकज कुमार एवं डॉ० अनुराधा अग्रवाल (प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) के प्रति जिनके आत्मीय सहयोग ने मुझे शोध कार्य की पूर्णता के लिए सतत उत्साहित किया।

अनेक अज्ञात तथ्यों पर प्रकाश डालने एवं शकाओं के समाधान के लिए प्रो० एस डी सिंह (समाज शास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी), डॉ० ए सी राव (विभागाध्यक्ष-सैन्य विज्ञान, आर आर पी. जी कॉलेज, अमेठी), डॉ० ललिता राव (प्रवक्ता-शिक्षा सकाय, यू० पी० कॉलेज, वाराणसी) जिनके दिशानिर्देश एवं परिश्रम को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती।

प्रस्तुत शोध सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मैं श्री एस के पाठक जी (बी एच यू पुस्तकालय) के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

मैं अपने विभाग के समस्त शिक्षाविदों एवं उन सभी विद्वानों के प्रति अपना अन्तरीण आभार प्रगट करती हूँ जिनके विचारों एवं ग्रन्थों से प्रत्यक्ष-परोक्ष सहायता लेकर मैं प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का निर्माण किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मेरे वन्दनीय, स्वर्गीय बाबू जी (डॉ० रामरूप सिंह, विभागाध्यक्ष, शिक्षा सकाय, आर आर पी जी कॉलेज, अमेठी) व श्रद्धेय अम्मा जी के असीम त्याग तप, अनथक परिश्रम, हित चिन्तना, शैक्षिक जागरुकता तथा शुभाशीर्वाद का प्रतिफलन है। इन्हीं की मूल प्रेरणा तथा हार्दिकेच्छा से मेरे इस स्वप्न को पूर्णता प्राप्त हो सकी।

मैं अपने चाचा जी (प्रो० सविन्द्र सिंह-विभागाध्यक्ष, भूगोल-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) के प्रति आभारी हूँ, जो शोधकार्य के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करते रहे।

मेरे पितृतुल्य श्री सूर्यनाथ सिंह एवं मातृतुल्य श्रीमती रानी सिंह के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ, जिन्होंने समय-समय पर अविस्मरणीय प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा स्नेह द्वारा इस शोध कार्य के प्रति सदैव रुचि जागृत रखी। इनके प्रति औपचारिक आभार प्रदर्शन धृष्टता ही होगी।

मैं अपने भइया भाभी, अरविन्द-कल्पना की स्नेहच्छाया एवं सद्भावनाओं से भावाविभूत हूँ। अपने अग्रज तुल्य अजय एवं स्नेहिल रूपा तथा परिवार के सभी सदस्यों को अपने अन्तस् का 'सु-भाव' ही अर्पित कर सकती हूँ क्योंकि इन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अपने ही प्रति धन्यवाद प्रकट करना है।

अन्तोगत्वा शिव कुमार गुप्ता, दीपक सिंह (लेजर टाइपिंग एण्ड सेटिंग), तथा प्रवीण श्रीवास्तव (ग्राफिक्स) के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता है अतः इनको सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ।

दिनांक-

मनीषा सिंह .
(मनीषा सिंह)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ सख्या
प्राक्कथन :	I - V
अध्याय प्रथम : भूमिका एवं शोध विधि	1 - 22
अध्याय द्वितीय : उत्तर प्रदेश- एक पार्श्व चित्र	23 - 68
अध्याय तृतीय : मंत्रिपरिषद की संरचना	69 - 98
अध्याय चतुर्थ : मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जाति, धार्मिक एवं क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि	99 - 186
अध्याय पंचम् : मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक स्थिति	187- 242
अध्याय षष्ठम् : मंत्रिपरिषद में स्त्री- पुरुष का प्रतिनिधित्व	243 -273
अध्याय सप्तम् : मंत्रिपरिषद एवं विधानसभा - विधानपरिषद	274 - 291
अध्याय अष्टम् : मंत्रिपरिषद में सम्मिलित दलों की स्थिति	292 - 305
उपसंहार :	306 - 308

परिशिष्ट -

- I. मंत्रालयों की सूची
- II. मंत्रियों की सूची
- III. प्रश्नावली - सूची
- IV. सन्दर्भ - ग्रन्थ सूची

सारिणी सूची

क्र० स०	सारिणी विवरण	सारिणी स०	पृष्ठ स०
	I उत्तर प्रदेश एक पार्श्वचित्र		
1	जनसख्या -	2 1 1	30
2	जनसख्या - क्षेत्रीय वितरण	2 1.2	30
3	स्त्री-पुरुष अनुपात	2 1 3	31
4	साक्षरता	2.1 4	32
5	साक्षरता - क्षेत्रीय विवरण	2.1 5	34
6	धार्मिक संरचना	2 1 6	35
7	अनु जा. एवं अनु. ज जाति	2 1 7	36
8	जातीय संरचना	2.1 8	38
9	मतदाताओं की जाति संरचना	2 1 9	40
10	राजकीय आय : क्षेत्रों से	2.2 1	50
11	राजकीय आय कुल राष्ट्रीय आय के अनुपात में	2.2.2	51
12	कामगार	2.2.3	54
13	कामगार : ग्रामीण एवं शहरी	2 2.4	55
14	नगरी जनसंख्या	2 2.5	56
15	अर्थव्यवस्था व क्षेत्रीय वितरण	2.2.6	58

क्र० सं०	सारिणी विवरण	सारिणी सं०	पृष्ठ सं०
	II जाति पृष्ठ भूमि		
16	कल्याण सिंह(1991)	4 1 1	103
17	मुलायम सिंह यादव(1993)	4.1.2	106
18	मायावती (1995)	4.1 3	109
19	मायावती (1997)	4 1.4	112
20	कल्याण सिंह(1997)	4.1 5	116
21	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में समग्र रूप से	4.1.6	119
22	1991-1997 के मध्य विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जाति पृष्ठ भूमि	4.1.7	124
	III धार्मिक पृष्ठ भूमि		
23	कल्याण सिंह(1991)	4 2.1	135
24	मुलायम सिंह यादव(1993)	4 2.2	137
25	मायावती (1995)	4 2.3	140
26	मायावती (1997)	4.2 4	143
27	कल्याण सिंह(1997)	4.2.5	145
28	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद	4.2.6	148
29	1991-1997 विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद	4 2.7	153

क्र० स०	सारिणी देवरा	सारिणी स०	पृष्ठ स०
	IV क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि		
25	कल्याण सिंह(1991)	4 3.1	161
26	मुलायम सिंह यादव(1993)	4.3.2	164
27	मायावती (1995)	4.3.3	166
28	मायावती (1997)	4.3.4	169
29	कल्याण सिंह(1997)	4.3 5	171
30	सन् 1991 से 1997 के मध्य मंत्रियो परिषदो मे क्षेत्रिय प्रतिनिधित्व	4.3.6	176
	V शैक्षिक प्रस्थिति		
30	कल्याण सिंह(1991)	5.1.1	189
31	मुलायम सिंह यादव(1993)	5.1 2	192
32	मायावती (1995)	5.1.3	195
33	मायावती (1997)	5.1.4	199
34	कल्याण सिंह(1997)	5.1.5	202
35	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद	5 1.6	206
36	शैक्षिक प्रस्थिति विधानसभा एवं मन्त्रिपरि	5.1.7	211

क्र० सं०	सारिणी विवरण	सारिणी सं०	पृष्ठ सं०
	VI व्यवसायिक पृष्ठ भूमि		
37	कल्याण सिंह(1991)	5 2 1	219
38	मुलायम सिंह यादव(1993)	5.2.2	223
39	मायावती (1995)	5 2 3	227
40	मायावती (1997)	5 2.4	230
41	कल्याण सिंह(1997)	5 2 5	233
42	सन् 1991 से 1997 के मध्य मंत्रियो परिषदों में व्यवसायिक प्रतिनिधित्व	5.2.6	237
	VII मंत्री परिषद में स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व		
43	कल्याण सिंह(1991)	6.1	249
44	मुलायम सिंह यादव(1993)	6.2	252
45	मायावती (1995)	6.3	254
46	मायावती (1997)	6.4	256
47	कल्याण सिंह(1997)	6.5	259
48	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद	6 6	262
49	शैक्षिक प्रस्थिति विधानसभा एवं मन्त्रिपरि. में स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व।	6.7	266

क्र० स०	सारिणी ।वेवर०	सारिणी स०	पृष्ठ स०
50	स्त्री प्रतिनिधित्व - दल	6 8.1	267
51	स्त्री प्रतिनिधित्व : धार्मिक प्रस्थिति	6 8 2	268
52	स्त्री प्रतिनिधित्व - जाति प्रस्थिति	6 8.3	269
53	स्त्री प्रतिनिधित्व - शैक्षिक स्तर	6 8.4	269
54	स्त्री प्रतिनिधित्व - व्यवसाय	6 8 5.	270
	VIII मंत्रिपरिषद मे विधान सभा एवं विधान परिषद से लिये गये सदस्य		
55	कल्याण सिंह(1991)	7 1	278
56	मुलायम सिंह यादव(1993)	7 2	279
57	मायावती (1995)	7.3	280
58	मायावती (1997)	7 4	281
59	कल्याण सिंह(1997)	7 5	282
	IX मंत्रिपरिषद मे सम्मिलित दलो की स्थिति		
60	कल्याण सिंह(1991)	8 1	295
61	मुलायम सिंह यादव(1993)	8 2	296
62	मायावती (1995)	8 3	297
63	मायावती (1997)	8 4	299
64	कल्याण सिंह(1997)	8 5	300

रेख।चेत्र सूची

क्र० स०	रेखाचित्र- विवरण	रेखाचित्र सं०	पृष्ठ स०
I	मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की जातीय पृष्ठ भूमि		
1	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद।	4 1 1 (अ)	104
2	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 1 1 (ब)	104
3	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद।	4 1 2 (अ)	107
4	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 1 2 (ब)	107
5	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद।	4 1 3 (अ)	110
6	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 1 3 (ब)	110
7	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद।	4 1 4 (अ)	113
8	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 1 4 (ब)	113
9	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद।	4 1 5 (अ)	117
10	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 1 5 (ब)	117
11	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद में उच्चजाति के सदस्य	4 1 6 (अ)	121

क्र० सं०	रेखाचित्र 1 वेवरु	रेखाचित्र सं०	पृष्ठ सं०
12	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद् मे मध्यम जाति के सदस्य	4 1 6 (ब)	123
13	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद् मे अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्य	4 1 6 (स)	125
II	मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की धार्मिक पृष्ठ भूमि		
14	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्।	4 2 1 (अ)	136
15	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 2 1 (ब)	136
16	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्।	4 2 2 (अ)	138
17	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 2 2 (ब)	138
18	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्।	4 2 3 (अ)	141
19	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 2 3 (ब)	141
20	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्।	4 2 4 (अ)	144
21	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 2 4 (ब)	144
22	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्।	4 2 5 (अ)	146

क्र० सं०	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं०	पृष्ठ सं०
23	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यों की	4 2 5 (ब)	146
24	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद में हिन्दू सदस्य	4 2 6 (अ)	150
25	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद में मुस्लिम सदस्य	4 2 6 (ब)	152
26	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद में अन्य सदस्य	4 2 6 (स)	154
III	मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठभूमि		
27	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	4 3 1	162
28	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	4 3 2	165
29	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	4 3 3	167
30	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	4 3 4	170
31	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	4 3 5	172
32	सन् 1991 से 1997 के मध्य मंत्रिपरिषद में उत्तरांचल का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (क)	176
33	सन् 1991 से 1997 के मध्य मंत्रिपरिषद में पश्चिमांचल का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (ख)	178

क्र० सं०	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं०	पृष्ठ सं०
34	सन् 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रिपरिषद् में मध्याह्न का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (ग)	180
35	सन् 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रिपरिषद् में बुदेलखण्ड का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (घ)	182
36	सन् 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रिपरिषद् में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (ङ)	184
IV	मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति		
37	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्।	5 1 1 (अ)	190
38	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	5 1.1 (ब)	190
39	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्।	5 1 2 (अ)	193
40	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	5 1 2 (ब)	193
41	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्।	5 1 3 (अ)	196
42	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	5 1 3 (ब)	196
43	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्।	5 1 4 (अ)	200
44	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	5 1 4 (ब)	200

क्र० सं०	रेखाचित्र: विवरण	रेखाचित्र सं०	पृष्ठ सं०
45	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	5 1 5 (अ)	203
46	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यों की	5 1 5 (ब)	203
47	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद में इण्टरमीडिएट तथा कम शैक्षिक स्तर वाले सदस्य	5 1 6 (अ)	208
48	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद में स्नातक स्तरीय शैक्षिक स्तर वाले सदस्य	4 3 6 (ब)	210
49	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद में स्नातकोत्तर एवं पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक स्तर वाले सदस्य	4 3 6 (स)	212
V	मंत्रिपरिषद के सदस्यों की व्यवसायिक पृष्ठभूमि		
49	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	5 2 1	221
50	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद	5 2 2	225
51	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	5 2 3	229
52	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	5 2 4	232
53	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	5 2 5	235
VI	मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व		
54	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद।	6 1 (अ)	251

क्र० सं०	रेखाचित्र लेख	रेखाचित्र सं०	पृष्ठ सं०
55	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	6 1 (ब)	251
56	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद्।	6 2 (अ)	253
57	मुलायम सिंह यादव (1993) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	6 2 (ब)	253
58	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद्।	6 3 (अ)	255
59	मायावती (1995) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	6 3 (ब)	255
60	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद्।	6 4 (अ)	257
61	मायावती (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	6 4 (ब)	257
62	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद्।	6 5 (अ)	260
63	कल्याण सिंह (1997) के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् के साथ विधान सभा के सदस्यों की	6 5 (ब)	260
64	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद् में पुरुष सदस्य	6 6 (अ)	264
65	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद् में स्त्री सदस्य	6 6 (ब)	265

क्र० सं०	रेखाचित्र १.८१५	रेखाचित्र सं०	पृष्ठ सं०
VII	मंत्रिपरिषद में विधानसभा तथा विधान परिषद से लिये गये सदस्य		
66	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्गित) मंत्रिपरिषद में विधान सभा के सदस्य	7 1 1	283
67	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्गित) मंत्रिपरिषद में विधान परिषद के सदस्य	7 1 2	285
68	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्गित) मंत्रिपरिषद में विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्य संयुक्त रूप से	7 1 3	287
69	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्गित) मंत्रिपरिषद में विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का उतार चढ़ाव।	7 1 4	289

પ્રથમ અધ્યાય

ભૂા.-૯૩ ંવં શોધ વિધિ.

भूमिका एव शोध—विधि

भारतवर्ष विश्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ससदीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है और उत्तर-प्रदेश इसका ऐसा राज्य है जो प० नेहरू से लेकर प० अटल बिहारी वाजपेयी तक के अधिकांश प्रधानमन्त्री देश को दिए हैं। इस प्रदेश ने देश की राजनीति को सर्वदा एक नई दिशा और दशा प्रदान की है, जिसके कारण यह राजनीतिक क्षितिज पर अत्यन्त आदरास्पद रहा है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय शासन की प्रकृति और प्रवृत्ति ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था पर ससदात्मक पद्धति पर अवलम्बित है। ब्रिटेन में ससदीय प्रभुता का सिद्धान्त, यद्यपि की सिद्धान्त स्वीकृति एव स्थापित माना जाता है, तथापि वस्तुतः वहाँ मन्त्रिमण्डल और प्रधानमन्त्री की सम्प्रभुता ही विद्यमान है। यही कारण है कि मन्त्रिपरिषद् को 'राज्य—रूपी जहाज का परिचालक चक्र' (रैम्जे म्योर), 'सरकार का केन्द्रीय निर्देशक' (ऐमरी) और ऐसा 'शक्ति—पुज' जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यन्त्र घूमता है (जॉन मेरियट)। लावेल ने इसे 'राजनीतिक भवन की आधारशीला' (द गवर्नमेण्ट ऑफ इंग्लैण्ड, खण्ड—1 पृ०—57) कहा है। इसी प्रकार, प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डल का अधिपति (रैम्जे म्योर), नक्षत्रों की बीच चन्द्रमा (सर विलियम हार कोर्ट), वह सूर्य—पिण्ड, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं (ग्लैडस्टोन) तथा सम्पूर्ण शासन तन्त्र की धुरी (लास्की—रिप्लेक्शन ऑन द कान्स्टीट्यूशन, पृ० 239) कहा गया है।

मन्त्रिपरिषद् का निर्माण प्रधानमन्त्री के लिए एक अत्यन्त दुष्कर एव दुरूह कार्य होता है। उसे मन्त्रिपरिषद् के गठन में अनेक क्षेत्रीय, गुटीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्थितियों—परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। लावेन ने इस

सन्दर्भ में ठीक ही लिखा है, “मन्त्रिमण्डल का निर्माण प्रधानमन्त्री का ऐसा कार्य है, जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लाको की सहायता से, जो एक-दूसरे से मेल न खाते हो, एक चित्र तैयार करना है।”¹

ब्रिटेन के सन्दर्भों में ही भारतीय मन्त्रिपरिषद की संरचना और उसमें प्रधानमन्त्री की भूमिका को समझना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के समान ही राज्य सरकारों के अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद की संरचना और मुख्यमन्त्री की भूमिका होती है। वर्तमान में, केन्द्र और उत्तर प्रदेश में जो मन्त्रिपरिषदीय संरचना है, वह प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री की भूमिका को अधिक सश्लिष्ट एवं दुष्कर बनाती हैं, क्योंकि उक्त दोनों स्तरों पर अनेक प्रकार के दलों की मिली-जुली सरकारें हैं।

उत्तरप्रदेश में आए दिन सरकारें बन-बिगड़ रही हैं। शोधकर्त्ता ने मन्त्रिपरिषद की सत्ता और महत्ता को दृष्टि में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद की संरचनात्मक संख्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु प्रस्तुत विषय का चयन किया है। इस विषय का जब निर्धारण किया गया था, उस समय प्रदेश की मन्त्रिपरिषद को विशाल संख्या की दृष्टि से ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद’ कहा जा रहा था। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की मन्त्रिपरिषद का गठन अनावश्यक माना गया। यह सब राजनीतिक सौदेबाजी, तुष्टीकरण, कुर्सी बचाने की लिप्सा और सत्ता की लोलुपता का परिणाम है। अच्छे-बुरे या राष्ट्रीय हित-अहित का ध्यान न देते हुए विचारधारा विहीन, विभिन्न दलों के बागी, अपराधी पृष्ठभूमि वाले दलीय तथा निर्दलीय विधायकों को मन्त्रि-पद अत्यन्त सरलता से प्रदान कर संख्यात्मक गणित के आधार पर सरकारें बनायी जा रही थी (और वर्तमानतः भी यही स्थिति है)।

शोध विषय के अन्तर्गत सन् 1991 से 1997 तक का काल—विशेष निर्धारित है, क्योंकि इस कालखण्ड में प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता, परिवर्तन, मूल्यहीनता, अवसरवादिता आदि का नग्न प्रदर्शन हुआ। नए प्रयोग का नाम देकर और प्रदेश को बार—बार चुनावी खर्च से बचाने के बहाने नेतागण अपनी सम्पूर्ण शक्ति और बौद्धिकता का प्रयोग सरकार बनाने और उसे बचाने में ही लगा रहे हैं, राष्ट्रीय हित या विकास का प्रश्न गौड़ हो गया है।

सन् 1991 से 1997 तक के काल में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मन्त्रिपरिषद् बनी। 1991 में भाजपा, 1993 में सपा (बसपा समर्थित), 1995 में बसपा (भाजपा समर्थित), 1997 में पुनः छ—छ महीने के लिए भाजपा—बसपा की मिली—जुली सरकार बनी। बसपा के कोटे के छ महीने व्यतीत होने के पश्चात्, जब भाजपा का शेष छ महीने का कार्यकाल श्री कल्याण सिंह के मुख्यमन्त्री के रूप में प्रारम्भ हुआ, तो परस्पर विद्वेष और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण बसपा समर्थित भाजपा सरकार एक महीने भी नहीं चल पायी और अन्ततः अन्य दलों के जोड़—तोड़ से जेम्बो मन्त्रिमण्डल बनाकर भाजपा ने सरकार बनायी। विधानसभा अध्यक्ष को अत्यन्त कौशल का परिचय देते हुए इस प्रकार की सरकार को बचाए रखना पड़ा।

इस काल—खण्ड की सरकारें राजनीतिक अवसरवादिता की द्योतक रही हैं। सत्ता के लिए सिद्धान्तहीनता, खरीद—फरोख्त, अशोभनीय आचरण और लोकतन्त्र के उपहास का दृश्य सर्वत्र परिलक्षित होता रहा था (हैं)। लोकतन्त्र और लोकमत के प्रति राजनेताओं का उपेक्षात्मक दृष्टिकोण, सवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन और कुर्सी तथा वोट की राजनीति के विकृत रूप—स्वरूप को देखकर देश और प्रदेशवासी का चिन्तित होना स्वाभाविक है।

राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण शोधार्थिनी ने प्रदेश की मन्त्रिपरिषद की संरचना की राजनीति को गहराई से जानने-समझने की जिज्ञासा के शमन हेतु इस विषय को अध्ययन का प्रतिपाद्य बनाया है। यह प्रश्न अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न करता है कि संविधान की व्यवस्थाओं के होते हुए भी मन्त्रिपरिषद की संरचना में गैर राजनीतिक और गैर संवैधानिक या संविधानेतर वे कौन से अदृश्य कारक हो सकते हैं, जो पूरी संरचना की राजनीति को प्रभावित करते हैं?

शोधार्थिनी की मान्यता है कि हमारा संविधान बुरा नहीं है। इसकी व्यवस्थाएँ देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बनायी गयी थी और उसमें यथोचित संशोधन की व्यवस्था भी है। इन समस्त राजनीतिक अधःपतन के कारण के रूप में संविधान को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। डा० राजेन्द्र प्रसाद, ने संविधान निर्मात्री सभाध्यक्ष के रूप में अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए कहा था कि “संविधान, जो कुछ भी व्यवस्था दे पाता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश का प्रशासन कैसे चलाया जाता है। यह उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि जो प्रशासन में लगे हुए हैं।

निर्वाचित सदस्य यदि सक्षम हैं, योग्य हैं, उच्च चरित्र वाले हैं, तो वे त्रुटियुक्त संविधान से भी अच्छा परिणाम निकाल सकते हैं। और यदि उनमें इन गुणों का अभाव है तो (अच्छा से अच्छा) संविधान देश की कोई सहायता नहीं कर सकता है। अन्ततः संविधान एक यन्त्र की भाँति निर्जीव वस्तु होता है। इसे जीवन, इसको चलाने वाले प्रदान करते हैं। आज भारत को ईमानदार व्यक्तियों (प्रशासकों) के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहिए ।” डा० राजेन्द्र प्रसाद के कथन से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि राजनेताओं का चरित्र ही देश और प्रजातन्त्र के लिए सम्बल बनता है। संविधान तो मात्र मार्ग निर्देशन करता है, उस निर्देशित मार्ग पर ईमानदारी से चलाना सुदृढ़ इच्छा-शक्ति पर निर्भर करता है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरचना के यथार्थ को जानने के लिए सवैधानिक उपबन्धों, विद्वानों और समीक्षकों की महत्त्वपूर्ण पुस्तकों, ससदीय प्रतिवेदनो आदि को आधार बनाकर अध्ययन करने से कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती है। इससे मात्र सवैधानिक स्वरूप ही ज्ञात हो सकता है, यथार्थ नहीं। हमें यथार्थ को जानने के लिए अन्य कारकों का विवेचन और विश्लेषण करना होगा।

जहाँ तक शोध-विधि के प्रयोग का प्रश्न है, शोधार्थिनी द्वारा राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अद्यतन प्रयुक्त किए जाने वाले शोध-पद्धतियों का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात् ही 'सरचनात्मक सख्यात्मक दृष्टिकोण' को स्वीकार किया गया है, जो ग्राहम वालास, डेविड ईस्टन तथा आमण्ड और पावेल जैसे राजनीतिविदों द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। संक्षेप में, विभिन्न शोध-पद्धतियों के गुण और दोषों का विवरण इस प्रकार है—

राजनीतिक सस्थाओं एवं संगठनों के अध्ययन की परम्परा अति प्राचीन रही है। पाश्चात्य एवं भारतीय राजनीतिक सस्थाओं का अध्ययन निरन्तर होता रहा है। 1950 के पूर्व तक के राजनीतिक अध्ययन का दृष्टिकोण दार्शनिक, मूल्यपरक एवं आत्मपरक (वैल्यू लोडेड—सब्जेक्टिवटी) माना जाता है। इस प्रकार के अध्ययन विवरणात्मक एवं सस्थात्मक होते थे। इन्हें सवैधानिक, यान्त्रिक या कानूनी दृष्टिकोण कहा गया। इसके अन्तर्गत सवैधानिक व्यवस्था के आलोक में ही अध्ययन किए जाते थे, जो हमें सस्थाओं की ऐतिहासिक विकास यात्रा तथा सवैधानिक स्थिति का ज्ञान तो प्रदान करते हैं परन्तु इनमें तथ्यपरकता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता का सर्वथा अभाव ही परिलक्षित होता था। यथार्थ—स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो पाता था। इस प्रकार के अध्ययन को सत्यता से परे और भ्रामक कहा³ गया है। इस प्रकार

3- लोवस्टाइन कार्ल-‘रिपोर्ट ऑन द रिसर्च पैनल आन कम्परेटिव गवर्मेण्ट’-(अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू,

की अध्ययन पद्धति सस्थाओं के औपचारिक स्वरूप को ही प्रकाशित कर पाती है। यह सत्य है कि इस उपागम ने आदर्श व्यवस्था की खोज के लिए सराहनीय प्रयास तो अवश्य किए किन्तु इस बात की ओर सम्भवतः यह ध्यान नहीं दे सके कि सरकारें या राजनीतिक सस्थाएँ वास्तव में किस प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपना कार्य करती हैं।

राजनीतिक शब्द की व्यापकता का प्रयोग प्रथमतः हमें अरस्तू के चिन्तन में परिलक्षित होता है। अरस्तू ने अपने राज्य की परिभाषा में परिवार, नगर-निगम, समूह और धर्म आदि को सम्मिलित करते हुए बताया था कि राजनीति की परिधि में राष्ट्रीय राज-व्यवस्थाएँ, नागरिक और अन्तर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्थाएँ, पैतृक व्यवस्था, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन और कर्मचारियों के संगठन सभी आते हैं।⁴ अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया था कि विधियों की विविध भौतिक तथा सस्थागत परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए और श्रेष्ठ शासन इसी सापेक्ष में श्रेष्ठ होना चाहिए। अरस्तू ने जलवायु तथा राष्ट्रीय चरित्र के सम्बन्ध का भी भली-भाँति निरूपण कर दिया था।⁵ इस प्रकार कहा जा सकता है कि अरस्तू द्वारा राज्य और राजनीति की लगभग वही व्याख्या की गयी थी, जो वर्तमान में आधुनिक राजनीतिक समीक्षकों ने की है।

आधुनिक लेखकों में बोदा ने इस सकल्पना पर अपने विचार व्यक्त किए। परन्तु अरस्तू तथा बोदा इन दोनों में से किसी ने भी व्यापक पैमाने पर अनुसंधान का प्रयास नहीं किया।⁶ मैकियावेल द्वारा प्रस्तुत अध्ययन की पद्धति में वर्तमान युग की

4- पोलिटिकल थ्योरी - *व्हाट इज इट?* (गोल्ड तथा थर्सबी द्वारा सम्पादित-पोलिटिकल साइन्स, क्वार्टरली, खण्ड-72, अंक-1, मार्च 1957, पृष्ठ 1-29)।

5- सेबाइन जार्च एच० - *राजनीतिक दर्शन का इतिहास*, एस० चन्द एण्ड क०, दिल्ली, 1970, पृष्ठ 515।

6- जार्च एच० सेबाइन- *राजनीतिक दर्शन का इतिहास*, एस० चन्द एण्ड क०, दिल्ली, 1970, पृष्ठ 516।

परिशुद्ध वैज्ञानिक शोध-शैलियों की पृष्ठभूमि माना जा सकता है।⁷ इसके बाद माण्टेस्क्यू (1688-1755) की रचना 'स्पिरिट ऑफ द लॉज' में अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण तथा निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय पद्धति का समर्थन किया गया है।

माण्टेस्क्यू ने सरकार को समाजशास्त्र और परिस्थिति के तथ्य के रूप में (ए मैटर ऑफ सोशियोलॉजी एण्ड इकोलॉजी के रूप में) प्रस्तुत करते हुए "जलवायु तथा भूमि जैसी भौगोलिक दशाएँ, जो राष्ट्रीय चरित्र पर सीधा प्रभाव डालती हैं, कला, उद्योग तथा उत्पादन की पद्धतियों, मानसिक तथा नैतिक मनोवृत्तियों, प्रथाओं तथा आदतों काराष्ट्रीय चरित्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान माना है।⁸ उसकी मान्यता थी कि सांस्कृतिक मामले (रीति रिवाज, धर्म), आर्थिक तत्व (व्यापार, वाणिज्य, गरीबी, कृषि आदि), परिस्थितिजन्य कारक (जलवायु, भूमि, जनसंख्या आदि) राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वह मानता है कि भौतिक, मानसिक तथा सस्थागत परिस्थितियों की उपयुक्तता अथवा सम्बन्ध ही विधि की अन्तरात्मा है।

स्पष्ट है कि माण्टेस्क्यू ने राजनीतिक सस्थाओं के सरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया। इस प्रकार, यह उस सरचनात्मक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, जिसे आमण्ड आदि आधुनिक राजनीतिक समीक्षकों ने माना है। जे०सी० मार्श ने माण्टेस्क्यू द्वारा प्रयोग किए गए प्रतिमानों को विवेकपूर्ण प्रतिमान कहा है।⁹ परन्तु, माण्टेस्क्यू के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि यह शैली सीमित हो गयी।

7- इक्स्टाइन तथा एप्टर- *कम्परेटिव पॉलिटिक्स*, न्यूयार्क, 1973, पृ० 7।

8- सेबाइन जार्ज एच० - *राजनीतिक दर्शन का इतिहास*, एस० चन्द एण्ड क०, दिल्ली, 1970, पृ० 513।

9- मार्श जे० सी - *एस्से ऑन बिहैविरियल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स*, अर्बाना, इल्लिनाय यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962, पृ० 103।

आधुनिक विचारको ने परम्परागत राजनीतिक अध्ययन की ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक और वर्णनात्मक अवधारणा के स्थान पर पुनः यथार्थवादी वैज्ञानिक शोध-विधि की आवश्यकता पर बल दिया। जेम्स ब्राइस ने इसी सन्दर्भ में कहा है कि “उसका उद्देश्य अमरीका की सस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है, जैसे वे हैं निगमनात्मक प्रणाली के प्रलोभनों को दूर रखना और घटना सम्बन्धी तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना है।”¹⁰ ग्राहम वालास (1908) ने अपनी रचना ‘ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स’ में राजनीति के लगभग सभी विद्यार्थियों द्वारा सस्थाओं के विश्लेषणात्मक विश्लेषण करने और व्यक्ति के विश्लेषण को टाल जाने की बात कहते हुए अध्ययन की मनोवैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया है।¹¹ बेजहॉट (1965-66) ने अपनी रचना ‘द इंगलिश कान्स्टीट्यूशन’ में इंग्लैण्ड की राजनीतिक सस्थाओं पर उसकी सामाजिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तार से वर्णन किया था और यह बताने की चेष्टा की कि राजनीतिक सस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ क्यों न हों उनके पिछे एक ‘अदृश्य राजनीतिक प्रक्रिया’ काम करती है और वास्तव में वही प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के अनुरक्षण में योगदान करती है।

बैण्टले¹² ने मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रणालियों पर बल देते हुए परिमाणीकरण और मापन में विश्वास व्यक्त किया। चार्ल्स ई० मेरियम तथा हेनरी एल्मर ने राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या और उनके आकार और गठन के सन्दर्भ में करने की अपेक्षा उन मनोवैज्ञानिक शक्तियों के अध्ययन के आधार पर

10- ब्राइस जेम्स - *द अमेरिकन कॉमनवेल्थ*, खण्ड-1, द मैकमिलन क०, न्यूयार्क, 1926, पृ० 2।

11- वालास ग्राहम - *ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स*, कौस्टेब्ले, न्यूयार्क, 1942, पृ० 18।

12- बैण्टले- *द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट*, ईवानस्टन, इलीनाय, 1809, पृ० 162

करने पर अधिक बल दिया, जो उन्हें प्रभावित करती है।¹³ मैरियम मानता है कि राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगोल, मानव-जाति-विज्ञान, जीवशास्त्र और सांख्यिकी के द्वारा आविष्कृत प्राविधियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।¹⁴ इस प्रकार, मैरियम ने सहकारी शोध और सहयोगात्मक प्रयत्न को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।

राजनीतिक विज्ञान को राज्य या सरकार के अध्ययन-क्षेत्र से बाहर लाकर विस्तृत फलक प्रदान करते हुए चार्ल्स हाइनेमन ने कहा कि, “राजनीतिशास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें सस्थात्मक संगठन, निर्णय-निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियन्त्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों और विधिबद्ध प्रशासन के मानवी वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा है।¹⁵” कैटलिन ने अन्तःशास्त्रीय उपागम पर बल दिया।¹⁶ इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक सस्थाओं के औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अतिरिक्त अब सस्थाओं के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करने के रूप में वातावरण तथा सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं आदि को जानना आवश्यक बताया गया।

परम्परागत शोध-विधि के असन्तोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणामस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में परिवर्तन आया, जिसका सम्पूर्ण श्रेय व्यवहारवादियों

13- मैरियम चार्ल्स ई० तथा हेनरी एल्मर बर्न्स (स०)- *ए हिस्ट्री पोलिटिकल थ्योरीज ऑफ रीसेन्ट टाइम्स*, न्यूयार्क, 1924, पृ० 19।

14- मैरियम चार्ल्स ई० - *द प्रजेन्ट स्टेट ऑफ द स्टडी ऑफ पालिटिक्स* (अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू, खण्ड-15, स० 1, 1921, पृ० 173-185)।

15- हाइनेमन सी०एस० - *द स्टडी ऑफ पालिटिक्स द प्रजेन्ट स्टेट ऑफ अमेरिकन पोलिटिक्स साइन्स*, अब्रीना, इलीनाय, वि०वि० प्रेस 1959, पृ० 40

16- कैटलिन जी०ई०जी० - *द साइन्स ऑफ मेथेड ऑफ पॉलिटिक्स*, केगन पॉल, लन्दन, 1927, पृ० 2

को दिया जा सकता है।¹⁷ 1850 ई० से पूर्व जो प्रागनुभविक और निगमनात्मक पद्धतियाँ प्रचलित थी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जो ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रचलन हुआ, उनकी तुलना से अब आधुनिक पद्धतियों में प्रेक्षण, सर्वेक्षण और मापन के प्रति एक स्पष्ट प्रकृति का विकास होने लगा।¹⁸ इस प्रकार वर्तमान में प्रचलित वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति की उपादेयता असंदिग्ध है।

लावेल ने अपनी अनेक रचनाओं में परम्परागत शोध-विधि के स्थान पर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पद्धति पर व्यापक चिन्तन किया है। उसका मत था कि परम्परावादी यह मान लेते हैं कि पुस्तकालय ही राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है, मौलिक स्रोतों का एकमात्र भण्डार है और आधारभूत सामग्री का संग्रहालय है। परन्तु, अधिकांश बातों के लिए पुस्तकें राजनीतिक संरचना को समझने के लिए मौलिक स्रोतों के रूप में कम उपयोगी होती हैं। पुस्तकालय को राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक संचालन को समझने के लिए प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में नहीं माना जा सकता। यह स्थान तो सार्वजनिक जीवन की बाहरी दुनिया को ही दिया जा सकता है। घटनाएँ अपने वास्तविक रूप में वही घटती हैं। उनके मूल उद्गम को हमें वही तलाश करना चाहिए।¹⁹ शासन के वास्तविक यन्त्र को तभी समझा जा सकता है, जब उसे उसकी क्रियाशील अवस्था में देखा जाय।²⁰ प्रत्येक घटना एक ऐसा तथ्य

17- पैट्रिक ए०एम० कर्क - *एस्सेज ऑन द बिहैवियरियल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स* (आस्टिन रैनी द्वारा स० - द इन्सैक्ट ऑफ द बिहैवियरियल एप्रोच ऑफन ट्रेडिशनल पोलिटिकल साइन्स, अर्बाना, इल्लिनाय, 1962, पृ० 10-11)।

18- गेटेल रेमेण्ड जी० - *हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पोलिटिकल थॉट*, न्यूयार्क, 1928, पृ० 611।

19- लॉवेल ए०एल० - *द फिजियोलॉजी आफ पॉलिटिक्स*, (अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स निव्यू, खण्ड 4, फरवरी 1910, पृ०-16)

20- लॉवेल ए०एल० - *एस्से ऑन गवर्नमेण्ट*, बोस्टन, 1889, पृ०-1

ब्लान्डल का उपर्युक्त विचार वस्तुतः ईस्टन के इस कथन के परिप्रेक्ष्य में एक व्याख्या है कि 'राजनीतिक मूल्यों का अधिकारिक आवटन है।' स्पष्ट है कि ब्लान्डल ईस्टन की अवधारणा से सहमत है और उसके अध्ययन पर विशेष रूप से बल देता है। इस प्रकार वह आधुनिक शोध में सैद्धान्तिक सन्धारो (थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क) पर ध्यान देने का आग्रह करता है।

माइकल ओकशॉट की मान्यता है कि "राजनीतिक क्रियाओं में मनुष्य ऐसे समुद्रों में जाता है जिसकी थाह नहीं है, जिसकी आरम्भ तथा अन्त नहीं है। केवल सदैव तैरना ही है। साथ ही समुद्र मित्र भी है और शत्रु भी।"²⁴ ब्रेवण्टी भी सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सदर्भ में राजनीतिक अध्ययन की बात करते हुए, "तुलनात्मक राजनीति को सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान व व्याख्या मानता है जो राजनीतिक कार्य और उसके सस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं।"²⁵ स्पष्ट है कि ओकशॉट के लिए राजनीतिक क्रिया अनन्त और असीम समुद्र की भाँति व्यापक और गहन है तो ब्रेवण्टी सामाजिक व्यवस्था में ऐसे निहित तत्वों की खोज पर बल देता है, जो राजनीतिक संरचना को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करते हैं।

राजनीतिक विज्ञान में शोध-विधि के सन्दर्भ में 'सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त' का विशेष महत्व है। यह संकल्पना सर्वप्रथम 1920 ई० के दशक में लुडविग वॉन बर्टलनफी नामक प्रसिद्ध जीवशास्त्री की रचना²⁶ में पायी जाती है, जहाँ से वह मानव-विज्ञान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अन्त में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में

24- ओकशॉट माइकल - *पोलिटिकल एजुकेशन*, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 1959, पृ०-15

25- ब्रेवण्टी रॉल्फ - *कम्परेटिव पोलिटिकल एनालिसिस, री कान्सीडरेशन*, अमेरिकन जर्नल ऑफ पोलिटिकल एण्ड सोशल साइन्स, न० 39, फरवरी, 1968, पृ०-36

26- बर्टलनफी लुडविग वॉन - *जनरल सिस्टम, खण्ड 1*, 1956, पृ० 1-10

समाविष्ट हुई। राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था सिद्धान्त को डेविड ईस्टन और ग्रेबियल आमण्ड (सरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त) तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मार्टन कैप्लान से सम्बद्ध माना जाता है। व्यवस्था का तात्पर्य बहुत से ऐसे तत्वों का एक साथ पाया जाना है जिनका एक दूसरे के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया का सम्बन्ध हो।²⁷ राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में अन्त क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं।²⁸ तात्पर्य यह कि किसी क्रिया के सम्पादन हेतु आवश्यक विभिन्न तत्वों का समूह ही व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था भी समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के अन्त क्रियाओं का समुच्चय है।

डेविड ईस्टन व्यवस्था विश्लेषण को सामाजिक और राजनीतिक शोध की विधि मानता है। उसने 1953 में 'द पोलिटिक सिस्टम' शीर्षक²⁹ से पुस्तक भी लिखी, जो इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसी पुस्तक में व्यवहारवादी उपागम की वृहद रूप से चर्चा की गयी थी, जिसे बाद में उसने 'एक फ्रेमवर्क फॉर पोलिकल एनालिसिस' में पृथक् रूप में व्याख्यायित किया।³⁰ उसने सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन को व्यवहार की एक राजनीतिक व्यवस्था मानते हुए लिखा है कि, राजनीतिक जीवन राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत, जो पर्यावरण को प्रभावित करता है, व्यवहार की एक प्रक्रिया है।³¹ व्यवस्था विश्लेषण में वह व्यवस्था, पर्यावरण, प्रतिक्रिया और

27- बर्टलनफी लुडविग वॉन - वहीं - पृ0 31

28- ईस्टन डेविड - *ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पोलिटिकल लाइफ*, जॉन वाहली एण्ड सन्स, न्यूयार्क, 1965, पृ0 50

29- ईस्टन डेविड - *द पोलिटिकल सिस्टम*, अल्फ्रेड ए0 नॉफ, न्यूयार्क, 1953

30- ईस्टन डेविड - *ए फ्रेम वर्क फॉर पोलिटिकल एनालिसिस*, प्रेन्टिस हॉल, इंग्लैण्ड, लन्दन, 1965, पृ0 1-22

31 ईस्टन डेविड - *ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पोलिटिकल लाइफ*, पृ0 181

प्रतिसम्भरण—चार तत्वों पर अधिक बल दिया है।³² इस प्रकार ईस्टन ने व्यवस्था—विश्लेषण को अत्यन्त विस्तार से प्रस्तुत किया है।

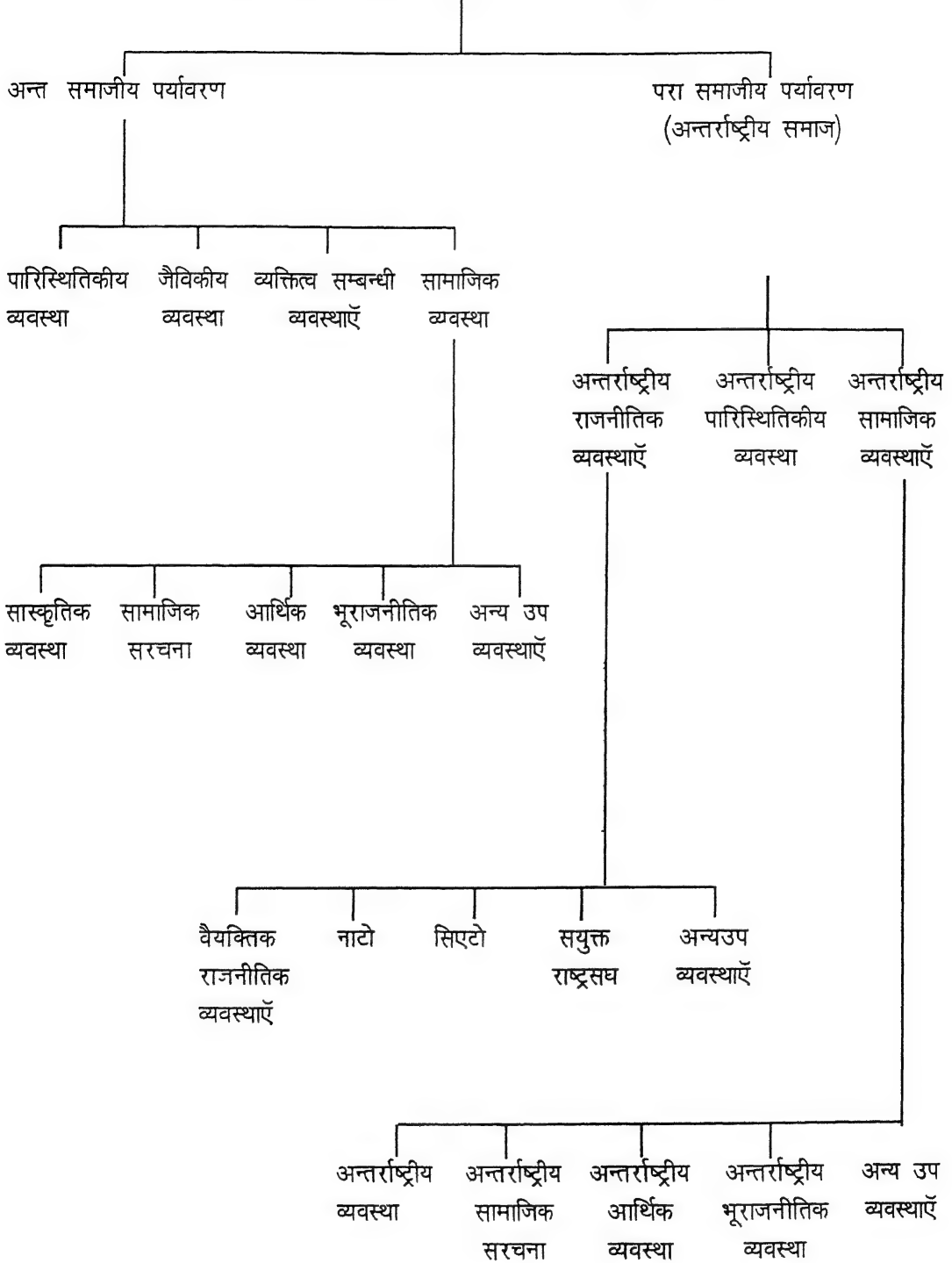
ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक आदि तत्वों को पर्यावरण के अन्तर्गत रखा है। संक्षेप में ईस्टन द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण की तालिका पृष्ठ संख्या 15 पर प्रस्तुत है।³³—

ईस्टन की इस तालिका से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण समाज एक व्यवस्था है, जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे—आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक और जैविक—व्यवस्थाओं से होता है। ये सभी व्यवस्थाएँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था समाज की अन्य सभी व्यवस्थाओं से अलग नहीं है। व्यक्ति का आचरण मात्र उसके राजनीतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों से ही प्रभावित नहीं होता है, वरन् रक्त सम्बन्ध, धर्म, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। ईस्टन ने पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था के मध्य होने वाले विनिमय (इक्सचेंज) को

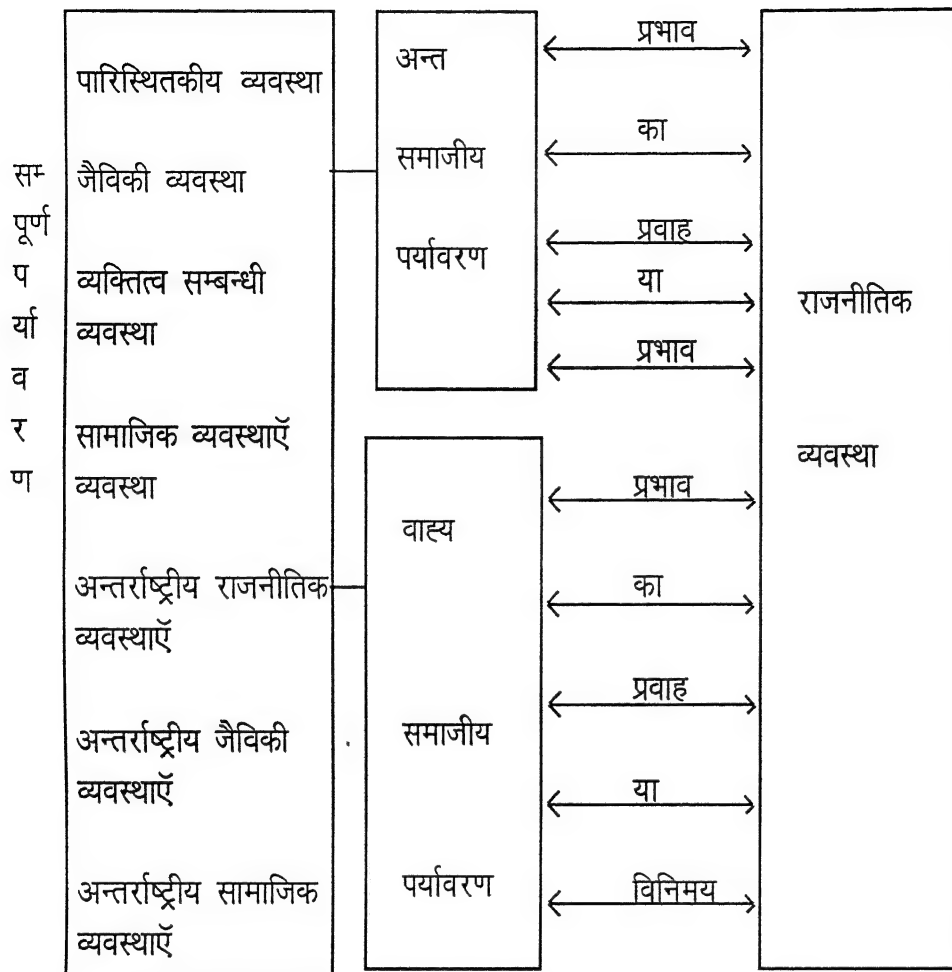
32 ईस्टन डेविड -ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पोलिटिकल लाइफ, पृष्ठ 24-25

33 ईस्टन डेविड -वहीं पृष्ठ 70- 70 (ऐबुल सं 1)

राजनीतिक व्यवस्था के समग्र पर्यावरण के तत्व



अधोलिखित तालिका मे स्पष्ट किया है³⁴ -



ईस्टन की पर्यावरण एव राजनीतिक व्यवस्था के मध्य प्रभाव से परस्पर विनिमय सम्बन्धी तालिका से यह भी पुष्टि हो जाती है कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण से पूर्णतया प्रभावित होती रहती है। अर्थात् राजनीतिक व्यवस्था के बाहर या परे दूसरी व्यवस्थाएँ अथवा पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को कमोबेश मात्रा मे सर्वदा प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को समाज मे होने वाली अन्त क्रियाओं की व्यवस्था कहा। ईस्टन यह भी कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था खुली हुई और अनुकूलनशील व्यवस्था होती है, इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण के मध्य चलने वाली गतिविधियों (क्रिया-प्रतिक्रिया)

पर निरन्तर ध्यान देते रहना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था अपने अन्तर्गत ऐसी बहुत सी क्रियाविधियों को विकसित कर लेती है, जिनके सहारे वह पर्यावरण के समक्ष टिके रहने का प्रयत्न करती है, अपना व्यावहारिक नियन्त्रण करती है और अपने आन्तरिक ढाँचे को बदल लेती है।

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष पर्यावरण से (प्रभावित होकर जनता द्वारा) कुछ माँगे रखी जाती है। इन माँगों के पीछे माँग रखने वालों का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन माँगों की ओर आकर्षित करता है। चूँकि, माँगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण से होता है, अतः माँगे राजनीतिक व्यवस्था को यह समझने में सहायता करती है कि किस प्रकार पर्यावरण सम्पूर्ण राजनीतिक तन्त्र पर अपना प्रभाव डालता है। इन्हीं सबके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के नीति या निर्णय निर्गत के रूप में आते हैं। पुनः प्रति सम्भरण के रूप में जनता तक ये नीति या निर्णय पहुँचते हैं और इनके पक्ष या विपक्ष में पुनः माँग या समर्थन का निर्माण होता है। इस प्रकार यह व्यवस्था निरन्तर चलती रहती है।

ईस्टन यह भी स्पष्ट करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था बाहर से आने वाले व्यवधानों के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करे। सम्भव है कि वह पर्यावरण से आने वाले सभी प्रभावों से अपने को अछूता रखने का प्रयत्न करे तथा यह भी सम्भव है कि व्यवस्था के सदस्य अपने आपसी सम्बन्धों को ही सर्वथा परिवर्तित कर लें और अपने लक्ष्यों और व्यवहारों को इस प्रकार सशोधित कर लें कि पर्यावरण से आने वाले निवेशों (माँग एवं समर्थन) से निपटने में वे अधिक आसानी से सक्षम हो सकें। ये सभी अवस्थाएँ एवं बातें पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के आपसी प्रभाव पर निर्भर करती हैं।

आमण्ड ईस्टन से पूर्णतया प्रभावित है। उसने ईस्टन के 'व्यवस्था सिद्धान्त' को ही विकसित और व्याख्यायित करते हुए अपना 'सरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण' का सिद्धान्त निर्मित किया है। वह मानता है कि "विकास की प्रक्रिया एक तार्किक प्रक्रिया है और पर्यावरण से आने वाले विभिन्न प्रकार के दबावों (मॉगों, समर्थनों आदि) की प्रतिक्रिया के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में निकट अथवा दूरस्थ भविष्य में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनके सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है।"³⁵ तात्पर्य यह कि आमण्ड राजनीतिक व्यवस्था को सम्पूर्ण पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकित करना चाहता है।

आमण्ड-पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र सरकारी संस्थाएँ यथा विधानमण्डल, न्यायलय, प्रशासनिक अभिकरण आदि को ही सम्मिलित नहीं किया है, प्रत्युत रक्त सम्बन्ध, जाति समूह, उदण्ड घटनाएँ, हत्याएँ, दंगे और प्रदर्शन तथा साथ ही साथ औपचारिक संगठन दल, हित समूह और संचार के माध्यमों आदि को भी सम्मिलित किया है। वह मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के भीतर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उप व्यवस्था है।

आमण्ड ने विस्तृत अध्ययन, यथार्थ, सटीकता एवं नवीन सैद्धान्तिकता की खोज के लिए अपने सरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, क्योंकि उसकी मान्यता है कि परम्परागतता सीमितता और औपचारिकता³⁶ के कारण परम्परागत, अध्ययन-पद्धति सन्तोषजनक नहीं हैं। उसने सरचनात्मक व्यवस्था को उन प्रबन्धों का संकेत माना है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में कार्य किए जाते हैं। उन गतिविधियों को, जिनका पर्यवेक्षण सम्भव है, तथा जिनको मिलाकर राजनीतिक पद्धति बनती है, सरचना कहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि

35- आमण्ड तथा पावेल *कम्परेटिव पॉलिटिक्स-ए डेवलपमेन्ट एप्रोच*, बोस्टन, 1996, पृष्ठ 207-208।

36- आमण्ड तथा पावेल *कम्परेटिव पॉलिटिक्स-ए डेवलपमेन्ट एप्रोच*, बोस्टन, 1996, पृष्ठ 2-5।

सरचना व्यवस्था के अन्तर्गत उन प्रबन्धों को बनाती है, जो प्रकार्यों का निष्पादन करते हैं। सरचनाएँ दो प्रकार की होती हैं—भौतिक और सामाजिक। भौतिक सरचनाएँ वे हैं, जो प्रकृति के निकट हैं और जिनका सम्बन्ध भूगोल इत्यादि से है। सामाजिक सरचनाएँ वे हैं, जिनका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है तथा जो मनुष्य की आवश्यकता पर निर्भर करती हैं, जैसे धर्म, संस्कृति आदि। आमण्ड मानता है कि इन्हीं विभिन्न प्रकार की सरचनाओं के सम्मिलित प्रयास के राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कार्य (प्रकार्य) किये जाते हैं। अतः किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सही एवं यथार्थपूर्ण अध्ययन के लिए इन सरचनाओं और उनके विभिन्न घटकों को निरीक्षित — परीक्षित करना आवश्यक है।

ईस्टन और आमण्ड—पावेल के राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण से सम्बन्धित उपर्युक्त सिद्धान्तों के गहन विवेचन से निष्कर्षित यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक उप व्यवस्था है जो खुली हुई और समज्जनीय है। राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का अधिकृत वितरण या आवंटन है। राजनीतिक व्यवस्था निरन्तर गतिशील रहती है और अनेक प्रकार के पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित होती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था का अपना एक सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण बन जाता है। इस पर्यावरण के प्रभाव में ही राजनीतिक पद्धति विभिन्न सामाजिक, मापदण्डों का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समूह या पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती रहती है।

अतः राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि संस्थाओं एवं कारकों में विश्लेषण के अभाव में न सम्भव है, न सत्य। राजनीतिक संरचना को इसी विभिन्न पर्यावरणों की दृष्टि से ही समझना चाहिए। यही कारण है कि वर्तमान में राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास आदि की अधुनातन अवधारणाओं का विकास हुआ है।

शोधार्थिनी ने ईस्टन और आमण्ड-पावेल के व्यवस्था विश्लेषण तथा सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को ही वैचारिक आधार मानकर प्रस्तुत शोध कार्य को सम्पादित करने का प्रयास किया है।

इस शोध कार्य में मन्त्रिपरिषद की सरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी परिवर्त्य लिए गए हैं। इनमें आर्थिक स्थितियों से लेकर जलवायु तक भौगोलिक विशेषताओं, ऐतिहासिक, जाति, धर्म आदि उन सभी परिवर्त्यों (वैरिएबल्स) को भली-भाँति जाँचने-परखने का प्रयत्न किया गया है। राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक व्यवहार प्रत्येक क्षण इन परिवर्त्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहता है। राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकता को समझने के लिए इन पृष्ठभूमि परिवर्त्यों की मात्र जानकारी ही आवश्यक नहीं है वरन् इनकी सही पहचान भी अपेक्षित है।

वस्तुतः पृष्ठभूमि परिवर्त्यों की संख्या इतनी अधिक है कि इनकी गणना करना कठिन कार्य है। राजनीतिक व्यक्ति का कार्य जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीयता, दलीय भावना, विचारधारा आदि से प्रभावित हो सकता है, परन्तु इनमें से किसका कितना प्रभाव पड़ता है, यह जाचना आसान नहीं है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्त्य परस्पर एक दूसरे से इतना अधिक गुथे हुए होते हैं, कि इनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है और कौन अधिक प्रभावशाली है, यह निर्धारित करना भी कठिन कार्य है। एक ही परिवर्त्य एक ही परिस्थिति में भी अलग-अलग प्रभाव डालते हुए देखा गया है। इन सब व्यावहारिक समस्याओं के होते हुए भी शोधार्थिनी ने प्रमुख परिवर्त्यों को निर्धारित कर उनके पृथक-पृथक प्रभाव एवं भूमिका को जाँचने-मापने का पूरा प्रयास किया है।

व्यक्तित्व सम्बन्धी परिवर्त्य के अन्तर्गत बौद्धिक स्तर, मूल्य, व्यवहार आदि शिक्षा सम्बन्धी चरो (परिवर्त्यो) का भी अत्यन्त सावधानी से मूल्यांकन किया गया है। इनके निर्धारण में सबसे बड़ी समस्या शोधार्थिनी के समक्ष यह आयी कि अनेक मन्त्रियों के शैक्षिक अभिलेख अनुपलब्ध पाए गए। पुनरपि, प्राप्त अभिलेखों के आधार पर इस प्रकार के चरो का भरपूर सदुपयोग करने का प्रयास किया गया है।

इस अध्ययन में प्रलेखीय स्रोत के रूप में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के प्रकाशित, अप्रकाशित लेख, पुस्तकें, रिपोर्ट, सरकारी ऑकड़ों, उ०प्र० विधान सभा की कार्यवाही के दस्तावेजों से पर्याप्त सहायता ली गई है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय स्रोत के रूप में कतिपय विधायकों, मन्त्रियों या अन्य महत्त्वपूर्ण वर्तमान या निवर्तमान राजनेताओं के साक्षात्कार तथा वार्ता से भी सहायता ली गई है इसमें प्रश्नावली तथा अनुसूची का भी सम्यक् प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली खुली और बन्द दोनों प्रकार की प्रयुक्त की गई है।

ध्यातव्य है कि प्रस्तुत शोध सरचनात्मक एवं सख्यात्मक दृष्टिकोण (स्ट्रक्चरल एण्ड क्वान्टिटेटिव एप्रोच) पर आधारित है, इसलिए प्राप्त सूचनाओं एवं तथ्यों के ऑकड़ों आदि का सकलन, विश्लेषण, वर्गीकरण, सारणीयन एवं विवेचन को विस्तार से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया गया है। ऑकड़ों एवं सूचनाओं का मुख्य स्रोत प्रश्नावली, साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएँ तथा विधानसभा के अभिलेख आदि हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य माध्यमों से प्राप्त आकड़ों का प्रयोग तुलनात्मक रूप से किया गया है।

उल्लेखनीय है कि डेविड ईस्टन और आमण्ड-पावेल के व्यवस्था विश्लेषण एवं सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोणों में ईस्टन से पर्यावरण का राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों तथा आमण्ड-पावेल के मात्र 'सरचनात्मक' पक्ष को

इस अध्ययन की वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप में माना गया है, ईस्टन या आमण्ड के सम्पूर्ण सिद्धान्त को नहीं। यह भी ध्यातव्य है कि प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र उत्तरप्रदेश की मन्त्रिपरिषद (199-1997) से ही सम्बन्धित है, अतः अन्य प्रदेशों या केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद आदि का उद्धरण प्रसंगवश ही किया गया है। अध्ययन का प्रायः पूरा कलेवर उत्तर प्रदेश की निर्धारित काल विशेष की मन्त्रिपरिषद से ही निर्मित है।

प्रस्तुत कार्य द्वारा शोधार्थिनी का ध्रुव विश्वास है कि प्रदेशीय मन्त्रिपरिषद के गठन के पीछे निहित कारकों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा एवं लोकतंत्र के प्रति हमारे कर्णधारों की मानसिकता का भी पता चल सकेगा। यही नहीं, अपितु केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद की संरचना के अन्तर्निहित कारकों का भी संकेत इन शोध द्वारा प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद की संरचना पर यह प्रथम या अन्तिम कार्य है, ऐसा शोधार्थिनी का कदापि दावा नहीं है। परन्तु, इतना कहने की दृष्टता अवश्य की जा सकती है कि इन कार्य में शोध की आधुनिकतम तकनीकी एवं मानकों के अनुसार प्राप्त तथ्यों एवं ऑकड़ों आदि के आधार पर सम्यक् प्रकार से वर्गीकरण, परीक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि द्वारा विषय को सुसंगत एवं क्रमबद्ध रूप से उसके नए कलेवर में यथाशक्ति प्रस्तुत करने का प्रयास निश्चयेन किया गया है।



द्वितीय अध्याय

उत्तर प्रदेश- एक पार्श्वचित्र

अध्याय - 2

उत्तर प्रदेश एक पार्श्वचित्र

सामाजिक शास्त्रों के वैज्ञानिक इस तथ्य से अवगत होने लगे हैं कि राजनीतिक कार्य स्वयं में अकेले ही नहीं होते। ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दशाये, जनता तथा शासन की राजनीतिक प्रवृत्ति, संवैधानिक ढंग और राजनीतिक प्रक्रियाओं को बहुत गहरे से प्रभावित करती हैं।

इस संदर्भ में यदि उत्तर प्रदेश पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि 30 प्र० भारतीय सभ्यता व संस्कृति का केन्द्र रहा है। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। चाहे प्रदेश की कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का, उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश को यह भी श्रेय प्राप्त है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सबसे अधिक संख्या में प्रधानमंत्री भी दिये हैं। पिछले पचास वर्षों में चालीस से अधिक वर्षों तक इसी प्रान्त के लोग इस कुर्सी पर बैठते आये हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं संस्कृति, इतिहास व सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह प्रान्त भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इस प्रान्त को अपना नाम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ प्राप्त हुआ था। 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था। वास्तव में अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रान्त (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेंसी का ही एक हिस्सा था। सुविधानुसार इसे कभी पश्चिमी प्रान्त के नाम से पुकार लिया जाता था। बाद में आगरा प्रेसीडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया। 1836 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया। तब इसका नाम "उत्तर पश्चिम प्रान्त" (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया। इसका मुख्यालय आगरा को बना दिया गया। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल

कर लिया गया। उस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे। 1857 की क्रान्ति के बाद 1858 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को एक ले० गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बना दिया। अब इस प्रान्त का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। 1868 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से इलाहाबाद स्थान्तरित कर दिया गया। परन्तु अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रान्त का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक व न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रान्तों का इलाहाबाद। 1877 में इन दोनों प्रान्तों को ले० गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। अब ले० गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रान्त का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया।¹

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले० गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रान्त की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थान्तरित कर दी गयी। 1921 में लखनऊ में ही विधान परिषद की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को अब इस प्रान्त की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1937 में इस प्रान्त का नाम एक बार फिर बदल कर संयुक्त प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया जो 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा।²

30 प्र० की भौगोलिक स्थिति

30 प्र० को भारत का हृदयस्थल कहा जाता है। यह भारत के सीमान्त प्रदेशों में से एक है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणी से लगी हुई है और दक्षिण पश्चिमी

1- उत्तर प्रदेश 99' सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 30प्र० पृष्ठ-2

सीमा पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हैं तथा दक्षिण से मध्य प्रदेश और पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई है। राजनीतिक सीमाएँ न्यूनाधिक प्राकृतिक सीमाओं का ही अनुसरण करती हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व में गण्डक नदी हैं। राज्य का तीन स्पष्ट प्राकृतिक विभाजन है- उत्तर में हिमालय का क्षेत्र, बीच में गंगा का मैदान और दक्षिण में पहाड़ी तथा पठारी भू-भाग।³

हिमालय क्षेत्र के अन्तर्गत टेहरी एवं गढ़वाल मण्डल का क्षेत्र आता है जो राज्य के उत्तर में स्थित है। इसमें नन्दादेवी (7817मी) कामेत (7756 मी०) बदरीनाथ (7138 मी०) आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं।

प्रदेश का बड़ा भू-भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसमें कोई भी स्थान (सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग को छोड़कर जहाँ से शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ शुरू होती हैं) समुद्र की सतह से 300 मीटर अधिक की ऊँचाई पर नहीं है। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक एक पतली सी चट्टी, भाभर और तराई कहलाती है।

सहारनपुर, बिजनौर, गढ़वाल, नैनीताल और पीलीभीत जिले में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के इर्द-गिर्द ही सिमटा हुआ है।

इसके अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया आदि जिले के भाग आते हैं। इधर कुछ वर्षों में राज्य सरकार के भूमि-उपार्जन के अन्तर्गत हुए कार्यों के फलस्वरूप इसकी चौड़ाई काफी कम हो गई है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, चावल और गन्ना हैं। प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झाँसी, जालौन, हमीरपुर और बादा जिले, इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती हैं। यह क्षेत्र दक्कन के

पठार का ही प्रसरण है। पूरे प्रक्षेत्र में वर्षा कम होती है और पानी का अभाव है। इधर कुछ वर्षों में जलाशयों का निर्माण कर सिचाई तथा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, चना और गेहूँ हैं।

30 प्र० का क्षेत्रीय वितरण

यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश को तीन भागों में बाटा जाता है¹ किन्तु यदि इसका सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधार पर विभाजन किया जाये तो इसे कुल पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है।²

1 उत्तराखण्ड

2 पश्चिम उत्तर प्रदेश

3 मध्य उत्तर प्रदेश

4 बुन्देल खण्ड

5 पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल

30 प्र० के विषय में यह तथ्य दृष्टिगोचर है कि मद्रास और आन्ध्रप्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खण्ड नहीं है। यह भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा कई क्षेत्रों को मिलाकर बनाया हुआ प्रदेश है जिसका शासन पहले कभी भी किसी एक शासक द्वारा नहीं हुआ। इस कारण इसके विभाजित खण्ड के पड़ोसी राज्यों से न केवल भौगोलिक सम्बन्ध बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक सम्पर्क भी रहे हैं उत्तरी पहाड़ी खण्ड के लोग मैदानी क्षेत्र की जनता की अपेक्षा हिमाचल की जनता से अधिक साम्य रखते हैं। इसी तरह से दक्षिण के पहाड़ी जिलों का सम्बन्ध बुन्देलखण्ड से ही है और यह इसी का एक हिस्सा है तथा इसके साथ इसका अधिक साम्य है। पश्चिम 30 प्र० के जाट एवं गूजर हरियाणा और राजस्थान में बहुतेक बड़ी संख्या में रहने वाली जाट एवं गूजर जाति से सम्बन्धित हैं। पूर्वी जिलों के क्षत्रिय,

1-उत्तर प्रदेश '99' सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 30८० पृष्ठ-101

2-उत्तर प्रदेश '99' सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 30८० पृष्ठ ३७

ब्राह्मण और भूमिहार आदि बिहार में रहने वाली इन्हीं जातियों से अभिन्न हैं और प्रायः उनमें विवाह आदि होता रहता है। इन्हीं समानताओं के कारण पड़ोसी राज्यों की जनता के साथ इस राज्य की कुछ जनता राज्य के पून बटवारे की माग करती रही है। इन दिनों उत्तरांचल का पृथक राज्य आन्दोलन अत्यधिक सक्रिय है तथा बुन्देलखण्ड, पश्चिम खण्ड 30 प्र० को हरित प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी अलग राज्य बनाने की माग की जा रही है।

इन सब के बाद भी सूक्ष्म अर्थों में 30 प्र० भारत है वह कभी भी एक स्थानीय खण्ड रूप में नहीं रहा। जबकि अन्य राज्यों की जनता बंगाली, बिहारी, गुजराती, पंजाबी, मद्रासी आदि नाम से पुकारी जाती है वही पर 30 प्र० की जनता का इस प्रकार कोई क्षेत्रीय नाम नहीं है। यहाँ के लोग अपने को 'यूपीइस्ट' या 'यूपियन' जैसा नाम न देकर 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं, जिसका अर्थ भारतीय है। भाषा और संस्कृतिकी दृष्टि से भी 30 प्र० की कोई अपनी अलग भाषा और संस्कृति नहीं।

प्रशासनिक संरचना

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 19 मण्डल हैं जिसके अन्तर्गत 83 जिले, 345 तहसीले तथा 904 सामुदायिक विकास खण्ड हैं।¹

मण्डल	जिला
1 सहारनपुर	सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर
2 मेरठ	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्द शहर, बागपत
3 आगरा	आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस
4 बरेली	बरेली, बदायूँ, शाहजहापुर, पीलीभीत
5 मुरादाबाद	मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर
6 कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया

☆ 1-सम्बन्धित विवरण उत्तराखण्ड बनने से पहले के हैं।

7	इलाहाबाद	इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी
8	झासी	झासी ललितपुर, जालौन
9	चित्रकूट	हमीरपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट
10	वाराणसी	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली
11	मिर्जापुर	मिर्जापुर, सोनभद्र, सतरविदासनगर
12	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया
13	गोरखपुर	गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर(पडरौना)
14	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त-कबीरनगर
15	लखनऊ	लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खारी
16	देवीपाटन	गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
17	फैजाबाद	फैजाबाद, सुलतानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर
18	कुमाऊँ	नैनीताल, अलमोडा, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ बागेश्वर, चम्पावत
19	गढ़वाल	चमोली, उत्तरकाशी, रुद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, गढ़वाल

क्षेत्रफल

उत्तर प्रदेश जो भारत का एक सीमान्त एवं विशाल राज्य है, का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग कि० मी० है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8.9 प्रतिशत है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के पश्चात देश में इसका चौथा स्थान है¹ और यदि इसके पांच खण्डों का क्षेत्रफल देखे तो क्रमशः

1	उत्तरांचल-	51 12 वर्ग किलोमीटर
2	पश्चिमी 30 प्र०	82 19 वर्ग किलोमीटर
3	मध्य 30 प्र०	48 83 वर्ग किलोमीटर

4	बुन्देलखण्ड	29 42 वर्ग किलोमीटर और
5	पूर्वी 30 प्र०	85 85 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या

भारत की कुल जनसंख्या में इसका सर्वाधिक 16 44 प्रतिशत अंशदान होने के फलस्वरूप जनसंख्या की दृष्टि से देश में इस प्रदेश का प्रथम स्थान है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 13,91,12,287 है, जिसमें 7,40,36,957 पुरुष, तथा 6,50,75,330 स्त्रियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की संख्या 11,15,06,372 (80 16 प्रतिशत) है तथा नगरीय क्षेत्रों में 2,76,05,915 (19 84 प्रतिशत) है। इस प्रकार हमारे प्रदेश में अभी भी 80 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। वर्ष 1981 की जनगणना के समय प्रदेश की कुल जनसंख्या 11,08,62,512 थी, जिसमें 5,88,19,535 पुरुष तथा 5,20,42,977 स्त्रियां हैं। इस प्रकार वर्ष 1981 से वर्ष 1991 के दशक के दौरान प्रदेश की कुल जनसंख्या में 25 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो इसके पूर्व के दशक (1971-81) की दशकीय प्रतिशत वृद्धि (23 51) से केवल 0 01 प्रतिशत कम है।

प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर (25 48) की तुलना सम्पूर्ण भारत की दशकीय वृद्धि दर (23 1) से करने पर यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की दशकीय वृद्धि भारतवर्ष की दशकीय वृद्धि दर की तुलना में 1 97 प्रतिशत अधिक रही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत वर्ष की कुल जनसंख्या 84,63,02,688 थी जिसमें पुरुष की संख्या 43,92,30,458 तथा स्त्रियों की संख्या 40,70,72,230 है।

इस प्रकार भारतवर्ष की सम्पूर्ण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंशदान 16 44 प्रतिशत है, अर्थात् प्रत्येक छठा भारतवासी उत्तर प्रदेश का निवासी है।¹

उपर्युक्त तथ्यो को निम्न सारिणी सख्या 2 1 1 मे दर्शाया गया है।

सारणी सख्या² 2 1 1

		वर्ष 1981	वर्ष 1991
1-जनसख्या	कुल व्यक्ति	110862013	139112287
	पुरुष	58819276	74036957
	स्त्री	52042737	65075330
	ग्रामीण व्यक्ति	90962898	111506372
	पुरुष	48041135	59197138
	स्त्री	42921763	52309234
	नगरीय व्यक्ति	19899115	27605915
	पुरुष	10778141	14839819
	स्त्री	9120974	12766096
2- जनसख्या मे दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)		25 49	25 48

प्रदेश की जनसख्या का क्षेत्रीय वितरण सारिणी 2 1 2 मे दर्शाया गया है।

सारणी सख्या² 2 1 2

क्रम सख्या	विवरण	उत्तरांचल क्षेत्र	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य पश्चिमी क्षेत्र	सम्पूर्ण क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सम्पूर्ण जनसख्या (लाख मे)/वर्ष १९९१	59 27	67 29	527 22	241 87	495 4	1391 12
2-	राज्य जनसख्या का	4 30	4 80	37 90	17 40	35 6	100 0
3 -	जनसख्या का घनत्व (प्रति वग कि.मी)	116	229	614	528	603	473

सारणी सख्या 2 1 2 मे दर्शाया गया है कि 1991 जनगणना के अनुसार उत्तरांचल, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्य क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसख्या क्रमशः 29 27 लाख, 67 29 लाख, 527 22 लाख, 241 27 लाख, 495 47 लाख है। जिसका प्रदेश की जनसख्या मे प्रतिशत क्रमशः 4 30, 4 80, 37 90, 17 40, 35 60 है। नगरी जनसख्या क्रमशः 21 75 लाख, 11 57 लाख, 23 72, 21 19 लाख है। अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है, कि जहाँ नगरी जनसख्या का प्रतिशत सबसे अधिक मध्यक्षेत्र मे है वही सख्या मे नगरीय जनसख्या सबसे अधिक पश्चिमी 30 प्र० की है। ग्रामीण जनसख्या प्रतिशत मे एव सख्या मे सबसे अधिक पूर्वी 30 प्र० मे है।

स्त्री-पुरुष अनुपात

उत्तर प्रदेश मे स्त्री-पुरुष का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना मे प्रति हजार पुरुषो पर स्त्रियों की सख्या 879 है। पिछली जनगणना (1981) मे यह अनुपात 885 था, अर्थात् पिछले दशक के दौरान प्रति हजार पुरुषो पर 6 स्त्रियों की कमी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रो मे यह अनुपात 884 रहा तथा नगरीय क्षेत्रो मे 860 आया है। इस प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो मे स्त्री-पुरुष के अनुपातो मे अभी भी अच्छा-खासा अन्तर है। वैसे स्त्री-पुरुष का अनुपात प्रदेश मे सदैव पुरुषो के पक्ष मे रहा है।¹

उपर्युक्त तथ्यों को सारणी सख्या 2 1 3 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारणी सख्या -2 1.3

		वर्ष	1981	1991
स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषो पर स्त्रियों की सख्या)	अ सामान्य	कुल	885	879
		ग्रामीण	893	884
		नगरीय	846	860
	ब अनु जाति	कुल	892	877
		ग्रामीण	898	880
		नगरीय	844	854
	स अनु जन जा	कुल	917	914
		ग्रामीण	920	920
		नगरीय	814	820

साक्षरता

इस जनगणना में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निरक्षर माना गया है। चाहे वे स्कूल जा रहे हों अथवा नहीं। इस सिद्धान्त को अपनाते हुए वर्ष 1991 की जनगणना में प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 4,61,44,196 है। दूसरे शब्दों में साक्षरता दर 41 60 प्रतिशत है।

साक्षर पुरुषों का प्रतिशत 55 73 है जो साक्षर स्त्रियों के प्रतिशत (25 31) के दुगुने से भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 36 66 प्रतिशत है जबकि नगरीय क्षेत्रों में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 61 आया है। यदि स्त्रियों तथा पुरुषों की साक्षरता दर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग देखे तो ज्ञात होता है कि पुरुषों की साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में 52 05 है जो स्त्रियों की साक्षरता दर 19 02 प्रतिशत से दुगुने से भी अधिक है, परन्तु नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की साक्षरता दर (50 38 प्रतिशत) तथा पुरुषों की साक्षरता दर (69 98 प्रतिशत) में बहुत अधिक अन्तर नहीं है। दशक वर्ष 1981-91 के दौरान कुल साक्षरता दर में 8 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पुरुषों (8 30 प्रतिशत) अक तथा स्त्रियों (8 13 प्रतिशत) के लिये लगभग समान रही है।¹ उपयुक्त तथ्यों को सारिणी संख्या 2 1 4 में दर्शाइये।

सारणी संख्या-2.1.4

साक्षर दर (0-6 आयु वर्ग के बच्चों को छोड़कर)	व्यक्ति	33 33
	पुरुष	47 43
	स्त्री	17 18
नगरी	व्यक्ति	61
	पुरुष	69 98
	स्त्री	50 38
ग्रामीण	व्यक्ति	36 66
	पुरुष	52 05
	स्त्री	19 02

उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की स्थिति काफी निराशाजनक है। सात वर्ष के वय . ग्रुप में चार में से केवल एक को पढ़ना और लिखना आता है। यह आकड़ा ग्रामीण इलाकों में लुढ़क कर 19 फीसदी पहुँच गया है। इनमें अनुसूचित जाति के 11 फीसदी और सामान्य तौर पर 8 फीसदी शामिल हैं यह प्रतिशत शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में देहात की आबादी वाले इलाकों का है। सन् 1981 की जनगणना के आकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता तेकरीबन नही के बराबर रही है। मसलन सन् 1981 में उत्तर प्रदेश के गावों की अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 18 जिलों में 18 फीसदी से भी कम रही है और कई जिलों में तो यह 2-5 फीसदी से भी नीची रही।

उत्तर प्रदेश में सन् 1992-93 के दौरान प्राइमरी और सेकेण्डरी को मिलाकर कुल शैक्षिक उपलब्धि पर गौर करें तो पायेंगे कि शिक्षित पुरुष और महिलाओं में क्रमशः 50 और 40 फीसदी लोग ही स्कूल में आठ वर्ष बिता पाये। एक और मुख्य बात यह है कि युवा वर्ग में साक्षरता की दर काफी अधिक पायी गयी है। यह दर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के युवाओं में ज्यादा रही है। सन् 1980 के उत्तरार्द्ध में 10-14 आयु वर्ग में देहात के लड़कों में साक्षरता दर 32 फीसदी और लड़कियों में दो फीसदी थी और इनमें से भी 12-14 आयु वर्ग की लड़कियों की दो तिहाई आबादी ने स्कूल का मुह तक नहीं देखा।

राज्य में शिक्षा की समस्या जनता की अरुचि और सरकार की तटस्थता के चलते विकराल रूप लेती जा रही है। सरकारी स्कूलों की स्थिति भी बहुत सुखद नहीं है। यहाँ निजी स्कूल तो फर्फटे से चल रहे हैं लेकिन आम लोगों की पहुँच से बाहर हैं। राज्य सरकार के सबको साक्षर करने के कई कार्यक्रम हैं। यथा विश्व बैंक अनुदानित डी पी इ पी स्वैच्छिक संस्थाओं और दूसरे संगठनों की मदद से इन कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के स्तर पर उत्तर प्रदेश में 26 सामान्य विश्वविद्यालय, 3 तकनीकी विश्वविद्यालय, एक आई0 आई0 टी (कानपुर), एक इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट (लखनऊ) और भारी संख्या में पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग

संस्थान और निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं।

यदि साक्षरता का क्षेत्रीय वितरण देखे तो 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र की साक्षरता क्रमशः 59.6, 42.3, 38.6, 42.6, 42.0 प्रतिशत हैं। महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः पर्वतीय क्षेत्र में 20.9 मध्यक्षेत्र में 28.3 तथा पश्चिमांचल में 26.6 प्रतिशत हैं। उपर्युक्त तथ्यों को निम्न सारिणी में दर्शाया गया है

सारिणी सख्या-2.1 5

विवरण	उत्तरांचल	बुन्देलखण्ड	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिमीक्षेत्र
कुल साक्षरता (प्रतिशत में) 1991के जन गणना	59.6	42.3	38.6	42.6	42
महिला साक्षर (प्रतिशत में)	42.9	23.9	20.9	28.3	26.6

भाषा

30 प्र0 की मुख्य भाषा हिन्दी है जो यहाँ के लगभग 85 प्रतिशत जनता के द्वारा बोली जाती है। 30 प्र0 ही वह पहला राज्य है जिसने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। इसके अतिरिक्त यहाँ की दूसरी राजभाषा उर्दू है जो यहाँ की 14 प्रतिशत जनता के द्वारा बोली जाती है। यद्यपि हिन्दी राज्य की मुख्य भाषा है किन्तु हिन्दी की भी तीन बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैं- भोजपुरी, अवधी और ब्रज। पिछले वर्षों में भाषा के आधार पर क्षेत्रीय का विकास प्रदेश में हुआ है।

धार्मिक संरचना

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या हिन्दू धर्म को मानने वाली है। इसके अन्तर्गत जो अन्य धर्मावलम्बी इस प्रदेश में पाये जाते हैं उसमें

मुस्लिम 17.33 प्रतिशत, सिख 0.48, बौद्ध 0.16, ईसाई 0.14 तथा पारसी 389(नगण्य)। इस प्रकार जहाँ अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 20 प्रतिशत या अधिक क्षेत्र है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला घोषित किया गया है।¹ उपर्युक्त तथ्यों को निम्न सारिणी में दिखाया गया है।

सारिणी संख्या 2.1.6

क्र० सं०	धर्म	जनसंख्या (प्रतिशत में)
1	मुस्लिम	17.33
2	सिख	0.48
3	बौद्ध	0.16
4	ईसाई	0.14
5	जैन	0.08
6	पारसी	389(नगण्य)

1991 की जनगणना के अनुसार

अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ

इस जनगणना में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रदेश में 2,92,76,455 आयी है जिसमें 1,55,99,178 पुरुष तथा 1,36,77,277 स्त्रियाँ हैं। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.05 प्रतिशत है। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि की तुलना कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि से करे तो ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों में वर्ष 1981 की जनगणना के पश्चात् 24.83 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई

1- उत्तर प्रदेश '99', पृ० 514

है, जो सामान्य जनसंख्या की दशकीय वृद्धि से कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों की संख्या में दशकीय वृद्धि 23.75 प्रतिशत रही है जो अनुसूचित जातियों की तुलना में भी कम है। जबकि अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 287,901 है जिसमें 150,420 पुरुष तथा 137,481 स्त्रियाँ थीं। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.21 है। उपर्युक्त तथ्यों को सारिणी 2.1.7 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 2.1.7

क्र.सं.	वर्ग	वर्ष 1981	1991
1	(अ) अनुसूचित जाति (व्यक्ति)	23,453,339	29,279,455
	पुरुष	12,307,321	15,599,178
	स्त्री	11,056,01	13,677,277
	(ब) कुल जनसंख्या में (प्र०)		
	व्यक्ति	21.66	21.05
	पुरुष	21.0	21.07
	स्त्री	21.24	21.02
2	(अ) अनुसूचित जनजाति (व्यक्ति)	232,705	287,901
	पुरुष	121,506	0,420
	स्त्री	111,199	7,481
	(ब) कुल जनसंख्या में (प्र०)		
	व्यक्ति	00.21	00.21
	पुरुष	00.21	00.20
	स्त्री	00.21	00.21

सामाजिक संरचना

30 प्र० की सामाजिक संरचना में जाति तथा धर्म मुख्य धुरी का कार्य करते हैं। जाति तथा धर्म यहाँ की राजनीति को न्यूनाधिक रूप से प्रारम्भ से प्रभावित करते आ रहे हैं किन्तु वर्तमान दशक में यह कहना अनुचित न होगा कि इसका प्रभाव राजनीति में बहुत बढ़ गया है। यदि प्रदेश की जातीय संरचना को देखें तो 1931 की जनगणना के अनुसार राज्य में चमारों की संख्या सबसे अधिक है। यह कुल जनसंख्या का 13.72 प्रतिशत है।¹ आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से तथा शास्त्रीय उक्ति के अनुसार वे सामाजिक स्तर में बहुत ही निम्न स्तर के हैं। वे अनुसूचित जातियों में से एक हैं जिन्हें विधानसभा तथा सदन में निश्चित सीटें प्राप्त हैं।

चमारों के बाद सबसे अधिक संख्या वाली जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर (यादव), राजपूत और कुर्मियों की हैं। राज्य की कुल आबादी में ब्राह्मणों का प्रतिशत 9.18 रहा।² सामाज तथा शास्त्रों में ब्राह्मण को सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त है। इसके बाद राजपूत आते हैं। जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.57 प्रतिशत है।³ ब्राह्मण तथा राजपूत दोनों ही भूमि के अधिक भागों पर अधिकार करने वाली जातियाँ हैं।⁴

शास्त्रों व सामाजिक स्तर की दृष्टि से अहीर और कुर्मि मध्यम श्रेणी के होते हैं। ये राज्य की पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत आते हैं। सन् 1931 की जनगणना के अनुसार आबादी में अहीरों का प्रतिशत 7.84 और कुर्मियों का प्रतिशत 3.54 रहा है।⁵ राज्य के केन्द्रीय व

1-सेन्सस रिपोर्ट ऑफ इण्डिया, सन् 1931 ई०, 30 प्र०, खण्ड 1, टेबुल 1, पृष्ठ-619

2-वही, पृष्ठ-619

3-वही, पृष्ठ-619

4-ब्लट ई० ए० एच० - द कास्ट सिस्टम ऑफ नार्दन इण्डिया, एस० चन्द्र एण्ड क०, 1967, पृ० 264

5-सेन्सस रिपोर्ट ऑफ इण्डिया, सन् 1931 ई०, 30 प्र०, खण्ड 1, टेबुल 1, पृष्ठ-619

पूर्वी जिलो मे ये दोनो जातिया अनाज पैदा करने वाली महत्वपूर्ण जातिया मानी जाती है।

कुछ अन्य जातिया है जो सख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु जिन क्षेत्रो मे रहती है वहा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है वे है जाट, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य । राज्य के पश्चिमी जिलो मे जाट जाति है जो कि राज्य के खाद्यान्न उत्पादक वर्गों मे बहुत ही महत्वपूर्ण जाति है।⁶ भूमिहार अपने को ब्राह्मण कहते है जिन्होने धर्म निरपेक्षता के लिए अपना पौरोहित्य छोडकर कृषि को अपना कार्य क्षेत्र माना।⁷ कायस्थ को लेखको का एक वर्ग माना गया है। सन् 1931मे प्रोविन्स (अब राज्य) मे यह सबसे अधिक पढी लिखी जाति रही है।⁸ वैश्य का अधिकाधिक काम व्यापार एव वाणिज्य रहा है। उपर्युक्त विवरण को सारिणी सख्या 2 1 8 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 2 1 8

जाति	कुल जनसख्या मे प्रतिशत *
चमार	13 72
ब्राह्मण	9 18
राजपूत ⁹	7 57
यादव	7 84
कुर्मी	3 54

* 1931 की जन गणना के अनुसार

6- ब्लट ई0 ए0 एच0 - वही, पृ0 271,

7-वही, पृ0 239,

8-सेन्सस रिपोर्ट ऑफ इण्डियाँ, सन् 1931 ई0, 30प्र0, खण्ड1, टेबुल1, पृष्ठ-619

9-राजपूत क्षत्रीय वर्ण के होते है, राज्य के पूर्वी जिलो मे इन्हे क्षत्रीय ठाकुर कहा जाता है।

मौटे तौर पर कुल आबादी पर उच्चजातिया 20 से 22 प्रतिशत पिछड़ी जातिया 40 से 42 प्रतिशत और अनुसूचित जातिया 21 प्रतिशत है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक राज्य में जातिगत कोई संघर्ष नहीं रहा। जातिगत संघर्ष तो अब होने लगा है।¹ परन्तु 30 प्र० का जातिगत संघर्ष भारत के कुछ दक्षिणी राज्यों के जातिगत संघर्ष से भिन्न है। जहाँ पर जातिया ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के रूप में धुवीकृत है। उत्तर प्रदेश में जाति संघर्ष ब्राह्मण बनाम् क्षत्रिय, ब्राह्मण बनाम् वैश्य, यादव बनाम् कुर्मी के रूपों में देखा जा सकता है।

मतदाता एवं सांख्यिकी क्षेत्रीय संरचना

30 प्र० के मतदाताओं की संख्या देश भर में सर्वाधिक लगभग 10 08 करोड़ है।¹ जाति एवं धार्मिक आधार पर इसका वितरण किया जाय तो मोटे तौर पर मुस्लिम 16 प्रतिशत, ब्राह्मण और अहीर(यादव) 9 प्रतिशत, राजपूत 8 प्रतिशत, कुर्मी 4 प्रतिशत, कोयरी/मौर्या 4 प्रतिशत अन्य जैसे लोधी, वैश्य जाट कायस्थ गुजर और केवट 2 प्रतिशत के लगभग हैं। अनुसूचित जाति में से चमार 14 प्रतिशत, पासी 4 प्रतिशत मुख्य जातिया हैं। अनुसूचित जनजातिया 0 21 प्रतिशत हैं।² यदि जातियों के जमाव के देखे तो मुस्लिमों का जमाव पश्चिम 30 प्र० मध्य प्र० से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में है इनकी 20 प्रतिशत से अधिक संख्या बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूँ, बरेली, शाहजहापुर, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, पडरौना(कुशीनगर), अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर,

1-के० के० सिंह - 'पैटर्न ऑफ कास्ट टेशन ए स्टडी इन इण्टर कास्ट टेशन एण्ड कॉम्प्लेक्ट, बम्बई, एसिया पब्लिशिंग हाउस, 1967, पृ० 61

2-स्वतंत्र भारत, लखनऊ, 5 सितम्बर, 1996 पृ० 3

3-सी० एस० डी० एस० और फेसेस ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, न्यूज मैन पब्लिशर के आकड़ों के आधार पर।

सहारनपुर, हरिद्वार में है।

सारिणी सख्या 2.1 9

जाति	प्रतिशत (लगभग)
मुस्लिम	16
ब्राह्मण	9
अहीर	9
राजपूत	8
कुर्मी	4
लोधी	2
जाट	2
कायस्थ	2
गूजर	2
केवट	2
चमार	14
पासी	4

सी० एस० डी० एस० और
फेसेस ऑफ इण्डिया, मुकेश
खोशला नई दिल्ली, न्यूज
मैन पब्लिशर के आकड़ों
के आधार पर।

यदि अनुसूचित जातियों का जमाव देखा जाए तो यह मुख्य रूप से बुन्देलखण्ड, पूर्वी उ० प्र० तथा मध्य उ० प्रदेश में व्यापक रूप से पायी जाती है यद्यपि हरिद्वार जैसे उत्तरी जिलों में इनकी संख्या अत्यधिक है। शाहजहाँपुर, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, अकबरपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती, आजमगढ़, राबर्टसगंज,

सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, बादा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, एटा तथा हरिद्वार में इनकी संख्या सबसे अधिक 25 प्रतिशत से ऊपर है, इनमें मुख्य जाति चमार है जिसका वितरण उपर्युक्त सभी जिलों में है किन्तु इस वर्ग की अन्य मुख्य जाति पासी है जिसका जमाव फर्रुखाबाद के आस पास के जिलों में है।

अगड़ी जातियों में प्रदेश में मुख्य रूप से ब्राह्मण 9 प्रतिशत तथा राजपूत 8 प्रतिशत हैं। यदि ब्राह्मणों के जमाव पर ध्यान दें तो इनकी अधिक संख्या उत्तराखण्ड में पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। यद्यपि इनका बिखराव प्रदेश के सभी भागों में है। पूरे उत्तराखण्ड, मेरठ, कानपुर, गोडा, में इनकी संख्या 15 प्रतिशत से ऊपर है। साथी ही अलीगढ़, आगरा, इटावा, फर्रुखाबाद, बादा, जालौन, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अकबरपुर, फैजाबाद, बलरामपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर तथा महाराजगंज में इनकी संख्या 10 से 15 प्रतिशत के बीच है।

ब्राह्मण के बाद उच्च जातियों में सबसे अधिक संख्या राजपूतों की है। राजपूतों का जमाव देखा जाय तो यह पूरे प्रदेश में समान रूप से फैले हैं। बस कुछ स्थान पर इनका प्रतिशत अधिक है जिसमें उत्तराखण्ड, का सम्पूर्ण भाग, बलिया, तथा फिरोजाबाद को शामिल किया जा सकता है जहां इनका प्रतिशत 15 से ऊपर है।

पिछड़ी जातियों में मुख्य अहीर (यादव) कुर्मी, जाट, लोधी, गुजर आदि हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या यादवों की है। यादवों का बिखराव ऐसे तो पूरे प्रदेश में है किन्तु मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम तथा मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इनकी आबादी काफी अधिक है। जाट मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं। लोधी भी पश्चिम तथा मध्य उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह प्रदर्शित करता है कि प्रदेश में जातियों का जमाव कहा और कैसा है। यद्यपि राजनीति में जातिवाद का प्रभाव प्रारम्भ से रहा किन्तु इधर इसका प्रभाव ज्यादा ही बढ़ गया है जिसके कारण जातियों का यह क्षेत्रीय सांख्यिकीय वितरण राजनीतिक

दलो एव उम्मीदवारो के सफलता एव असफलता तथा नीतियो के अध्ययन मे महत्वपूर्ण कारक साबित होता जा रहा है।

राजनीतिक इतिहास

पुरातन काल मे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रमणो के रास्ते मे पडने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच मे उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास के निकटतम सम्बन्ध है। यद्यपि हमे इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध मे बहुत कम जानकारी है तथापि मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र मे खुदाई के फलस्वरुप प्राचीन एव नवपाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर मे हडप्पाकालीन जो वस्तुए मिली हैं वे हमे सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती हैं।

आर्य काल

ऋग्वेद के समय से कुछ सश्लिष्ट ऐतिहासिक वृत्तात मिलता है। आर्यों ने सबसे पहले भारत मे सप्त-सिंधु या सात नदियो द्वार सिंचित प्रदेश (अविभाजित पंजाब) मे बस्तिया बनायीं। धीरे-धीरे आर्यों ने अपने क्षेत्र का पूर्व मे विस्तार किया। शतपथ ब्राह्मण मे कोशल(अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राणु और क्षत्रियो ने जिस प्रकार जीता, उसका रोचक वर्णन है। धीरे-धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और सस्कृति का केन्द्र बना सरस्वती और गंगा के बीच का मैदान, जहा कुरु, पंचाल, काशी एव कोशल (अवध) राज्य थे।

रामायण एव महाभारत काल मे जिन महान व्यक्तियो और देवताओ का वर्णन आया है, वे यही रहते थे। यहा के निवासी सर्वाधिक सुसस्कृत आर्य माने जाते थे। इसके बाद का इतिहास एक लम्बे समय तक के लिए हिन्दुओ की धार्मिक पुस्तको और पुराणो के आख्यानो

से मिश्रित हो गया। जिससे कि ऐतिहासिक वृत्तात की कड़ी टूट गयी। जब अधिकार छटता है और ईसा पूर्वी छठी शताब्दी में इतिहास की रेखाएँ फिर से उभरती दिखाई पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तत्कालीन जनपदों में जो जनपद वर्तमान 30 प्र० में स्थित थे वे थे-

- 1- कुरु (मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर) राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)
- 2- पाचाल (बरेली, बदायूँ और फारूखाबाद) राजधानी अहिछत्र (बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य (फर्रुखाबाद)
- 3- शूरसेन (मथुरा के आसपास के क्षेत्र) राजधानी मथुरा
- 4- वत्स (इलाहाबाद और आसपास), राजधानी कौशाम्बी (इलाहाबाद के पास कोसम)
- 5- कोशल (अवध), राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोडा जिले में सहेत महेत)
- 6- मल्ल (जिला देवरिया), राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पाव (पड़रौना)
- 7- काशी (वाराणसी), राजधानी वाराणसी
- 8- चेदि (बुन्देलखण्ड), राजधानी शुक्तिमती (सम्भवत बादा के पास)

उपर्युक्त जनपदों में से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतन्त्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिरि का भग्गा राज्य और पावापुरी तथा कुशीनगर का मल्ल जनपद।

ईसा से ठीक पूर्व

इन 16 जनपदों में सर्घष की अन्तिम परिणति मगध के उत्कर्ष से होती है। मगध में क्रमशः हरयाल, शिशुनाग, और नन्दवश का राज्य रहा। नन्दवश ने ई० पू० 343 से ई० पू० 321 तक राज्य किया। इस वश का साम्राज्य पंजाब और सम्भवत बंगाल को

छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था। इसी के शासन में 326 ई० पू० भारत पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ था।

सिकन्दर के वापसी के साथ ही भारत में एक महान् क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप नन्द शासकों को हटा ई० पू० 323 में चन्द्र गुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा तथा मौर्यवंश की नींव रखी।

अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तम्भ पर सिंहों की आकृति बनी है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसे ही अपना राष्ट्रीय चिह्न बनाया। अशोक के स्तम्भ और शिलालेख, सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, सक्तिसा, कालसी, सिद्धार्थनगर और मिर्जापुर में पाये गये हैं। ये सभी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था।

अशोक की मृत्यु होते ही मगध के राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। पतञ्जलि के महाभाष्य में एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) के यवनो (यूनानियों) द्वारा घेरे जाने का आता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन आता है।

वासुदेव ने ईसा से 73 वर्ष पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश 45 वर्ष तक चला और ईसा से 28 वर्ष सिमुक ने जो सात वाहन या आध्र वंश के संस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया।

यह वह समय था, जब मध्य एशिया के शासकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। ईसा के 60 वर्ष पूर्व तक इन लोगों ने मथुरा में अपने क्षेत्रों स्थापित कर लिए थे। प्रथम शक राजा मायूस हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58 वे वर्ष में मृत्यु हुई थी। फिर ईसा से लगभग 40 वर्ष पूर्व कुषाणों के भी आक्रमण हुए।

कुषाण राज वंश

कुषाण राज वंश की स्थापना कुजुल कदफिसेस प्रथम ने की थी। कनिष्क

प्रथम, जो निसन्देह सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनिष्क की सोकेत (साकेत) के राजा से लड़ाई की गाथाएँ सुरक्षित रखे हैं तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एवं खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग में मिले हैं इस बात की ओर सकेत हैं कि यह भू भाग किसी समय कुषाण साम्राज्य का अंश था। उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था।

ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्य देश से समाप्त हो चुका था तथा उनके स्थान पर बहुत से दूसरे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस समय के इन राजाओं में कुछ के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) द्वारा इलाहाबाद के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ज्ञात हैं, तथापि तीसरी सदी में उत्तर भारत पर राज्य करने वाला सबसे सशक्त राजवंश नाग-वंश था।

द्वितीय सदी मध्य से लेकर के चौथी सदी में गुप्त राजाओं के उत्कर्ष तक का इतिहास अत्यन्त धूमिल रहा।

गुप्तवंश और उसका पराभव

ईसा बाद चौथी सदी में गुप्त वंश का प्रारंभ होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई लगभग दो सौ वर्षों के उनके शासन-काल के मध्य देश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ शान्ति और समृद्धि का भागीदार बना।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेंद्रित हो गयी। इसके अनन्तर गृहवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश आपस में मिल गये। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था।

हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर उथल-पुथल मच गयी। उपलब्ध सामग्री के आधार

पर इस काल का कोई सश्लिष्ट इतिहास तैयार करना सम्भव नहीं है। केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। जिसमें प्रमुख थी 1992 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय जिसके फलस्वरूप मुस्लिम शासकों का भारत में प्रादुर्भाव हुआ।

दिल्ली के यवन शासक

सन् 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और तभी से गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ। गुलाम वंश के राजाओं और उसे बाद खिलजी वंश तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे-धीरे दिल्ली की बादशाहत की सीमा बढ़ायी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के साम्राज्य का अंग रहा। सन् 1394 में सारे क्षेत्र के पूर्वांचल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी। यह शर्की साम्राज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर में नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहाँ ने की थी। शर्की शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की बादशाहत का जमकर विरोध किया और कन्नौज एवं सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं माना।

सन् 1412 में महमूद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मृत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली में तुगलक राजवंश की समाप्ति हो गयी।

सन् 1414 से 1526 तक सैय्यद और लोदियों ने दिल्ली साम्राज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया, किन्तु दोआब का अधिकतर भाग अनेक हिन्दू एवं मुसलमान सरदारों के अधीन बना रहा। तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया।

मुगल शासनकाल

बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन् 1526 में लोदियों के अन्तिम बादशाह

इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया, किन्तु उसके बाद भी अफगानो ने गगा की घाटी और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा, और कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कड़ी लड़ाई के बाद ही आत्मसमर्पण किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, किन्तु उसके लड़के हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह के हाथों करारी हार उठानी पड़ी थी। मुगलों और शेरशाह के बीच हुई लड़ाइयों में चुनार, चौसा तथा बिलग्राम प्रमुख रणस्थल थे। शेरशाह सूरी स्वयं सन् 1545 में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चन्देलों से लड़ते हुए मारा गया।

उसकी मृत्यु से मानो मध्ययुगीन इतिहास के गगन का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया। इसके उपरान्त महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमारम्भ हुआ। हुमायूँ फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। सन् 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। यह युग था शान्ति, समृद्धि और सुदृढ़ प्रशासन का, उदारता और हिन्दू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का।

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उत्तराधिकारियों जहाँगीर एवं शाहजहाँ के समय भी चलती रही। उत्कर्ष के इस युग में हिन्दुस्तान का जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उत्तर प्रदेश को कहते थे, महत्वपूर्ण अंशदान रहा है। अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक कि शाहजहाँ के समय में दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था, तब तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा।

औरंगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के बाद ही कुछ दशकों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया।

बुन्देलखण्ड, अवध तथा रुहेलखण्ड के रूप में स्वतन्त्र राज्य कायम किया गया। बाद में अवध के नबाब ने उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया। कुछ

समय तक मराठो ने गंगा-यमुना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये, किन्तु सन् 1761 में पानीपत में हुई हार ने उसकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया। अवसर से लाभ उठाकर अंग्रेजी ने दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

अवध के नवाब

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775) तक के शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी। शुजाउद्दौला ने बगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में वह अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एव इलाहाबाद अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी धमकी देकर तो कभी फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति बना ली।

सन् 1775, 1798 और 1801 में नवाबों से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त किये और सन् 1803 में ग्वालियर के सिधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते, वे सब शुरू में बगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये और उन्हें जीते एव मिले हुए प्रदेश की सज़ा दी गयी। सन् 1816 में सगौली की संधि द्वारा वर्तमान कुमाऊँ गढ़वाल और देहरादून के जिले गोरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये। इस प्रकार से जो विस्तृत क्षेत्र बना, उसे 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद

अंग्रेजों की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्वाभाविक परिणाम था कि

राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भडक उठी और सन् 1857 में यही हुआ। इस विद्रोह में जो राष्ट्र की आजादी के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के लोगो ने शानदार भूमिका अदा की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खॉ, नाना साहब, मौलवी अहमदउल्ला शाह, राजा बेनी माधव सिंह, अजीमउल्ला खॉ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तों ने इस ऐतिहासिक संघर्ष में जिस दृढ़ता का परिचय दिया, उससे वे अमर हो गये।

सन् 1858 में दिल्ली डिवीजन उत्तर-पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी। उसी वर्ष एक नवम्बर को एक शाही घोषणा द्वारा राजनीतिक सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गयी।

सन् 1858 में उत्तर-पश्चिम प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। उसी समय से इस वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिम प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1902 में इस नाम को बदलकर संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी। सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र संयुक्त प्रांत कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद अर्थात् 12 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसके तुरन्त बाद पास-पड़ोस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना।

आर्थिक स्थिति

आधुनिक राजनीति व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप था आधुनिक हो। इस सन्दर्भ में यदि 30 प्र0 की आर्थिक स्थिति का अन्वेषण करें तो देश की सबसे अधिक जनसंख्या तथा विस्तार में चतुर्थ

स्थान रखने वाला यह राज्य वर्तमान समय में आर्थिक रूप से लगातार पिछड़ता जा रहा है। उड़ीसा (रु04726) और बिहार (रु 3620) को छोड़कर इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे विभिन्न है। 1950-51 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय रु0 259 थी जो देश की प्रतिव्यक्ति आय 367 रु से 3 प्रतिशत पीछे थी। किन्तु आज यह अत्यन्त दयनीय स्थिति में है। यदि आठवें दशक के वर्षों को देखें तो निश्चय ही उस काल में आर्थिक प्रगति हुई किन्तु जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण न कर पाने के कारण यह विकास बेकार साबित हुआ। किन्तु वर्तमान वर्षों में राज्य की आय में फिर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही। यदि राज्य की आय में हिस्सा देखा जाय तो सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र 42.6 प्रतिशत (1994-95) आता है। सेकण्डरी क्षेत्र से 20 प्रतिशत तथा तृस्तरी क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) से 37.4 प्रतिशत हिस्सा आता है। इसके उतार चढ़ाव को सारिणी संख्या 2.2.1 से देखा जा सकता है।

सारिणी संख्या 2.2.1

राज्य की आय का स्वरूप वर्तमान मूल्य पर

क्षेत्र	1970-71	1980-81	1984-85	1989-90	1991-92	1994-95
1 प्राथमिक	60.2	52.3	54.4	41.1	43.7	42.6
2 द्वितीयक	14.9	15.3	18.0	21.2	20.3	20.0
3 तृस्तरीय	24.9	32.4	36.6	37.7	36.0	37.4

2 प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002

भाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य योजना आयोग अक्टूबर 1997

सारिणी संख्या 2.2.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य की आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है तथा द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। अतः यह स्पष्ट प्रदर्शित होता

है कि राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है तथा सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि यह दिखाता है कि राज्य की विकास की दिशा तो उचित है। किन्तु हाल के वर्षों में (1989 के बाद) देखा जाय तो निश्चय ही द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र के हिस्से में गिरावट हुआ है जो यह दिखाता है कि औद्योगिक तथा बौद्धिक विकास में इस दौरान कमी आयी है। साथ ही इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि 30 प्र० का द्वितीय क्षेत्र में अधिकतम योगदान 21.2 प्रतिशत भी महाराष्ट्र जैसे जिसका द्वितीय क्षेत्र का योगदान 37 फीसदी है, से काफी कम है।

राज्य की समृद्धि बोध करने का एक आधार राज्य की कुल आय होती है। सारिणी सख्या 2.2.2 में राज्य की कुल आय तथा कुल राष्ट्रीय आय में इसके योगदान को दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 2.2.2

3774-10
6.029

वर्ष	कुल राज्य आय करोड रुपये		कुल राष्ट्रीय आय में राज्य आय का योगदान	
	प्रचलित भावों पर	1980-81 के स्थायी भावों पर	प्रचलित भावों पर	1980-81 के स्थायी भावों पर
1980-84	14012		12.7	12.7
1984-85	21514	16331	11.7	12.2
1989-90 ☆	41664	21501	11.7	12.1
1990-91 ☆	49496	22780	11.8	12.2
1993-94 ☆	69682	23742	10.6	11.5
1995-96 ☆	88552	25151	10.0	10.5
1996-97 ☆	103170	27018	10.2	10.5
☆ अंतिम अनुमान ☆ त्वरित अनुमान				

T-924
10.5

तालिकागत आंकड़ों से विदित होता है कि प्रदेश की कुल राज्य आय

मे अबाध वृद्धि हुई है। फिर भी कुल राष्ट्रीय आय मे प्रदेश के योगदान मे वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा प्रदेश की आर्थिक विकास की गति मंद रही है।

भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है तथा देश की अधिकांश क्रियाशील जनता इसमे सलग्न है। 30 प्र0 जो जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है उसकी भी स्थिति इसी प्रकार रही है। राज्य की कुल आय मे सबसे अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि तथा पशुपालन आदि से आता है।

यदि प्रदेश मे कृषि के स्वरूप पर ध्यान दे तो अंग्रेजों ने जब पूर्वांचल 30 प्र0 उनके अधिकार मे आया तब स्थायी भूमि हिसाब या निस्तारण विधि कहे उसे लागू किया। स्थायी निस्तारण के तहत उच्च एवं समानुपातिक अचल राजस्व की मांग से ग्रामीण समाज का वर्गीकरण हुआ जहा भूस्वामियों का एक समूह समाज मे सबसे ऊपर आरुढ़ हो गया और बाकी अशक्त और अधिकारहीन उसके अधीन हो गए। छोटे-छोटे किसान कृषि के लिए जमींदारों अथवा सेठ साहूकारों से कर्ज लेते और अदायगी मे मनचाही सस्ती दर पर बड़ों के घर भरते। जबकि पश्चिम मे भाईचारे की व्यवस्था मे वहा बड़े-बड़े कृषक हुए।

जबकि पश्चिम मे जमींदार, सेठ-साहूकारों और व्यापारियों ने किसानों का शोषण करना चाहा लेकिन भाईचारा व्यवस्था के कारण बड़ी तादाद मे ऐसा संभव नहीं हो सका। कुछ ही लोग रहे जिन्होंने बड़े के अधीन खेती -बाड़ी की। आजादी के बाद ऐसे किसान बड़े एवं धनी खेतिहर हो गए जिन्होंने जमीन मे निवेश किया और बेहतर खेती के लिए नयी तकनीक को अपनाने मे रुचि दिखलायी।

कृषि मे एकरूपता लाने के लिए 30 प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम को सन् 1951 मे पारित किया गया ताकि-विचौलियों का वर्चस्व खत्म किया जा सके। इस बाबत जमीन की बहुव्यवस्था को एकरूपता देने के लिए इसे दो श्रेणियों मे बाँटा गया

(मालिक) और सीरदार (पैतृक)। सन् 1997 के बाद की श्रेणी भी समाप्त कर दी गयी और सभी सीरदारी को आनुपातिक अधिकार दिए गए।¹

निश्चय ही कृषि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का मेरुदण्ड है। यह प्रदेश के कर्मकारों में से 72.2 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिलाता है तथा राज्य की कुल आय (वर्ष 1995-96) में से 41.5 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन से ही आता है।²

उद्योग

उद्योग का क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा क्षेत्र है इसका सन् 1994-95 में राज्य की आय में 20 प्रतिशत योगदान रहा है। सन् 1991 में इस क्षेत्र ने राज्य की कुल श्रमशक्ति में से 8 फीसदी लोगों को रोजगार दिया। सन् 1980-81 में राज्य की आय में 10 प्रतिशत और श्रमशक्ति में 9 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की आय से इस हिस्से की हिस्सेदारी बढ़ती ही रही। लेकिन फिर भी यह देश के अन्य अति औद्योगीकृत राज्यों से काफी पीछे है। यदि इसके कारणों पर प्रकाश डाले तो मुख्य समस्या कृषि आधारित उत्पाद, बिजली और अभियांत्रिकी है।³

राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों की तलाश करें तो एक मुख्य कारण है योजनागत व्यय में कमी है व्यय का ज्यादा हिस्सा गैर योजनागत व्यय में होता है। जिसका एक कारण भारी-भरकम सरकारी मशीनरी, बड़े-बड़े मन्त्रिमण्डलों का निर्माण, राजनैतिक लाभ के लिए किए जाने वाले खर्च एवं कार्य है।

काम करने वालों का अनुपात

इस जनगणना के आकड़ों के अनुसार कुल व्यक्तियों में से 29.73 प्रतिशत काम करने वाले हैं। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में यह अनुपात क्रमशः 30.52 प्रतिशत तथा 26.26 प्रतिशत है। यदि स्त्रियों तथा पुरुषों में काम करने वालों का अनुपात देखा जाये तो ज्ञात होता है कि पुरुषों में कुल जनसंख्या के 49.31 प्रतिशत काम करने वाले हैं। जबकि स्त्रियों में यह प्रतिशत केवल 7.45 है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पुरुषों की जनसंख्या

उनकी कुल सख्या के आधे से अधिक (50 10) हैं जबकि काम करने वाली स्त्रिया केवल 8 36 प्रतिशत हैं। नगरीय क्षेत्रो मे काम करने वाली स्त्रियो का अनुपात तो और भी कम (3 75) प्रतिशत है। काम करने वाले पुरुष नगरीय क्षेत्रो मे 46 19 प्रतिशत हैं। यदि इन आकडो की तुलना वर्ष 1981 की जनगणना मे प्राप्त आकडो से करे तो कुल काम करने वालो के प्रतिशत मे 0 51 प्वाइन्ट की वृद्धि हुई है अर्थात् काम करने वालो का प्रतिशत वर्ष 1981 मे 29 22 से वर्ष 1991 29 73 हो गया है जबकि पुरुषो के प्रतिशत वर्ष 1981 मे 50 31 से वर्ष 1991 मे 49 31 रह गया है। काम करने वाली स्त्रियो के प्रतिशत मे 2 06 अक की वृद्धि हुई है अर्थात् 1981 मे जो 5 39 प्रतिशत था, वह वर्ष 1991 से बढकर 7 45 हो गया है। उपर्युक्त तथ्यो को सारिणी सख्या 2 2 3 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 2 2 3

कुल जनसख्या मे प्रतिशत		वर्ष 1981	वर्ष 1991
1 मुख्य काम करने वाले	व्यक्ति	29 22	29 73
	पुरुष	50 13	49 31
	स्त्री	05 41	07 45
2 सीमान्तिक काम करने वाले	व्यक्ति	01 49	02 47
	पुरुष	00 45	00 36
	स्त्री	02 67	04 87
3 काम न करने वाले	व्यक्ति	69 29	67 80
	स्त्री	91 93	87 68

मुख्य काम करने वालों का ग्रामीण एवं शहरी अनुपात सारिणी सख्या 2 2 4 में प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 2 2 4 ☆

विवरण	जनसख्या में प्रतिशत	
मुख्य काम करने वाले ग्रामीण	व्यक्ति	30 52
	पुरुष	50 10
	स्त्री	8 36
मुख्य काम करने वाले शहरी	व्यक्ति	26 26
	पुरुष	46 19
	स्त्री	3 75

☆ 1991 के जनगणना के अनुसार

इस प्रकार आकड़ों के तथ्यगत विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि राज्य की अधिकांश जनसंख्या अक्रियाशील है। इस प्रकार राज्य में अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। स्त्रियों की दशा तो और खराब है। वस्तुतः स्त्रियों का इस दशा के लिए आर्थिक ही नहीं सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण अधिक महत्व रखता है। राज्य में आज स्त्रियों की स्थिति आज भी द्वितीय दर्जे की है। जिसका प्रभाव यह है कि आज भी इनकी साक्षरता पुरुषों से कम है तथा रोजगार में इनकी भागीदारी नगण्य है। जो रोजगार में सलग्न हैं उनमें अधिकांशतः कृषि एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों में लगी हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता

हैं महिलाओं की भागीदारी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी काफी सीमित हैं। अभी हाल में प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने का विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो इस वर्ग को मुख्यधारा में जोड़ने में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

नगरीकरण

30 प्र0 अधिकांश (80 फीसदी से अधिक) जनसंख्या आज भी ग्रामीण है। यहाँ 1991 की जनगणना के अनुसार केवल 19.84 फीसदी जनसंख्या शहरों में रहती है। यद्यपि यह 1981 की जनगणना के अनुसार 17.65 से अधिक है किन्तु अत्यन्त ही कम है और इस शहरी आबादी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत और भी कम है जो क्रमशः 11.79 और 5.86 फीसदी मात्र है। इन्हीं तथ्यों को निम्न सारिणी प्रदर्शित करती है।

सारिणी संख्या 2.2.5

नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत	वर्ष 1981	वर्ष 1991
सामान्य	17.65	19.84
अ0 जा0	10.46	11.79
अनु0 ज0 जा0	4.72	5.86

वस्तुतः आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास एक दूसरे से अन्तः सम्बन्ध रखते हैं। आज यह समझा जाने लगा है कि एक आधुनिक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था जिसको फल-फूल सकती है। ससदीय लोकतन्त्र एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपनाया गया है इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था भी आधुनिक हो। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जातिवाद, अस्पृश्यता, स्थानीय तथ्यों सकीर्ण तथा क्षेत्रीयता की कुरीतियों का विरोध तथा धर्मनिरपेक्षता, समानता कार्य वितरण आदि की मांग करता है। इस प्रकार सामन्तवादी और मध्ययुगीय सामाजिक दशाओं के परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि सामन्तवादी और मध्य युगीय आर्थिक प्रणाली में भी परिवर्तन किया जाय तथा औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के माध्यम से इस परिवर्तन को देखा जा सकता है। किन्तु प्रदेश की आर्थिक आधुनिकीकरण या आर्थिक विकास की गति अत्यन्त धीमी है जिसका परिणाम यहाँ की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर निश्चित पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था व क्षेत्रीय वितरण

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो उल्लेखनीय पक्ष है वह है इसकी क्षेत्रीय विविधता। आर्थिक अर्थ में मसलन कृषि उत्पादन आधारभूत सुविधाएँ, एवं औद्योगिक विकास। इस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पाँच क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है यथा-पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखण्ड, और उत्तरांचल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की पर है। यह अपेक्षाकृत उद्योग के रूप में है और इसका अधिकतम शहरीकरण भी हो चुका है। ठीक इसके विपरीत बुंदेलखण्ड में कृषि विकास की दर धीमी है। उद्योग धंधे कम हैं। इस प्रकार राज्य में इसे सबसे कम विकसित क्षेत्र माना जाता है। इसी तरह से तीन अन्य क्षेत्र में बाकी चीजें यथा रहन-सहन शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधाएँ विकसित क्षेत्र की तुलना में काफी कम होंगी जो आर्थिक ढाँचे के साथ ही

सामाजिक ढांचे को भी दर्शाती हैं। इस तरह से पश्चिमी उ० प्र० जहाँ सम्पन्न है वहीं बुंदेलखण्ड काफी पिछड़ा हुआ है।¹

सारिणी सख्या 2 2 6 में इन तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी 2 2.6

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन

विकास संकेतक	पूर्वांचल	पश्चिमांचल	मध्यांचल	बुंदेलखण्ड	उत्तरांचल	उ०प्र०
1 जनसंख्या						
जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि० मी०)	614	603	528	229	116	473
जनसंख्या में वृद्धि दशमलव में (1981-91)	25.6	25.9	23.4	24.0	22.5	25.5
कुल जनसंख्या (1991)	11.6	26.3	23.7	21.3	21.7	19.8
की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत						
2 कुल साक्षरता (प्रतिशत) (1991)	38.6	42.0	42.6	42.3	29.6	41.6
साक्षरता प्रतिशत (महिला 1991)	20.9	26.6	28.3	23.9	42.9	25.3
3 भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख हे० में)	51.12	29.42	85.85	45.83	82.19	294.4
4 कृषि योग्य क्षेत्रफल (लाख हे० 93-94)	10.54	23.67	64.77	36.47	67.39	202.8

विकास सकेतक	पूर्वांचल	पश्चिमांचल	मध्यांचल	बुंदेलखण्ड	उत्तरांचल	उ०प्र०
5 रोजगार एवं मानव शक्ति	29 5	28 3	30 6	32 6	36 4	29 7
कुल जनसंख्या में से खास कर्मियों का प्रतिशत(1991)						
कुल खास कर्मियों में से	77 2	66 4	72 9	78 5	64 6	72 2
कृषि में लगे लोगों की संख्या (1991)						
6 प्रति बिजली की खपत (कि० वा० हा०)(1993-94)	161 1	235 1	157 4	111 8	245 6	188 2
7 विद्युतीकरण वाले गांवों का प्रतिशत (1994-95)	74 0	84 8	66 8	64 0	76 1	75 3
8 सिविल क्षेत्र का प्रतिशत (1993-94)	60 480 80	65 8	37 9	34 8	67 0	
9 फसली क्षेत्र का प्रतिहेक्टेयर कृषि उत्पादन की कुल कीमत (1992-93) वर्तमान कीमतों पर	9237	1205	9664	6658	9068	10117
10 प्रति ग्रामीण कुल कृषि उत्पादन (वर्तमान कीमत रु० में) (1992-93)	1627	3066	2218	2695	2095	2266
11 वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र से प्रति व्यक्ति कुल-उत्पादन (वर्तमान मूल्य रु० (1992-93))	1675	3024	2096	2546	2419	2302

संवैधानिक प्रणाली

भारतीय संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधान मण्डल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद कहलाता है। राज्य में एक उच्च न्यायालय भी है।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष से कम आयु का न हो, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की सत्पुष्टि तक अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यवधि पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदासीन रह सकता है।

राज्यपाल न तो सदन के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है। वह अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर सकता है और बिना किराये दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है। साथ ही वह ऐसे वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों का भी अधिकारी है जो समय-समय पर सदन द्वारा इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं होता, वह संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वेतन भत्तों व विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता है।

राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण के लिये तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने की शपथ लेता है।

राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने का अधिकार है।

राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता अथवा मंत्रणा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद् होती है। यह परिषद् ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं जिसमें राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस विषय पर राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है तथा इस सम्बन्ध में उसके कार्य के औचित्य पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है।

राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। मंत्रि-परिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये गये परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि कोई मंत्री निरन्तर छ मास की अवधि तक राज्य के विधान मण्डल का सदस्य न रहे तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता।

मंत्रियों को समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भत्ते देय होते हैं। वे अन्य लाभों के भी अधिकारी होते हैं। उन्हें निशुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधायें प्राप्त हैं। राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है।

मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि परिषद् के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिये प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देता है। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। यदि किसी मामले में किसी एक मंत्री ने एक पक्षीय निर्णय ले लिया है तो राज्यपाल मंत्रि परिषद् से उस पर पुनर्निर्णय

लेने के लिये कह सकते हैं। इस कार्य के लिये वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। वह विधान मण्डल के किसी भी सदन में लम्बित किसी विधेयक के विषय में सम्बन्धित सदन को सदेश भेज सकता है। जिस सदन को ऐसा सदेश भेजा जाय उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा।

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात् तथा प्रत्येक वर्ष विधान मण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर उन्हें अवगत कराता है कि विधान मण्डल की बैठक किन कार्यों के निष्पादन के लिये बुलाई गयी है। राज्यपाल विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देता है या उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये सुरक्षित रखता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। वह विधान परिषद के लिये 12 सदस्यों तथा विधानसभा के लिये एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करता है।

राज्यपाल प्रतिवर्ष दोनों सदनों के समक्ष सम्बन्धित वर्ष का वित्तीय लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और भारत के नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक का राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विधान मण्डल सत्र में न होने के समय यदि वह सतुष्ट है कि स्थिति ऐसी है कि तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है। विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है।

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा में मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्यों को मिलाकर 426 सदस्य हैं। सन् 1967 तक एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर विधान सभा के 431 सदस्य होते थे। परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात् गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है

विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाच साल का होता है। बशर्ते कि वह उसे पहले विघटित न कर दी जाये। निर्वाचन एक वयस्क एक वोट के आधार पर किया जाता है।

सदन अधिनियम

विधान सभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। विधान सभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत द्वारा निर्णीत होते हैं और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है।

विधान सभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संचालित करता है। यह सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। विधान सभा का मुख्य कार्य अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिये धन स्वीकृत करना, प्रश्नो, प्रस्तावों व संकल्पों द्वारा चर्चा करके और विवाद छेड़कर तथा अविलम्ब महत्व विषयों की चर्चा करके सरकार की कार्यविधियों पर नियंत्रण रखना है। उसका कार्य हिन्दी भाषा में व देवनागरी लिपि में किया जाता है।

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के रूप में सदन के समक्ष अध्यक्ष की पूर्ण अनुज्ञा से रखे जाते हैं। उसके पश्चात् या तो सीधे सदन में ही विचारार्थ ले लिये जाते हैं अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिये जाते हैं। सदन विभिन्न उपबन्धों पर विचारोपरान्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसे संशोधनों सहित पारित कर सकती है। इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा विधेयक को पुनः विचारार्थ विधान परिषद भेज सकती है। यदि इस प्रकार विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक परिषद के भेजने के बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिससे विधान सभा सहमत न हो या ऐसा विधेयक एक मास की अवधि तक परिषद अपने यहां लम्बित रखती है तो यह समझा जायेगा कि वहां विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा। धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार,

परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परिषद द्वारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनो सदनों से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा।

अन्य प्राक्कलन सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनों पर मतदान के लिये पांच दिन की सामान्य बहस के अतिरिक्त 24 दिन का समय ले सकता है। प्राक्कलित व्ययों के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के रूप में होते हैं। विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

सविधान में इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकृत धनराशि कम पड़ती है या व्यय की धनराशि से बढ़ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक अतिरिक्त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

विधान परिषद्

प्रदेश में सन् 1937 से दोनो सदनों का विधान मण्डल है। उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है और यह स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिये निर्वाचित या मनोनीत किये जाते हैं और उनमें से एक तिहाई प्रति दूसरे साल निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 है जिसमें से 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं 39 स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, 39 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा स्नातकों और अध्यापकों द्वारा 9-9 सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक उसमें पेश किया जा सकता है। अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता, जब तक दोनो सदनों से पारित न हो जाये। विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते हैं। और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की ही भांति होता है, जो उन्हीं की भांति अपने पदों पर बन रहते हैं।

विधान मण्डल के सदनों के पृथक-पृथक अपने सचिवालय और सचिव हैं जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवों से पूर्णतया स्वतंत्र है। दोनो

सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है जो ससदीय लेखा कार्यवाही और समितियों का कार्य देखते हैं। विधान मण्डल के सदस्यों के प्रयोग के लिये एक विधान मण्डल पुस्तकालय भी है। यह देश के विधान मण्डल पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय है।

दोनों सदनों के सदन की समितियों के सदस्यों को वही विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को मिली हैं। इसके अतिरिक्त सदन में भाषण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

नेता विरोधी दल

उत्तर प्रदेश ने एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातंत्र प्रणाली में एक विशिष्ट योगदान किया है। विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्री के समकक्ष प्रतिष्ठा दी गई है। नेता, विरोधी दल के लिये मंत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित, निशुल्क आवास का प्राविधान है। उसे वाहन भत्ता, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधाएँ, जो उसके पद के अनुरूप हों, दी जाती हैं। अधिनियम के अनुसार सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है किन्तु ऐसे दल के सदस्यों की संख्या कम से कम गणपूर्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

कार्यपालिका

मन्त्रिपरिषद् संयुक्त रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ में एक सुव्यवस्थित सचिवालय है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने-अपने विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए

जिम्मेदार है और सम्बन्धित मंत्री तथा मन्त्रिमण्डल के आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। उनके इस कार्य में विशेष सचिव, सयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं। विभागों के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिये उचित स्थायी आदेश तथा निर्देश देता रहता है। इन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन यह भी निश्चित होता है कि कौन से कार्य सचिव द्वारा या उससे नीचे के अधिकारियों द्वारा निपटाये जा सकते हैं और कौन से ऐसे मामले हैं, जो मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलों से सम्बन्धित राज्य में एक उच्च न्यायालय है। राजस्व के मामलों के लिये सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद है। सविधान के अनुच्छेद 127 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका तात्पर्य यह है कि इसकी कार्यवाहियाँ शाश्वत साक्ष्य हैं। इसके अभिलेखों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे अपनी अवमानना के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति योग्य जाते हैं जो भारत के नागरिक हों और जिन्होंने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता के रूप में या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी को सविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने में सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में विभाजित किया गया है-उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। इसमें प्रथम के अन्तर्गत मुन्सिफ और लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल सेशन जज(अब अतिरिक्त जिला सेशन जज) आते हैं। जिले स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण होता है। प्रदेश 46 न्यायिक जिलों में बंटा है जिसमें प्रत्येक का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन है। मुन्सिफ और असिस्टेंट कलेक्टर को जूडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं और सिविल जज पदेन असिस्टेंट सेशन जज भी होता है। जिला न्यायाधीश का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिले में फैला है।

दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय, मुन्सिफ का न्यायालय होता है। उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे उच्च न्यायालय जिला जज का होता है। फौजदारी के मामलों में मुन्सिफ को न्यायिक दण्डाधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं। 2 अक्टूबर 1967 से न्यायिक दण्डाधिकारी(जो पहले सीधे शासन के अधीन थे) उच्च न्यायालय के अधीन कर दिये गये हैं। इस प्रकार राजस्व के मामलों को छोड़कर प्रदेश में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पूर्ण पृथक्करण हो चुका है।

राजस्व के मामलों में सहायक कलेक्टर और उसके ऊपर अतिरिक्त कलेक्टर और कलेक्टर होता है, जो अपील के मामलों की सुनवाई करते हैं। राजस्व मामलों में राजस्व परिषद ही सर्वोच्च न्यायालय है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। इनका कार्य सिविल है और ये कुछ निर्दिष्ट मामलों में 500 रुपये तक के मूल्य केवादों की सुनवाई कर सकती हैं। इनको फौजदारी के निर्दिष्ट छोटे-छोटे मामलों में भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतों को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण

सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या अदालतों में निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे मुकदमों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कंपनियों के धन और समय का अपव्यय होता है। इसलिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्थापित किये गये। इनकी स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।



तृतीय अध्याय

मंत्रिपरिषद् की संरचना

मन्त्रि परिषद की संरचना

3.1 मन्त्रि-परिषद की ऐतिहासिकता -

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने स्वतन्त्रता के पश्चात् जिस स्वरूप को केन्द्र व राज्यो में अपनाया गया उसे संसदीय शासन (मन्त्रि-मण्डलीय) व्यवस्था के नाम से जाना जाता है । इस शासन व्यवस्था के अपनाने के पक्ष में सर्वाधिक प्रबल तर्क यह दिया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दिनों में भारत कुछ अंशों में इससे परिचित हो गया था । जैसा कि स्वयं के एम मुंशी ने कहा - "इस समूचे अनुभव के पश्चात् हम इन परम्पराओं का परित्याग क्यों करें - और क्यों एक अभिनव प्रयोग करें ?"¹ इस सम्बन्ध में नेहरू ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हुए संविधान सभा में कहा था- "हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते ।"² अतः इस शासन के व्यवस्था के उद्भव एवं विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बाटा जा सकता है---

(1) आधुनिक भारत मन्त्रिपरिषद

(2) प्राचीन भारत मन्त्रिपरिषद

(3) उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद

आधुनिक भारत मन्त्रिपरिषद

भारत में विद्यमान वर्तमान शासन पद्धति की मन्त्रिमण्डलात्मक-संसदात्मक पद्धति लगभग 50 वर्ष पुरानी हो गई है । परन्तु इसके प्रारम्भ एवं विकास को भली-भांति

1 हेनसन, एच एम एवं डगलस जेनेन 'इण्डियन डेमोक्रेसी,' दिल्ली विकास (1927)।

पृ० 95-96 ।

2 सी० ए० डी०, वॉल्यू 4, पृ० 916 ।

समझने के लिए हमे इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा । दीर्घकालीन परतन्त्रता के उपरान्त भारत मे जिस राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, उसे एक ओर ब्रिटिश शासन द्वारा कुचलने और दबाने का प्रयास किया गया, वही दूसरी ओर उस जन-जागृति से प्रस्फुटित आक्रोश को सुधारो के कुछ प्रयासो

द्वारा शान्त करने का भी असफल प्रयास किया गया । ब्रिटिश शासन काल मे सुधारों की श्रृंखला इन्ही प्रयासो का प्रतिफल थी ।

एक दीर्घकाल तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य से सतत सम्बद्ध रहा है । सुधारो के रूप मे विभिन्न भारतीय परिषद् अधिनियमो द्वारा हमे क्रमश प्रांतीय आशिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन, केन्द्र मे आशिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर ससदीय प्रजातन्त्र और मन्त्रिपरिषद् प्रणाली का आशिक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । अत स्वातन्त्र्योत्तर काल मे भारतीयो का ब्रिटिश परम्पराओ पर आधारित एव उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक है । यहा तक कि भारतीय सवैधानिक धाराओ की पृष्ठभूमि का निर्माण भी व्यापक रूप से इन अधिनियमो और ब्रिटिश अभिसमयो पर आधारित है । इनसे भारत के लोग पूर्वपरिचित ही नही थे, वरन् ब्रिटिश शासन के अर्न्तगत प्राप्त अनुभवो और प्रशिक्षण के कारण भारत के लोगो की भारत मे भी उनकी सफलता मे पूर्ण विश्वास ओर आस्था थी । उत्तराधिकार मे प्राप्त सुस्थापित ब्रिटिश परम्पराए भारतीय शासन-प्रणाली का आदर्श और मन्त्रिण्डलात्मक पद्धति का आधार स्तम्भ है । इन्हे भारतीय सविधान मे अधिग्रहीत कर आवश्यकतानुसार रूपान्तरित कर लिया गया है ।

मन्त्रिपरिषद् शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैण्ड मे "बेकन" ने कान्सल (काउन्सिल) के विशेषण के रूप मे किया । जिस समय सन् 1625 ई० मे चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा था, उस समय कैबिनेट कान्सल (मन्त्रिपरिषद्) शब्द का प्रयोग मिलता है ।³ उस काल

3 कश्यप डा सुभाष 'राजनीतिक शब्द कोष', दिल्ली, राजकमल प्रकाशन (1971) पृ०

मे ब्रिटिश सम्राट के परामर्शदाताओं की औपचारिक परिषद् “प्रिवी परिषद्” (प्रिवी कोन्सिल) थी । सम्राट के अतिरिक्त परामर्शदाताओं अथवा मन्त्रिपरिषद् के उत्थान के साथ ही प्रिवी परिषद् का महत्व कम होने लगा था ।

भारत में मन्त्रिपरिषद् का प्रादुर्भाव 1857 की क्रान्ति के बाद 1858 के गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट में देखने को मिलता है । भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाने का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास सन 1857 ई० में हुआ । 1857 का जनव्यापी विद्रोह भारतीय जनता की विदेशी शासन के विरुद्ध वर्षों से जमी हुई शिकायत का परिणाम था । यद्यपि इस क्रान्ति द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकालने में सफलता नहीं मिली परन्तु इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप को पलट दिया गया, यही से भारत के इतिहास में संवैधानिक शासन का सूत्रपात हुआ और यही से भारतवर्ष में मन्त्रिपरिषद् सरीखी संस्था का प्रादुर्भाव हुआ । 1858 के गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट में राज्यशक्ति के प्रयोग का अधिकार भारत सचिव को सौंपे जाने की व्यवस्था की गयी तथा उसकी सहायतार्थ एक पन्द्रह सदस्यों की “काउंसिल ऑफ इण्डिया” के निर्माण की व्यवस्था की गयी ।⁴ इस काउंसिल ऑफ इण्डिया के सदस्यों की ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्ति तथा इसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था थी । यही से शासन की वह व्यवस्था शुरू हुई जिससे मैकाले ने उदार निरंकुशता की नीति की शुरुआत कहा है ।

इस दिखावटी सहयोग और उदार निरंकुशता की नीति के परिणामस्वरूप 1861 और 1892 के भारत शासन अधिनियम पारित किये गये । 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् को कानून-निर्माण करने का अधिकार दिया गया । पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों

4 वर्मा एस पी भारतीय संविधान और शासन' एम. सी आई आर टी , दिल्ली, पृ० 73।

को कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित की जाने की व्यवस्था की गयी । इन सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी तथा यह व्यवस्था थी कि कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी हों । गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् के लिए यह आवश्यक था कि कानून निर्माण के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों से परामर्श करे । इन सदस्यों को कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था परन्तु ये सरकार की आलोचना करने के अधिकारी नहीं थे । इनका कार्य मात्र गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारिणी के समक्ष रखे गये प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने तक सीमित था ।⁵

सन् 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम विधेयक कार्यों में भारतीयों के सहयोग की दिशा में एक और कदम था । इस अधिनियम द्वारा परिषद् की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गयी । केन्द्रीय काउन्सिल में बंगाल चैम्बर आफ कामर्स तथा प्रान्तीय विधान परिषदें, गैर सरकारी सदस्य नामांकित करके भेज सकती थी । प्रान्तीय विधान परिषदों में विश्वविद्यालयों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं आदि संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी सदस्य नामांकित किये जा सकते थे । इस अधिनियम द्वारा एक सीमा तक विधायिनी शक्तियों ने भी विस्तार हुआ ।⁶ सदस्यों को बजट पर वाद-विवाद करने का अधिकार दिया गया । इस अधिनियम द्वारा सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया ।

उपर्युक्त सुधारों के उपरान्त भारत में ब्रिटिश शासन की निरकुशता में कोई कमी नहीं आयी । लार्ड लिटन के शासन-काल में अनेक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिये गये । इसी काल में शनैः शनैः विकसित होने वाली राष्ट्रीय चेतना के परिणामस्वरूप प्रस्फुटित होने

5 वर्मा, एस पी — वही — पृष्ठ — 11 ।

6. वही, पृ० 12 ।

वाले जन आकोश से ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने के लिए "फूट डालो और शासन करो" (डिवाइड एण्ड रूल) की नीति अपनायी गयी । 1909 में मार्ले मिन्टो सुधार योजना में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसीलिए स्वीकार की गई । यद्यपि 1908 ई० के अधिनियम से प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई तथा गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का निर्वाचन किए जाने की व्यवस्था की गई तथापि उत्तरदायी शासन व्यवस्था का अभाव ही बना रहा ।

भारत के संवैधानिक इतिहास की प्रक्रिया में यद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों के सन्दर्भ में उपर्युक्त अनेक अधिनियम प्रदान किये गये परन्तु भारत में सर्वप्रथम आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की दृष्टि से 1919 का अधिनियम विशेष महत्वपूर्ण है । 1919 के अधिनियम से मन्त्रिपरिषद् का विस्तार प्रारम्भ हुआ तथा भारतीय विधानपरिषद् को अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाया गया । उसमें दो सदनों की व्यवस्था की गयी— उच्च सदन, "कौंसिल आफ स्टेट— जिसमें 60 सदस्यों की व्यवस्था थी, इनमें कुछ निर्वाचित होते थे, निम्न सदन— 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' में 144 सदस्यों की व्यवस्था थी, इनमें से 104 सदस्यों को निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गयी थी ।⁷ इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास हुआ । प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के साथ अधिकाधिक सहयोग तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषित नीति के फलस्वरूप, द्वैध शासन प्रणाली के रूप में प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी शासन प्रदान किया गया था । इसके अनुसार कार्यपालिका परिषद् को सुरक्षित एवं हस्तान्तरित दो भागों में बाँटकर क्रमशः अनुत्तरदायी कौंसिल और उत्तरदायी मन्त्रियों के आधीन कर

दिया गया था । गवर्नर और उसके कौंसिल सरक्षित विषयों के प्रशासन में अभी भी गवर्नर जनरल और भारतमन्त्री के माध्यम से ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी थे । हस्तान्तरित विषय गवर्नर के द्वारा मन्त्रिमण्डल की सहायता से प्रशासित होते थे तथा मन्त्रिमण्डल मन्त्रिपरिषद् के प्रति उत्तरदायी होता था, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का अनुपात कुल सदस्यों का 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया । यद्यपि ये तथाकथित जन प्रतिनिधि साम्प्रदायिक और सकुचित निर्वाचन मण्डल के आधार पर चुने जाते थे ।¹⁸ तथापि हस्तान्तरित विषय पर मन्त्रियों को प्रान्तीय विधान मण्डलों के प्रति प्रथम बार उत्तरदायी बनाकर आशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुयी थी । उस समय के प्रमुख कांग्रेस दल द्वारा विधान सभाओं के आविष्कार, व्यवस्था में निहित अनेक आन्तरिक दोषों तथा वाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा यह व्यवस्था पूर्णतः असफल सिद्ध हुयी, फिर भी भारत में प्रथम बार आशिक उत्तरदायी शासन विधान-मण्डलों की स्थापना की दृष्टि से सवैधानिक विकास की दिशा में इस अधिनियम को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में निरूपित किया जा सकता है ।

सन् 1935 का अधिनियम इस श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम था, जिसके अन्तर्गत प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी स्वायत्त शासन तथा केन्द्र में आशिक उत्तरदायी शासन की असफल द्वैध-व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया था । प्रान्तों में समस्त सरक्षित विषयों को हस्तान्तरित कर प्रान्तीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रियों को सौंप दिये गये थे । इन मन्त्रिमण्डलों में दायित्वों का परिपालन कर उत्तरदायी शासन का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया । प्रधानमन्त्री के नेतृत्व का अभाव गवर्नर जनरल और गवर्नरों के स्वविवेक और व्यक्तिगत निर्णय सहित अनेक सुरक्षित विशेषाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, व्यवस्थापिका सभाओं

का अप्रजातान्त्रिक सगठन इत्यादि अनको ससदात्मक उत्तरदायी शासन की आवश्यक विभिन्न विशेषताओं का पूर्णतया अभाव था । गवर्नर जनरल और गवर्नर सवैधानिक औपचारिक प्रमुख के स्थान पर वास्तविक अधिशासकीय शक्तियों से सम्पन्न थे । फिर भी केन्द्र में आशिक उत्तरदायी शासन और प्रान्तों में पूर्ण स्वायत्त शासन, सवैधानिक विकास की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे । भारतीय सविधान की मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी धाराओं पर 1935 के अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । यद्यपि भारतीय सविधान निर्माताओं में मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था के सम्बन्ध में ब्रिटिश ससदीय सरकार के आदेश को सदैव अपने सम्मुख रखकर, ब्रिटिश कैबिनेट पद्धति के अनेक अभिसमय को अपने सविधान के अन्तर्गत अपनाकर लिपिबद्ध कर लिया है, परन्तु इन धाराओं की शब्द रचना और भावनाओं पर 1935 के अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारूप सविधान के निर्माण और सविधान सभा में वाद-विवाद, विचार विमर्श, विभिन्न सशोधन प्रस्तावों, उनकी स्वीकृति तथा अस्वीकृति के मध्य सविधान-निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम को कभी दृष्टिपटल से ओझल नहीं किया ।

भारतीय सविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम से प्रभावित होकर 'कैबिनेट' के स्थान पर 'मन्त्रिपरिषद्', शब्द का प्रयोग किया है । 1935 के अधिनियम की धारा 9 का वर्तमान सविधान की धारा 74 (1) पर पर्याप्त प्रभाव है, जिसके अनुसार एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यह मन्त्रिपरिषद् गवर्नर जनरल को उसके स्वविवेकीय कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता एवं परामर्श प्रदान करेगी । इस धारा की दो बातों को छोड़कर भारतीय सविधान में इसे पूरा-पूरा स्वीकार कर लिया है । केवल उसकी निश्चित सदस्य संख्या और गवर्नर जनरल की भांति राष्ट्रपति को स्वविवेकीय अधिकार प्रदान नहीं किये हैं यद्यपि सविधान सभा में मन्त्रिपरिषद् की संख्या 15 निर्धारित करने और राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकीय अधिकार प्रदान करने का कुछ सदस्यों ने अपने सशोधन प्रस्तावों द्वारा आग्रह किया था । भारतीय सविधान की धारा 74(1) में 1935 के अधिनियम की भांति एक मन्त्रिपरिषद् का प्रावधान है, गवर्नर जनरल के स्थान पर प्रधानमंत्री उसका प्रमुख है । इस

मन्त्रिपरिषद् का कार्य गवर्नर जनरल के स्थान पर राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श प्रदान करना है । 'सहायता' और 'परामर्श' की शब्द — रचना भी १९३५ के अधिनियम से अधिगृहीत की गयी है ।

वर्तमान सविधान की धारा 75(1) भी 1935 के अधिनियम की धारा 10 से प्रभावित है, जिसके अनुसार गवर्नर—जनरल मन्त्रियों की नियुक्ति करे। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा । सविधान की धारा 75(2) पूर्णतया शब्दशः 1935 के अधिनियम की धारा 10 के समान है, जिसके अनुसार मन्त्रीगण राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे । इस धारा में केवल 'गवर्नर—जनरल' के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द परिवर्तित किया गया है ।

इसी भाँति भारतीय सविधान की धारा 75(5) भी 1935 के अधिनियम की धारा 10(2) से लिया गया है जिसके अनुसार यदि कोई मन्त्री निरन्तर 6 मास की अवधि तक ससद के किसी सदन का सदस्य न रहे, तो उस अवधि की समाप्ति पर मन्त्री नहीं रहेगा । 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल ससद के बाहर के व्यक्तियों को मन्त्री बना सकता था और 6 महीने में उन्हें निर्वाचित या नामांकित कर ससद का सदस्य बना सकता था । इसीलिए डा० अम्बेडकर ने निर्वाचित और नामांकित सदस्यों में कोई भेद न करके प्रधानमंत्री को इस विषय में प्रतिबद्ध नहीं किया है ।

वर्तमान सविधान की धारा 75(6) भी 1935 के अधिनियम की धारा 10(3) से ली गयी है, जिसके अनुसार ससद समय—समय पर मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित करेगी । परन्तु 1935 के अधिनियम से ससद उसे कम भी कर सकती थी, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । दूसरे 1935 के एक्ट के अन्तर्गत मन्त्रियों के वेतन और भत्तों पर ससद मतदान नहीं कर सकती थी परन्तु सदस्यों द्वारा वाद—विवाद और मतदान के लिए खुले हुए हैं ।⁹

9 बसु, दुर्गादास - 'कमेन्ट्री आन दी कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया', एस सी सरकार, कलकत्ता, 1961,

सविधान निर्माताओं ने भी 1935 के एक्ट की भांति प्रारम्भ में राष्ट्रपति के लिए एक निर्देश-पत्र तैयार किया था। गवर्नर के लिए भी ऐसे ही निर्देश-पत्र की व्यवस्था थी।¹⁰ 1935 में गवर्नर-जनरल और गवर्नर के लिए ऐसे ही निर्देश-पत्र अधिनियम के साथ सन्निहित किये गये थे। जिसके अनुसार मन्त्रियों के चुनने, वर्गीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने के लिए मार्गदर्शन दिया गया था ताकि स्वायत्त शासन और उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके। इनका नामकरण "इम्सट्मेन्ट आफ इन्सट्रक्शन" 1935 के अधिनियम के अनुसार ही किया गया था, परन्तु बाद में उन्हें अनावश्यक समझकर छोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान भारतीय सविधान की प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी अनेक धाराओं पर 1935 के भारत परिषद् अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोच्य होता है। उसकी अनेक सुपरिचित एवं प्रचलित विशेषताओं को भारतीय सविधान में सन्निहित कर लिया गया है।

भारतीय सविधान निर्माताओं ने प्रारम्भ से ही अपने पूर्वकालीन अनुभव और प्रशिक्षण को दृष्टिगत कर तथा ब्रिटिश शासन-पद्धति की परम्पराओं से प्रभावित होकर उसके आदर्श को अपनी ससदात्मक मन्त्रिमण्डल प्रणाली का आधार बनाकर देश में प्रचलित करने का निर्णय लिया था। सरदार बल्लभभाई पटेल ने 15 जुलाई, 1947 को सविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि "सविधान सभा की संघीय संवैधानिक समिति तथा प्रान्तीय संवैधानिक समिति दोनों ही इस निष्कर्ष पर पहुँची हैं कि हमारे देश की परिस्थितियों में ब्रिटिश नमूने का ससदात्मक पद्धति वाला सविधान सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल है जिससे कि हम भली भाँति परिचित हैं।"¹¹

10 अम्बेडकर, डॉ० बी. आर - सविधान सभा बहस - खण्ड 7, पृ० 985 ।

11 सविधान सभा बहस - खण्ड - 4, पृ० 580 ।

प्रारूप सविधान के निर्माण के समय से ही संघीय सविधान समिति में यह निर्णय लिया गया था कि हमारी केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश नमूने पर आधारित होगी तथा हमने अमेरिका की तरह अध्यक्षतात्मक पद्धति की सरकार के नमूने को ठुकरा दिया था।¹² श्री हुसैन इमाम, महमूदअली बेग, हाजी अब्दुल सत्तार, हाजी इशाक, सैयद करीमुद्दीन इत्यादि मुसलमान सदस्यों ने अमेरिकन पद्धति की अध्यक्षतात्मक सरकार अथवा स्विस् पद्धति की कार्यपालिका के पक्ष में विचार व्यक्त किये थे परन्तु पटेल, नेहरू, पटेल, अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, एच वी कामथ, के हनुमैया, टी टी कृष्णामाचारी, डा पी एस देशमुख आदि सभी प्रमुख व्यक्तियों ने बहुमत से संसदीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और कैबिनेट पद्धति की उत्तरदायी मंत्रिमण्डलीय वास्तविक कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति को वैधानिक प्रमुख के रूप में प्रतिष्ठित करने और परामर्श से बाध्य करने के पक्ष में एक मत निर्णय दिया। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने इस बात की पुष्टि की कि “संघीय सविधान समिति और सविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत प्रारूप में संसदीय पद्धति की सरकार को स्वीकार किया गया है।¹³ राष्ट्रपति की शक्तियों के समर्थक श्री के एम मुशी तक ने इस बात को स्वीकार किया कि केन्द्र के लिये प्रारम्भ से ही अत्यधिक बहुमत से कैबिनेट पद्धति की सरकार के पक्ष में राय प्रकट की गयी थी।¹⁴

ऐतिहासिक सन्दर्भ में 1935 के गवर्नर जनरल को औपचारिक प्रमुख के रूप में रूपान्तरित कर सविधान सभा ने हमारे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट के समरूप प्रतिष्ठित किया है।¹⁵

12 वही, खंड - 7, पृष्ठ 986 ।

13 राव, वी शिवा ‘दि फ्रेमिंग ऑफ इण्डिया कान्स्टीट्यूशन’, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनेस्ट्रेशन, दिल्ली, खण्ड-2, 1976, पृष्ठ 556 ।

14 मुन्शी, के एम ‘प्रेसीडेंट ऑफ दी इण्डिया’, वन्दई, भारतीय विद्याभवन, 1963, पृष्ठ 2 ।

15 जैन, एच एम दी यूनियन एक्जीक्यूटिव, चैतन्य पब्लिशर, इलाहाबाद, 1969, पृष्ठ 134 ।

श्री अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि वास्तविक और नाममात्रीय कार्यपालिका की द्वैधता ब्रिटिश ससदीय पद्धति का निचोड है। भारत में भी राष्ट्रपति के रूप में ब्रिटिश सम्राट की भांति नाममात्रीय औपचारिक कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद् के रूप में वास्तविक कार्यपालिका की स्थापना की गयी है। अतः भारतीय संविधान में ब्रिटिश ससदीय और कैबिनेट पद्धति के अभिसमयों को लिपिबद्ध कर कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया है।

संविधान की धाराओं के अनुसार भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट के समरूप औपचारिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद् की परामर्श से कार्य करेगा। प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के प्रमुख के रूप में सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्यपालिकाईय प्रशासन का नेतृत्व करेगा। ब्रिटिश ससदीय प्रणाली की भांति व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी, अर्थात् प्रधानमंत्री और उसकी मन्त्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इंग्लैण्ड की भांति भारत में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण का अभाव है। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को ससद का सदस्य होना अनिवार्य है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और नेतृत्व, दलीय समरूपता, एकता, गोपनीयता इत्यादि कैबिनेट पद्धति की आवश्यक विशेषताओं को भी सन्निहित किया गया है।

अतः अपने पूर्व अनुभव प्रशिक्षण के आधार पर वेस्मिस्टर आदेश को प्रमुख प्राथमिकता देकर ब्रिटिश पद्धति की ससदात्मक सरकार को स्वीकार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद् का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। ससद में अपने दल का बहुमत और विश्वास प्राप्त कर वही देश के वास्तविक प्रशासन को संचालित, नियंत्रित और निर्देशित करता है।

कैबिनेट पद्धति के सम्बन्ध में जिन ब्रिटिश अभिसमयों को विकसित और वर्तमान रूप में सुस्थापित होने में दीर्घकाल लगा, भारत को वे समस्त परम्पराएँ आदर्श रूप में

अनुसरण कर अपनाने और लिपिबद्ध करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई।

प्राचीन भारत मन्त्रिपरिषद्

वर्तमान भारत में विधानमन्त्रिमण्डलीय शासन व्यवस्था से परिचित कराने का श्रेय -- ब्रिटिश शासन को जाता है। प्राचीन काल में भी भारतीय शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य संस्था थी। इसका महत्व तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सभी आचार्यों ने इसको सप्ताग में द्वितीय स्थान प्रदान किया है।¹⁶ राजा को परामर्श देने वाली इस संस्था के सदस्यों, को आमात्य, सचिव, मंत्री आदि नामों से सम्बोधित किया गया है।

हिन्दू मन्त्रि-परिषद् वास्तव में एक ऐसी संस्था थी, जो प्राचीन वैदिक काल की राष्ट्रीय सभा से, उसकी शाखा के रूप में निकली थी।¹⁷ वैदिक युग में राजकृत राजान की सहायता से राजा शासन-कार्य का सम्पादन करता था, जिन्हें उत्तर वैदिक युग में 'रत्निन्'¹⁸ कहा जाता था। वैदिक यज्ञों का प्रचार हटने से धीरे-धीरे रत्निन् वर्ग का भी अन्त हो गया। बाद के वाङ्मय में यदा-कदा 'रत्निन्' का उल्लेख मिल जाता है, परन्तु 'रत्निन्' का अर्थ राजा के परामर्श दाता या सहायता ही नहीं रह गया था।¹⁹ बाद में जब जनपद व राज्य सुव्यवस्थित स्थिति में पहुँचे तब राजा की सहायता के लिए मन्त्रिपरिषद् का निर्माण हुआ। इसे अर्थशास्त्र²⁰ में मन्त्रिपरिषद्, जातको,²¹ महावस्तु²² और अशोक के

16 अर्थ. 6/1/1, मनु 9/294, शुक्र 1/61, शा पृ 69/65, कमन्दक 1/16 ।

17 'जायसवाल हिन्दू पॉलिटी' - बैंगलोर प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी, 1995, पृ0 268 ।

18 अर्थ. 3/5/6-7 ।

19. ब्रा. 5/1 ।

20 अल्लेकर 'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति', भारतीय भंडार, इलाहाबाद, 1959, पृ0 138

21 अर्थ 1/15/53 ।

22 जातको ।

अभिलेख²³ में 'परिषा' कहा गया। दीघनिकाय में मन्त्रियों के लिये 'राजकृत'²⁴ रामायण में राजकर्ता²⁵ तथा अशोक के अभिलेखों में 'राजुक'²⁶ शब्द का प्रयोग हुआ प्राचीन भारतीय आचार्यों ने मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता पर जोर डाला है। मनु के अनुसार सरल कार्य भी अकेले मनुष्य के लिए कठिन होता है तो राज्य संचालन जैसा महान कार्य बिना (मन्त्रियों) सहयोग के कैसे सम्भव है।²⁷ महाभारत में भी कहा गया है कि राजा अपने मन्त्रियों पर उतना ही निर्भर रहता है जिनता प्राणिमात्र पर्जन्य पर, ब्रह्मण वेदों पर आर्य स्त्रियों अपने पतियों पर।²⁸ याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा को चितन मन्त्रियों के साथ ही करना चाहिए।²⁹ शुक्रनीति में शुक्राचार्य के अनुसार छोटे से छोटे कार्य भी एक आदमी के लिए कठिन होता है तो राज्य संचालन जैसा महान कार्य बिना सहयोग के कैसे प्राप्त हो सकता है।³⁰ आगे वह कहते हैं कि सभी प्रकार के विधाओं से कुशल और नीति दक्ष राजा को भी बिना मन्त्रियों के सहयोग के अकेले किसी विषय पर विचार नहीं करना चाहिए।³¹ कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में जिसकी गणना शासन पर लिखी सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ग्रन्थों में होती है, मन्त्रियों की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुये कहा है कि जिस प्रकार एक पहिया से रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार बिना मन्त्रियों की सहायता से राज्य का संचालन अकेले राजा से नहीं हो सकता अतएव उसे मन्त्रियों की नियुक्ति कर उसके परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए।³² यहाँ तक

23. यहा वस्तु, 2/419 ।

24. शिला, 3 तथा 5 ।

25. दो. हा. महागोविन्द सुत्तन्त, 32, राजकान्तारो ।

26. अमौ का 79/1 ।

27. मनु, 7/55 ।

28. महाभारत 5-37-32 अल्लेकर- "प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पृ 138 से उद्धृत

29. याज्ञवल्क्य 1/3111

30. शुक्र. 2/1

31. वही 2/2

32. अर्थ. 1/7/15

कि राजा को सभी कार्यों के प्रारम्भ के पूर्व उन पर मन्त्रिपरिषद से परामर्श कर लेना आवश्यक था।³³

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है प्राचीन भारतीय आचार्यों ने राज्य कार्य के संचालन में मन्त्रि-परिषद की अनिवार्यता एक स्वर से स्वीकार की है। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में भी मन्त्रियों के परामर्श के महत्व को स्वीकार कर उन्होंने स्वेच्छाधारी शासन के उन्मूलन की व्यवस्था प्रस्तुत कर भारतीय शासन विज्ञान को एक महत्वपूर्ण देन प्रदान की है।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् के साथ 'अमात्य सभा' का भी वर्णन मिलता है। वस्तुतः अमात्य तथा मन्त्री दो भिन्न-भिन्न पद थे। फिर भी मन्त्री होने के लिए अमात्य पद आवश्यक था, परन्तु इसके विपरीत अमात्य पद के लिए मन्त्रीपद की अपेक्षा न थी। वस्तुतः मन्त्रिपद अमात्य पद से बड़ा और महत्वपूर्ण था। प्रो अल्लेकर ने अमात्य मण्डल को ब्रिटेन की प्रिवी कौंसिल के समान बताया है।³⁴ परन्तु यह यथार्थ नहीं प्रतीत होता क्योंकि प्रिवी कौंसिल की सदस्य संख्या तीन सौ के लगभग है जिसमें मन्त्रिमण्डल के वर्तमान मन्त्रियों के अतिरिक्त भूतपूर्व सभी मन्त्री और अन्य लोग भी सम्मिलित रहते हैं जिसका कार्य स्वीकृति देना है। परन्तु अमात्य मण्डल की सदस्य संख्या प्रिवी कौंसिल से कम थी। उसमें भूतपूर्व मन्त्रियों एवं अधिकारियों को स्थान प्राप्त था। वर्तमान मन्त्री न्यायाधीश एवं अन्य शासन विभागाध्यक्ष ही उसके सदस्य होते थे जिसका कार्य केवल स्वीकृति देना ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप में कार्यों का सम्पादन करना था। मन्त्रिपरिषद के अतिरिक्त राजा को मुख्य एवं गुप्त मन्त्रणा देने के लिए एक छोटी परिषद रहती थी। इसे 'मन्त्र परिषद' का नाम दिया गया जो वर्तमान में कैबिनेट के सदृश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस मन्त्रपरिषद का उल्लेख मिलता है।³⁵

... ..

33. अर्थ. 1/15/5

34 अल्लेकर वही. पृ. 138

35 मिश्र डॉ० भुवनेश्वर दत्त . 'कौटिल्य राजनीति' वैशाली प्रकाशन गोरखपुर, 1989, पृ० 150

मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का स्थान संभवतः मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की अपेक्षा ऊँचा था। कार्यों के आरम्भपूर्व उन पर इसी परिषद में सर्वप्रथम विचार किया जाता था। तत्पश्चात् उसे मन्त्रिपरिषद के सम्मुख लाया जाता था। सामान्यतया मन्त्र परिषद में तीन या चार सदस्य होते थे। परन्तु कौटिल्य ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि राजा उचित समझे तो देश, काल और कार्य के अनुसार एक या दो के साथ अथवा अकेला ही किसी विषय पर निर्णय कर सकता है। रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थों में तीन या पाँच मन्त्रियों की संख्या निश्चित की गई है। नीतिवाक्यामृत में तीन, पाँच या सात मन्त्रियों को रखे जाने की व्यवस्था की चर्चा है।³⁶

कौटिल्य शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद था जिसे मंत्री, अमात्य, महामात्य आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। अन्य ग्रन्थों में इसे अग्रमात्य तथा सर्वाधिकार³⁷ नाम प्राप्त हैं। प्रशासन में उसका पद सबसे ऊँचा माना जाता था। उसके बाद राजा के अन्य मन्त्रियों एवं अधिकारियों का स्थान था।

यद्यपि मन्त्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी तथापि उनकी परीक्षा में प्रधानमंत्री और पुरोहित का महत्वपूर्ण भाग होता था।³⁸ अर्थात् प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति का कार्य सम्पन्न किया जाता था।

प्रधानमंत्री का स्थान अन्य सदस्यों से ऊँचा तो था ही, उनके कार्यों के निर्धारण आदि में भी वह राजा को परामर्श देता था। यद्यपि आधुनिक युग की संसदीय शासन पद्धति की भाँति कौटिलीय व्यवस्था का प्रधानमंत्री, 'की स्टोन आफ दी कैबिनेट आर्क' नहीं होता था, तथापि अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति हेतु परीक्षा तथा कार्यों के निर्धारण आदि में उसका महत्वपूर्ण भाग रहता था।

36 नीति वाक्यामृत, 10 ।

37 मुखर्जी 'चन्द्र गुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम्स', मोतीलाल बानासीदास दिल्ली, 1960, पृष्ठ 81 ।

38 अर्थ 0 1/10/01

इस प्रकार प्राचीन भारतीय आचार्यों ने राज्य व्यवस्था में राजतन्त्रात्मक प्रणाली का समर्थन किया है तथापि उसमें मन्त्रिपरिषद् का महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली स्थान था। राजा के लिए प्रायः यह कठिन था कि वह मन्त्रियों के निर्णय के विपरीत कार्य करे। सामान्यतया बिना मन्त्रियों की राय के कोई कार्य प्रारम्भ तक नहीं होता था।

उत्तर प्रदेश में मन्त्रिपरिषद् का उद्भव एवं विकास —

तीन जनवरी 1921 उत्तर प्रदेश के राजनैतिक इतिहास में एक अविस्मरणीय तिथि रही है। इसके पूर्व लेफ्टिनेंट ही गवर्नर जनरल की अधीनता में इस प्रान्त का शासन करता था। तब तक इस प्रान्त को 'आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रान्तों' के नाम से जाना जाता था। उपर्युक्त तिथि को ही इस प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर पर कार्यरत 'सर हारकोर्ट बटलर' को गवर्नर अथवा राज्यपाल पद की शपथ दिलायी गयी। राज्यपाल ने सर्वप्रथम दो कार्यकारी पार्षदों — महमूदाबाद के राजा और श्री एम सी पोर्टर को शपथ दिलायी तथा सी वाई चिन्तामणि एवं पंडित जगत नारायण जो कि विधान परिषद् के सदस्य थे, मन्त्री के रूप में नियुक्त किये गये।³⁹ इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की भारत में क्रमशः प्रगतिशील एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की नीति का क्रियान्वयन आरम्भ हुआ। साथ ही, उत्तर प्रदेश में मन्त्रिपरिषद् रूपी संस्था का उद्भव हुआ।⁴⁰

उपर्युक्त सवैधानिक विकास का प्रारम्भ माटेग्यू के 20 अगस्त 1947 की घोषणा से होता है जिसमें कहा गया था कि हिज मैजेस्टी की सरकार की नीति यह है कि 'प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक सम्मिलित किया जाय और धीरे-धीरे

39 "फिफ्टी ईथर आफ गवर्नर शिप इन यू पी" उ प्र सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित जनवरी

1971 पृ 31

40 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा बी गोपाल रेड्डी द्वारा 3 जनवरी 1971 को "फिफ्टी ईथर आफ गवर्नर शिप" के उद्घाटन अवसर पर दिया गया सम्बोधन भाषण

स्वतंत्र सस्थाओं का विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके।⁴¹

भारत के लिए तत्कालीन सेक्रेटरी आफ स्टेट (श्री ई एस माटेग्यू) और गवर्नर जनरल (लार्ड चेम्सफोर्ड) को उक्त नीति में क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव बनाने का कार्य सौंपा गया और भारत शासन अधिनियम 1919 में उनकी सिफारिशों को एक विधिक रूप प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत प्रान्तीय क्षेत्र में आशिक अत्तरदायी शासन का श्री गणेश किया गया। इस अधिनियम की अनिवार्य विशेषता शासन के विषयों को भारत शासन के अधीन केन्द्रीय एवं प्रान्तीय को पुनः रक्षित एवं हस्तान्तरित में वर्गीकृत करने सम्बन्धी प्रावधान थे।⁴² रक्षित विषयों का प्रशासन प्रान्तीय गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों (पार्षदों) एवं हस्तांतरित विषयों का प्रशासन लोकप्रिय मन्त्रियों द्वारा किये जाने की व्यवस्था थी। पार्षदों को काउन्सिल द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसके विपरीत मन्त्रीगण प्रान्तीय विधानपरिषद के निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे तथा परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे।

किन्तु यह शासन व्यवस्था जिस 'द्वैध शासन' के नाम से जाना जाता है अपने अन्तर्निहित दोषों के कारण असफल सिद्ध हुई। शासकीय विभागों के पृथक-पृथक विभाजन एवं वर्गीकरण सम्पूर्ण प्रशासन को निष्क्रिय बना दिया और शासन में गतिरोध उत्पन्न हो गया। सर रीजीनल्ड क्रॉड्क ने "लन्दन इवनिंग पेपर" में प्रकाशित अपने लेख में इस तथ्य को व्यक्त करते हुए कहा था कि द्वैध शासन एक वर्ण सकट व्यवस्था

41 वसु डी डी 'भारत का संविधान एक परिचय' प्रेंटिस- हल आफ इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998, पृष्ठ 6

42 कैथ ए वी 'द कान्स्टीट्यूशन हिस्ट्री आफ इण्डिया' प्राइस पब्लिकेशन दिल्ली, पृष्ठ 274 ।

है। यह चल नहीं सकती क्योंकि कोई देश या प्रान्त स्वतन्त्र मन्त्रिमण्डलो द्वारा सफलता पूर्व शासित नहीं हो सकता।⁴³

उपर्युक्त अन्तर्दोषो व 1919 ई के अधिनियम में यह प्रवधान कि दस वर्षों बाद इसकी समीक्षा की जायेगी का परिणाम ब्रिटिश ससद द्वारा पारित 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इस अधिनियम द्वारा राज्य प्रशासन का सम्पूर्ण दायित्व कुछ अपवादो को छोड़कर, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में दे दिया गया। 1937 में सम्पूर्ण देश के प्रान्तीय विधान मण्डलो के लिए निर्वाचन कराये गये। कांग्रेस ने निर्वाचन में भाग लिया और उसे उत्तर प्रदेश (सयुक्तप्रात), मध्यप्रान्त, बिहार तथा उडीसा में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ जबकि बाम्बे, बंगाल, असम तथा पश्चिमी प्रान्तो में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी।⁴⁴

सयुक्त प्रान्त की विधानसभा ने निर्वाचित होने वाले 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 133, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी आफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी अवध के 9 लिबरल 1 तथा स्वतन्त्रत 14 सदस्य निर्वाचित होकर आये जबकि कुल 64 मुस्लिम स्थानो में मुस्लिम लीग को 29, स्वतन्त्रो को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी आफ आगरा को 7, तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी अवध को तीन स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार सयुक्त प्रान्त की कुल 228 में से 134 स्थानो पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी थी।⁴⁵

समस्त चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तो में मन्त्रिपरिषद बनाने की थी। दक्षिणपथी इन प्रान्तो में सरकार बनाने के पक्ष में थे जबकि वामपथी कांग्रेस की घोषित नीतियों के अनुरूप सरकार न

43 रेजीनाल्डस सर : आइ बुक सिविल बाइ इकबाल नागयण, 'फार्म डाइरची आफ सेल्फ'

44 उत्तर प्रदेश '99 सूचना एव जनमम्पर्क विभाग उ० प्र०, पृ० 25 ।

45 वही, पृ० 26 ।

बनाकर सवैधानिक सकट उत्पन्न करना चाहते थे। 17-18 मार्च 1937 के दिल्ली ए आई सी सी बैठक में अन्ततोगत्वा यही तय हुआ कि कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों में सरकार बनायी जाय साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि विधान सभा में कांग्रेस दल के नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की जानी चाहिए कि राज्यपाल द्वारा न सविधान में प्रदत्त विशेषाधिकार का प्रयोग किया जायेगा न ही सवैधानिक क्रियाकलापों में उनके द्वारा मंत्रियों के परामर्श को नकारा जायेगा।⁴⁶

दिल्ली प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस के प्रान्तीय नेताओं ने अपने-अपने राज्यपालों से मिलकर उन्हें प्रस्तावित आश्वासन देने का निवेदन किया। राज्यपाल के द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर कांग्रेस ने सरकार बनाने में भी असमर्थता जाहिर कर दी।

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तों में नयी सवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937 तक लागू कर देना था। इसलिये ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी बहुल वाले प्रान्तों में 1 अप्रैल को अल्पमत की सरकारों का गठन कर दिया। संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छनारी के नेतृत्व में यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया। इस मन्त्रिमंडल में सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल थे। अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्पष्ट वक्तव्य देकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिये राजी कर लिया। इस वक्तव्य में यह आश्वासन दिया गया कि राज्यपाल प्रभावशाली व विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं करेगा और राज्यपाल मंत्रियों की मन्त्रणा से ही कार्य करेगा।⁴⁷ इसके बाद 7 जुलाई 1937 पंडित गोविन्द वल्लभ पंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल गठित हुआ।

46 उत्तर प्रदेश '99' सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ० प्र० पृ० 25 ।

47 फिफ्टी ईयर ऑफ गवर्नरशिप इन यूपी, वही, पृ० 31 ।

इस प्रकार प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् प्रान्तीय सरकार के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नियन्त्रण रखने वाली, महत्वपूर्ण राजनैतिक एकक बन गयी। राज्यपाल को प्रत्येक प्रान्त में उन लोगों से मन्त्रणा करके मन्त्रियों का चुनाव करना था जिनके हाथों में स्थायी विधायी बहुमत सुरक्षित रहने की उम्मीद होती। उसे शासन का संचालन निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की मन्त्रणा से ही करना था। यद्यपि प्रान्तों में ससदीय विकास का क्रम आरम्भ कर दिया गया था तथापि जो कुछ भी शक्तियाँ प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय स्वायत्तता के नाम पर दी गयी थी, उन्हें गर्वनर या गर्वनर जनरल स्वविवेकीय शक्तियों एवं विशिष्ट उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों से क्षीण कर सकते थे। इसलिये इस ब्रिटिश उपक्रम को एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने का कौशल कहा गया था। इस ब्रिटिश कौशल का सार यह था कि सम्पूर्ण प्रशासन की धुरी मुख्यमन्त्री नहीं अपितु राज्यपाल स्वतः था।

3.2 मन्त्रि परिषद् का गठन सवैधानिक उपबन्ध

भारतीय गणतन्त्र का संविधान देश के लिए सघीय शासन की व्यवस्था करता है जिसमें सघ और इसकी इकाइयों, जिन्हें राज्य कहा जाता है, हेतु पृथक् प्रशासनिक व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। संविधान के षष्ठ भाग में राज्य शासन के एकरूपीय (यूनीफार्म) स्वरूप का उल्लेख है जो मात्र जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों के लिए व्यवहार्य होगा।

सघ एवं राज्य के लिए शासन का संगठनात्मक स्वरूप ससदीय प्रणाली के रूप में एक ही है। राज्यों में भी कार्य पालिका प्रधान राज्यपाल सवैधानिक शासक के रूप में मन्त्रिपरिषद् के परामर्श पर कार्य करता है जो कि राज्य विधायिका अथवा उसके जनप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। परन्तु राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ इस परिधि में नहीं आती। संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार — “जिन बातों में इस संविधान

गान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 'मुख्यमंत्री' को 'प्रधानमंत्री' की सजा दी गयी थी, परन्तु केन्द्र में भी इसी पद की व्यवस्था के कारण स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्यों के प्रधानों को मुख्यमंत्री की पृथक् सजा से सम्बोधित किया गया। मुख्यमंत्री की सहायता करने वाली मन्त्रिपरिषद् के गठन के सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि "मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।"⁴⁸

उपरिलिखित है कि राज्यपाल राज्य कार्य पालिका का संवैधानिक प्रधान होता है तथा वह अपनी मन्त्रिपरिषद् के परामर्श पर कार्य करता है।⁴⁹ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। कोई भी व्यक्ति अथवा परिषद् का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसे विधान सभा अथवा परिषद् की सदस्यता प्राप्त हो अथवा मन्त्री पद पर नियुक्त होने के पश्चात् छ महीने के भीतर—भीतर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बन जाये, परन्तु यदि वह छ महीने की अवधि तक विधान मण्डल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो पाता तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मन्त्री नहीं रहेगा।⁵⁰ मन्त्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण समय—समय पर राज्य विधान मण्डल करता है।⁵¹

48 भारतीय संविधान अनुच्छेद, 164 (1)।

49 वही, अनुच्छेद- 163

50 वही अनुच्छेद-164 (4)

51 वही, अनुच्छेद- 164 (5).

व्यवहारत मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है जिसे राज्यपाल अपनी औपचारिक सहमति प्रदान करता है। वस्तुतः मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के पश्चात दलीय आधार पर अपने मन्त्रियों की सूची तैयार करता है और उसी सूची की औपचारिक घोषणा होती है। मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्भवतः राज्यपाल को इससे अधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मन्त्रियों की पदच्युति के सन्दर्भ में स्पष्टतः कहा गया है कि “ मन्त्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।⁵² तात्पर्य यह है कि मन्त्रीगण राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी हैं और दायित्व की विमुखता उनकी पदमुक्ति का रूप ले सकती है। परन्तु व्यवहार में मन्त्री या मन्त्रिपरिषद विधान सभा अथवा विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मन्त्रियों का वैयक्तिक दायित्व राज्यपाल के प्रति न हो कर मुख्यमंत्री के प्रति होता है जो कि उसका वास्तविक नियोक्ता होता है। दूसरे यह भी स्पष्ट है कि राज्यपाल अपनी विवेकीय या विशिष्ट शक्तियों को प्रयोग राष्ट्रति के निर्देशन में करता है परन्तु कोई भी राष्ट्रपति विधान सभा के बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री अथवा उसकी मन्त्रिपरिषद को अपदस्थ करने का निर्देश राज्यपाल को देकर ससदीय शासन की मान्यताओं पर कुटराघात नहीं करेगा और न ही उसे ऐसा करना चाहिए।⁶ यदि वह ऐसा करता भी है तो उसका कारण या तो उसकी दलीय प्रतिबद्धता हो सकती है अथवा सविधान के अनुच्छेद- 356 के अनुरूप राष्ट्रहित की रक्षा। अतः यह स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदमुक्ति मुख्यतः मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल मात्र उसे अपनी स्वीकृति देता है।

मुख्यमंत्री एवं उसकी मन्त्रिपरिषद के राज्य विधायिका या लोकप्रिय सदन में विश्वास खो देने की स्थिति में राज्यपाल को उन्हें अपदस्थ करने की शक्ति है अथवा नहीं? इस पर एक गहन विवाद पैदा हुआ था। दो राज्य के राज्यपालों ने एक ही

52 भारतीय सविधान अनुच्छेद 164 (1)

53 वसु दुर्गादास ‘भारत का सविधान एवं परिचय,’ सातवाँ संस्करण, नई दिल्ली कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड पृष्ठ 231

स्थिति में दो विपरीत निर्णय लिये थे। 1967 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने, अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पदार्ढ्य सयुक्त मन्त्रिपरिषद् (यूनाइटेड फ्रण्ट मिनिस्ट्री) को इस दृष्टि से कि सरकार ने अपने दल-बदल के परिणाम स्वरूप बहुमत खो दिया, मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि अल्पकालीन सूचना पर राज्य विधान सभा की बैठक बुला कर विश्वास मत प्राप्त करे। परन्तु श्री मुखर्जी के ऐसा करने से मना करने पर मुख्यमंत्री सहित उनकी मन्त्रिपरिषद् को अपदस्थ कर दिया।⁵⁴ दूसरी ओर 1970 में राज्यपाल श्री गोपाल रेड्डी ने चरण सिंह की सरकार को, बिना विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त करने का मौका दिये ही, अपदस्थ कर दिया, जबकि मात्र दो दिन बाद विधान सभा की बैठक बुलायी जाने वाली थी।⁵⁵

3.3 मन्त्रिपरिषद् एवं मन्त्रिमंडल

ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 163 (1) व 74 (1) के अनुसार राज्यपाल/राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद् का प्रावधान किया गया है। मन्त्रिपरिषद् के सभी मंत्री समान पक्ति के नहीं होते हैं। उनका तीन पक्तियों में वर्गीकरण किया जाता है— (क) मन्त्रिमंडलीय स्तर के मंत्री (ख) राज्यमंत्री (ग) उपमंत्री।

संविधान में मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को विभिन्न पक्तियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इंग्लैण्ड की पद्धति का अनुसरण करते हुए यह अनौपचारिक रूप से किया गया है। विभिन्न मंत्रियों की पक्ति का अवधारण मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री करता है और उसकी सलाह के अनुसार राज्यपाल/राष्ट्रपति नियुक्त करता है⁵⁶ तथा उनके बीच कामकाज

54 डॉ० दुर्गादास वसु, पृ० 232

55 वही,

56 भारतीय संविधान अनुच्छेद 164(1) एवं 75 (1)

का आवंटन करता है।⁵⁷ मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बताया गया है कि जब राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाय तो वह किसी विषय को जिस पर किसी मन्त्री ने निश्चय कर लिया है किन्तु जिस पर मन्त्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।⁵⁸ व्यवहार में मन्त्रिपरिषद निकाय के रूप में कहीं अधिक विविष्ट नहीं होती है। यह कार्य मन्त्रिपरिषद के भीतर एक छोटा निकाय 'मन्त्रिमण्डल' करता है। यही शासन की नीतियों को रूप देता है।

मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मन्त्री साधिकार मन्त्रिमण्डल की बैठक में भाग लेते हैं। राज्यमन्त्री मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते। यदि राज्य मन्त्री को स्वतन्त्र रूप से कोई विभाग दिया गया है तो जब उसके विभाग से संबंधित कोई बात विषय सूची में होती है तब वह मन्त्रिमण्डल की बैठक में भाग लेता है। उपमन्त्री मन्त्रालय के किसी विभाग का धारसाधक होता है और मन्त्रिमण्डल के विचार विमर्श में उसकी भागीदारी नहीं होती।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद के सभी सदस्य अनिवार्यतः मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते जबकि मन्त्रिमण्डल के सदस्य मन्त्रिपरिषद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और यही शासन की नीतियों का निर्धारण करता है।

3.4 मन्त्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री

ध्यातव्य है कि भारत में राज्यों की शासन पद्धति मोटे-तौर पर संघ के समान ही है। अर्थात् संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति/राज्यपाल संवैधानिक शासक होता है जो संसद/विधानमण्डल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।⁵⁹ यद्यपि मन्त्रिमण्डल के समस्त

57 वही 166 एवं 77

58 वही 167 (ग) एवं 78 (ग)

59 जिन विषयों की वास्तव में राज्य के राज्यपाल को संविधान द्वारा अपने विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, वहाँ उसे सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं है।

सदस्य एक समान आधार पर खड़े रहते हैं, उनके बोल समस्वरी होते हैं, और जब कभी किसी अवसर विशेष पर मतदान होता है तो उनकी गणना भी 'एक व्यक्ति-एक मत' के सिद्धान्त के आधार पर होती है फिर भी प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री समकक्षों में प्रथम तथा मन्त्रिमण्डल का प्रधान होता है। इसी कारण लार्ड मार्ले ने कहा था कि प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डलीय मेहराब का मुख्य प्रस्तर है।⁶⁰ उसने यहाँ तक कहा है कि "उसे (प्रधानमंत्री) जब तक कॉमन सभा का बहुमत प्राप्त है उसकी स्थिति एक तानाशाह से कम की नहीं होती।" प्रधानमंत्री की यह स्थिति भी उसकी वास्तविक स्थिति का न्यून रूप ही हो सकता है। वस्तुतः वह राज्यपोत का चालक होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की मन्त्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। (संघ में इसके तत्समान प्रधानमंत्री होता है)।⁶⁰

यह विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।⁶¹ मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल/मुख्यमंत्री की सलाह से करता है।⁶²

यद्यपि सवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री मन्त्रिपरिषद् के अन्य सहयोगी सदस्यों के चुनाव के विषय में अत्याधिक शक्ति रखता है जैसा कि अनुच्छेद 164(1) के उत्तरार्ध में यह स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जो परामर्श राज्यपाल को देगा, उसके अनुसार ही राज्यपाल नियुक्तियाँ करने को बाध्य होगा। लेकिन व्यावहारिक रूप से मन्त्रियों के चुनाव करते समय उसे अनेक पक्षों पर विचार

60 बसु0 डी0 डी0 भारत का संविधान एक परिचय, वही पृ0 229

61 राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है यदि उसके प्राक्कलन के अनुसार ऐसे व्यक्ति को राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो जायेगा और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग विधान सभा के पूरी तरह गठन के पहले भी कर सकता है। ऐसा करने पर राज्यपाल की दुर्भावना साबित नहीं होती (राजनयन बनाम भजनलाल 1982)

भारत का संविधान अनु0 164 (1)

करना पड़ता है और कभी-कभी तो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में शामिल करना पड़ता है क्योंकि वे सदस्य दल में काफी प्रभाव रखते हैं।

भारतीय राजनीति व्यवस्था के अतीत पर दृष्टि डाले तो भारत में ससदीय शासन की स्थापना से ही कांग्रेस की विशिष्ट स्थिति एवं उसपर प्रधानमंत्री नेहरू, श्रीमती गांधी तथा राजीव गांधी के प्रभावी राजनीति की कारण मुख्यमंत्री तथा उसकी मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति उनकी इच्छा एवं राजनीतिक सुविधा का परिणाम है।⁶³ 1967 में एस के पाटिल द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि सरकार के निर्माण में कांग्रेस हाईकमान भाग ले परन्तु मुरारजी देसाई ने इसका विरोध किया।⁶⁴ अतः दल लोकसभा या किसी दूसरी सत्ता, सत्ता द्वारा अपनी मन्त्रिपरिषद के निर्माण में उसके स्वतन्त्र अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता, उसका यह विशेषाधिकार होता है।⁶⁵

सामान्यतया मन्त्रिमण्डल का निर्माण विधान सभा में बहुमत दल के सदस्यों में से किया जाता है जैसा कि ज्ञात है कि राज्यपाल अपनी सवैधानिक शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद को बहुत से ऐसे अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिसका प्रयोग कर वह विधानसभा की कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए विधान मण्डल के अधिवेशन बुलाने, उसके स्थगन और विघटन का कार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद की सलाह से करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्राथमिकता को निर्धारित करने उस पर वाद-विवाद के लिए समय निर्धारित करने, दल के सदस्यों द्वारा मतदान सम्बन्ध में निर्देश आदि देने का अधिकार मुख्यमंत्री व मन्त्रिपरिषद को प्राप्त है।

63 जैन पुखराज, 'भारतीय प्रधानमंत्री' साहित्य भवन आगरा, 1981, पृ० 36

64 माइकल ब्रेकर शक्सेशन इन इण्डिया, राटिनाइन्सेन ऑफ पोलिटिकल चेन्ज, एशियन सर्वे खण्ड- 6,7 1967, पृ० 427

65. विशेषाधिकार "प्रेरोगेटिब्स्" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था इसका अनुसरण भारत में श्रीमती गांधी और शास्त्री ने भी किया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को मन्त्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में यह अधिकार है कि राज्यपाल से कहकर विधानसभा को भग करा दे। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसकी धमकी देकर कार्यकारिणी विधानमण्डल को बड़ी हद तक नियन्त्रित कर सकती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मन्त्रिपरिषद तथा विधानमण्डल को एक दूसरे को नियन्त्रित करने की शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं तथापि यह बहुत हद तक इस तथ्य से निर्धारित होता है कि मन्त्रिपरिषद को विधानसभा में किस सीमा तक दलीय समर्थन प्राप्त है। जब भी विधान सभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तथा विभिन्न दलों के सहयोग द्वारा मन्त्रिपरिषद का सृजन किया गया है तब मन्त्रिपरिषद की स्थिति विधानसभा में कमजोर रही है। तथा यदि विधानसभा में सत्तारूढ़ दल को निर्देश तथा व्यापक बहुमत प्राप्त होता है तो मन्त्रिमण्डल अत्यन्त शक्तिशाली होकर विधानमण्डल को नियन्त्रित करने में सफल रहती है। वस्तुतः विशेषाधिकार का यह शोध मन्त्रिमण्डल सरकार की मान्यताओं एवं व्यवहार के लिये समीचीन भी है क्योंकि इस व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व की मान्यताओं के अनुरूप कार्य करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा में डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था कि “वास्तव में प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब का प्रमुख प्रस्तर है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन इस आधार पर ही किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को मन्त्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार दिया जाय।”⁶⁶

विभिन्न मन्त्रियों के बीच विभागों का वितरण करना भी मुख्यमंत्री/ प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है, लेकिन इस विशेषाधिकार का प्रयोग भी बहुत कुछ मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे अनेक

उदाहरण है जब मुख्यमंत्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों के बीच उन्हीं की इच्छा के अनुसार विभागों का वितरण करना पड़ा। वस्तुतः विभिन्न मन्त्रियों के विभागों के वितरण तथा उनमें परिवर्तन में मुख्यमंत्री उस समय ज्यादा स्वतन्त्र होता है जब उसकी स्थिति अपने दल में सुदृढ़ हो, अन्यथा उसे दल के विभिन्न गुटों से स्वभाविक रूप से समझौता करना पड़ता है, विशेषकर वरिष्ठ सदस्यों तथा केन्द्रीय नेतृत्व के आगे झुकना पड़ता है। जेनिंग्स के अनुसार जिस प्रकार प्रधानमंत्री को अपने आधे मन्त्रियों की नियुक्ति अपनी अनिच्छा होने हुए भी करना पड़ता है, उसी प्रकार राज्य मन्त्रिपरिषद् में भी कुछ मन्त्रियों की नियुक्ति राजनैतिक विवशता की परिणति होती है।

3.5 मन्त्रिपरिषद् एवं विधानमण्डल

भारत के संविधान में संघ तथा राज्य के लिए संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गयी है जिसकी प्रमुख विशेषता है कार्यकारणी का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होना है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) में यह घोषणा है कि मन्त्रिमण्डल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी ही व्यवस्था संघ के सरकार के लिए अनुच्छेद 75(3) में की गई है। कार्यकारणी का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ यह है कि विधानमण्डल को कार्यकारणी के कृत्यों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है। विधानमण्डल यह नियन्त्रण विभिन्न संसदीय उपकरणों के द्वारा करता है।

भारत के संविधान के अनुसार मन्त्रिपरिषद् केवल विधानसभा के प्रति (जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमण्डल है⁶⁷ वहाँ भी) उत्तरदायी है। इसीलिए विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी समय मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का

67 भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 (2) में स्पष्टतः विधानसभा शब्द का प्रयोग है अर्थात् जिन राज्यों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है वहाँ द्विसदनीय विधानपरिषद् के प्रति मन्त्रिपरिषद् उत्तरदायी नहीं होगी।

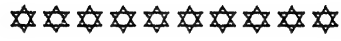
प्रस्ताव पारित करके उसे विघटित करा दे। एक ससदीय शासन प्रणाली में विधानमण्डल अप्रत्यक्ष रूप से भी मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक विधानसभा द्वारा रद्द कर दिया जाय तो उसे मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास समझा जाता है और ऐसी दशा में मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ता है। इस प्रकार के कई और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से विधानसभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करके उसका अन्त कर सकता है।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इंग्लैण्ड की तरह भारत में भी व्यावहारिक रूप से विधानमण्डल की अपेक्षा मन्त्रिपरिषद् अधिक शक्तिशाली होता है। इसका मूल कारण दल प्रणाली तथा दलीय अनुशासन का विकास है। ध्यातव्य है कि मन्त्रिमण्डल का निर्माण विधानसभा अर्थात् निम्नसदन के बहुमत से होता है, उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने की सम्भावना नहीं रहती है। विधानमण्डल उस समय मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखने की स्थिति में आवश्यक होता है जब विधानसभा में कोई एक राजनीतिक दल निरपेक्ष बहुमत में न हो और मिश्रित मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जाए। ऐसी स्थिति में मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की अवश्य सम्भावना होती है।

अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करने के अधिकार के अतिरिक्त कुछ अन्य उपायों द्वारा भी विधान मण्डल मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखते हैं इनमें सरकार से प्रश्न पर सरकार द्वारा व्यक्तव्य देने की माँग करने का अधिकार उल्लेखनीय है। विधानमण्डल के दोनों सदनों⁶⁸ में विरोधी दलों के सदस्य सरकार के विभिन्न प्रशासन सम्बन्धी मामलों में

68 उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का विधानमण्डल द्विसदनीय है।

प्रश्न पूछते हैं और विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद के समय सरकार की कठोर आलोचना करते हैं। इसीलिए सरकार सदैव इस बात का प्रयत्न करती है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे विरोधी दलों को सरकार की आलोचना करने का अवसर मिले।



चतुर्थ अध्याय

मन्त्रीपरिषद् के सदस्यों की जातीय, धार्मिक एवं क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की जातीय, धार्मिक, एवं क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

4.1 जातीय पृष्ठ भूमि

भारतीय शासन व्यवस्था के सदर्थ में यह तथ्य सर्वमान्य है कि यहाँ राज्य की शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद एवं मन्त्रिमण्डल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। सवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर मन्त्रिपरिषद एवं मन्त्रिमण्डल निर्माण की औपचारिक शक्ति राज्यपाल के पास है परन्तु वास्तव में मन्त्रिपरिषद के गठन का दायित्व तथा वास्तविक शक्ति का उपयोग मुख्यमंत्री करता है, इसलिए मुख्यमंत्री को मन्त्रिमण्डल का आदि और अन्त माना जाता है। यद्यपि मुख्यमंत्री को मन्त्रिमण्डल के गठन की निरपेक्ष शक्तियाँ प्राप्त हैं तथापि मुख्यमंत्री मन्त्रिपरिषद् के गठन के समय विभिन्न तथ्यों से प्रभावित होता है। राजनैतिक शक्तियों एवं परिस्थितियों के अतिरिक्त सामाजिक शक्तियाँ यथा- जाति, धर्म, भाषा आदि भी मन्त्रिपरिषद के गठन के समय प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह करती हैं। इस कारण मन्त्रिपरिषद के निर्माण में जाति की भूमिका का ज्ञान मन्त्रिपरिषद के अध्ययन की सम्पूर्णता के लिए आवश्यक है।

भारत की वर्तमान जनसंख्या एक लम्बे समय से इस महाद्वीप के आबाद होने की प्रक्रिया का परिणाम है। विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि वाले विभिन्न मानव समूह अलग-अलग समय में इस प्रदेश में आये और इसे आबाद किया। भारत में उनके आव्रजन, अधिवास, तथा बाद में हुए स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न नृजातीय एवं सांस्कृतिक धाराएँ काफी हद तक आपस में मिली सामाजिक सम्मिलन की इस प्रक्रिया द्वारा भारत की जनसंख्या ने मिलने वाली सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता ने एक स्पष्ट विविधता प्राप्त कर ली है।¹

भारत वर्ष में जातियों की बहुलता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न जातियों

1- राजा, (प्रो) मुनीस एवं अहमद डा० एजाज- 'भारत का सामान्य भूगोल', एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली, 1978 पृष्ठ 89

मे अधिकाधिक अन्तर है। कुछ जातियाँ सारे देश में पायी जाती हैं, कुछ जातियाँ प्रादेशिक हैं, तथा कुछ मात्र स्थानीय जाति के एक समूह के रूप में देखने को मिलती हैं। हर समूह में अलग-अलग जातियों के अलग-अलग रीतिरिवाज, परम्पराएँ, कर्मकाण्ड आदि देखने को मिलते हैं। जो जातियाँ क्षेत्रीय नहीं हैं, उनके मध्य भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नता विद्यमान है।

जाति-प्रथा किसी-न-किसी रूप में ससार के हरकोने में पायी जाती है परन्तु एक गम्भीर कुरीति के रूप में यह हिन्दू समाज की ही विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समाज में भारत में वर्ण-व्यवस्था थी जो कि कर्म के साथ जुड़ी हुयी थी। सामान्यतया यह माना जाता है कि कार्यगत दक्षता के आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुयी। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का सम्पादन करते थे, क्षत्रिय देश की रक्षा और प्रशासन, वैश्य कृषि और वाणिज्य तथा शूद्रों का कार्य उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था।² प्रारम्भ में जाति-प्रथा के बन्धन अत्यधिक कठोर नहीं थे और वह कर्म पर आधारित थी। कालान्तर में जाति-प्रथा में कठोरता आती गयी तथा वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गयी।

जाति जन्म से प्राप्त होती है। अतः कोई अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। यही कारण है कि जाति ने सामाजिक संरचना में दरारे उत्पन्न कर दी हैं तथा एक जाति से दूसरी जाति के विरोध ने जातीय संकीर्णता में वृद्धि की है। साथ ही साथ एक क्षेत्र की जाति के एकता के सूत्र में बाधने से क्षेत्रीयता की भावना में स्थिरता स्थापित हुयी है। भारतवर्ष में जातियों की छोटी-छोटी दुनिया के इलाके बन गये हैं। बड़े-बड़े नेता जाति विहीन समाज की स्थापना की घोषणा कर सकते हैं लेकिन देहात के लोग परम्परागत राजनीति की भाषा को

2 शर्मा, रामशरण-प्राचीन भारत-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद-दिल्ली 1997 पृष्ठ 491

ही जानते हैं जो विशाल स्तर पर जाति से घिरी हुयी है।³ हर स्तर और हर प्रकार की राजनीति में जाति एक ऐसी शक्ति बन गयी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

पश्चिमीकरण के प्रभाव में भौतिक उन्नति की नवीन धारणाओं के बलवती होने पर एक सामाजिक बंधन या शक्ति के रूप में जाति की अत्यधिक कठोरता नहीं रह गयी परन्तु स्वतन्त्र भारत में जाति एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बन गयी है। भारत के राजनीतिक लोकतन्त्र के सन्दर्भ में जाति वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों एवं तरीकों की खोज की जा रही है। जाति वास्तव में ऐसा माध्यम बन गयी है जिसके कारण भारतीय जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने को जोड़ सकी है।⁴

जाति-व्यवस्था का प्रभावशाली राजनीतिक स्वरूप मात्र हिन्दू समाज में ही नहीं बल्कि मुस्लिम, ईसाई एवं सिख समुदाय भी जातीयता से मुक्त नहीं है। जाति एवं राजनीति के अनन्त सम्बन्धों की विवेचना में हिन्दू समुदाय के अतिरिक्त अन्य समुदायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि जाति और राजनीति के सम्बन्ध स्थिर न होकर गतिशील हैं।⁵ भारतवर्ष के सन्दर्भ में जाति एवं राजनीति के अन्तः सम्बन्धों के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विस्तृत अध्ययन किये हैं। जिनके परिणाम स्वरूप यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका बन गयी है। यह भूमिका स्थानीय स्तर तथा प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती है।

3 मोरिस जोन्स, डब्ल्यू0 एच0- द गवर्नमेंट एण्ड पालिटिक्स आफ इण्डिया (हिन्दी अनुवाद) सुरजीत, दिल्ली 1970 पृष्ठ 58

4- रुडाल्फ लायड आई 'दि माडर्निटी आफ ट्रेडिशन', 'ओरियन्ट लागमेन', 1969, पृष्ठ-111।

5- जौहरी जे सी - 'रिफ्लेक्शन ऑन द इण्डियन पालिटिक्स', नई दिल्ली, विशाल पब्लि0 1974 पृष्ठ स -7

यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नहीं है जितनी राज्य एवं स्थानीय राजनीति में है।⁶ निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन एवं मतदान व्यवहार तक ही जाति की भूमिका सीमित नहीं है वरन् सत्ता के उपयोग की भागीदारी में जाति दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट हुई है। राजनीतिक सम्बन्धों में सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति भी होती है। जाति-व्यवस्था और राजनीतिक-व्यवस्था में पूर्ण ध्रुवीकरण कभी नहीं रहा है। प्रारम्भ में सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियाँ ही राजनीति से प्रभावित रहीं और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहा।

शिक्षा के प्रसार, औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ बदलते परिवेश में मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियाँ भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होने लगीं। मध्यम, पिछड़ी तथा निम्न जातियों की राजनीतिक सत्ता भोगने की आकांक्षा ने जाति को राजनीति में और अधिक प्रभावशाली बनाया है। ए० आर० देसाई ने अपनी पुस्तक सोशल बैंक ग्राउण्ड आफ इण्डियन नैशनलिज्म में भारत में राजनीति को वर्ग या जाति की प्रतिच्छाया के रूप में स्वीकार किया है। इसी कारण एक समय पर सर्वोदय नेता जय प्रकाश नारायण ने कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है।⁷

भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही यह आवश्यक हो

6- माइकल श्रेचर के अनुसार-अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति जातिवाद का प्रभाव अधिक है- जैन एस फाडिया 'भारतीय शासन एवं राजनीति', आगरा, साहित्य भवन 1968 पृष्ठ सं० 686।

7 जैन एव फडियों - 'भारतीय शासन एवं राजनीति', आगरा, साहित्य भवन, 1986, पृष्ठ सं० 684।

जाता है कि शोध काल खण्ड 1991 से 1997 ई० के बीच गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में

जाता है कि शोध काल खण्ड 1991 से 1997 ई० के बीच गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों की जातीय प्रतिनिधित्व का अवलोकन किया जाय। मन्त्रिपरिषद में उच्च, मध्यम और निम्न जातियों का किस अनुपात में प्रतिनिधित्व हुआ है यह ज्ञात कर ही मन्त्रिपरिषद के निर्माण में जाति की भूमिका के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकालना सम्भव होगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1991-1997 ई० के बीच गठित मन्त्रिपरिषदों को तीन जाति वर्ग में उच्च जाति वर्ग, मध्यम जाति वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति में बाँट कर अवलोकित करने का प्रयास किया गया है।

मई जून 1991 में एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 24-6-91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमवार गठित तथा दिनांक 6-12-92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी संख्या- 4.1.1 में प्रदर्शित है।

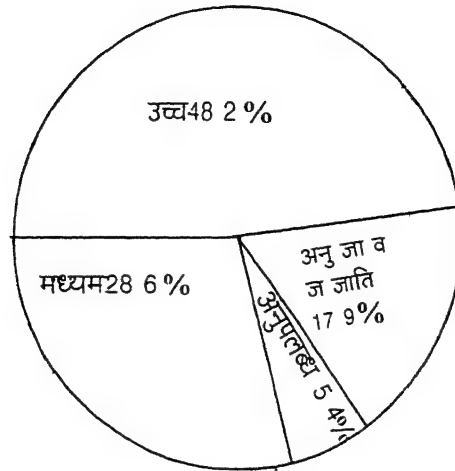
सारिणी संख्या-4.1.1

सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

क्रम सं०	जाति	विधान सभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा एवं मन्त्री परिषद के मध्य) 1 मन्त्री - विधानसभा सदस्य
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	153	36.6	27	48.2	15.6
2	मध्यम	108	25.8	16	28.6	16.8
3	अनुसूचित जाति	107	25.6	10	17.9	11.07
4	एवं जन जाति अनुपलब्ध	50	12	3	5.4	11.67
योग		418	100	56	100.1	17.5 (अनुपात)

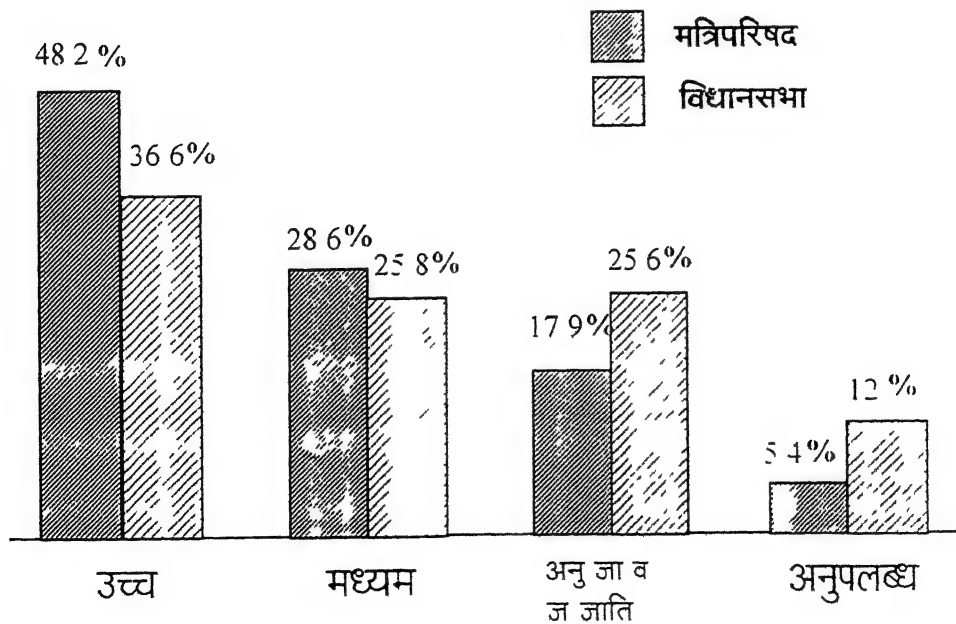
सारिणी संख्या 4.1.1 के अन्तर्विष्ट आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 24-6-91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमवार गठित मन्त्रिपरिषद

रेखा चित्र संख्य -4.1.1(अ)



सन् 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.1(ब)



सन् 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की जाति

मे कुल 56 सदस्य थे, जिसमे 27 उच्च जाति से, 16 मध्यम जाति से तथा 10 अनुसूचित जाति एव जनजाति से थे।

इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद के 3 सदस्यों की जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। जबकि इस काल में विधानसभा के कुल 418 सदस्यों में 153 उच्च जाति से, 108 मध्यम जाति से तथा 107 सदस्य अनुसूचित जाति एव जनजाति से रहे। इसके अतिरिक्त 50 ऐसे सदस्य रहे जिनकी जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा में उच्चजातियों का प्रतिनिधित्व 36.6 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 48.2 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात् विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में उच्च जातियों को लगभग 12 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधानसभा में मध्यम जातियों का प्रतिनिधित्व 25.8 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 28.6 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में मध्यम जाति के सदस्यों को लगभग 3 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति एव जनजाति का प्रतिनिधित्व विधान सभा में 25.6 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 17.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में उन्हें लगभग 8 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियों के सदस्यों का विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले तो उच्च जाति का 1:5.6, मध्यम जाति का 1:6.8 तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का अनुपात 1:10.7 ठहरता है। अतः इस आधार पर स्पष्ट है कि उच्च जाति के 5.6 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद में एक स्थान प्रदान किया गया वहीं मध्यम जाति के 6.8, विधान सभा सदस्यों पर तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति को 10.7 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद में एक स्थान प्राप्त किया गया।

इस प्रकार सारणी सख्या 4.1.1 के सम्पूर्ण तथ्य यह प्रदर्शित कर रहे कि इस काल में विधान सभा व मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उच्च जातियों का वर्चस्व रहा है

जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति सबसे कमजोर रही है। कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित इस मन्त्रिपरिषद में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र संख्या 4.1.1(अ) में तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रूप से रेखाचित्र संख्या 4.1.1(ब) में दर्शाया गया है।

नवम्बर 1993 में द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप दिनांक 4-12-93 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी संख्या 4.1.2 में प्रदर्शित है।

सारिणी संख्या -4.1.2

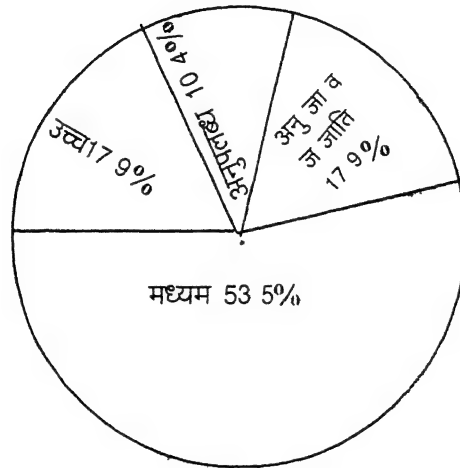
सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

क्रम	जाति	विधान सभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा एवं मन्त्री परिषद के मध्य) 1 मन्त्री - विधानसभा सदस्य
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	135	31.7	5	17.9	1:27
2	मध्यम	151	35.5	15	53.5	1:10.1
3	अनुसूचित जाति एवं जन जाति	107	25.1	5	17.9	1:21.4
4	अनुपलब्ध	33	7.7	3	10.7	1:11
योग		426 [☆]	100	28	100	1:15.2 (अनुपात)

☆ विधानसभा के 426 सदस्यों का आकड़ा है, इसमें मृत सदस्य के साथ उप चुनाव में विजयी सदस्य को शामिल किया गया है जिस कारण यह 426 तक पहुँच गया है

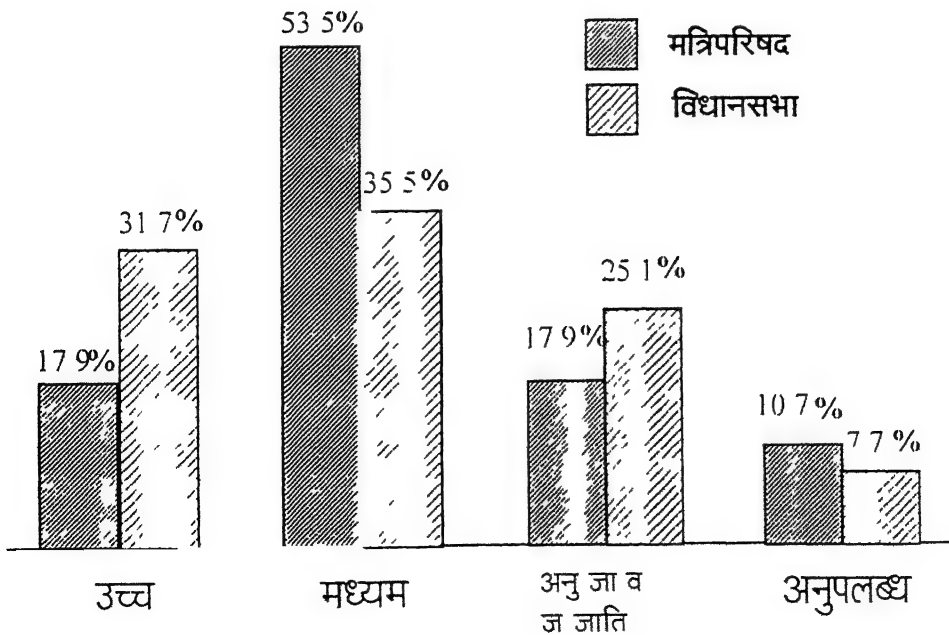
सारिणी संख्या 4.1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 4-12-93 को मुलायम

रेखा चित्र संख्या-4.1.2(अ)



सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.2(ब)



सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की जाति

सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा 3-6-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद् में कुल 28 सदस्य थे। जिसमें उच्च जाति से 15 मध्यम जाति से तथा 5 अनुसूचित जाति एवं जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद् के 3 सदस्यों के जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। जबकि इस काल में विधानसभा के कुल 426 सदस्यों में 135 उच्च जाति से, 151 मध्यम जाति से तथा 107 अनुसूचित जाति एवं जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त 33 ऐसे सदस्य थे जिनकी जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा में उच्च जाति का प्रतिनिधित्व 31.7 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 17.9 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात् आधा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा में मध्यम जातियों का प्रतिनिधित्व 35.5 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 53.5 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में उन्हें लगभग डेढ़ गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वहीं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधान सभा में प्रतिनिधित्व 25.1 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 17.9 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियों से सदस्यों का विधानसभा व मन्त्रिपरिषद् के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले तो उच्च जाति का अनुपात 1:27, मध्यम जाति का 1:01 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 1:21.4 ठहरता है। अतः इस आधार पर स्पष्ट है हो रहा है कि जहाँ उच्च जाति के 27 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद् में 1 स्थान प्रदान किया गया है वहीं मध्यम जाति के 10.1 विधानसभा सदस्यों पर तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 21.4 विधान सभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद् में एक स्थान प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.1.2 के सम्पूर्ण तथ्य यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस काल में विधान सभा एवं मन्त्रिपरिषद् में मध्यम जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। मन्त्रिपरिषद् में तो मध्यम जाति के सदस्यों को आधे से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। जहाँ तक उच्च एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रश्न है तो इन्हें मन्त्रिपरिषद् में समान

भागीदारी प्राप्त थी। किन्तु विधानसभा के अनुपात में मन्त्रिपरिषद में सम्मिलित किये जाने का दर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का उच्च जाति से अधिक था। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण मन्त्रिपरिषद में नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया ही यह प्रतीत होता है कि इस काल में मध्यम जाति को मन्त्रिपरिषद में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र संख्या 4 1 2(अ) में तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रूप से रेखाचित्र संख्या 4 1 2(ब) दर्शाया गया है।

मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद के पतन के पश्चात दिनांक 3-6-1995 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी संख्या 4 1 3 में प्रदर्शित है।

सारिणी संख्या -4 1 3

सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

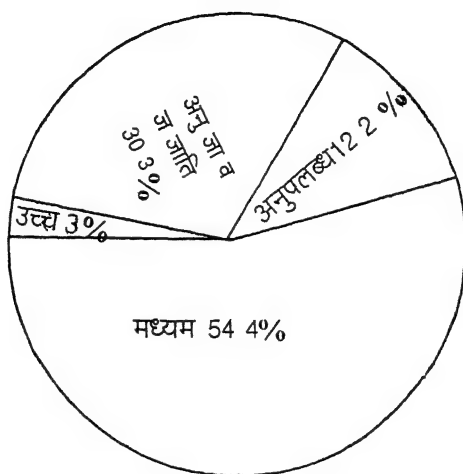
क्रम	जाति	विधान सभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा एवं मंत्री परिषद के मध्य) 1 मंत्री - विधानसभा सदस्य
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	135	31.7	1	3	1:135
2	मध्यम	151	35.5	18	54.5	1:8.4
3	अनुसूचित जाति	107	25.1	10	30.3	1:10.7
4	एवं जन जाति					
	अनुपलब्ध	33	7.7	24	12.2	1:1.4
योग		426	100	33	100	1:12.9 (अनुपात)

✽ विधानसभा के 426 सदस्यों का आकड़ा है, इसमें मृत सदस्य के साथ उप चुनाव में विजयी

✽ सदस्य को शामिल किया गया है जिस कारण यह 426 तक पहुँच गया है।

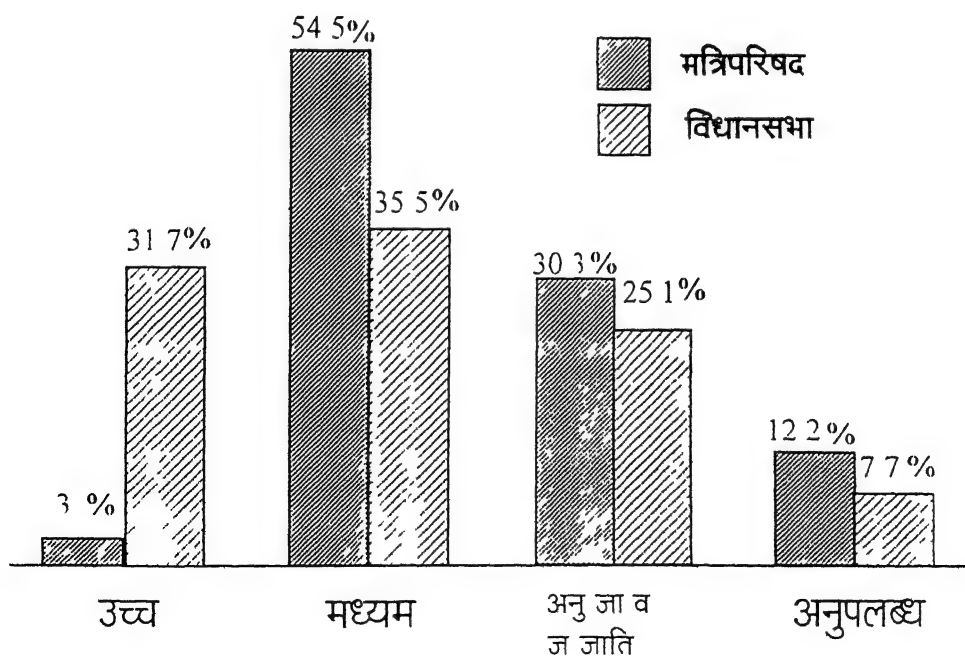
सारिणी संख्या-4 1 3 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि

रेखा चित्र संख्या-4.1.3(अ)



सन 1995 में मायावती के मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.3(ब)



सन 1995 में मायावती के मन्त्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की जाति

दिनांक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व में प्रथम बार गठित तथा 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में कुल 33 सदस्य थे जिसमें एक उच्च जाति से 18 मध्यम जाति से तथा 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति से थे इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद के 4 सदस्यों की जाति के विषय में ज्ञान नहीं था, जबकि इस काल में विधान सभा के कुल 426 सदस्यों में 135 उच्च जाति से, 151 मध्यम जाति से तथा 107 अनुसूचित जाति एवं जनजाति से रहे। इसके अतिरिक्त 33 ऐसे सदस्य रहे जिनकी जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा में उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व 31.7 रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात् विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में उच्च जातियों को लगभग 10 गुना कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा में मध्यम जातियों का प्रतिनिधित्व 35.5 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 5.4 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में मध्य जातियों के सदस्यों को लगभग 20 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वही अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व विधान सभा में 25.1 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 3.0 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लगभग 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियों के सदस्यों का विधान सभा एवं मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डालें तो उच्च जाति का 1:135, मध्यम जाति का 1:8.4 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का अनुपात 1:0.7 ठहरता है। अतः इस आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ उच्च जाति के 135 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद में 1 स्थान प्रदान किया गया वहीं मध्यम जाति के 8.4 विधानसभा सदस्यों पर तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 0.7 विधानसभा सदस्यों पर 1 स्थान मन्त्रिपरिषद में प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.1.3 के सम्पूर्ण तथ्य यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस काल में विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद में मध्यम जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस काल में विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद् में मध्यम जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। मन्त्रिपरिषद् में तो इन्हें आधे से भी अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मन्त्रिपरिषद् में केवल एक सदस्य के रूप में मात्र 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उच्च जाति को प्राप्त था। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व में व्यापक असन्तुलन विद्यमान था। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टि गोचर है कि विधानसभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण मन्त्रिपरिषद् में नहीं किया गया। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित इस मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4.1.3(अ) में तथा मन्त्रिपरिषद् तथा विधानसभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रूप से रेखाचित्र सख्या 4.1.3(ब) दर्शाया गया है।

सितम्बर-अक्टूबर 1996 में त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 21-3-97 तक कार्यरत, भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4.1.4 में प्रदर्शित है।

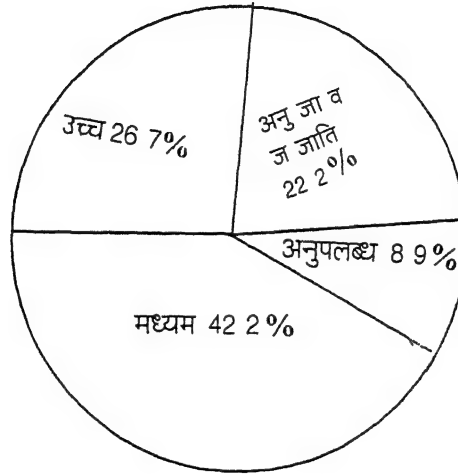
सारिणी सख्या-4.1.4

सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्

क्रम	जाति	विधान सभा		मन्त्रिपरिषद्		अनुपात (विधानसभा एवं मन्त्री परिषद् के मध्य) 1 मन्त्री - विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	171	40.2	12	26.7	1:14.3
2	मध्यम	132	31	19	42.2	1:6.9
3	अनुसूचित जाति	99	23.2	10	22.2	1:9.9
4	एवं जन जाति	24	5.6	4	8.9	1:6
योग		426 [☆]	100	45	100	1:9.5 (अनुपात)

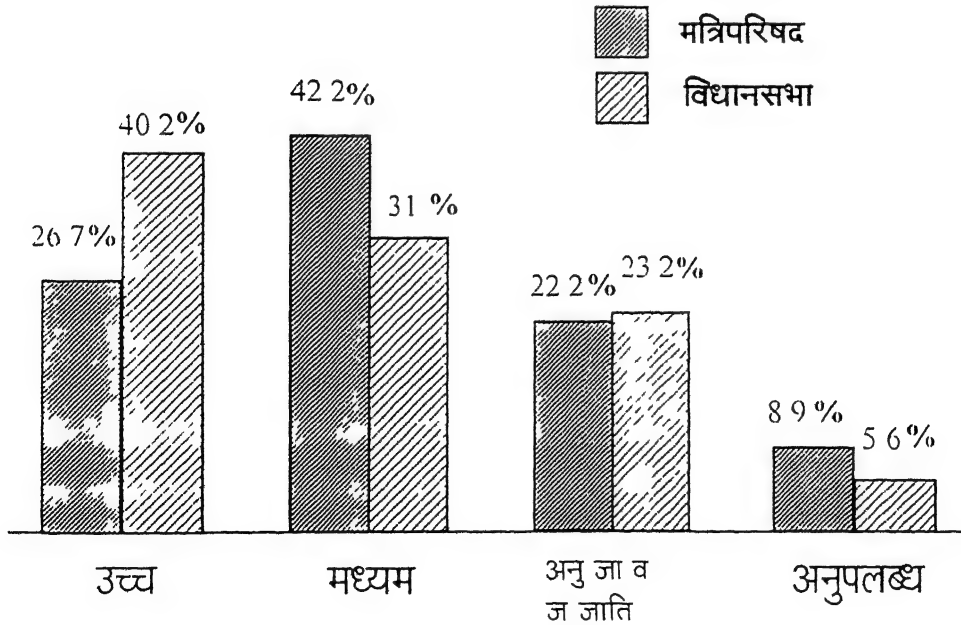
☆ वही

रेखा चित्र संख्य -4.1.4(अ)



सन 1997 में मायावती के मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की जाति

रेखा चित्र संख्य -4.1.4(ब)



सन 1997 में मायावती के मन्त्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की जाति

दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व में द्वितीयवार गठित मन्त्रिपरिषद में कुल 45 सदस्य थे, जिसमें 12 उच्च जाति से, 19 मध्यम जाति से तथा 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद के 4 सदस्यों की जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। जबकि इस काल विधान सभा में कुल 426 सदस्यों में 171 उच्च जाति से, 132 मध्यम जाति से तथा 107 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति से रहे। इसके अतिरिक्त 24 ऐसे सदस्य रहे जिनकी जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा में उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व 40.2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 26.7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात् विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में उच्च जातियों को लगभग 14 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधानसभा में मध्यम जातियों का प्रतिनिधित्व 31 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 42.2 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में मध्यम जाति के सदस्यों को लगभग 11 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वही अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व विधान सभा में 23.2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 22.2 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में 1 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियों के सदस्यों का विधान सभा एवं मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले तो उच्च जाति का 1:14.3, मध्यम जाति का 1:6.9 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का अनुपात 1:9.9 ठहरता है। अतः इस आधार पर स्पष्ट है कि उच्च जाति के 14.3 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद में एक स्थान प्रदान किया गया, वही मध्यम जाति के 6.9 विधानसभा सदस्यों पर तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 9.9 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद में एक स्थान प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.1.4 के सम्पूर्ण तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि जहाँ विधानसभा में उच्च जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही मन्त्रिपरिषद में मध्यम

जाति के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधानसभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण मन्त्रिपरिषद में नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इस काल में मध्यम जाति को मन्त्रिपरिषद में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। किन्तु यदि प्रदेश की कुल जनसंख्या में विभिन्न जातियों के अनुपात के आधार पर देखें तो विधानसभा की जातीय संरचना में जो असन्तुलन विद्यमान था उसे मन्त्रिपरिषद में दूर करने का प्रयास किया गया। इस मन्त्रिपरिषद में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र संख्या 4 1 4(अ) में तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रूप से रेखाचित्र संख्या 4 1 4(ब) दर्शाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणाम स्वरूप छ महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री मायावती द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनांक 21-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में 31 दिसम्बर 1997 तक विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति को सारिणी संख्या 4 1 5 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 4 1 5 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 21-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में दिनांक 31 दिसम्बर 1997 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए जिसमें 51 सदस्य उच्च जाति से, 39 सदस्य मध्यम जाति से, तथा 16 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त 7 ऐसे सदस्य थे जिनके जाति के विषय में ज्ञान नहीं था। जबकि इस काल में विधानसभा के कुल 426 सदस्यों में से 171 उच्च जाति से, 132 मध्यम जाति से, तथा 99 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति से रहे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा में उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व 40 2 प्रतिशत रहा

सारिणी सख्या 4 1 5

सन् 1997 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

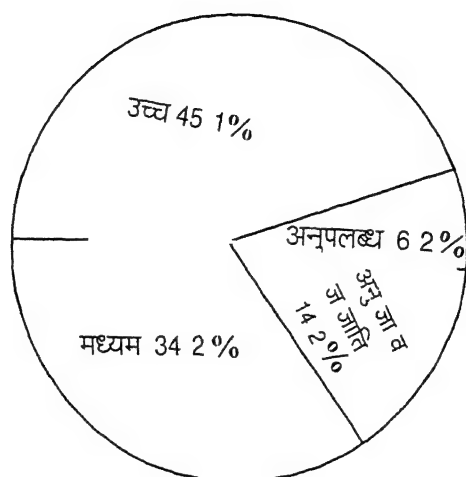
क्रम	जाति	विधान सभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा एव मन्त्री परिषद के मध्य) 1 मन्त्री - विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	171	40 2	51	45 1	1 3 4
2	मध्यम	132	31	39	34 5	1 3 4
3	अनुसूचित जाति एव जन जाति	99	23 2	16	14 2	1 6 2
4	अनुपलब्ध	26	5 6	7	6 2	1 3 4
योग		426 [☆]	100	113	100	1 3 8 (अनुपात)

☆ वही

मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 45 1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात् विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे उच्च जातियो को लगभग 5 प्रतिशत अधिक स्थान प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे मध्यम जाति का प्रतिनिधित्व 31 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 34 5 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 3 5 प्रतिशत स्थान अधिक प्राप्त हुआ। वही अनुसूचित जाति एव जनजाति का विधानसभा मे प्रतिनिधित्व 23 2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 14 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के सदस्यों को 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

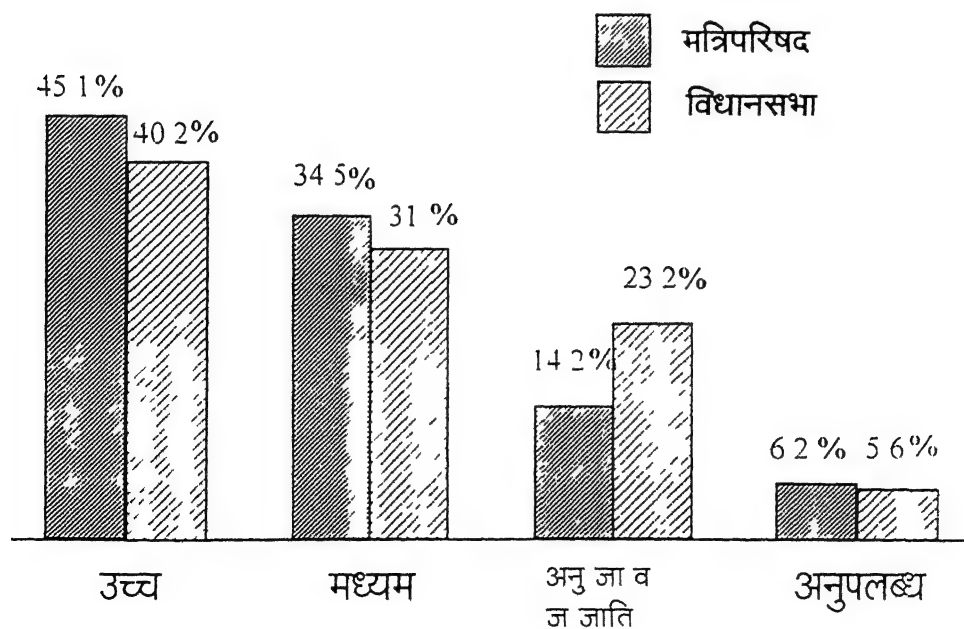
यदि विभिन्न जातियो के सदस्यों का विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले उच्च जाति का 1 3 4, मध्यम जाति का भी 1 3 4 तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का अनुपात 1 6 2 ठहरता है। अतः स्पष्ट है कि जहा उच्च जाति के 3 4

रेखा चित्र संख्या-4.1.5(अ)



सन 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.5(ब)



सन 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की जाति

विधानसभा तथा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे 1 स्थान प्राप्त किया गया वही मध्यम जाति के भी 3 4 विधान सभा सदस्यो पर तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के 6 2 विधान सभा सदस्यो पर एक स्थान मन्त्रिपरिषद मे प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 1 5 के सम्पूर्ण तथ्यो के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि इस काल मे विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद मे उच्च जातियो का वर्चस्व रहा जबकि अनुसूचित जाति एव जनजाति को मन्त्रिपरिषद मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही प्रदान किया गया। यद्यपि विधान सभा के जाति सरचना का कुछ हद तक अनुसरण मन्त्रिपरिषद के निर्माण मे दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश की आबादी की जाति सरचना का अनुसरण न तो विधान सभा मे और न ही मन्त्रिपरिषद मे हुआ है। कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित इस मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 1 5(अ) मे तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रुप से रेखाचित्र सख्या 4 1 5(ब) दर्शाया गया है।

सन् 1991 से सन् 1997 तक के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे विभिन्न जातियो के सदस्यो का प्रतिनिधित्व सारिणी सख्या 5 1 6 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 4 1 6 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे भिन्न-भिन्न जातियो का वर्चस्व रहा है। यदि उच्च जाति के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इसे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 48 2 प्रतिशत सन् 1991 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ। तदपश्चात सन् 1997 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 45 1 प्रतिशत, 1997 मे ही गठित मायावती के नेतृत्व मे द्वितीयबार गठित मन्त्रिपरिषद मे 26 7 प्रतिशत, 1993 मे मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे 17 9 प्रतिशत 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद मे 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उच्च जाति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा कल्याण सिंह के दोनो मन्त्रिपरिषदो मे उच्च जातियो को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पाचो मन्त्रिपरिषदो

सारिणी संख्या 4.1.6

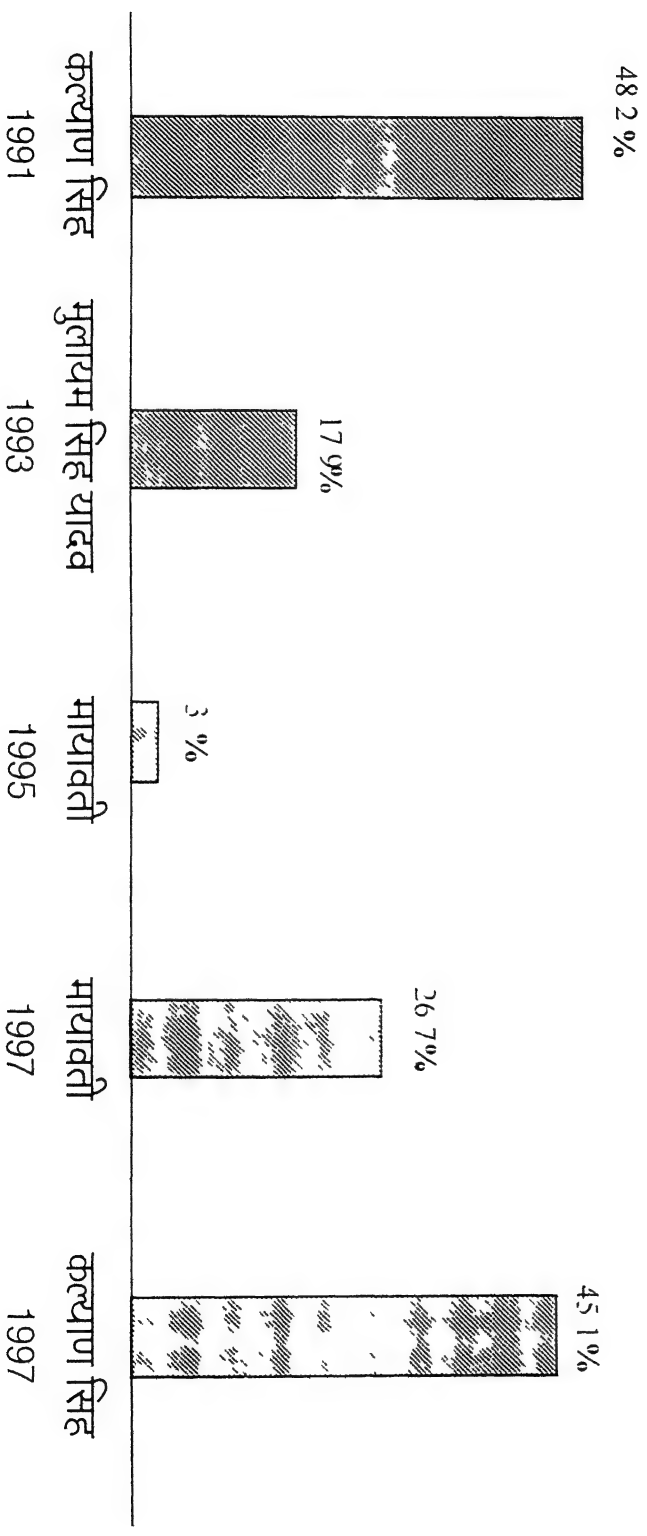
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : जाति

जाति	प्रदेश की जनसंख्या में (अनुमानित)	मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व											
		कल्याण सिंह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिंह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिंह द्वितीय 21-09-97 से -----तक		समग्र 1991 से 1997 तक	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उच्च	21	27	48.2	5	17.9	1	3	12	26.7	51	45.1	96	34.9
मध्यम	41	16	28.6	15	53.5	18	54.5	19	42.2	39	34.5	107	38.9
अनुसूचित जाति एवं जन जाति	21 26	10	17.9	5	17.9	10	30.3	10	22.2	16	14.2	51	18.6
अनुपलब्ध	-	3	5.4	3	10.7	4	12.2	4	8.9	7	6.2	21	7.6
न		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

मे उच्च जाति के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल मे (1991 से 1997 तक) उच्च जातियों को 34.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका। जिसके सापेक्ष कल्याण सिंह के दोनों मन्त्रिपरिषदों में अधिक तथा अन्य मन्त्रिपरिषदों में निम्न प्रतिनिधित्व उच्च जातियों को प्राप्त हुआ। यदि उच्च जातियों का प्रदेश की जनसंख्या में हिस्सा 21 प्रतिशत से विभिन्न मन्त्रिपरिषदों की तुलना करे तो 1993 में गठित मुलायम सिंह की मन्त्रिपरिषद तथा 1995 में गठित मायावती की प्रथम मन्त्रिपरिषद में जहाँ निम्न वही अन्य मन्त्रिपरिषदों में उच्च प्रतिनिधित्व, उच्च जाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में मध्यम जातियों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट है कि सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद में मध्यम जातियों को सर्वाधिक 54.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तदपश्चात् सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में 53.5 प्रतिशत, 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद में 42.2 प्रतिशत, 1997 में ही कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद में 34.5 और 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद में 28.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मध्यम जातियों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ कल्याण सिंह के दोनों मन्त्रिपरिषदों में मध्यम जातियों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही अन्य मन्त्रिपरिषदों में इसकी अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पाँचों मन्त्रिपरिषदों में मध्यम जाति के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाली तो इस काल में (1991 से 1997 तक) मध्यम जातियों को समग्र रूप से 38.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका, जिसके सापेक्ष कल्याण सिंह के दोनों मन्त्रिपरिषदों में निम्न तथा अन्य मन्त्रिपरिषदों में उच्च प्रतिनिधित्व मध्यम जातियों को प्राप्त हुआ। यदि मध्यम जातियों का प्रदेश की जनसंख्या में हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत से विभिन्न मन्त्रिपरिषदों की तुलना करे तो जहाँ मुलायम सिंह यादव तथा मायावती की दोनों मन्त्रिपरिषदों में उच्च वही कल्याण सिंह की दोनों मन्त्रिपरिषदों में निम्न प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ।

रेखा चित्र संख्या-4.1.6(अ)

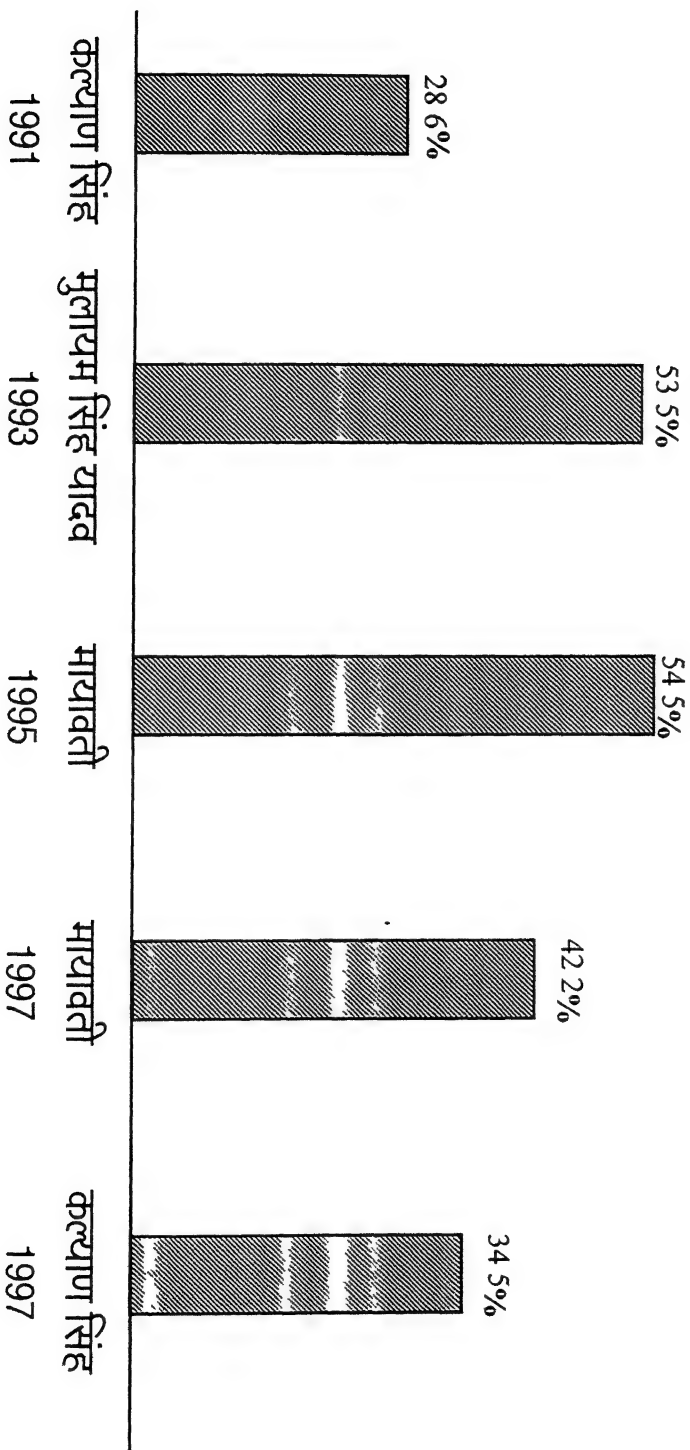


सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद्‌ओं में उच्च जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

इसी प्रकार यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट है कि सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सर्वाधिक 30.3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तदपश्चात् सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीय वार गठित मन्त्रिपरिषद में 22.2 प्रतिशत, सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथम वार गठित मन्त्रिपरिषद में 17.9 प्रतिशत एवं 1997 कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय वार मन्त्रिपरिषद में 14.2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि मायावती के दोनो मन्त्रिपरिषदों में जहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पांचों मन्त्रिपरिषदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल में (1991 से 1997तक) अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को समग्र रूप से 18.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका जिसके सापेक्ष मायावती के नेतृत्व में गठित दोनो मन्त्रिपरिषदों में उच्च तथा अन्य मन्त्रिपरिषदों में निम्न प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को प्राप्त हुआ। यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रदेश की जनसंख्या में हिस्सा 21.26 प्रतिशत से विभिन्न मन्त्रिपरिषदों की तुलना करें, तो मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में ही उच्च, वहीं अन्य मन्त्रिपरिषदों में निम्न प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ।

यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषदों में 5.4, मुलायम सिंह के मन्त्रिपरिषद में 10.7, मायावती के मन्त्रिपरिषदों में 12.2 व मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 8.9 तथा कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषदों में 6.2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के जाति की विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं था। इस काल में मन्त्रिपरिषद के सदस्यों में उच्च जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र संख्या 4.1.6(अ), मध्यम जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र संख्या 4.1.6(ब) तथा अनु.जा. एवं ज. जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या-4.1.6(ब)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में मध्यम जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र संख्या 4 1 6(ब) तथा अनु जा एव ज जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र संख्या 4 1 6(स) में प्रदर्शित किया गया है।

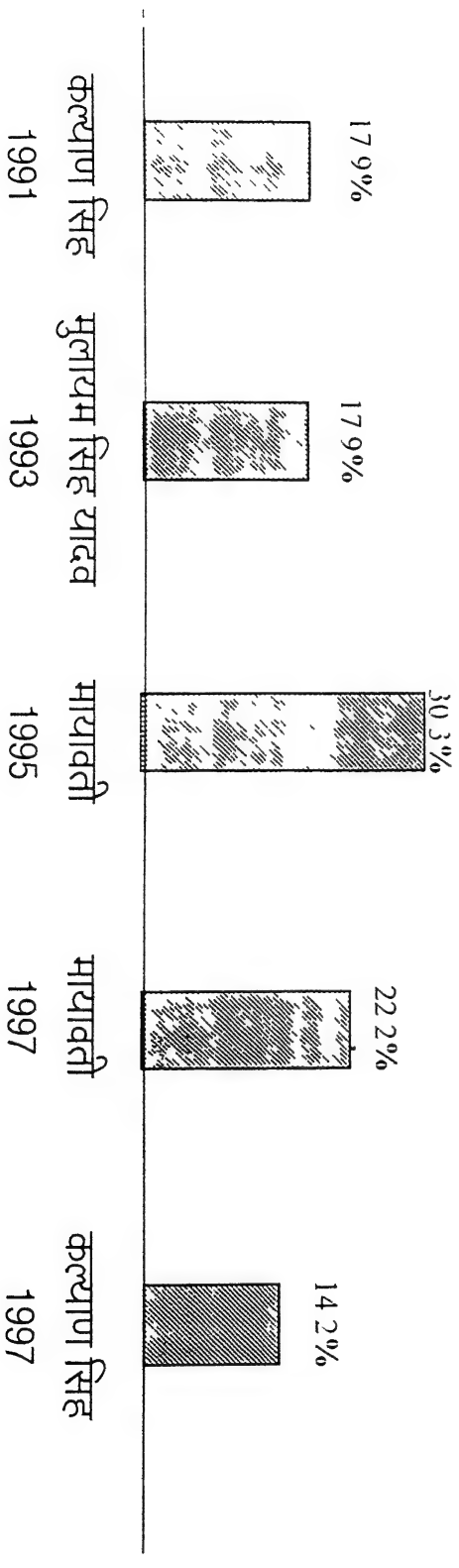
सन् 1991 से 1997 के मध्य विधानसभा व मन्त्रिपरिषदों में विभिन्न जातियों के सदस्यों का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, यह सारिणी संख्या 4 1 7 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 4.1.7

क्र० स०	मन्त्रिपरिषद	उच्च जाति		मध्यम जाति		अनु जा एव ज जाति		अनुपलब्ध	
		विधानसभा (% में)	मन्त्रिपरिषद (% में)	विधानसभा (% में)	मन्त्रिपरिषद (% में)	विधानसभा (% में)	मन्त्रिपरिषद (% में)	विधानसभा (% में)	मन्त्रिपरिषद (% में)
1	कल्याण सिंह (प्रथम)	36 6	48 2	25 8	28 6	25 6	17 9	12	5 4
2	मुलायम सिंह यादव	31 7	17 9	35 5	53 5	25 1	17 9	7 7	10 7
3	मायावती (प्रथम)	3	3	54 5	54 5	30 3	30 3	12 2	12 2
3	मायावती (द्वितीय)	40 2	26 7	31	42 2	23 2	22 2	5 6	8 9
4	कल्याण सिंह (द्वितीय)	45 1	45 1	34 5	34 5	14 2	14 2	6 2	6 2

सारिणी संख्या 4 1 7 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीन विधानसभाओं में उच्च जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा जहाँ सन् 1991 में गठित एकादश विधान सभा में उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व 36 6 प्रतिशत वही 1993 में गठित द्वादश विधान सभा में घटकर 31 7 प्रतिशत तथा त्रयोदश

रेखा चित्र संख्या-4.1.6(स)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में अ.जा.व अ.जन जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

विधान सभा में बढ़कर 40.2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उच्च जातियों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 1991 से 1997 के मध्य विधान सभाओं में उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व 31.7 प्रतिशत से 40.2 प्रतिशत के मध्य रहा। जबकि इस काल में (सन् 1991 से 1997) तक मन्त्रिपरिषद् में उच्च जातियों के प्रतिनिधित्व में कोई निश्चित स्थिरता न होकर घटता-बढ़ता रहा है और भिन्न-भिन्न समयों पर यह 48.2 से 3 प्रतिशत के मध्य रहा। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि मायावती के दोनों मन्त्रिपरिषदों में तथा मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषदों में जहाँ उच्च जातियों को विधान सभा सदस्यों के अनुपात में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वहीं इस काल में गठित अन्य मन्त्रिपरिषदों में उच्च जाति को विधानसभा के अनुपात में निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनों विधानसभाओं में मध्यम जाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो रहा है और यह 25.8 प्रतिशत से 35.5 प्रतिशत के मध्य रहा। सन् 1993 में गठित द्वादश विधानसभा में जहाँ मध्यम जाति के सदस्यों को सर्वाधिक 35.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वहीं 1991 में गठित एकादश विधान सभा में केवल 25.8 प्रतिशत त्रयोदश विधानसभा में 31 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ। जबकि इस काल में (सन् 1991 से 1997) तक मन्त्रिपरिषदों में भी मध्यम जाति के प्रतिनिधित्व में स्थिरता न होकर घटता-बढ़ता रहा है और भिन्न भिन्न समय पर यह 54.5 प्रतिशत से 28.6 प्रतिशत के मध्य रहा। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि मध्यम जातियों को हमेशा विधानसभा के अनुपात में मन्त्रिपरिषद् में उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनों विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट है कि इस काल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व में विधान सभा दर विधानसभा कमी आयी है। जहाँ 1991 में गठित एकादश विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व

25 6 रहा वहीं यह घटकर द्वादश विधान सभा में 25 1 हो गया तथा त्रयोदश विधान सभा में और घटकर मात्र 23 2 प्रतिशत रह गया। जबकि इस काल में (सन् 1991 से 1997) तक मन्त्रिपरिषद् में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा है और भिन्न-भिन्न समयों पर यह 30 3 प्रतिशत से 14 2 प्रतिशत के मध्य रहा। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जहाँ 1995 में मायावती के नेतृत्व में प्रथमवार गठित मन्त्रिपरिषद् में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा सदस्यों के अनुपात में उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वहीं अन्य मन्त्रिपरिषद् में विधान सभा के सदस्यों के अनुपात में निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यहाँ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि एकादश विधानसभा में 12 प्रतिशत, द्वादश विधानसभा में 7 7 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधान सभा में 1 6 प्रतिशत सदस्यों की जाति के विषय में कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है।

इस काल (सन् 1991 से 1997) में गठित सभी मन्त्रिपरिषद् की जातीय संरचना से संभावित समस्त आकड़ों के अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि इस काल में मन्त्रिपरिषद् में जातीय आधार पर सामंजस्य बनाये रखने का कोई विशेष प्रयास दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है बल्कि जिस दल की सरकार बनी है वह अपने सामाजिक दर्शन, संसदों की जातीय संरचना, भविष्य के लिए सामाजिक अभियंत्रिकी को ध्यान में रखकर मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न जातीय वर्ग के सदस्यों के प्रतिनिधि वर्ग का निर्धारण करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद् को छोड़कर इस काल की अन्य सभी मन्त्रिपरिषद् विभिन्न दलों की संविदा का परिणाम रहीं और निश्चय ही संविदा सरकार की विवशता उनके साथ भी जुड़ी रही होगी।

सन् 1991 में एकादश विधानसभा के लिए हुए चुनाव के पश्चात् कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथम बार गठित भारतीय जनता पार्टी के मन्त्रिपरिषद् की जातीय संरचना में उच्च जातियों को अन्य जातियों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया

मन्त्रिपरिषद में 48.02 प्रतिशत स्थान अर्थात् लगभग आधा प्रतिनिधित्व इस जाति के सदस्यों को प्राप्त था। जबकि इसके पश्चात् सबसे अधिक प्रतिनिधित्व 28.6 प्रतिशत मध्यम जाति के तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को न्यूनतम मात्र 17.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद में प्रदान किया गया। इस प्रकार कल्याण सिंह की इस प्रथम मन्त्रिपरिषद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व मध्यम जाति के सदस्यों को प्रदेश की जनसंख्या में उनके अनुपात से कम प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद में प्राप्त हो गया साथ ही विधानसभा में भी विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व के अनुपात का अनुसरण न करते हुए उच्च जाति को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्यम जाति के लोगों को भी विधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व के सापेक्ष मन्त्रिपरिषद में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और चौथाई से भी अधिक हिस्सा मन्त्रिपरिषद में इस जाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि भारतीय जनता पार्टी के इस मन्त्रिपरिषद के प्रमुख, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मध्यम जाति से आते हैं। जहाँ तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है तो निश्चय है उनको अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व इस मन्त्रिपरिषद में प्रदान किया गया।

कल्याण सिंह के नेतृत्व में 1997 में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद भारतीय जनता पार्टी तथा विभिन्न दलों के आपसी सहयोग का परिणाम था फिर भी विधान सभा की 174 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों में ही नहीं अपितु विधान सभा में सबसे बड़ा दल था।

इस मन्त्रिपरिषद में भी पूर्व की भांति उच्च जाति के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कल्याण सिंह की द्वितीय मन्त्रिपरिषद में इस काल में गठित अन्य मन्त्रिपरिषदों की तुलना में उच्च जाति के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अतः यह प्रतीत होता है कि कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषदों में उच्च जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था।

यहा यह तथ्य भी स्मरणीय है कि यद्यपि भारतीय जनता पार्टी अपने को एक राष्ट्रवादी दल के रूप में प्रस्तुत करती रही लेकिन आम मान्यता है कि यह हिन्दुओं के उच्च जाति की पार्टी है और इस वर्ग का बड़ा समर्थन इसके साथ है।¹

जबकि 1993 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी एवम् बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक 53.5 प्रतिशत भाग प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यों को प्राप्त था, तथा उच्च एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को बराबर-बराबर 17.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद में प्राप्त था, अतः स्पष्ट है कि मुलायम सिंह के इस मंत्रिपरिषद में मध्यम जाति के प्रतिनिधित्व को अन्य की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह यादव स्वयं मध्यम जाति से हैं तथा उनके दल समाजवादी पार्टी का दर्शन यद्यपि समाजवाद पर आधारित है किन्तु यह आम धारणा है कि मुलायम सिंह यादव को मध्यम जातियों का समर्थन प्राप्त है तथा उनके राजनैतिक क्रियाकलाप इस वर्ग की राजनीति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होते हैं। यदि इस काल में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषदों की जाति संरचना का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट है कि 1995 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर आधारित मायावती की प्रथम मंत्रिपरिषद में उच्च जातियों के एक मात्र सदस्य को सम्मिलित किया गया था जबकि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यों को प्राप्त था तथा एक तिहाई से अधिक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राप्त था। अतः प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मन्त्रिपरिषद में मध्यम जाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन प्रदान किया गया किन्तु यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मायावती के इस मंत्रिपरिषद में उच्च जाति का एक मात्र सदस्य और मध्यम जाति के अनेक सदस्य ऐसे थे जो उसी दौरान समाजवादी पार्टी से अलग होकर बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित

1 चौधरी एन0 के0, 'एसेम्बली एलेक्शन-1993' शिप्रा पब्लिकेशन, पृष्ठ 257

हुए थे। और उन्हें मंत्री पद भी प्रदान किया गया।

अतः यह कहा जा सकता है कि मायावती के इस मंत्रिपरिषद में उच्च जाति के केवल एक मात्र सदस्य को सम्मिलित कर न के बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। और वह भी सदस्य समाजवादी पार्टी से आया था। लेकिन यहाँ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि बहुजन समाज पार्टी का तत्कालीन विधानसभा (द्वादश विधान सभा) के चुनाव में तथा उसके पूर्व का राजनैतिक सफर उच्च जाति के विरोध पर ही आधारित था। यहाँ पार्टी ने अभी तक किसी सवर्ण (उच्च जाति) को टिकट नहीं दिया था, ¹ वही पार्टी प्रमुख कांशी राम ने अपने सवर्ण विरोधी नीति को स्पष्ट करते हुए चुनाव प्रचार के समय कहा कि प्रदेश की विधान सभा चुनाव में जिन स्थानों पर समाजवादी पार्टी ² में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय उम्मीदवार खड़े किये हैं, उन्हें न तो बहुजन समाज पार्टी ³ का समर्थन होगा न तो वोट। किन्तु मायावती ने अपने मंत्रिपरिषद के गठन के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी जिसे वो उच्च जाति के हितों का समर्थन करने वाली पार्टी मानती थी, ⁴ सहयोग लिया वही उच्चजाति के एक सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया।

जबकि 1997 में गठित मायावती के द्वितीय मंत्रिपरिषद में भी मध्यम जाति के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था किन्तु यह तथ्य भी स्मरणीय है कि प्रथम तो यह मंत्रिपरिषद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सविदा का परिणाम था और सविदा की विवशता का सामना मायावती को भी सत्ता में बने रहने के लिए करना पड़ा होगा, द्वितीय

1 राष्ट्रीय सहारा 30 अक्टूबर-1993

2 बसपा व सपा ने यह विधान सभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था

3 राष्ट्रीय सहारा 30 अक्टूबर -1993

4 सिंह आर. के. कांशी राम एवम् बी एस पी. -पृष्ठ 59 एवम् दैनिक जागरण - 30 अक्टूबर-1993

इस काल में आते आते बसपा का सर्वण विरोध नीति उतना तीव्र नहीं रह गया। जितना आरम्भ में था क्योंकि एक तरफ जहाँ उसने भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से समझौता कर सरकार बनाया वहीं इस विधान सभा चुनाव में उसने उच्च जातियों को भी पार्टी का उम्मीदवार बनाया तथा कांग्रेस के साथ चुनाव समझौता किया।

अतः इन विश्लेषणों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इस काल में (1991 से 1997 के मध्य) विभिन्न दलों ने अपनी मंत्रिपरिषदों में जातीय सतुलन को बनाये रखने का प्रयास नहीं बल्कि अपने सामाजिक दर्शन और जातीय समर्थन के आधार पर मंत्रिपरिषद में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर है कि इस काल में गठित संयुक्त मंत्रिपरिषदों को मंत्रिपरिषद के निर्माण में सविदा की विवशता का भी सामना करना पड़ा।

4.2 धार्मिक पृष्ठभूमि

जाति के समान ही धर्म भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मानव इतिहास में धर्म के नाम पर सदैव विवाद उठते रहे हैं। धर्म की दृष्टि से भारत विशेष रूप से हतभाग्य रहा है। स्वाधीनता आन्दोलन के समय अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए धार्मिक भेद-भाव का विशेष लाभ उठाया। भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालिक है। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो (डिवाइड एण्ड रूल) की नीति को अपनाया ¹ जिससे वे भारत में राष्ट्रीयता की भावना को तोड़कर अपना शासन चलाते रहे।

ब्रिटिश शासन काल में साम्प्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का प्रमुख कारण यहाँ प्रतिनिधि एवं निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना करना भी था। अंग्रेजों ने प्रतिनिधित्व

1 तारा चन्द्र - हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मोमेंट इन इण्डिया वल्यूम 11, दिल्ली पब्लिशिंग मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन 1967, पृष्ठ 514

को पृथक्-पृथक् समूहों वर्गों, हितों, क्षेत्रों सस्थाओं और जातियों के प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने भारत में अनेक जातियों एवं सम्प्रदायों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्वबोध और एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की समस्या के रूप में स्वीकार किया तथा इसी कारण धार्मिक समूहों को पृथक्-पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार 1909 के सुधारों, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मण्डल की व्यवस्था की गयी, आधुनिक राजनीतिक साम्प्रदायिकता का उद्घाटन किया।² समय-समय पर हरेक अल्प सख्यक समुदाय ने विधान मण्डलों में अपने प्रतिनिधित्व और सरकारी पदों नियुक्ति में अपनी सख्या बढ़ाने के लिए अपनी माँगों में वृद्धि की। सरकार एक के एक बाद ऐसी सभी माँगों को स्वीकार करती गई, ताकि राष्ट्रीय जनता की शक्ति को कमजोर किया जा सके।³ हर लिहाज से यह भारतीय राजनीति की एक जहरीली विशेषता बन गई।⁴ इसने साम्प्रदायिकता की वृद्धि को प्रेरणा प्रदान की जिसकी अन्तिम परिणति भारत के विभाजन तथा अलग मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान के सृजन से हुई।⁵

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त यद्यपि साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया तथापि राजनीति एवं निर्वाचन में धर्म की भूमिका समाप्त नहीं हुई। यद्यपि संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित

2 नार्मन ब्राउन 'द यूनाइटेड स्टेट एण्ड इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड बंगला देश, स03, इलिनाश हार्बर्ट यूनि0 प्रेस, 1972, पृ0 141

3 जौहरी जे0 सी0 - 'भारतीय राजनीति' जालधर, विशाल पब्लि0-पृ0 335

4 नार्मन ब्राउन, 'वही, पृ0 142

5 स्मिथ इण्डिया एस ए सेक्यूलर स्टेट- न्यू जर्सी, प्रिंसटन यूनिवर्सल प्रेस (1963) पृ0 102

किया गया तथापि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका बनी रही। सविधान के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो की गई परन्तु धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना नहीं हो सकी।

स्वाधीनता के उपरान्त प्रारम्भ हुई निर्वाचन राजनीति में धर्म और सम्प्रदाय के नकारात्मक महत्व को प्रश्रय मिला है। प्रारम्भ में यह समझा जाता था कि राजनीति, धर्म और सम्प्रदाय का शोषण करती हैं, परन्तु अब यह धारणा भी बनने लगी है कि धर्म और सम्प्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे हैं। जब एक समुदाय समझबूझकर धार्मिक तथा सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगें रखने का निर्णय करता है, तब सामुदायिक चेतना सम्प्रदायवाद के रूप में एक राजनीतिक सिद्धान्त बन जाती है। राजनीतिक स्वायत्तता को तब, सांस्कृतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखने की अनिवार्य शर्त घोषित कर दिया जाता है। बहुसांस्कृतिक समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराव वास्तव में विभिन्न समूहों के बीच चल रहे सत्ता द्वन्द्व के लक्षण हैं। इस पारस्परिक द्वन्द्व को सैद्धान्तिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में सम्प्रदायवाद का मूल सार है।⁶ अभी तक भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या को हिन्दू और मुसलमान-इन दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के मध्य तनाव के रूप में देखा जाता रहा था। कुछ वर्षों से सिख सम्प्रदाय के कुछ लोगों के संकीर्ण दृष्टिकोण तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण हिन्दू एवं सिख सम्प्रदायों के बीच बढ़ते हुए तनाव ने साम्प्रदायिकता की समस्या को और अधिक भीषण रूप प्रदान कर दिया है। भारत में साम्प्रदायिकता को सभी सम्प्रदायों चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों, ईसाई अथवा सिख, के राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले परम्परावादी अभिजन लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए सैद्धान्तिक जामा पहनाकर बढ़ावा दिया है। परिणामतः भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

1 दीक्षित, (श्रीमति) प्रभा - साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक सन्दर्भ, मेकमिलन 1980, भूमिका -

भारतीय राजनीति में धर्म और साम्प्रदायिकता अत्यधिक प्रभावशाली निर्धारक तत्व हैं। धर्म का प्रयोग भारतीय राजनीति में जहाँ एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वहाँ दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति अर्जित करने के लिए भी धर्म एक प्रभावी माध्यम बना हुआ है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका इतनी प्रभावी है कि धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण भी हुआ है। जनता से की जाने वाली अपीलें, उन्हें दिए जाने वाले आश्वासनों, निर्वाचनों में प्रत्याशियों का चयन तथा मतदान व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट देखने को मिलता है।

निर्वाचन की राजनीति और मतदान व्यवहार तक ही धर्म अथवा साम्प्रदायिकता की भूमिका नहीं है, वरन् शासन के महत्वपूर्ण निर्णय भी धर्म और साम्प्रदायिकता की राजनीति से प्रभावित रहते हैं। प्रत्याशियों के चयन से लेकर वोट बटोरने तक तो धार्मिक मठाधीशों का प्रभाव रहता ही है, उसके बाद शासन के गठन तथा शासन द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों में धार्मिक संगठन तथा धर्म के मठाधीश दबाव समूह की भूमिका का निर्वाह करते हैं।

केन्द्र एवं राज्यों में मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रिपरिषदों के गठन के समय भी धर्म की एक प्रभावी भूमिका रहती है। प्रदेश की मन्त्रिपरिषद अथवा मन्त्रिमण्डल के गठन के समय सदैव इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख सम्प्रदायों एवं धार्मिक विश्वास रखने वालों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल जाये। धार्मिक अल्पसंख्यकों को मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सदैव ही प्रयास किया गया है। सदैव ही यह प्रयास होता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देते हुये एक सन्तुलित मन्त्रिपरिषद की रचना की जाये।

मई-जून 1991 में एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 24-6-91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथम बार गठित तथा दिनांक 6-12-92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4.2.1 में प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 4 2.1

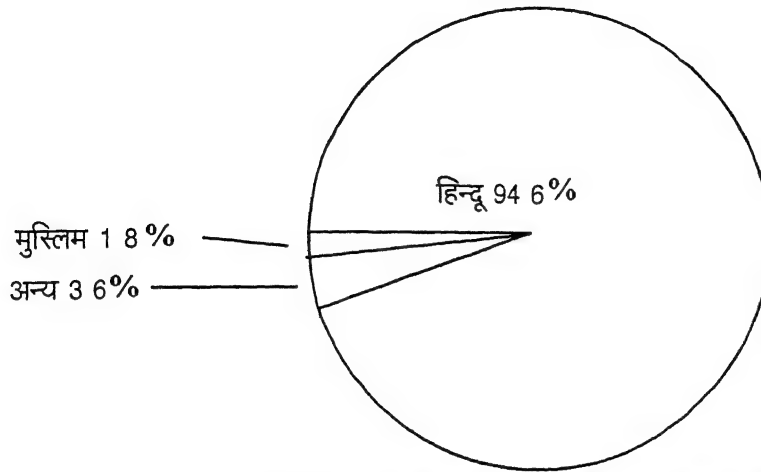
सन् 1991 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्

क्र० स०	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	389	93 1	53	94 6
2	मुस्लिम	23	5 5	1	1 8
3	अन्य	06	1 4	2	3 6
योग		418	100	56	100

सारिणी सख्या 4 2 1 के अर्न्तविष्ट आँकड़ो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 24-6-91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद् मे कुल 56 सदस्य थे, जिसमे 52 सदस्य हिन्दू धर्म से, 1 सदस्य मुस्लिम धर्म से, तथा 2 सदस्य अन्य धर्मों से थे। जबकि इस काल मे विधानसभा के 418 सदस्यो मे 389 सदस्य हिन्दू धर्म से 23 मुस्लिम धर्म से, तथा 6 सदस्य अन्य धर्मों से रहे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, विधानसभा मे हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व 93 1 प्रतिशत रहा, और मन्त्रिपरिषद् मे 94 5 प्रतिशत रहा अर्थात् विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद् मे हिन्दू धर्म के सदस्यो को लगभग 1 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा मे 5 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् मे उन्हे 1 8 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार मुस्लिमो को विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद् मे लगभग 3 गुना कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मों का विधानसभा मे 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् मे उन्हे 1.4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अतः अन्य धर्मों का विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद् मे लगभग 2 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.2 1 के समस्त आँकड़ो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस काल मे मुस्लिमो को विधानसभा तथा मन्त्रिपरिषद् मे अत्यन्त अल्प

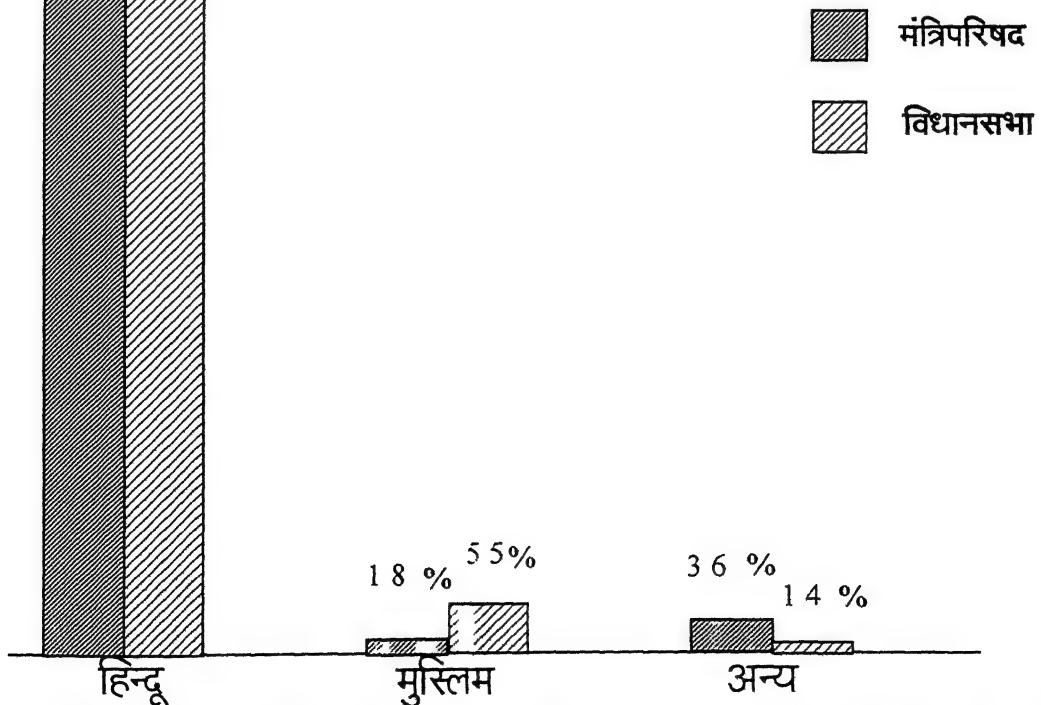
रेखा चित्र संख्या -4.2.1(अ)



सन 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

94.6% 93.1%

रेखा चित्र संख्या-4.2.1(ब)



सन 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि अन्य धर्मों के सदस्यों को भी विधानसभा तथा मन्त्रिपरिषद् में अत्यन्त ही अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका, किन्तु प्रदेश में उनकी जनसंख्या (कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत) के सापेक्ष मन्त्रिपरिषद् एवं विधानसभा में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों की स्थिति रेखा चित्र संख्या 4.2.1 (अ) में दर्शायी गयी है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र संख्या 4.2.1 (ब) में दर्शायी गयी है-

नवम्बर 1993 में विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 4-12-93 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी संख्या 4.2.2 में प्रदर्शित है।

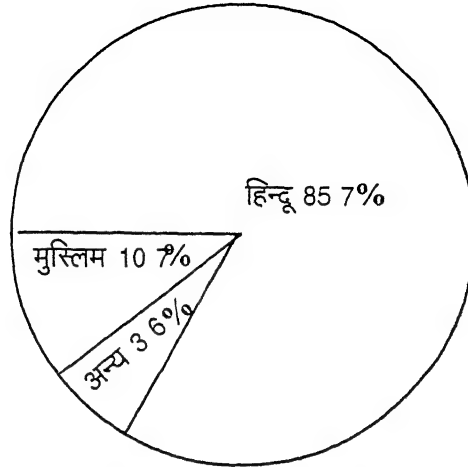
सारिणी संख्या 4.2.2

सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्

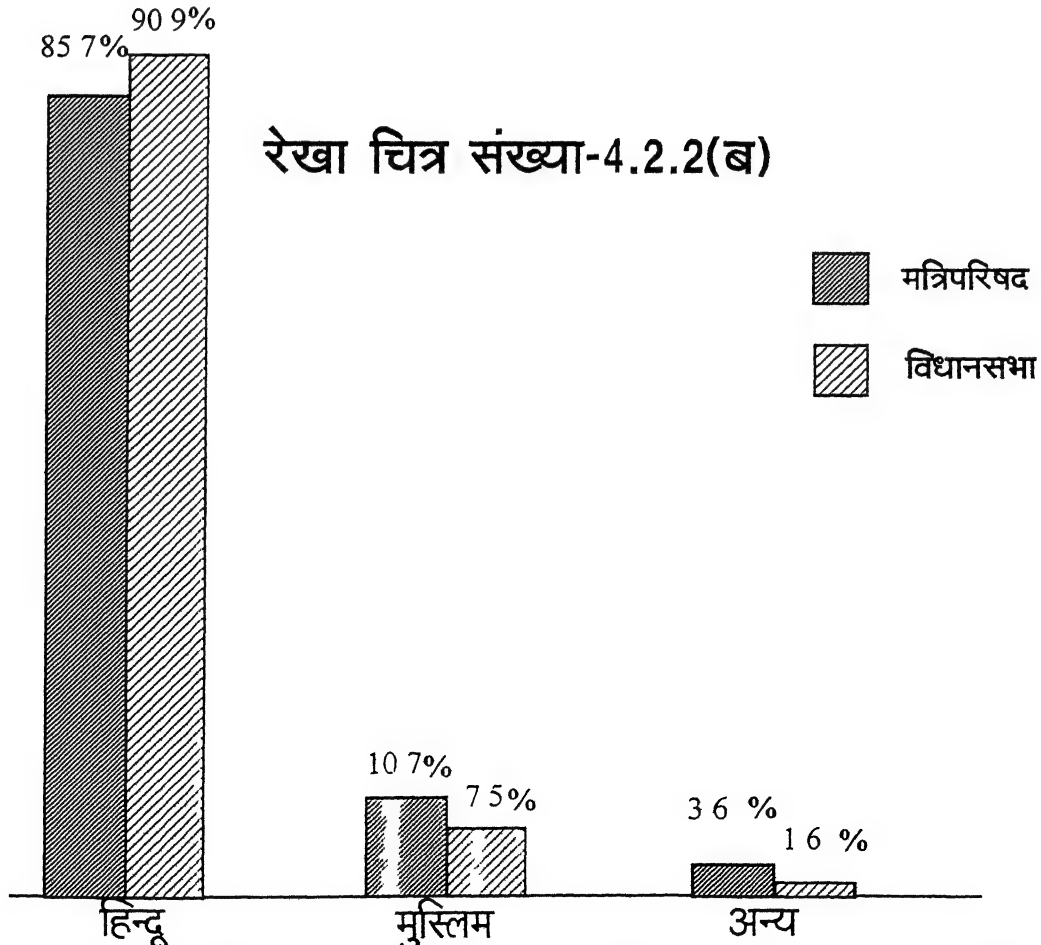
क्र० सं०	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	387	90.9	24	85.7
2	मुस्लिम	32	7.5	3	10.7
3	अन्य	7	1.6	1	3.6
योग		426	100	28	100

सारिणी संख्या 4.2.2 के अन्तर्विष्ट आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में कुल 28 सदस्य थे, जिसमें 24 सदस्य हिन्दू धर्म से, 3 सदस्य मुस्लिम धर्म से, तथा 1 सदस्य अन्य धर्म से रहा। जबकि इस काल में विधानसभा के 426 सदस्यों में 387 हिन्दू धर्म से, 32 मुस्लिम धर्म से तथा 7 अन्य धर्म से रहे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा में हिन्दू

रेखा चित्र संख्या-4.2.2(अ)



सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की धार्मिक स्थिति



सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

धर्म का प्रतिनिधित्व 90.9 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 85.7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात् विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में हिन्दू धर्म के सदस्यों को लगभग 5 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा में 7.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 10.7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, इस प्रकार मुस्लिमों को विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में लगभग 3 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मों का विधान सभा में 1.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 3.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, अतः अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों को विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में लगभग 2 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.2.2 के समस्त आकड़ों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो रहा है कि विभिन्न धर्मावलम्बियों के विधानसभा में प्रतिनिधित्व अनुपात में काफी असन्तुलन रहा। जिसे मन्त्रिपरिषद् में दूर करने का प्रयास दृष्टिगोचर हो रहा है किन्तु फिर भी प्रदेश में उनकी जनसख्या ¹ के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया है। इस मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों की स्थिति को रेखा चित्र सख्या 4.2.2 (अ) में दर्शाया गया है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र सख्या 4.2.2 (ब) में दर्शाया गया है-

1- प्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 20.1 प्रतिशत है जिसमें मुस्लिम 17.3 प्रतिशत तथा अन्य धर्मावलम्बी 8 प्रतिशत हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें प्रस्तुत शोध के अध्याय 2 में देखें।

मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद् के पतन के पश्चात् दिनांक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4.2.3 में प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या-4.2.3

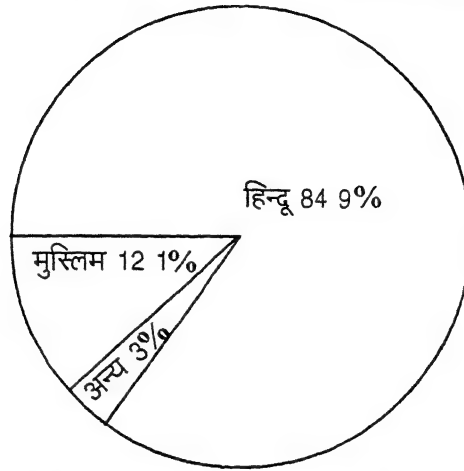
1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्

क्र० सं०	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	387	90.9	28	84.9
2	मुस्लिम	32	7.5	4	12.1
3	अन्य	7	1.6	1	3
योग		426	100	33	100

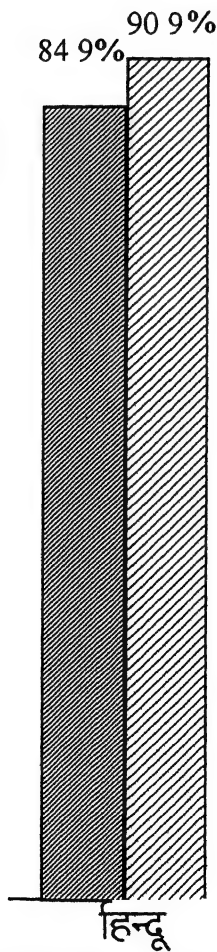
सारिणी सख्या 4.2.3 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है दिनांक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद् में कुल 33 सदस्य थे जिसमें 28 सदस्य हिन्दू धर्म से 4 मुस्लिम धर्म से तथा 1 सदस्य अन्य धर्म से था। जबकि इस काल में विधानसभा के 426 सदस्यों में 387 हिन्दू धर्म से, 32 मुस्लिम धर्म से तथा 7 अन्य धर्म से थे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा में हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व 90.9 प्रतिशत रहा है और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 84.9 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात् विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में हिन्दू धर्म के सदस्यों को लगभग 6 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका, जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा में 7.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 12.1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, इस प्रकार मुस्लिमों को विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में लगभग 5 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मों का विधानसभा में 1.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अतः अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों को विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में लगभग 2 गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारणी सख्या 4.2.3 के समस्त आकड़ों के प्रकाश में स्पष्ट हो रहा

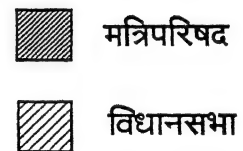
रेखा चित्र संख्या -4.2.3(अ)



सन 1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की धार्मिक स्थिति



रेखा चित्र संख्या-4.2.3(ब)



सन 1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

हैं कि विभिन्न धर्मावलम्बियों का प्रतिनिधित्व अनुपात में असंतुलन विद्यमान था, यद्यपि अन्य धर्मावलम्बियों सदस्यों को प्रदेश में उनकी जनसंख्या (कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत) के अनुपात से अधिक अनुपात में विधानसभा और मंत्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। किन्तु मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से (कुल जनसंख्या के 17.3 प्रतिशत) कम अनुपात में विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि विधानसभा की तुलना में मंत्रिपरिषद् में मुस्लिमों को अधिक भागीदारी प्रदान करके जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व को सन्तुलित करने का प्रयास मंत्रिपरिषद् में किया जा रहा है। इस मंत्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों की स्थिति को रेखा चित्र संख्या 4.2.3 (अ) में दर्शाया गया है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र संख्या 4.2.3 (ब) में दर्शाया गया है।

सितम्बर-अक्टूबर 1996 में त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 21-9-97 तक कार्यरत, भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मंत्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारणी संख्या 4.2.4 में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 4.2.4 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मंत्रिपरिषद् में कुल 45 सदस्य थे। जिसमें 38 हिन्दू धर्म से, 4 मुस्लिम धर्म से तथा 3 सदस्य अन्य धर्म से थे। जबकि इस काल में विधानसभा के 426 सदस्यों में से 377 हिन्दू धर्म से 39 मुस्लिम धर्म से तथा 10 सदस्य अन्य धर्मों से थे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि

सारिणी सख्या 4.2 4

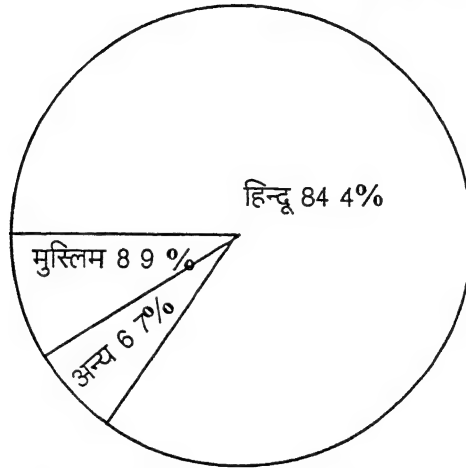
सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद्

क्र० सं०	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	377	85.5	38	84.4
2	मुस्लिम	39	9.1	4	8.9
3	अन्य	10	2.4	3	6.7
योग		426	100	45	100

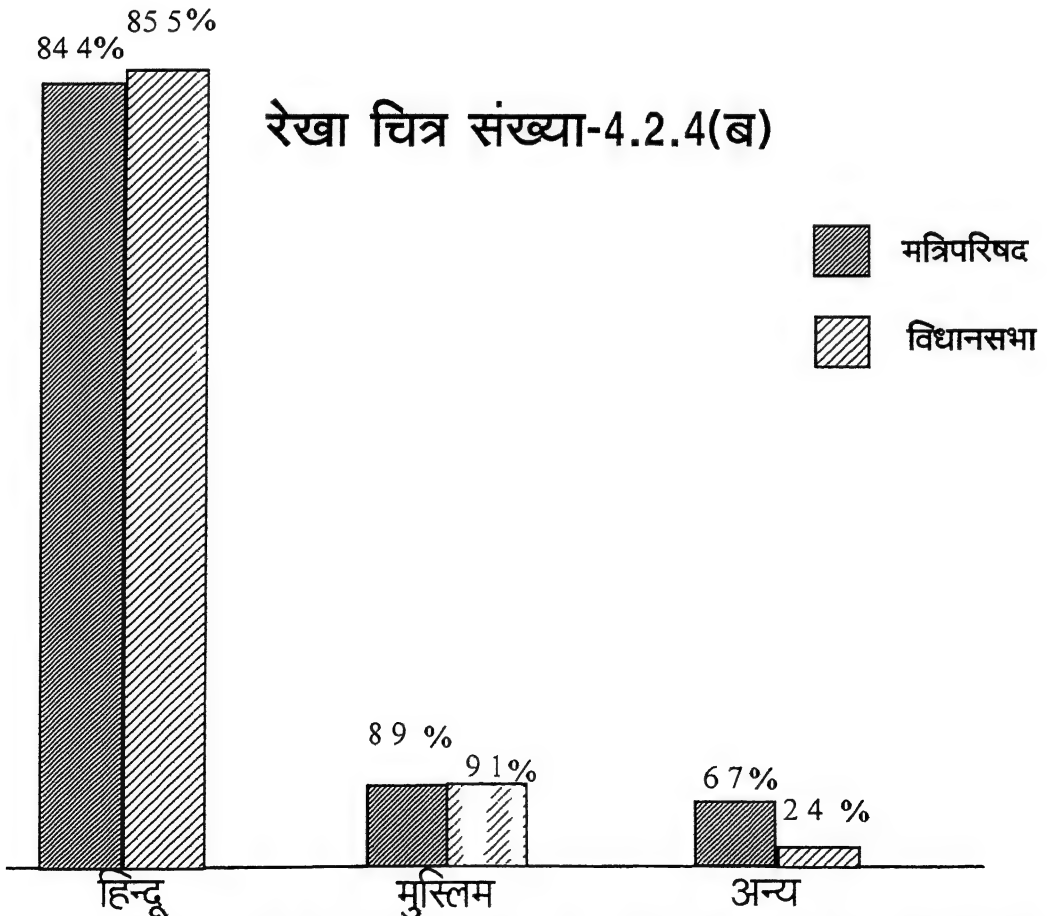
विधान सभा मे हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व 88.5 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् मे 84.4 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात् विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद् मे हिन्दू धर्म के सदस्यों को लगभग 4 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा मे 9.1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् मे उन्हें 8.9 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार मुस्लिमों को विधानसभा की तुलना मे 1 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों का विधानसभा मे प्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् मे उन्हें 6.7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ अतः अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों को विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद् मे लगभग 3 गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.2 4 के समस्त आकड़ों के प्रकाश मे स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा तथा मन्त्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मावलम्बियों के प्रतिनिधित्व मे अत्यधिक असन्तुलन विद्यमान था। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों को प्रदेश मे उनकी जनसख्या (कुल जनसख्या के 8 प्रतिशत) के अनुपात से अधिक अनुपात मे विधानसभा मे और उससे भी

रेखा चित्र संख्या-4.2.4(अ)



सन 1997 में मायावती के मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की धार्मिक स्थिति



सन 1997 में मायावती के मन्त्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

अधिक मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सारणी में प्रदर्शित अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों में कई ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म मानव धर्म तथा भारतीय धर्म बताया। जहाँ तक मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो इस काल में विधानसभा में उन्हें प्रदेश में अपनी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम तथा मन्त्रिपरिषद् में और भी कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों की स्थिति को रेखा चित्र संख्या 4.2.4 (अ) में दर्शायी गयी है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र संख्या 4.2.4 (ब) में दर्शायी गयी है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणाम स्वरूप छ महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री मायावती द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनांक 21-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में 31 दिसम्बर 1997 तक विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व की स्थिति को सारणी संख्या 4.2.5 में प्रदर्शित किया गया है।

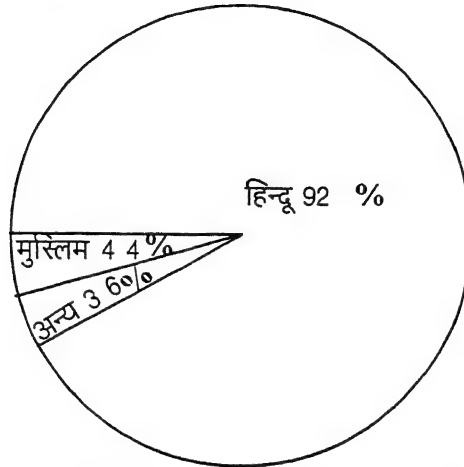
सारणी संख्या-4.2.5

सन् 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्

क्र० सं०	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	377	85.5	104	92
2	मुस्लिम	39	9.1	5	4.4
3	अन्य	10	2.4	4	3.6
योग		426	100	113	100

सारणी संख्या 4.2.5 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 31-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद् में 31-12-97 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए जिसमें 104 हिन्दू धर्म से, 5 मुस्लिम धर्म से तथा 4 सदस्य अन्य

रेखा चित्र संख्या-4.2.5(अ)

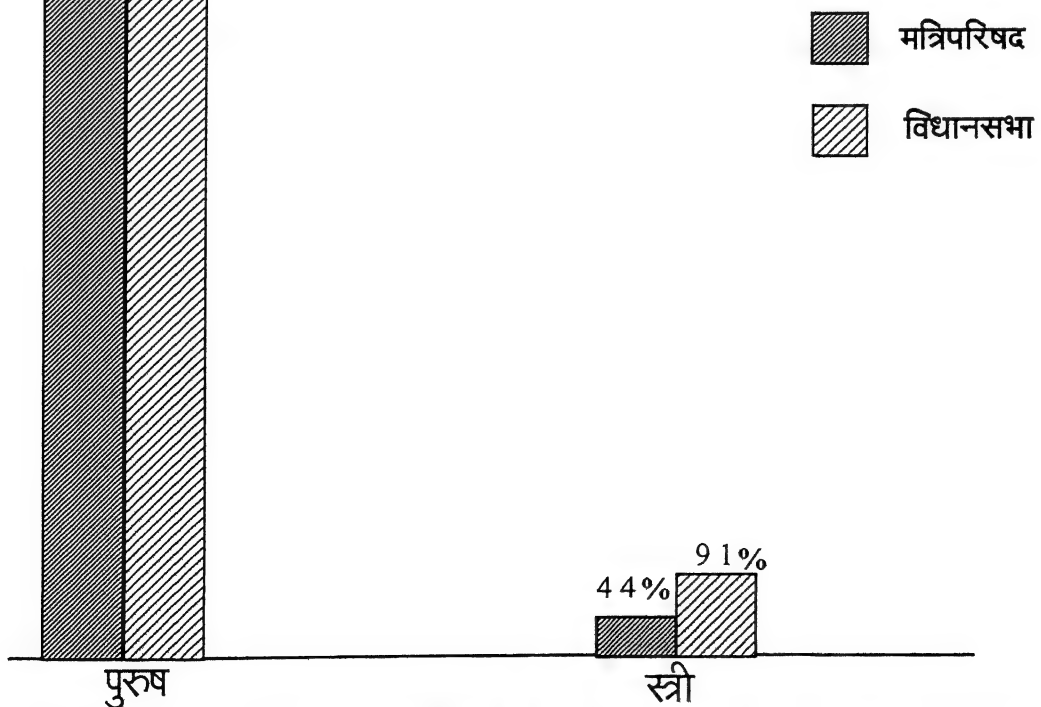


सन 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

92 %

85.5 %

रेखा चित्र संख्या-4.2.5(ब)



सन 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

धर्म से थे। जबकि इस काल में विधानसभा के 426 सदस्यों में से 377 हिन्दू धर्म से 39 मुस्लिम धर्म से तथा 10 सदस्य अन्य धर्म से थे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा में हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व 88.5 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् में 92 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात् विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में हिन्दू धर्म के सदस्यों को लगभग 4 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा में 9.1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 4.4 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, इस प्रकार मुस्लिमों को विधानसभा की तुलना में लगभग आधा प्रतिनिधित्व ही प्राप्त हुआ। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों को विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में एक प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.2.5 के समस्त आकड़ों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो रहा है कि यद्यपि विधानसभा में विभिन्न धर्मावलम्बियों के प्रतिनिधित्व में अत्यधिक असन्तुलन विद्यमान था तथापि मन्त्रिपरिषद् में यह असन्तुलन विधानसभा की तुलना में और अधिक हो जा रहा है। इस काल में मन्त्रिपरिषद् में मुस्लिमों को बहुत ही अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाया जो उनके प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात का मात्र लगभग चौथाई था। इस मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न धर्मों की स्थिति को रेखा चित्र सख्या 4.2.4 (अ) में दर्शाया गया है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र सख्या 4.2.4 (ब) में दर्शाया गया है।

सन् 1991 से सन् 1997 तक के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में विभिन्न धर्मावलम्बी सदस्यों के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4.2.6 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 4.2.6 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित पाँचों मन्त्रिपरिषदों में प्रदेश के बहुसंख्यक हिन्दू आबादी को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनमें हिन्दुओं को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद् में 94.6 प्रतिशत प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद्

सारणी संख्या 4.2.6

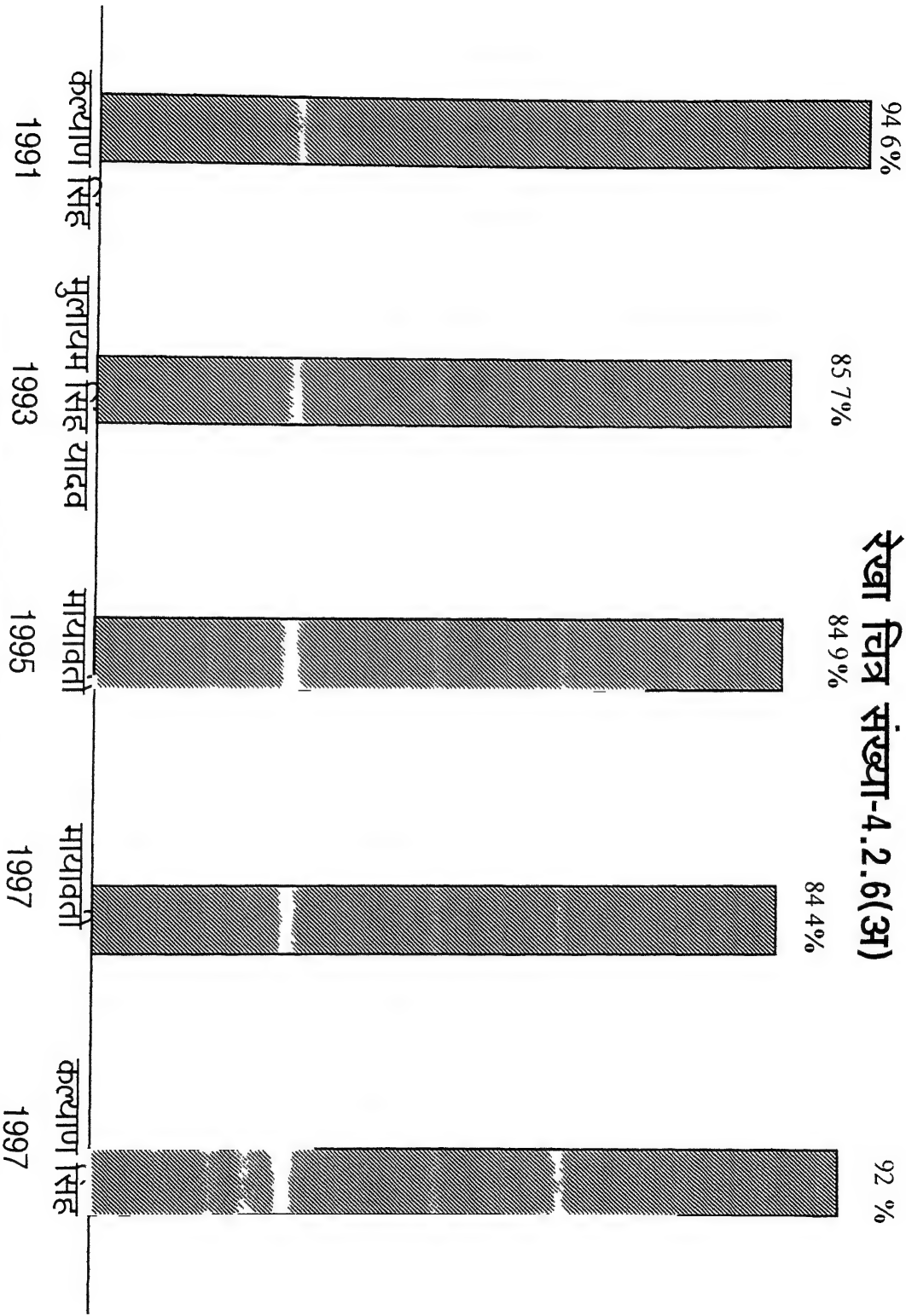
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : धार्मिक स्थिति

क्रम सं०	धर्म	जनसंख्या (1991 की जनगणना) के अनुसार	मंत्रिपरिषद											
			कल्याण सिंह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक	मुलायम सिंह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक	मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक	मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक	कल्याण सिंह द्वितीय 21-09-97 से ... तक	समग्र 1991 से 1997 तक						
	प्रदेश मे प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	हिन्दू	81 9	53	94 6	24	85 7	24	84 9	38	84 4	104	92	247	89 8
2	मुस्लिम	17 3	1	1 8	3	10 7	4	12 1	4	8 9	5	4 4	70	6.2
3	अन्य	8	2	3 6	1	3 6	1	3	3	6 7	4	3 6	11	4
योग		100	56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

मे 92 प्रतिशत, 1993 मे मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषद मे 85 7 प्रतिशत, 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषद मे 84 9 प्रतिशत और 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मंत्रिपरिषद मे 84 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हिन्दुओ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा कल्याण सिंह की दोनो मंत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ को 90 प्रतिशत से भी अधिक को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ , वही अन्य मंत्रिपरिषदो को उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत थोडा कम 85 प्रतिशत के आस पास रहा। यदि पाचो मंत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल मे (1991 से 1997 तक) हिन्दुओ को 88 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका। इसी के साथ यदि हिन्दुओ की प्रदेश मे जनसंख्या 81 1 प्रतिशत से विभिन्न मंत्रिपरिषदो मे उनके प्रतिनिधित्व से तुलना करे तो यह स्पष्ट होता है कि सभी मंत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ को प्रदेश मे उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदो मे मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट है कि मुस्लिमो को प्रदेश मे उनकी जनसंख्या (कुल जनसंख्या का 17 3 प्रतिशत) के अनुपात मे किसी भी मंत्रिपरिषद मे उन्हे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। मुस्लिमो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मंत्रिपरिषद मे 12 1 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि सबसे निम्न प्रतिनिधित्व 1991 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मंत्रिपरिषद मे 1 8 प्रतिशत प्राप्त हुआ। अन्य मंत्रिपरिषदो मे उनका प्रतिनिधित्व क्रमशः 1993 मे मुलायम सिंह के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषदो मे 10 7 प्रतिशत, 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय बार गठित मंत्रिपरिषद मे 8 9 प्रतिशत तथा 1997 के कल्याण सिंह के नेतृत्व मे द्वितीय बार गठित मंत्रिपरिषद मे 4 4 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा कल्याण सिंह के दोनो मंत्रिपरिषदो मे 5 फीसदी से कम प्रतिनिधित्व मुस्लिमो को प्राप्त हुआ वही अन्य मंत्रिपरिषदो मे अपेक्षाकृत थोडा अधिक (10 से 12 प्रतिशत के आस पास) प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। यदि पाचो मंत्रिपरिषदो मे मुस्लिमो के प्रतिनिधित्व पर समग्र रूप से दृष्टि डाले तो इस काल में (1991 से 1997 के मध्य) मे

रेखा चित्र संख्या-4.2.6(अ)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद्‌ों में हिन्दू धर्म के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

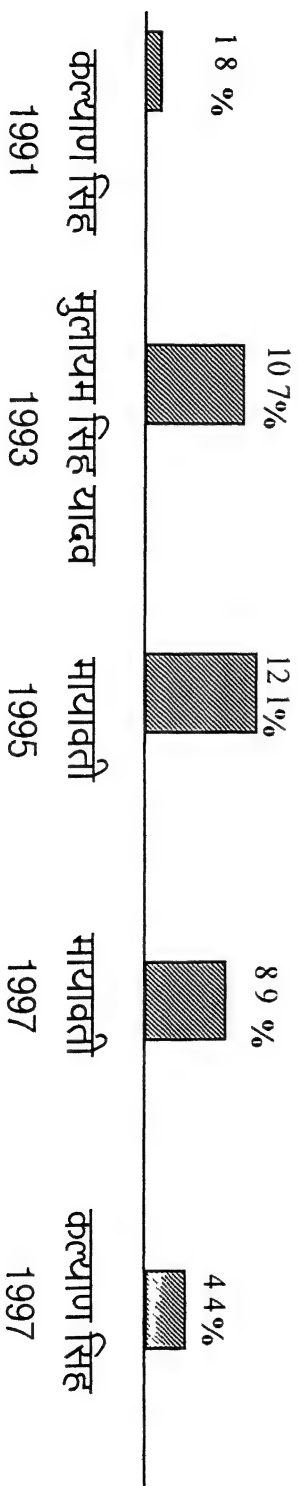
उनको कुल 6 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाया है।

यदि अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों को 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट है कि अन्य धर्मावलम्बियों को प्रदेश में उनकी जनसंख्या (कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत) के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रत्येक मन्त्रिपरिषदों में प्राप्त हुआ। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद में 6 7 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि सबसे निम्न प्रतिनिधित्व 1995 में मायावती के ही नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद में 3 प्रतिशत प्राप्त हुआ। जब की अन्य मन्त्रिपरिषदों में उनको 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पाचों मन्त्रिपरिषदों में अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों पर समग्र रूप से दृष्टि डाले तो इस काल में (1991 से 1997 के मध्य) उनको कुल 4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाया। मन्त्रिपरिषद में हिन्दुओं के प्रतिनिधित्वको रेखा चित्र संख्या 4 2 6(अ), मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को रेखा चित्र संख्या 4 2 6(ब), तथा इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व को रेखा चित्र संख्या 4 2 6(स) में प्रदर्शित किया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य विधानसभा व मन्त्रिपरिषदों में विभिन्न धर्म के सदस्यों का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। यह सारिणी संख्या 4 2 7 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 4 2 7 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीन विधानसभाओं में हिन्दू सदस्यों का प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है। सन् 1991 में गठित एकादश विधानसभा में जहाँ हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व 93 1 प्रतिशत रहा वही द्वादश विधानसभा में यह कम होकर 90 9 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधानसभा में और भी कम होकर 88 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हिन्दुओं को प्राप्त हुआ। जबकि इस काल (1991 से 1997 तक) में मन्त्रिपरिषद में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा और यह भिन्न-भिन्न समयों पर 94 6 प्रतिशत से 84 4 प्रतिशत के मध्य रहा। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद में जहाँ हिन्दुओं को विधानसभा सदस्यों के अनुपात

रेखा चित्र संख्या-4.2.6(ब)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में मुस्लिम धर्म के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या-4 2.7

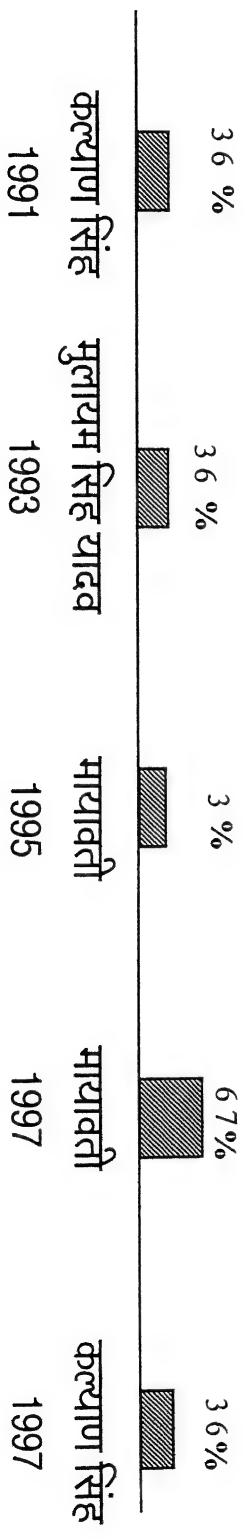
सन् 1991 से 1997 के मध्य विधानसभाओं एव मन्त्रिपरिषदों में - विभिन्न धर्मावली

क्रम सं०	मन्त्रि परिषद	हिन्दू		मुस्लिम		अन्य	
		विधानसभा (% में)	मन्त्रिपरिषद (% में)	विधानसभा (% में)	मन्त्रिपरिषद (% में)	विधानसभा (% में)	मन्त्रिपरिषद (% में)
1	कल्याण सिंह (प्रथम)	93 1	94 6	5 5	1 8	1 4	3 6
2	मुलायम सिंह यादव	द्व वा 90 9	85 7	द्व वा 7 5	10 7	द्व वा 1 6	3 6
3	मायावती (प्रथम)	स द स	84 9	स द स	12 1	स द स	3
4	मायावती (द्वितीय)	त्र यो 88 5	84 4	त्र यो 9 1	8 9	त्र यो 2 4	6 7
5	कल्याण सिंह (द्वितीय)	स द स	92	स द स	4 4	स द स	3 6

में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, वहीं इस काल में गठित अन्य मन्त्रिपरिषदों में हिन्दुओं को विधानसभा के सदस्यों के अनुपात में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनो विधानसभाओं में मुस्लिम सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सन् 1991 में गठित एकादश विधानसभा में जहाँ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 5 5 प्रतिशत रहा, वहीं द्वादश विधानसभा में यह बढ़कर 7 5 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधानसभा में यह और बढ़कर 9 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि इस काल (सन् 1991 से 1997 के मध्य) में मन्त्रिपरिषद में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व लगातार घटता-बढ़ता रहा और यह भिन्न-भिन्न समयों पर 12 1 प्रतिशत से 1 8 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर

रेखा चित्र संख्या-4.2.6(स)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद्‌ों में अन्य धर्म के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

होता है कि सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद् व 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद् में जहाँ मुस्लिमों को विधानसभा सदस्यों के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वहीं सन् 1991 में कल्याण सिंह, सन् 1997 में मायावती तथा सन् 1997 में ही कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषदों में मुस्लिमों का विधानसभा सदस्यों के अनुपात में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनों विधानसभाओं में अन्य धर्मावलम्बी सदस्यों के प्रतिनिधित्वों पर दृष्टि डालें तो इसमें लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है। सन् 1991 में गठित एकादश विधानसभा में जहाँ अन्य धर्म के सदस्यों का प्रतिनिधित्व 14 प्रतिशत रहा वहीं द्वादश विधानसभा में यह बढ़कर 16 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधानसभा में और बढ़कर 24 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जब कि इस काल (सन् 1991 से 1997 के मध्य) में मन्त्रिपरिषद् में अन्य धर्म के सदस्यों का प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा है। यह भिन्न-भिन्न समय पर 3 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषदों में अन्य धर्म के सदस्यों को विधानसभा सदस्यों के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों के सदस्यों की धार्मिक स्थिति सम्बन्धी अध्ययन के आधार पर यह तथ्य उजागर हो रहा है कि इस काल में गठित मन्त्रिपरिषदों में प्रदेश के बहुसंख्यक हिन्दू धर्म के सदस्यों का प्रभुत्व प्रत्येक मन्त्रिमण्डल में विद्यमान रहा किन्तु अन्य धर्मों के प्रतिनिधित्व को भी अनदेखा नहीं किया गया।

यद्यपि इस काल में गठित सभी मन्त्रिपरिषदों में हिन्दुओं को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ किन्तु इनके अनुपात में घट बढ़ देखा गया और यह 94.6 प्रतिशत से 84.4 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न मन्त्रिपरिषदों में रहा। जहाँ कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में हिन्दुओं को इस काल में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और

यह लगभग 95 प्रतिशत तक था, वही मुलायम सिंह यादव एवं मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मंत्रिपरिषदों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम और लगभग 85 प्रतिशत के आस पास रहा। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस काल में भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दु राष्ट्रवाद का नारा देकर चुनाव में भाग लिया था और 1991 के एकादश विधानसभा में जहाँ उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। वहीं द्वादश एवं त्रयोदश विधानसभा चुनाव में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बहुसंख्यक हिन्दुओं को अपनी तरफ मोड़ने के प्रयास के तहत रामजन्म भूमि, हिन्दू राष्ट्रवाद और समान सिविल सहिता जैसा विवादित प्रश्न उठाया ताकि हिन्दुओं की सहानुभूति तथा समर्थन उसे प्राप्त हो सके जिसमें एक सीमा तक उसे सफलता भी प्राप्त हुई।

अतः इस काल में भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दू सम्प्रदायिकता का दोहन करने और उसे एक वोट बैंक की शक्ति प्रदान करने का जो प्रयास किया उसने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद में हिन्दू धर्मावलम्बियों के व्यापक प्रतिनिधित्व को उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में देखा जा सकता है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस काल में विधानसभाओं में भी हिन्दू सदस्यों का वर्चस्व रहा है।

धार्मिक दृष्टि से हिन्दुओं के बाद प्रदेश की जनसंख्या में दूसरा स्थान मुसलमानों का है। प्रादेशिक राजनीति के ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के प्रजातांत्रिक इतिहास में मुस्लिम सम्प्रदाय का महत्व वोट बैंक के रूप में प्रायः सभी राजनैतिक दलों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में स्वीकार किया है। इस वोट बैंक पर अपना आधिपत्य बनाये रखने के प्रयास

के कारण मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति को प्रोत्साहन मिला है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ रहा, किन्तु अस्सी के दशक के पश्चात राम जन्मभूमि सम्बन्धित कांग्रेस नीतियों के कारण यह कांग्रेस से विमुख हो अन्य दलों की तरफ उन्मुख हुए। प्रारम्भ में जनता दल, तदपश्चात समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी की तरफ उन्मुख हुए। मुसलमानों के तुष्टीकरण नीति का ही परिणाम है कि इस काल (सन् 1991 से 1997 तक) में विधान सभा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के अनुपात की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के मंत्रिपरिषद में सदैव ही इनको अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वही इस काल में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिपरिषद में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व की अनदेखी नहीं हो पाई और जहाँ 1991 के कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद में एक मुस्लिम सदस्य सम्मिलित किया गया वही 1997 के इनके मंत्रिपरिषद् में 5 मुस्लिम सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषदों के गठन में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सम्प्रदायिकता की दृष्टि से हिन्दू और मुस्लिम आबादी को छोड़कर प्रदेश में अन्य धर्मों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र लगभग 8 प्रतिशत रहा है तथा प्रदेश की राजनीति में इन धर्मावलम्बियों की भूमिका अप्रभावी रही है फिर भी मंत्रिपरिषद में इनको प्रदेश में इनकी जनसंख्या तथा विधानसभा में इनकी संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषदों के निर्माण में धर्म की विशेष भूमिका रही है।

4.3 क्षेत्रीय पृष्ठभूमि—

‘क्षेत्र’ शब्द का कई अर्थ हो सकता है, किन्तु उन सब में जो समान सूत्र संचरित होता है वह यह बुनियादी सांस्कृतिक धारणा है कि यह आकार में अपेक्षाकृत उस इलाके से छोटा होता है, जिसे सन्दर्भ में इसका उपयोग किया जाता है।¹ उदाहरण के लिए किसी देश के लिए प्रदेश, किसी प्रदेश के लिए जिले, मण्डल या किसी मण्डल के लिए जिला क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। ‘क्षेत्र’ का आवश्यक लक्षण यह होता है कि क्षेत्र के लोगो में व्यापक रूप से एक दूसरे के साथ रहने की कई प्रकार के स्रोतों से आभ्यातरिक की गई भावना पाई जाती है, जिसमें समान समृद्धि, समान-सर्घष के द्वारा विकसित की गई सहयोग की इच्छा तथा अन्य से अलग होने की भावना तर्कनिहित होती है।² दूसरे शब्दों में क्षेत्र की विशेषता आंतरिक रूप से अधिकतम समरसता है।³ जिसे भाषा, बोलियों, सामाजिक घटनाओं, जातीयता, जनसंख्या की संरचना, भौगोलिक सामीप्यता, सांस्कृतिक प्रतिमान, आर्थिक जीवन, ऐतिहासिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि और मनोवैज्ञानिक सज्जा या सामूहिक अस्तित्व की मान्य चेतना से बल प्राप्त होता है।⁴

इस प्रकार क्षेत्रवाद की संकल्पना को भूगोल, स्थालाकृति, धर्म, भाषा, संस्कृति, आर्थिक जीवन रीति रिवाजों, राजनीतिक परम्पराओं और समान ऐतिहासिक अनुभवों से जीवन प्राप्त होता है। इस दिशा में एक नही बल्कि कई चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महेश्वरी का मानना है कि विभिन्नता और विषमता के कारण क्षेत्रवाद का पोषण करते हैं और उसे जीवन प्रदान करते हैं।⁵ क्षेत्रवादी समस्याओं का जन्म तभी होता है जब भौगोलिक पृथक्कता, स्वतन्त्र ऐतिहासिक परम्परावाद, जातीय या वर्गगत माध्यमिक

1 महेश्वरी एस आर स्टेट गवर्नमेंट इन इण्डिया, दिल्ली, मैकमिलन (2000), पृष्ठ 219

2 महेश्वरी वही पृष्ठ 186

3 जौहरी, जैसी भारतीय राजनीति जालन्धर, विशाल पब्लिकेशन (1995), पृष्ठ 250

4 खान रशीउद्दीन रीजनल डेवेलपमेंट नई दिल्ली के सेमिनार में नं० 164, अप्रैल 1973, पृष्ठ 39
उद्धृत जौहरी जैसी भारतीय राजनीति वही पृष्ठ 250

5 महेश्वरी एस आर वही पृष्ठ 186

विचित्रताओं और स्थानीय या आर्थिक वर्ग हितों में दो या दो से अधिक कारकों की अन्त क्रिया होती है।⁶ क्षेत्रवाद के व्यापक और सकीर्ण दोनों लक्षणार्थ हैं, अपने व्यापक अर्थ में इसके अन्तर्गत केन्द्रवाद के खिलाफ आरम्भ किये गये आन्दोलनों का मामला आता है। अपने सकीर्ण अर्थ में इसका निर्देश स्थानीय या सामाजिक महत्व के हितों के साथ लोगों के सम्बन्धों या ससक्तों से है और इस बारे में यह स्थानीय वाद एक वर्गवाद के सादृश्य है।⁷ प्रस्तुत शोध में क्षेत्र को क्षेत्रवाद के विषय में उपर्युक्त द्वितीय अर्थ के सन्दर्भ में ग्रहण किया गया है।

यदि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विभाजन को देखा जायें, तो भौगोलिक दृष्टि से इसे मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है। उत्तर में हिमालय का क्षेत्र, बीच में गंगा का मैदान और दक्षिण में पहाड़ी एवं पठारी भू-भाग।⁸ किन्तु सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से इसे पाँच भागों में बाँटा जा सकता है— उत्तरांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल। इनमें अनेक विषमता एवं भिन्नता पाई जाती है।⁹ यद्यपि भाषा या धर्म की दृष्टि से इन क्षेत्रों को अलग नहीं किया जा सकता जबकि सामान्यतः सम्पूर्ण प्रदेश में हिन्दी भाषा ही सम्वाद के रूप में प्रचलित है। यद्यपि इसके कई रूपों का जैसे अवध, गी, ब्रज, भोजपुरी आदि का प्रयोग किया जाता है किन्तु भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप में इनमें काफी विषमता विद्यमान है। उदाहरण के लिए उत्तरांचल जो हिमालय क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण एक पर्वतीय इलाका है तथा देश की अन्य पर्वतीय इलाकों की समस्या यहाँ भी विद्यमान है, जैसे आर्थिक पिछड़ापन, आधारभूत ढाँचा की कमी, उद्योगों का कम विकास, बेरोजगारी आदि। जबकि पश्चिम का भाग अधिक समृद्ध प्रतीत होता है। औद्योगीकरण, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता, आधारभूत

6 महेश्वरी एस0 आर0 'स्टेट गर्वमेन्ट इन इण्डिया', वही, पृ0 219

7 जौहरी जे0 सी0 'भारतीय राजनीति' जालन्धर विशाल पब्लिकेशन्स, पृ0 251

8 उत्तर प्रदेश वार्षिकांक 1999 -पृ0 220

9 प्रस्तुत शोध के ही अध्याय दो में क्षेत्रीय विवरण में विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है।

सरचना, शिक्षा, नगरीकरण, कार्यशील जनसख्या आदि में ये प्रदेश के अन्य भागों से काफी आगे नजर आता है। इसी प्रकार यदि बुन्देलखण्ड पर दृष्टि डाले तो यह पठारी भाग अपनी भूमि से लगे मध्यप्रदेश के भागों से अपनी भौगोलिक अवस्थितिकी तथा सांस्कृतिक दृष्टि से समीप्य रखता है। कमोवेश पूर्वांचल तथा मध्यांचल की भी यही स्थिति है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश की विषमता दूर करने एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रयास किये गये किन्तु इसका लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों को ही प्राप्त हो सका। उदाहरण के लिए हरित क्रान्ति का लाभ प्रदेश के पश्चिम भाग को ही मिला जबकि अन्य भाग इससे अछूते रहे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विकास की यह असमानता प्रत्येक राज्य के अन्दर भी दिखाई देती है। कई सदर्भों में यह असमानता तनाव का स्रोत भी बन गयी है।¹⁰

‘उत्तरांचल’ को अलग राज्य बनाने के लिए होने वाले व्यापक आन्दोलनों को इसी सन्दर्भ में देखा जा सकता है।^{*} इसी प्रकार पश्चिमांचल या हरित प्रदेश के रूप में प्रदेश का पश्चिम भाग, पूर्वांचल के रूप में पूर्वीभाग तथा बुन्देलखण्ड की भी अलग राज्य की मांग उठती रही है। यद्यपि इसको व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है।

आर्थिक असन्तुलन और आर्थिक शोषण पारस्परिक मतभेदों को बढ़ावा देने में प्रभावकारी कारक रहा है।¹¹ किन्तु यह विडम्बना है कि आर्थिक विषमता में दोनों पक्ष समृद्धशाली तथा विपन्न अपने को शोषित होता मानते हैं। जहाँ सम्पन्न पक्ष को यह लगता है कि उनकी समृद्धि का लाभ दूसरों को मिल रहा है, वही विपन्न को लगता है कि उनकी विपन्नता का कारण सम्पन्न पक्ष ही है। अतः एक आधुनिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति से सकुचित हितों से ऊपर उठकर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् किसी मन्त्री को किसी क्षेत्र का मन्त्री नहीं अपितु सम्पूर्ण प्रदेश का मन्त्री होना चाहिए किन्तु वे राजनीतिक

10 चन्द्र विपिन, आजादी के बाद व्याप्त (1947-2000) दिल्ली विश्वविद्यालय, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, पृष्ठ 173

11 सईद, एस0 एम0 ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था’ लखनऊ, सुवर्ध प्रकाशन (1996) पृष्ठ 370

12 वही0 पृष्ठ 370

वर्तमान में उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया है।

कारणों से ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास और अन्य आर्थिक योजना अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं भले ही राष्ट्रीय हित या प्रादेशित हित की दृष्टि से ऐसा करना अनुपयुक्त ही क्यों न हो।¹²

प्रदेश की जनता में व्याप्त क्षेत्रीयता की भावना तथा प्रदेश में व्याप्त राजनीतिक संस्कृति के कारण शासन में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल कराने की मांग दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है। आज यह माँग सामान्य रूप से सुनी जा सकती है कि 'हमारे क्षेत्र को कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।'

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध के इस अध्याय में सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित हुई विभिन्न मन्त्रिपरिषदों के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अनुपात का अध्ययन करने का प्रयास किया गया।

इस सन्दर्भ में सन् 1991 में मध्यावधि चुनावों के पश्चात् कल्याण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 24/6/91 को गठित तथा दिनांक 6/12/92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3 1 में दर्शाया गया है।

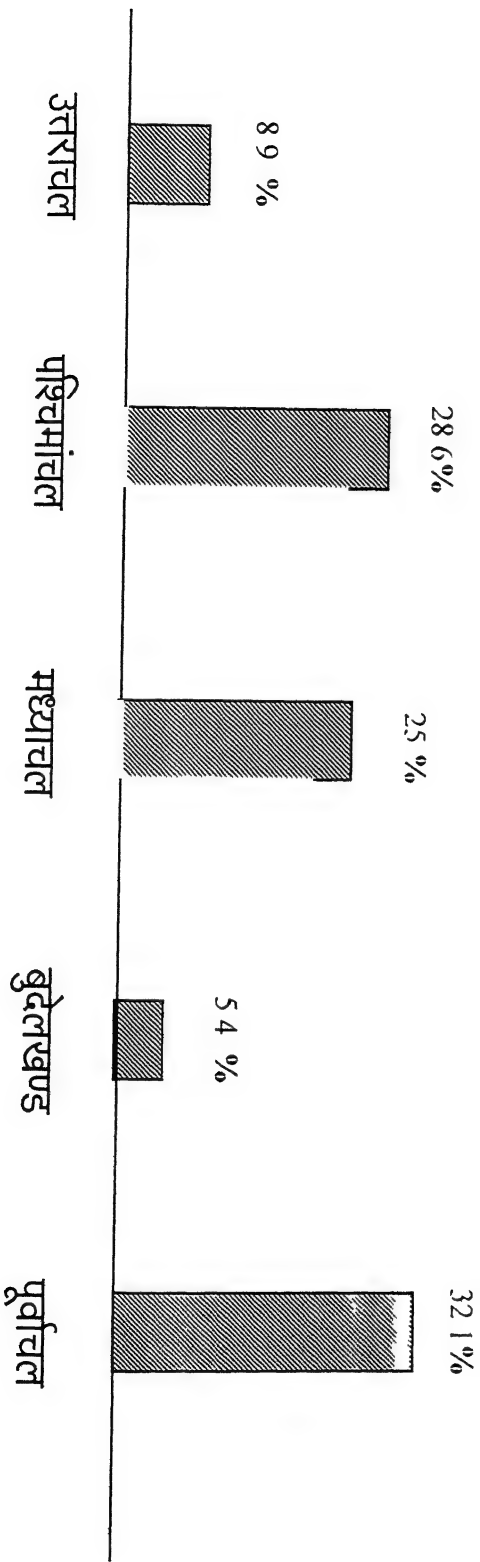
सारिणी सख्या-4 3 1

1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

क्र० स.	क्षेत्र	जनसख्या (लाख में) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व		मन्त्री-जनसख्या अनुपात 1 मन्त्री -- लाख जनसख्या
			सख्या	प्रतिशत	
1	उत्तरांचल	59 27	5	8 9	10 1
2	पश्चिमांचल	495 47	16	28 6	31
3	मध्यांचल	241 87	14	25	17 3
4	बुन्देलखण्ड	67 29	3	5 4	2204
5	पूर्वांचल	527 22	18	32 12	29 3
योग		1391 12	56	100	24

सारिणी सख्या 4 3.1 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24/6/91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित तथा 6/12/92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में कुल 56 सदस्य थे। जिसमें सबसे उच्च 18 सदस्यों के रूप में पूर्वांचल को प्रतिनिधि

रेखा चित्र संख्या-4.3.1



सन् 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद् के सदस्यो की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

त्व प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पश्चिमाचल के 16 सदस्य, मध्याचल के 14 सदस्य, उत्तराचल के 5 सदस्य एवं बुंदेलखण्ड को सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, उसके 3 सदस्यों को मन्त्रिपरिषद में स्थान दिया गया। इनका मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः अवरोही क्रम में पूर्वाचल 32.1 फीसदी, पश्चिमाचल 28.6 फीसदी, मध्याचल 25 फीसदी, उत्तराचल 8.9 फीसदी तथा बुंदेलखण्ड 5.3 फीसदी रहा। परन्तु यदि मन्त्री-जनसंख्या अनुपात पर दृष्टि डाले तो उत्तराचल को 10.1 लाख जनसंख्या पर ही एक मन्त्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त मध्याचल को 17.3 लाख पर, बुंदेलखण्ड को 22.4 लाख पर तथा पश्चिमाचल व पूर्वाचल को 29.3 लाख जनसंख्या पर एक मन्त्री प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य संख्या की दृष्टि से पूर्वाचल तदपश्चात् पश्चिमाचल को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया किन्तु जनसंख्या के अनुपात में देखे तो इन क्षेत्रों को सबसे निम्न अनुपात में ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका।

यदि जनसंख्या के अनुपात में, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तुलना कल्याण सिंह के सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद से करे तो स्पष्ट है कि प्रदेश की 1391.12 लाख जनसंख्या पर कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद में 56 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद का मन्त्री-जनसंख्या अनुपात 24.8 लाख पर एक सदस्य है। उत्तराचल, मध्याचल व बुंदेलखण्ड को उच्च तथा पश्चिमाचल व पूर्वाचल को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमबार गठित इस मन्त्रिपरिषद में क्षेत्रीय भागीदारी को रेखा चित्र संख्या 4.3.1 में दर्शाया गया है।

कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद के पतन के पश्चात् हुए मध्यावधि चुनावों के उपरान्त मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित समाजवादी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सारिणी संख्या 4.3.2 में दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-4.3 2

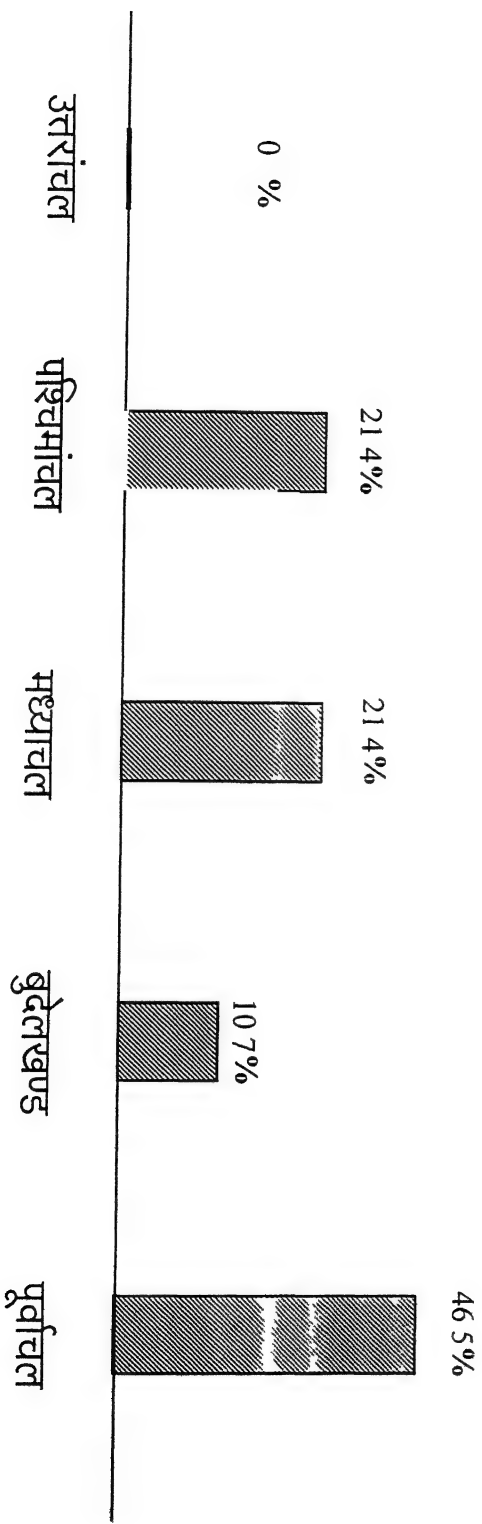
1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

क्र० स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख में) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व		मन्त्री-जनसख्या अनुपात 1 मन्त्री -- लाख जनसख्या
			सख्या	प्रतिशत	
1	उत्तरांचल	59.27	0	0	0
2	पश्चिमांचल	495.47	6	21.4	82.6
3	मध्यांचल	241.87	6	21.4	40.3
4	बुन्देलखण्ड	67.29	3	10.4	22.4
5	पूर्वांचल	527.22	13	46.5	40.6
योग		1391.12	28	100	49.7 समग्रका

सारिणी सख्या 4.3.2 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 4/12/93 को मुलायम सिंह के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 3/6/98 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में कुल 28 सदस्य थे। जिसमें सबसे उच्च, 13 सदस्यों के रूप में पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तदपश्चात् पश्चिमांचल व मध्यांचल के 6 सदस्य तथा बुन्देलखण्ड के 3 सदस्य को मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इनका मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः अवरोही क्रम में पूर्वांचल 46.5 फीसदी, पश्चिमांचल व मध्यांचल 21.4 फीसदी तथा बुन्देलखण्ड का 10.7 फीसदी रहा। परन्तु यदि मन्त्री जनसख्या अनुपात पर दृष्टि डाले, तो बुन्देलखण्ड को 22.4 लाख जनसख्या पर ही एक मन्त्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था।

तदपश्चात् मध्यांचल को 40.3 लाख पर, पूर्वांचल को 40.6 लाख पर तथा पश्चिमांचल को 82.6 लाख पर एक मन्त्री प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रदेश की 139.112 लाख जनसख्या पर मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में कुल 28 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद का मन्त्री-जनसख्या अनुपात 49.7 लाख पर एक है। अर्थात् मन्त्रिपरिषद में 49.7 लाख

रेखा चित्र संख्या-4.3.2



सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

जनसख्या पर एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यदि इसकी तुलना क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वितरण से करे तो स्पष्ट है कि जहाँ बुन्देलखण्ड, मध्याचल तथा पूर्वाचल को समग्र मन्त्रिपरिषद के अनुपात से अधिक अनुपात में, वही पश्चिमाचल को कम अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में उत्तराचल के किसी सदस्य को प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया था।

इस प्रकार समग्र आँकड़ों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य सख्या की दृष्टि से पूर्वाचल को जहाँ सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, वही जनसख्या के अनुपात में पश्चिमाचल को, उत्तराचल को छोड़कर जिसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया, सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मुलायम सिंह के नेतृत्व में गठित इस मन्त्रिपरिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 3 2 में दर्शाया गया है।

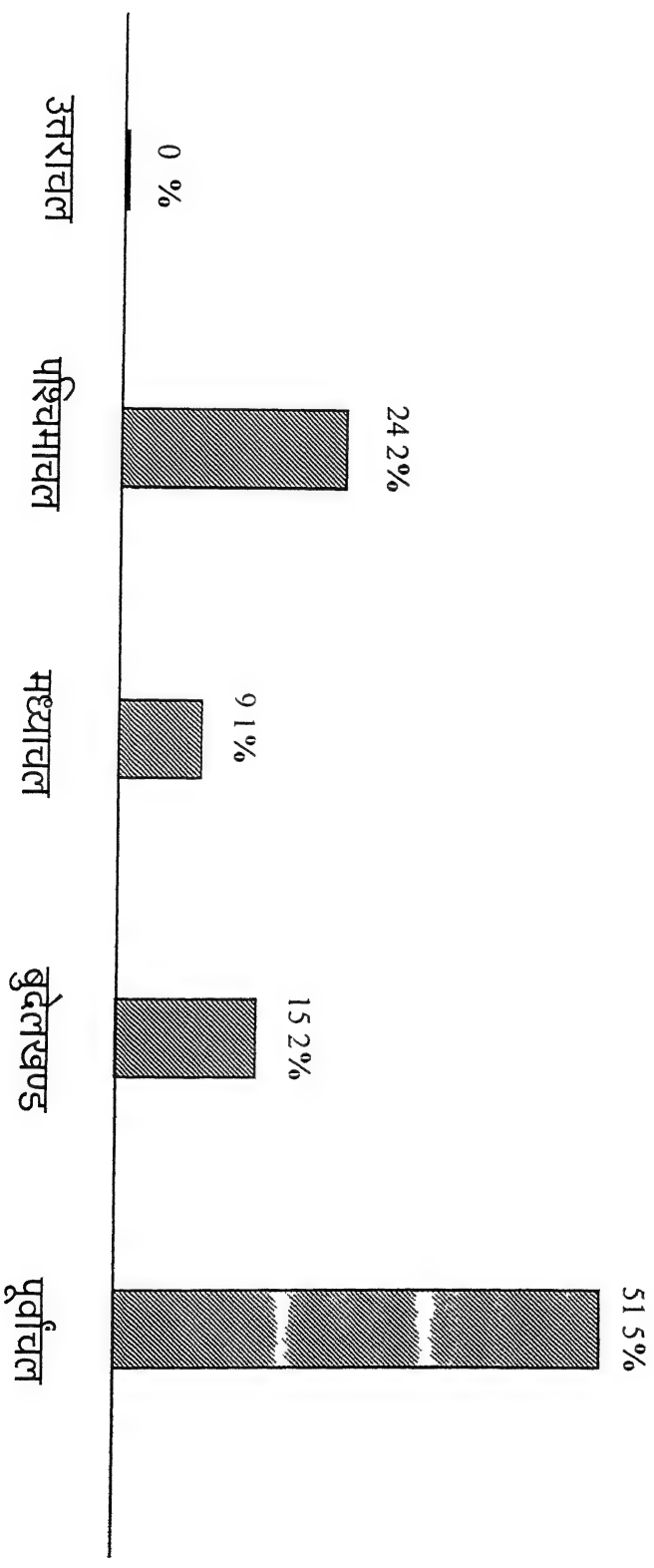
मुलायम सिंह यादव मन्त्रिपरिषद में पतन के पश्चात् दिनांक 3 6 95 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा 18.10 95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3 3 में दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-4 3.3

1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

क्र० स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख में) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व		मन्त्री-जनसख्या अनुपात 1 मन्त्री -- लाख जनसख्या
			सख्या	प्रतिशत	
1	उत्तराचल	59 27	0	0	0
2	पश्चिमाचल	495 47	8	24 2	61 9
3	मध्याचल	241 87	3	9 1	80 6
4	बुन्देलखण्ड	67 29	5	15 2	13 5
5	पूर्वाचल	527 22	17	51 5	31 0
योग		1391 12	33	100	42 2 (सम्पूर्ण का अनुपात)

रेखा चित्र संख्या-4.3.3



सन् 1995 में मायावती के मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

सारिणी सख्या 4 3 3 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 3/6/95 को नेतृत्व में गठित तथा 8/10/95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद् में कुल 33 सदस्य थे जिससे सबसे उच्च 17 सदस्यों के रूप में पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पश्चिमांचल के 8 सदस्य, बुन्देलखण्ड के 5 सदस्य तथा मध्यांचल के 3 सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इनका मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः अवरोही क्रम में पूर्वांचल 51.5 फीसदी, पश्चिमांचल 24.2 फीसदी, बुन्देलखण्ड 15.2 फीसदी तथा मध्यांचल का मात्र 9.1 फीसदी रहा। परन्तु यदि जनसख्या के अनुपात में मंत्रियों की सख्या पर दृष्टि डाले तो बुन्देलखण्ड को 13.5 लाख जनसख्या पर ही एक मंत्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल को 31 लाख पर पश्चिमांचल को 61.9 लाख पर एक तथा मध्यांचल के 80.6 लाख जनसख्या पर एक मंत्री प्रदान किया गया।

यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के उपर्युक्त वर्णित मन्त्रिपरिषद् में उत्तरांचल में किसी सदस्य को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था। मायावती के नेतृत्व में प्रथमबार गठित इस मन्त्रिपरिषद् में क्षेत्रीय भागेदारी को रेखा चित्र सख्या 4.3.3 में दर्शाया गया है।

त्रयोदश विधान सभा चुनाव के परिणाम स्वरूप मायावती के नेतृत्व में दिनांक 21/3/97 को गठित तथा बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3 4 में दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 4 3 4 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मायावती (21.3.97 से 21.9.97) के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित 45 सदस्य थे जिसमें सबसे उच्च 17 सदस्यों के रूप में पश्चिमांचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल को 14, बुन्देलखण्ड को 5, मध्यांचल को 3 तथा उत्तरांचल को

सारिणी सख्या-4 3.4

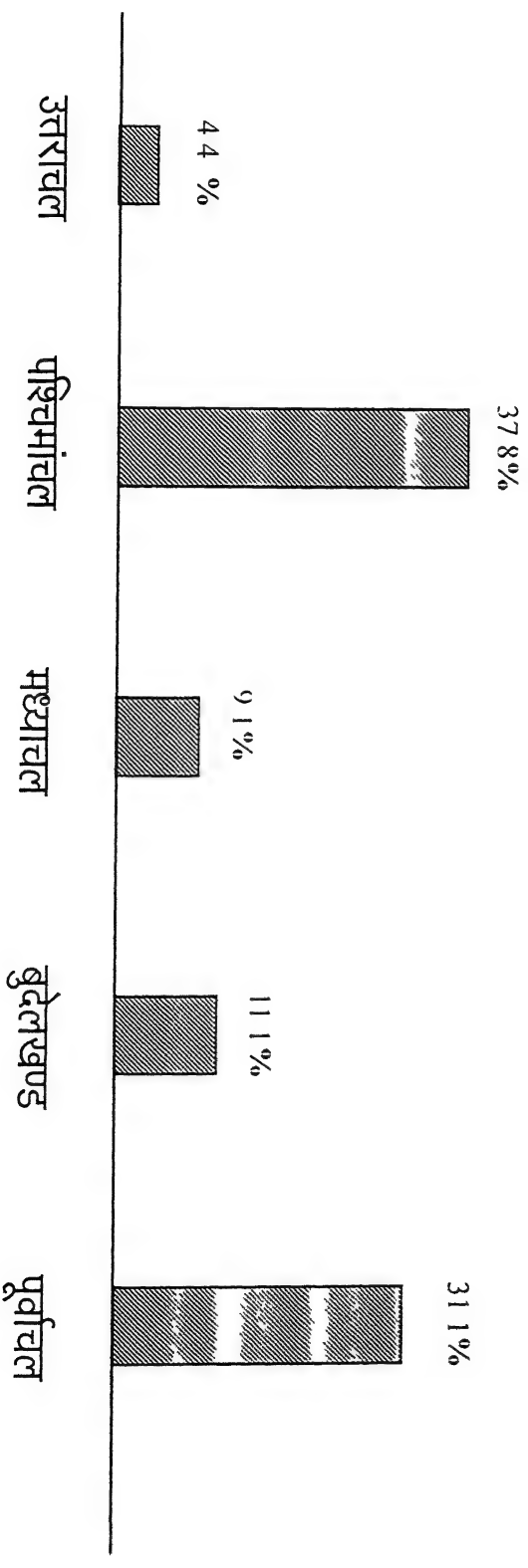
1997 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

क्र० स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख में) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व		मन्त्री-जनसख्या अनुपात 1 मन्त्री -- लाख जनसख्या
			सख्या	प्रतिशत	
1	उत्तराचल	59 27	2	4 4	25 2
2	पश्चिमाचल	495 47	17	37 8	29 2
3	मध्याचल	241 87	3	9 1	80 6
4	बुन्देलखण्ड	67 29	5	11 1	13 5
5	पूर्वाचल	527 22	14	31 1	37 7
योग		1391 12	45	100	30 9 (सम्पूर्ण अनुपात)

सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, उसके 2 सदस्यों को मन्त्रिपरिषद में स्थान दिया गया। इनका मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः अवरोही क्रम में पश्चिमाचल 37.8 फीसदी, पूर्वाचल 31.1 फीसदी, बुन्देलखण्ड 11.1 फीसदी, मध्याचल 9.1 फीसदी तथा उत्तराचल 4.4 फीसदी रहा। परन्तु यदि मन्त्रिजनसख्या अनुपात पर दृष्टि डाले तें बुन्देलखण्ड को 13.5 लाख जनसख्या पर ही एक मन्त्री प्रदान किया गया, जो सबसे उच्च प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त उत्तराचल को 25.2 लाख पर पश्चिमाचल 29.2 लाख पर तथा मध्याचल को 80.6 लाख पर एक मन्त्री प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य सख्या की दृष्टि से पश्चिमाचल तदपश्चात् पूर्वाचल को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किन्तु जनसख्या के अनुपात में देखे तो बुन्देलखण्ड को सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका।

यदि जनसख्या के अनुपात में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तुलना मायावती के सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद से करे तो स्पष्ट है कि प्रदेश की 1391.12 लाख जनसख्या पर मायावती के मन्त्रिपरिषद में 45 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया इस प्रकार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद का मन्त्री जनसख्या अनुपात 30.9 लाख पर एक सदस्य है। जिसके सापेक्ष

रेखा चित्र संख्या-4.3.4



सन् 1997 में मायावती के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

बुन्देलखण्ड, उत्तराचल को उच्च तथा मध्याचल, पूर्वाचल एवं पश्चिमाचल को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मायावती के नेतृत्व में शामिल द्वितीय मन्त्रिपरिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की स्थिति को रेखाचित्र सख्या 4 3 4 में दर्शाया गया है।

कल्याण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 21 9 97 को गठित मन्त्रिपरिषद में जो शोध काल खण्ड के अन्त अर्थात् 31 दिसम्बर 1997 तक विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3.5 में दर्शाया गया है।

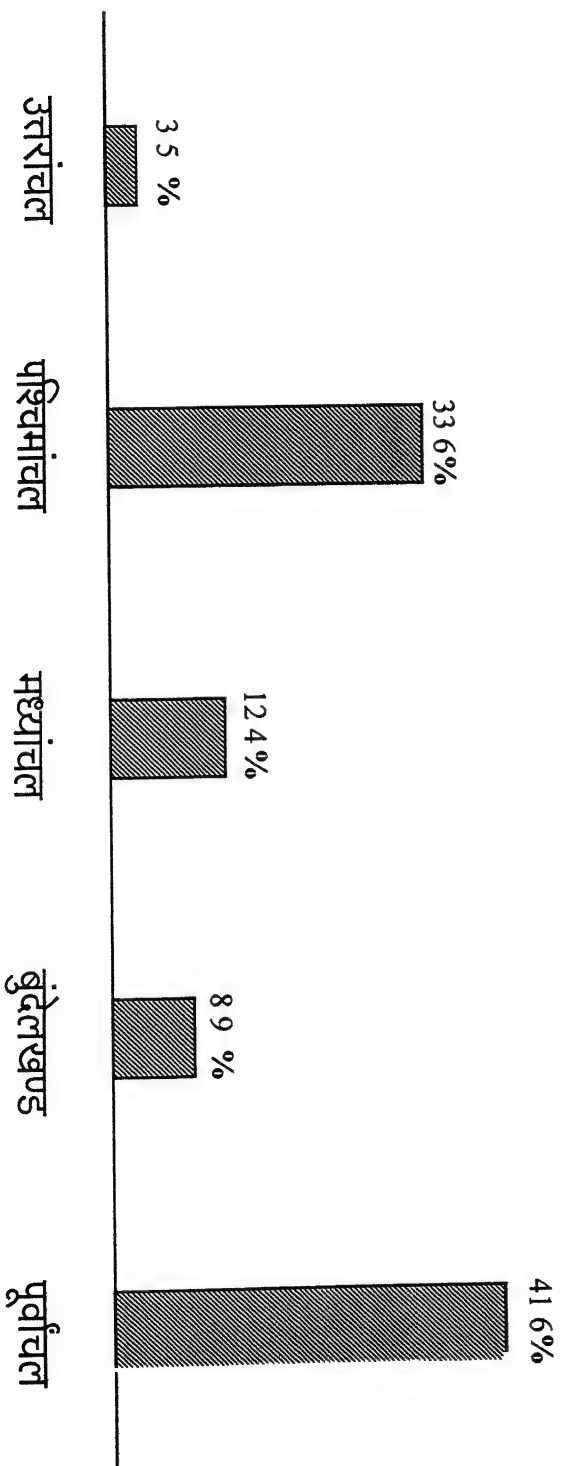
सारिणी सख्या-4 3 5

1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

क्र० स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख में) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व		मन्त्री-जनसख्या अनुपात 1 मन्त्री -- लाख जनसख्या
			सख्या	प्रतिशत	
1	उत्तराचल	59 27	4	3 5	12 6
2	पश्चिमाचल	495 47	38	33 6	13 1
3	मध्याचल	241 87	14	12 4	17 2
4	बुन्देलखण्ड	67 29	10	8 9	6 7
5	पूर्वाचल	527 22	47	41 6	11 2
योग		1391 12	113	100	12 3 (सम्पूर्ण का अनुपात)

सारिणी सख्या 4 3.5 के अन्तर्विष्ट आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीयबार गठित मन्त्रिपरिषद में कुल 113 सदस्य थे जिसमें सबसे उच्च 47 सदस्यों के रूप में पूर्वाचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिमाचल के 38 सदस्य, मध्याचल के 14 सदस्य, बुन्देलखण्ड के 10 सदस्य एवं उत्तराचल को सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, उसके 4 सदस्यों को मन्त्रिपरिषद में स्थान दिया गया। इनका मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः अवरोही क्रम में पूर्वाचल 41 6 फीसदी, पश्चिमाचल 33 6 फीसदी, मध्याचल 12 4 फीसदी, बुन्देलखण्ड 8 9 फीसदी तथा उत्तराचल 3 5 फीसदी रहा। परन्तु यदि मन्त्री

रेखा चित्र संख्या-4.3.5



सन् 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

जनसंख्या अनुपात पर दृष्टि डाले तो बुन्देलखण्ड को 67 लाख जनसंख्या पर ही एक मंत्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल को 11.2 लाख पर, उत्तरांचल को 12.6 लाख पर, पश्चिमांचल को 13.1 लाख पर तथा मध्यांचल को 17.2 लाख पर एक मंत्री प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य संख्या की दृष्टि से पूर्वांचल तदपश्चात् पश्चिमांचल को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किन्तु जनसंख्या के अनुपात में देखे तो बुन्देलखण्ड को सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका।

यदि जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तुलना कल्याण सिंह के सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् से करे तो स्पष्ट है कि प्रदेश की 1391.12 लाख जनसंख्या पर कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद् में 113 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, इस प्रकार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का मंत्री जनसंख्या अनुपात 12.3 लाख पर एक सदस्य है। जिसके सापेक्ष बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल को उच्च तथा उत्तरांचल, पश्चिमांचल एवं मध्यांचल को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित इस द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र संख्या 4.3.5 में दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 ई० के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व समग्र रूप से सारिणी संख्या 4.3.6 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 4.3.6 के अन्तर्विष्ट आँकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरांचल के सदस्यों को कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद् (24.6.91 से 6.12.92 तक) में सर्वाधिक 8.9 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद् (21.3.97 से 19.9.97 तक) मन्त्रिपरिषद् में 4.4 फीसदी तथा कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में 3.5 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह यादव तथा मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद् में उत्तरांचल के किसी सदस्य को स्थान नहीं प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में उत्तरांचल का प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या 4.3.6

1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

क्रम संख्या		क्षेत्र	मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व													
			जनसंख्या		कल्याण सिंह प्रथम (24 6 91 से 6 12 92 तक)		मुलायम सिंह यादव (4 12 93 से 3 6 95)		मायावती (प्रथम) (3 6 95 से 18 10 95)		मायावती (द्वितीय) (21 3 97 से 21 9 97)		कल्याण सिंह (द्वितीय) 21 9 97 से '		समग्र	
					सदस्य लाख में	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत		
1	उत्तरांचल	59 27	4 3	5	8 9	0	0	0	0	2	4 4	4	3 5	11	4	
2	पश्चिमांचल	495 47	35 6	16	28 6	6	21 4	8	24 2	17	37 8	38	33 6	85	30 9	
3	मध्यांचल	241 87	17 4	4	25	6	21 4	3	9 1	3	6 7	14	12 4	44	16	
4	बुद्धेलखण्ड	67 29	4 8	3	5 4	3	10 7	5	15 2	5	11 1	10	8 9	26	9 5	
5	पूर्वांचल	527 22	37 9	18	32 1	13	46 5	17	51 5	14	31 1	47	41 6	100	39 6	
		1391 12	100	56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100	

' कल्याण सिंह की द्वितीय मन्त्रिपरिषद (21 9 97 से 12 9 99 तक) में मन्त्रियों का प्रतिनिधित्व 31 दिसम्बर 1997 तक दर्शाया गया है।

प्रतिशत 4 रहा है, जिसके सापेक्ष कल्याण सिंह के (प्रथम) तथा मायावती के (द्वितीय) मन्त्रिपरिषद में उच्च तथा कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में निम्न प्रतिनिधित्व उत्तरांचल को प्राप्त हुआ है।

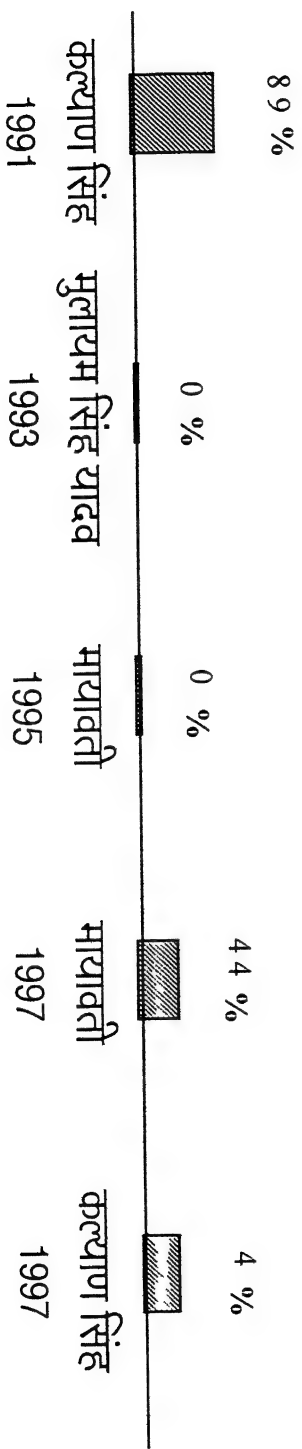
पुन यदि जनसंख्या को आधार बनाकर मन्त्रिपरिषदों में उत्तरांचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि उत्तरांचल की कुल 59.27 लाख जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका ही हू-ब-हू प्रतिनिधित्व मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में दृष्टिगोचर होता है, जिसमें 44 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उत्तरांचल को प्रदान किया गया है। जबकि कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 89 प्रतिशत के रूप में उच्च तथा कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 35 प्रतिशत के रूप में निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

यदि पश्चिमांचल का मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो यह दृष्टिगोचर होता है पश्चिमांचल के सदस्यों को मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में सर्वाधिक 37.8 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तदपश्चात् कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 33.6 फीसदी कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद 28.6 फीसदी, मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 24.2 फीसदी एवं मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में 21.4 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में समग्र दृष्टि से पश्चिमांचल का प्रतिनिधित्व प्रतिशत 30.9 फीसदी रहा जिसके सापेक्ष जहाँ मायावती व कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमशः 37.8 फीसदी व 33.6 फीसदी था। वही कल्याण सिंह व मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद के साथ मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद को निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमशः 28.6 फीसदी, 24.2 फीसदी तथा 21.4 फीसदी रहा।

पुन यदि जनसंख्या को आधार बनाकर मन्त्रिपरिषदों में पश्चिमांचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि मध्यांचल की कुल 495.47 लाख जनसंख्या, प्रदेश

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(क)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद्‌ों में उत्तरांचल का प्रतिनिधित्व

की कुल जनसंख्या के 35.6 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका ही लगभग हू-ब-हू अनुसरण मायावती व कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में दृष्टिगोचर होता है, जिसमें क्रमशः 37.8 फीसदी व 33.6 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया। जबकि कल्याण सिंह व मायावती के प्रथम मन्त्रिमण्डल के साथ मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिमण्डल में इस क्षेत्र को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था जो क्रमशः 28.6 फीसदी, 24.2 फीसदी तथा 21.4 फीसदी था।

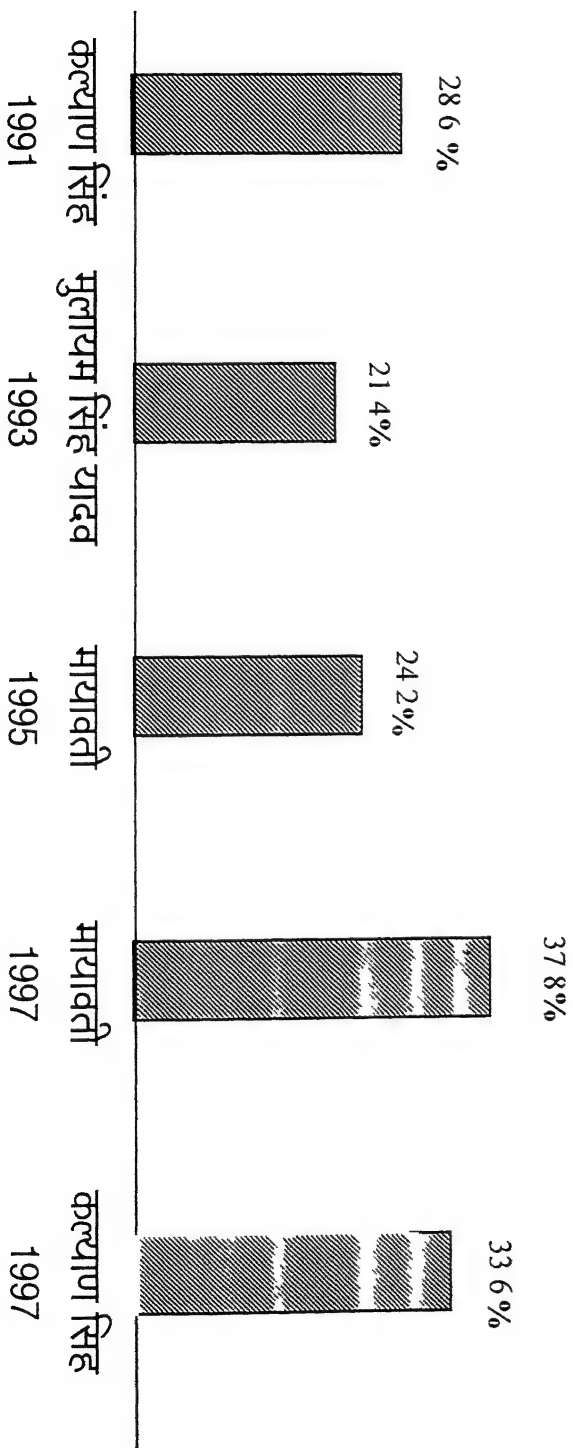
यदि मध्याचल का मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें, तो यह स्पष्ट है कि पश्चिमांचल के सदस्यों को कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में सर्वाधिक 25 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तदपश्चात् मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में 21.4 फीसदी, कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 12.4 फीसदी तथा मायावती के दोनों मन्त्रिपरिषदों में 9.1 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में समग्रदृष्टि से मध्याचल का प्रतिनिधित्व प्रतिशत 16 फीसदी रहा जिसके सापेक्ष जहाँ कल्याण सिंह के प्रथम व मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में इस क्षेत्र को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमशः 25 फीसदी व 21.4 फीसदी रहा, वहीं कल्याण सिंह के द्वितीय व मायावती के दोनों मन्त्रिपरिषदों में इस क्षेत्र को निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जो क्रमशः 12.4 फीसदी 9.1 फीसदी तथा पुनः 9.1 फीसदी रहा।

पुनः यदि जनसंख्या को आधार बनाकर मन्त्रिपरिषदों में मध्याचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि मध्याचल की कुल 241.87 लाख जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या के 17.4 फीसदी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सापेक्ष जहाँ कल्याण सिंह के प्रथम व मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद को उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, वहीं मायावती के प्रथम व द्वितीय दोनों मन्त्रिपरिषदों में निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जो क्रमशः 12.4 फीसदी, 9.1 फीसदी व पुनः 9.1 फीसदी रहा।

इसी प्रकार यदि बुन्देलखण्ड का मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(ख)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में पश्चिमांचल का प्रतिनिधित्व

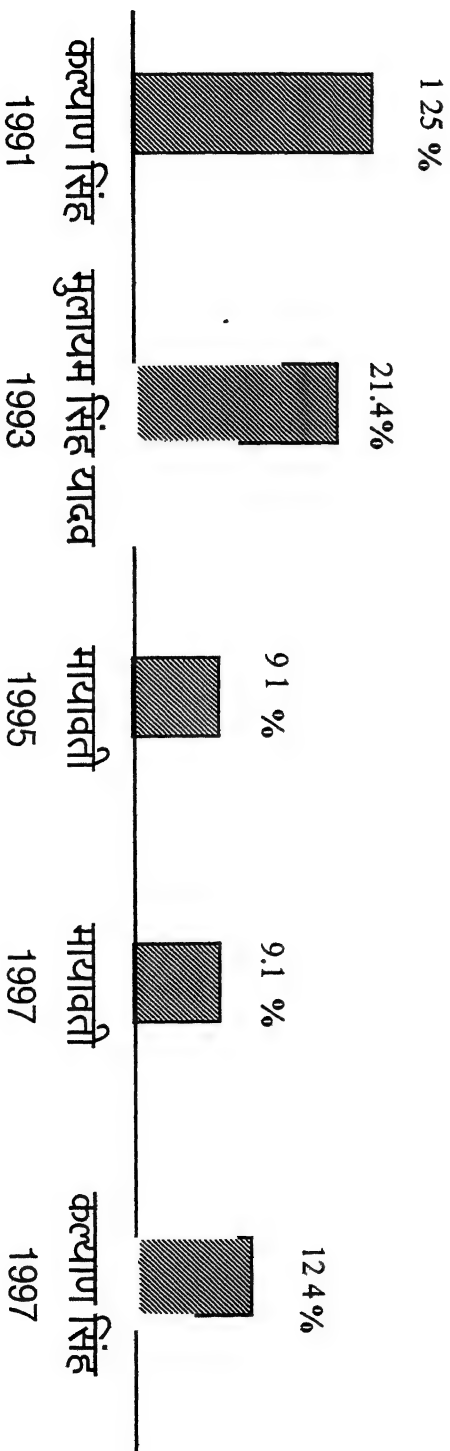
तो यह स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड को मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद में सर्वाधिक 15.2 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तदपश्चात् मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 11.1 फीसदी मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में 10.7 फीसदी कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 8.9 फीसदी तथा कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद को सबसे निम्न 5.4 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में समग्र दृष्टि से बुन्देलखण्ड का प्रतिनिधित्व प्रतिशत 9.5 फीसदी रहा है, जिसके सापेक्ष जहाँ मायावती के प्रथम व द्वितीय मन्त्रिपरिषद के साथ मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जो क्रमशः 15.2 फीसदी, 11.1 फीसदी व 10.7 फीसदी रहा, वहीं कल्याण सिंह के द्वितीय व प्रथम मन्त्रिपरिषद को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जो क्रमशः 8.9 फीसदी व 5.4 फीसदी रहा।

पुनः यदि जनसंख्या के आधार पर मन्त्रिपरिषदों में बुन्देलखण्ड के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड की कुल 67.29 लाख जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या के 4.8 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सापेक्ष प्रत्येक मन्त्रिपरिषद में इस क्षेत्र को उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जो क्रमशः मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 15.2 फीसदी, मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 11.1 फीसदी, मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद 10.7 फीसदी, कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 8.9 फीसदी तथा कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 5.4 फीसदी रहा।

यदि पूर्वांचल का मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि पूर्वांचल को मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद में सर्वाधिक 51.5 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तदपश्चात् मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में 46.5 फीसदी, कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 41.6 फीसदी, मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 31.1 फीसदी तथा कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 32.1 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया।

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(ग)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद् में मध्यांचल का प्रतिनिधित्व

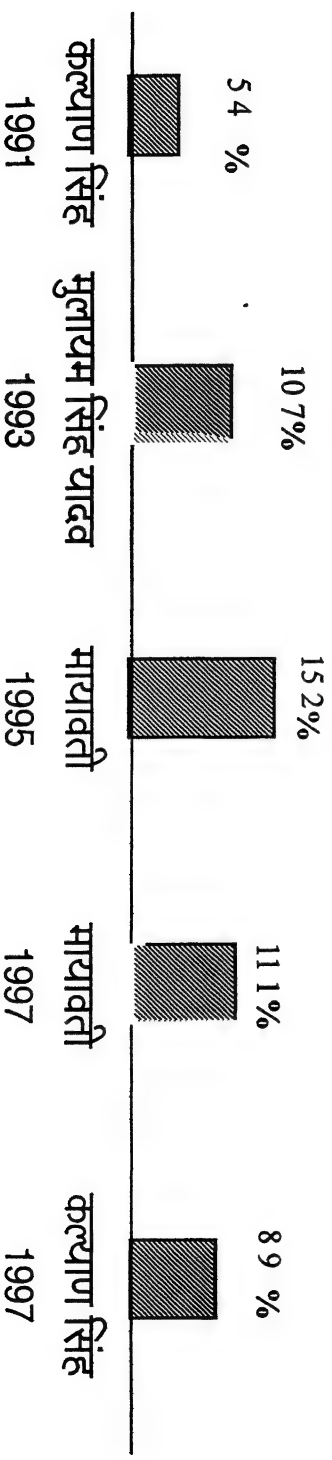
1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में समग्र दृष्टि से पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व 39.6 फीसदी रहा, जिसके सापेक्ष जहाँ मायावती के प्रथम, मुलायम सिंह यादव व कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में इस क्षेत्र को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमशः 51.5 फीसदी, 46.5 फीसदी व 41.6 फीसदी रहा। वही मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद व कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जो क्रमशः 31.1 फीसदी व 32.1 फीसदी रहा।

पुनः यदि जनसंख्या को आधार बनाकर मन्त्रिपरिषदों में पूर्वांचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि पूर्वांचल की कुल 527.22 लाख जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या के 37.9 फीसदी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सापेक्ष जहाँ मायावती के प्रथम, कल्याण सिंह के द्वितीय व मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जो क्रमशः 51.5 फीसदी, 46.5 फीसदी व 41.6 फीसदी रहा, वही मायावती के द्वितीय व कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जो क्रमशः 31.1 फीसदी व 32.1 फीसदी रहा। सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में उत्तरांचल के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सं० 4.3.6 (क), में, पश्चिमांचल के प्रतिनिधित्व रेखाचित्र संख्या 4.3.6 ख मध्यांचल के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सं० 4.3.6 (ग) में, बुन्देलखण्ड के प्रतिनिधित्व को 4.3.6 (घ) तथा पूर्वांचल के प्रतिनिधित्व में 4.3.6 (ङ) में प्रदर्शित किया गया।

शोधकालखण्ड सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अध्ययन से जो तथ्य प्रकाश में आ रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन्त्रिपरिषदों में विभिन्न क्षेत्रों को किसी निश्चित अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि यदि उत्तरांचल को अलग कर दिया जाय तो सभी क्षेत्रों को मन्त्रिपरिषद में स्थान देने का प्रयास किया गया है।

सन् 1993 व 1995 में क्रमशः मुलायम सिंह यादव व मायावती के नेतृत्व में गठित

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(घ)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में बुन्देखण्ड का प्रतिनिधित्व

मन्त्रिपरिषदे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सन्तुलित नहीं थी। इन दोनों मन्त्रिपरिषदों में उत्तरांचल को कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि उत्तरांचल में समाजवादी तथा बहुजन समाज पार्टी ने विधान सभा चुनावों में बहुत दयनीय प्रदर्शन किया था और मात्र एक स्थान ही यहाँ प्राप्त कर सके थे।

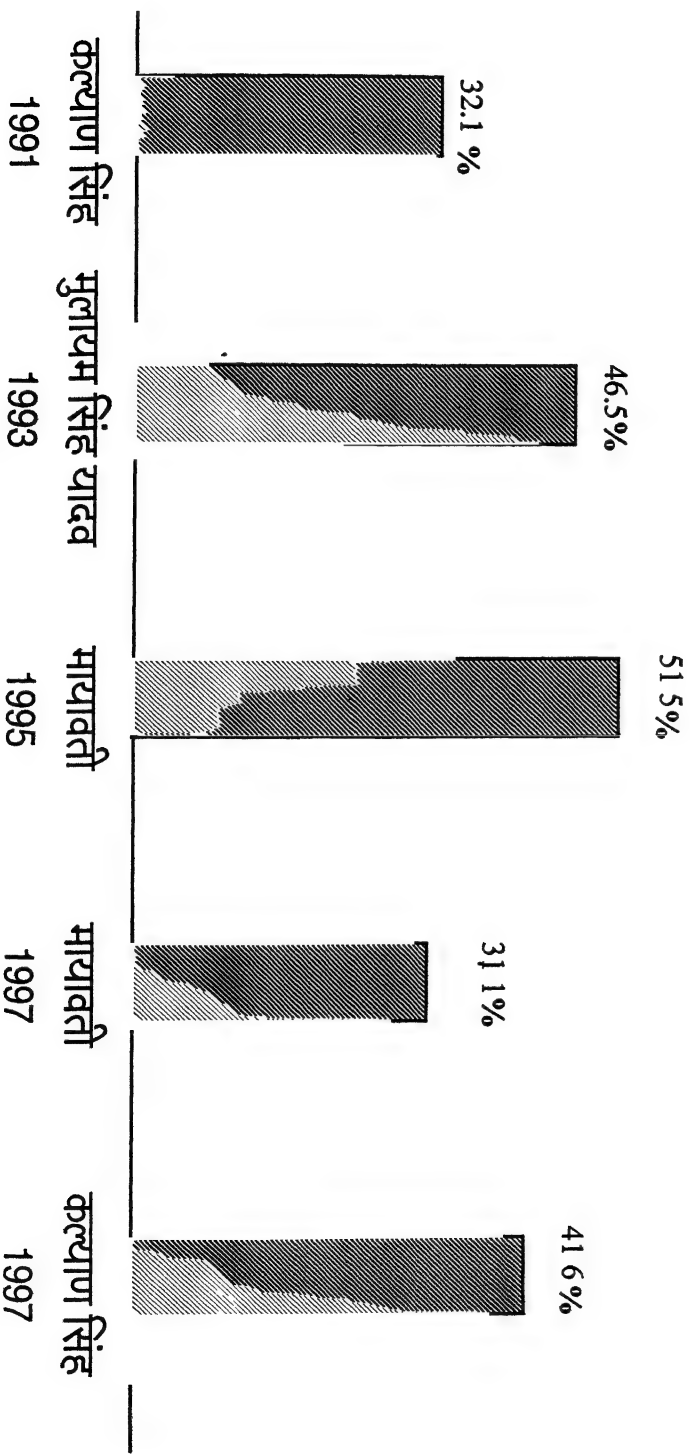
इसके अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्रिपरिषदों में उत्तरांचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि इन सभी मन्त्रिपरिषदों में भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित रही है जिसका उत्तरांचल में प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होने और उत्तरांचल के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध को इस तथ्य से बल प्राप्त होता है कि जब सन् 1991 में मध्यावधि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ तथा कल्याण सिंह के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद का गठन किया गया तो उत्तरांचल को सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस समय 8.9 फीसदी प्रतिनिधित्व उत्तरांचल को प्राप्त हुआ।

पश्चिमांचल को मन्त्रिपरिषदों में सदैव प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी मायावती के नेतृत्व में सन् 1997 में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 37.8 फीसदी रही तथा सबसे निम्न भागीदारी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में 21.4 फीसदी रही। यहाँ पर यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि सन् 1995 के पूर्व के मन्त्रिपरिषदों की तुलना में सन् 1995 के पश्चात् गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में इस क्षेत्र को अधिक भागीदारी प्राप्त हो सकी।

पश्चिमांचल के समान ही मध्यांचल को भी सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित प्रत्येक मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहा। इस क्षेत्र को सर्वाधिक भागीदारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में सन् 1991 में गठित मन्त्रिपरिषद में प्राप्त हुई जो 25 फीसदी रही। वही सबसे निम्न भागीदारी मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में 9.1 फीसदी रही।

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(इ)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में पूर्वाचल का प्रतिनिधित्व

1 फीसदी रही। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि शोध काल खण्ड में गठित प्रथम दो मन्त्रिपरिषदों में जहाँ इस क्षेत्र की भागीदारी अधिक रही वहाँ शेष तीन मन्त्रिपरिषदों में इसकी भागीदारी काफी कम हो गयी और यह गिरावट आधे सेमेतिहाई (2/3) तक रही।

बुन्देलखण्ड को भी सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषदों में निरन्तर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहा है। इस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी मायावती के नेतृत्व में सन् 1995 में प्रथमबार गठित मन्त्रिपरिषद में 15.2 फीसदी रही तथा सबसे निम्न भागीदारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में सन् 1991 में प्रथमबार गठित मन्त्रिपरिषद में 5.4 रही। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में इस क्षेत्र को अन्य मन्त्रिपरिषदों की तुलना में अधिक हिस्सा प्रदान किया गया जिसका कारण सम्भवतः बुन्देलखण्ड का, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ होना है।

चुनावों के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने निरन्तर यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में अन्य मन्त्रिपरिषदों की तुलना में इस क्षेत्र को कम भागीदारी प्राप्त हो रही है।

जहाँ तक पूर्वांचल का प्रश्न है तो इसे सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषदों में निरन्तर प्रतिनिधित्व ही नहीं प्राप्त हुआ बल्कि अधिकांशतः इस क्षेत्र को मन्त्रिपरिषदों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी मायावती के नेतृत्व में सन् 1995 में प्रथमबार गठित मन्त्रिपरिषद में 51.5 फीसदी रही तथा सबसे निम्न भागीदारी भी मायावती के नेतृत्व में सन् 1997 में द्वितीयबार गठित मन्त्रिपरिषद में 31.1 फीसदी रही।

यदि जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो बुन्देलखण्ड को सबसे कम जनसंख्या पर मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जबकि

पश्चिमांचल को सबसे अधिक जनसंख्या पर मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। लेकिन इस आधार पर यदि विभिन्न मन्त्रिपरिषदों का अलग-अलग विश्लेषण किया जाय तो कल्याण सिंह की प्रथमबार गठित सन् १९६१ के मन्त्रिपरिषद में उत्तरांचल तथा शेष सभी मन्त्रिपरिषदों में बुन्देलखण्ड को उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अर्थात् कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में उत्तरांचल तथा शेष में बुन्देलखण्ड को जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक स्थान मन्त्रिपरिषद में प्रदान किया गया।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि शोधकाल खण्ड सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषदों के मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही निर्वाचित हो कर आये, जैसे कल्याण सिंह अतरौली (अलीगढ़), मुलायम सिंह यादव इटावा तथा मायावती आरक्षित सीट हरौडा (सहारनपुर) से चुनकर विधानसभा में पहुँचे।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि अपवादों को छोड़ दिया जाय तो मन्त्रिपरिषदों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में सन्तुलन बनाने का प्रयास किया गया है और यह तथ्य कल्याण सिंह के दोनों मन्त्रिपरिषद में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। अन्य मन्त्रिपरिषद के विषय में साझा सरकारों की विवशता तथा विधानसभा चुनावों में इन दलों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाय तो यह स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब-जब मन्त्रिपरिषद का निर्माण किया, उसे विधान सभा में मात्र 67 स्थान ही प्राप्त हुआ और इन स्थानों में भी अधिकांशतः प्रदेश के कुछ निश्चित क्षेत्र में प्राप्त हुए थे। तथा इस काल में गठित सभी सरकारें कल्याण सिंह की प्रथम मन्त्रिपरिषद को छोड़कर साझा सरकारें थीं। इन मजबूरियों के पश्चात् भी इस काल में गठित मन्त्रिपरिषदों में क्षेत्रीय सन्तुलन बनाये रखने का यथा सम्भव प्रयास दृष्टिगोचर हो रहा है।



पंचम अध्याय

मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक स्थिति

मंत्रि परिषद के सदस्यों की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक स्थिति

5.1 शैक्षिक स्थिति

शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो व्यक्ति को पशुता से उठाकर मानव बनाता है। शिक्षा के प्रधान उद्देश्य व्यक्ति को प्रभावित करते हुए उसे इस योग्य बनना है कि वह अपने समाज के मूल्यों तथा आदर्शों का अनुशीलन करते हुए समाज के स्वस्थ तथा वाछित विकास में योगदान प्रदान कर सके। समनर ने लिखा है कि शिक्षा यह सिखाती है कि कौन सा आचरण समाज के द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत है, किस प्रकार का मनुष्य सबसे अधिक प्रशंसनीय होता है, सब प्रकार के कार्यों में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और उसे किस बात में विश्वास अथवा अविश्वास करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा को भावी जीवन के समायोजन का एक आदर्श माना जाता है। शिक्षा वह महत्वपूर्ण अवयव है जो किसी समाज या राष्ट्र के नागरिकों के राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वस्तुतः शिक्षा का अर्थ प्रचलित मूल्यों के अनुकूल ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करना है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में ही नहीं बल्कि समाज, राज्य, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रगति एवं उत्थान में अनिवार्य एवं अपरिहार्य अवयव है। इस प्रकार प्राचीन समय से ही शिक्षा के महत्व को समझ कर उसकी समुचित व्यवस्था की गयी थी। प्राचीन काल के आचार्यों का विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक विकास कर सकता है। ज्ञान से मनुष्य के अन्तर्मुख खुल जाते हैं। अतएव उनके अनुसार ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है तथा उसे सही कार्यों में प्रवृत्त करता है।

ज्ञान तृतीय मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्त्वार्थं विलोकिदक्षम।

ते जो नपेक्ष विगतान्तराय प्रवृत्तिं भत्सर्वं जगत्पयपि ॥¹

इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है कि विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता।

नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति सत्यसम तपः।²

इस प्रकार विद्या के महत्व को इस काल में इतनी प्राथमिकता दी जाती थी कि भर्तृहरि में नीतिशतक में विद्या विहिन मनुष्य को पशुतुल्य बताया है- विद्याविहीन पशु।

महात्मा गाँधी ने भी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व व्यक्ति को शरीर मन तथा आत्मा में अन्तर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण विकास है।³

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा समाज तथा राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक है अर्थात् वही समाज तथा राज्य अधिक प्रगति तथा उत्थान कर सकता है जिसके निवासी शिक्षित एवं सुसभ्य हों।

प्राचीन राजनीतिक आचार्यों ने शिक्षा को राज्य व्यवस्था के लिये आवश्यक तत्त्व माना है विशेष रूप से राज्य के शासक वर्ग के शिक्षा के प्रति यह अति सन्चेत थे। प्राचीन भारतीय साहित्यों में राजा के लिए गुरुओं की शिक्षा एवं मंत्रणा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया था। इसे अकर्तव्य निष्ठता और निरकुशता को नियंत्रित करने के प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया गया था। प्राचीन यूनानी चिन्तक 'प्लेटो' ने भी अपने आदर्श राज्य के विचार में शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की बात करता है। जिसके महत्व को दर्शाते हुए 'इवेन्स्टीन' का कथन है- 'उत्तमतर तथा सार्वजनिक सेवा का मार्ग एक समुचित रूप से नियोजित शिक्षा पद्धति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।'⁴

यद्यपि वर्तमान शासन व्यवस्था का स्वरूप प्रायः लोकतांत्रात्मक है, इसमें राज्य का शासन

2- महाभारत, 12, 339, 6

3 महात्मा गाँधी 'बेसिक एजुकेशन', पृष्ठ 30-31

4 इवेन्स्टीन डब्ल्यू ई 'ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर', एन डी ऑक्सफ़ोर्ड, आई बी एच 1960, पृष्ठ 50-4

जनता के द्वारा उनके ही मध्य से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और यही विधान मंडल तथा मंत्रिपरिषद् में शासन की नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करते हैं। इस प्रकार यह आम जनता के प्रतिनिधि होने के साथ उनका नेतृत्व भी करते हैं। अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्रियाकलापों एवं व्यवहार से समाज में आदर्श स्थापित करें। जिसके लिए उनका शिक्षित एवं सुसभ्य होना आवश्यक है।

आधुनिक राजनीतिक सामाजिक वैज्ञानिकों का यह मत है कि किसी व्यवस्था के आधुनिकीकरण में शिक्षा एक प्रमुख तत्व है, क्योंकि शिक्षा का स्तर व्यक्ति के विचारों में व्यापकता ला देता है उसे सर्किणता तथा जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वंशवाद आदि से ऊपर उठने में सहायता प्रदान करता है। 'डब्लू सी स्मिथ' ने आधुनिकीकरण की तीन आवश्यक दशाओं - प्रथम-ज्ञान, द्वितीय-विकल्पों के बीच चयन की स्वतंत्रता और तृतीय-कार्यान्वयन की क्षमता⁵ को माना है। इस प्रकार आधुनिकीकरण के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार का परिवर्तन लाना है और क्या यह संभव है। निश्चय ही यह ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए स्मिथ ने शिक्षा को आधुनिकीकरण की पहली शर्त मानी है।⁶ माइनर विनर का मानना है कि शिक्षा के अभाव में कोई भी परम्परागत समाज आधुनिकीकरण से नहीं गुजर सकता⁷ और मंत्रिपरिषद् क्योंकि शासन की मुख्य धुरी होती है इसलिए उनका शैक्षिक स्तर आधुनिकीकरण की गति से सीधे सम्बद्ध होता है।

वस्तुतः व्यक्ति शिक्षा तो जन्म से मृत्यु तक दिन-प्रतिदिन चेतन या अचेतन रूप में प्राप्त करता है। किन्तु प्रस्तुत शोध में जिस शिक्षा के अध्ययन का विषय बनाया गया है वह औपचारिक शिक्षा है जिसे संस्थागत शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है।

5- स्मिथ डब्लू सी 'मार्डनाइजेशन ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाईटी', बम्बई (1965), पृष्ठ 20-22

6 वही पृष्ठ 20

7 माइनर विनर, 'मार्डनाइजेशन द डायनिमिक्स ऑफ ग्रोथ', उद्धृत, सिंह जे पी 'सामाजिक परिवर्तन स्वरूप एवं मिद्धान्त, नई दिल्ली, प्रेंटिस-हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (1999) पृष्ठ 166

मई जून 1991 में एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनांक 24-6-91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमवार गठित तथा दिनांक 6-12-92 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति सारिणी सख्या 5 1 1 में प्रदर्शित है।

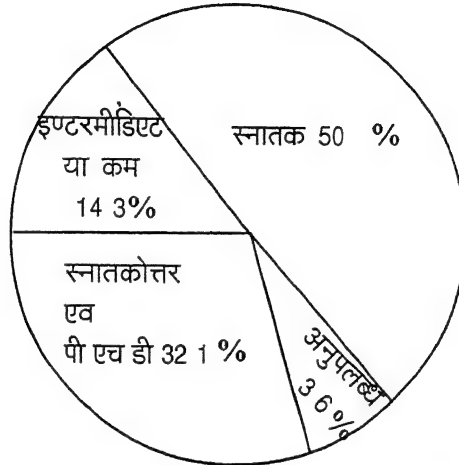
सारिणी सख्या -5.1 1

सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मंत्रिपरिषद		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मंत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	112	26 8	8	14 3	7 1
2	स्नातक	127	30 4	28	50	39 4
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	114	27 3	18	32 1	15 8
4	अनुपलब्ध	65	15 6	2	3 6	3 1
योग		418	100	56	100	13 4 प्रतिशत

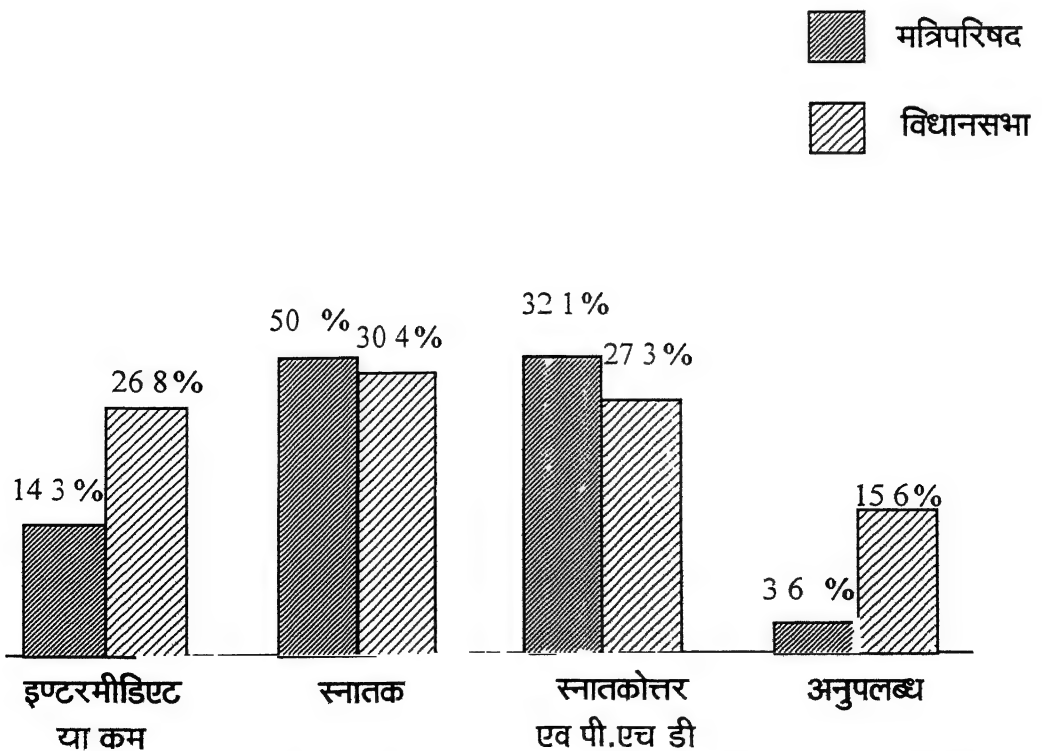
सारिणी सख्या 5 1 1 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 24 6 91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 6-12-92 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद में कुल 56 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमें 8 सदस्यों की शैक्षिक अवस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे कम स्तरीय रही है 28 सदस्यों की स्नातक स्तरीय रही जबकि 18 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय रही है। शेष 2 सदस्य ऐसे रहे हैं जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इसी काल में विधान सभा के कुल 418 सदस्यों में 112 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय रही, 127 सदस्यों की स्नातक स्तरीय तथा 114 सदस्यों की स्नाकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय रही है शेष 65 सदस्य ऐसे रहे हैं कि जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात

रेखा चित्र संख्या-5.1.1 (अ)



सन 1991 मे कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद मे शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.1.(ब)



सन 1991 मे कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोक से यह स्पष्ट होता है कि विधान सभा में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व 26.8 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 14.3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ इस प्रकार विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक स्तर के सदस्यों को लगभग 12 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि विधानसभा में स्नातक स्तरीय शैक्षिक स्तर प्राप्त सदस्यों का प्रतिनिधित्व 30.4 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 50 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ इस प्रकार विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में स्नातक स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त सदस्यों को लगभग 20 प्रतिशत अधिक स्थान प्राप्त हुआ। वहीं स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक स्तर प्राप्त सदस्यों का विधान सभा में प्रतिनिधित्व 27.3 रहा और मन्त्रिपरिषद् में उन्हें 32.1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शिक्षा प्रस्थिति वाले सदस्यों को लगभग 5 प्रतिशत अधिक स्थान प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5.1.1 के समस्त आकड़ों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो रहा है कि कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमवार गठित मन्त्रिपरिषद् में सर्वाधिक सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय रही है तथा इस काल में विधान सभा में भी सर्वाधिक सदस्य इसी शैक्षिक स्तर के रहे हैं। जबकि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों की सख्या इस काल में विधान सभा एवं मन्त्रिपरिषद् में निम्नतम रही है। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा के सदस्यों के आधार पर मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दर (प्रतिशत) स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का सबसे उच्च एवं इण्टरमीडिएट एवं कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का सबसे निम्न रहा है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कल्याण सिंह की मन्त्रिपरिषद् में विधानसभा शैक्षिक स्तर के सदस्यों को प्रतिनिधित्व के पैटर्न का ही अनुसरण किया गया है अर्थात् दोनों जगह इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को सबसे कम, इसके सापेक्ष में स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को

उच्च तथा स्नातक शैक्षिक प्रास्थिति वाले सदस्यों को सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। किन्तु यह तथ्य दृष्टिगोचर हो रहा है कि मन्त्रिपरिषद् में विधान सभा के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण नहीं किया गया है। कल्याण सिंह की प्रथम मन्त्रिपरिषद् में सदस्यों के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 1 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 1 (ब) में प्रदर्शित किया गया है।

नवम्बर 1993 के द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनावों के परिणाम स्वरूप दिनांक 4-12-93 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति सारिणी सख्या 5 1 2 में प्रदर्शित है।

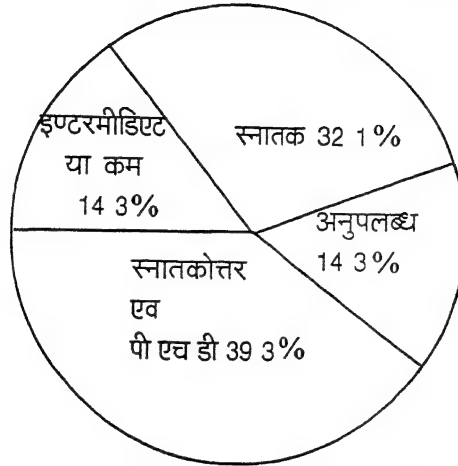
सारिणी सख्या 5 1 2

सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	99	23 2	4	14 3	4
2	स्नातक	138	32 4	9	32 1	6 5
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	134	31 5	11	39 3	8 2
4	अनुपलब्ध	55	12 9	4	14 3	7 3
	योग	426	100	28	100	6 6 (प्रतिशत)

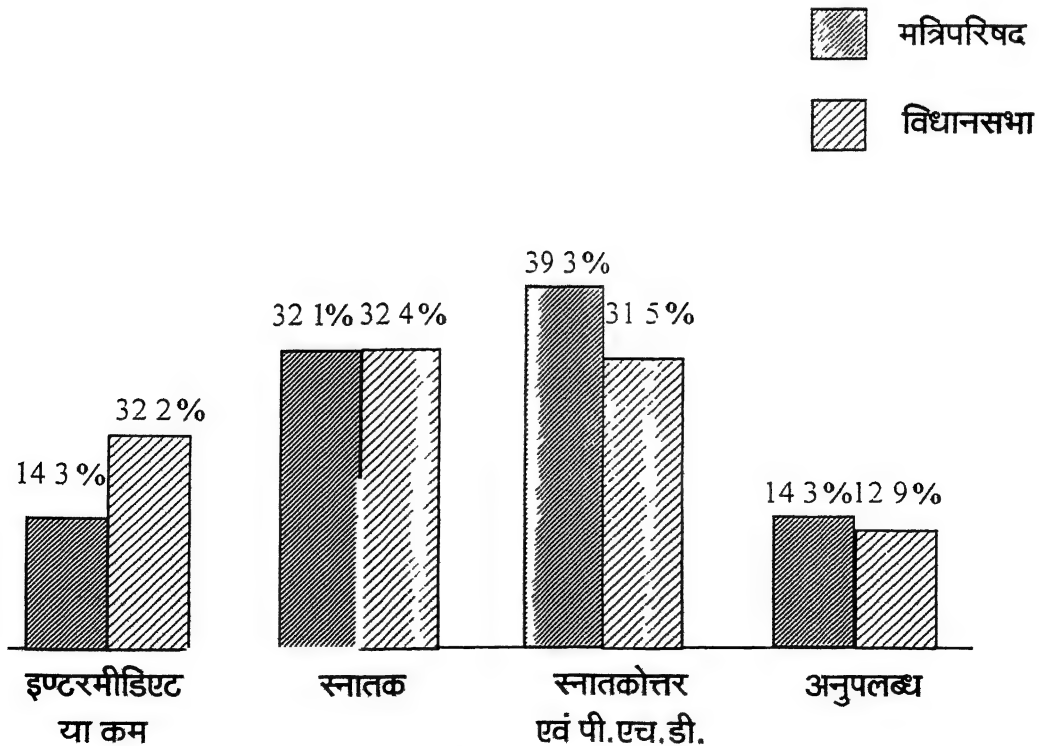
सारिणी सख्या 5 1 2 के अंतर्विष्ट आकड़ों के अवलोक से यह स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 4-12-93 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 3-6-95 तक कार्यरत

रेखा चित्र संख्या-5.1.2 (अ)



सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद में शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.2.(ब)



सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

मन्त्रिपरिषद में कुल 28 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमें 4 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे निम्न स्तरीय रही है 9 सदस्यों की स्नातक स्तरीय रही 138 सदस्यों की स्नातक स्तरीय तथा 134 सदस्यों की स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है। शेष 55 सदस्य ऐसे रहे हैं जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रस्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व 23.4 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 14.3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को लगभग 9 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधानसभा में स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व 32.4 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 32.1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व विधान सभा एवं मन्त्रिपरिषद में लगभग समान प्राप्त हुआ। वहीं स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का विधान सभा में प्रतिनिधित्व 31.5 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 39.3 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में लगभग 8 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

सारिणी सख्या 5.1.2 के समस्त आकड़ों के प्रकाश में यह तथ्य उजागर हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में सर्वाधिक सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है तथा इस काल में विधान सभा में सर्वाधिक सदस्यों की शैक्षणिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय रही है। जबकि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व विधान सभा एवं मन्त्रिपरिषद में न्यूनतम रहा। अतः यह प्रतीत होता है कि इस काल मन्त्रिपरिषद में अधिक शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों की तुलना में प्रतिनिधित्व

प्रदान करने की वरीयता दी गई है। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा के सदस्यों के आधार पर मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले (प्रतिशत) स्नातकोत्तर का सबसे उच्च रहा है वहीं इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का न्यूनतम रहा। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा में विभिन्न शैक्षिक स्तर के सदस्यों को प्राप्त प्रतिनिधित्व के पैटर्न का अनुसरण मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में नहीं किया गया प्रतीत होता है। मुलायम सिंह यादव की मन्त्रिपरिषद में सदस्यों के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 2 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 2 (ब) में प्रदर्शित किया गया है।

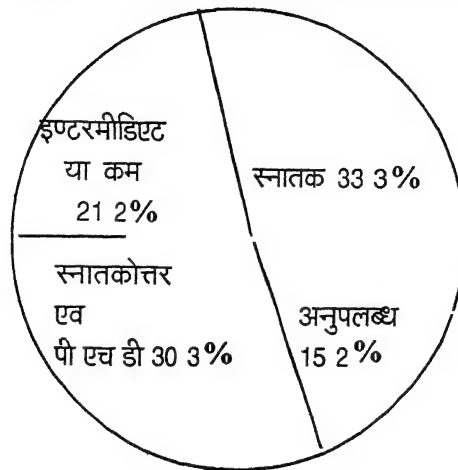
मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद के पतन के पश्चात दिनांक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की शैक्षणिक प्रस्थिति सारिणी सख्या 5 1 3 में प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 1 3

सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

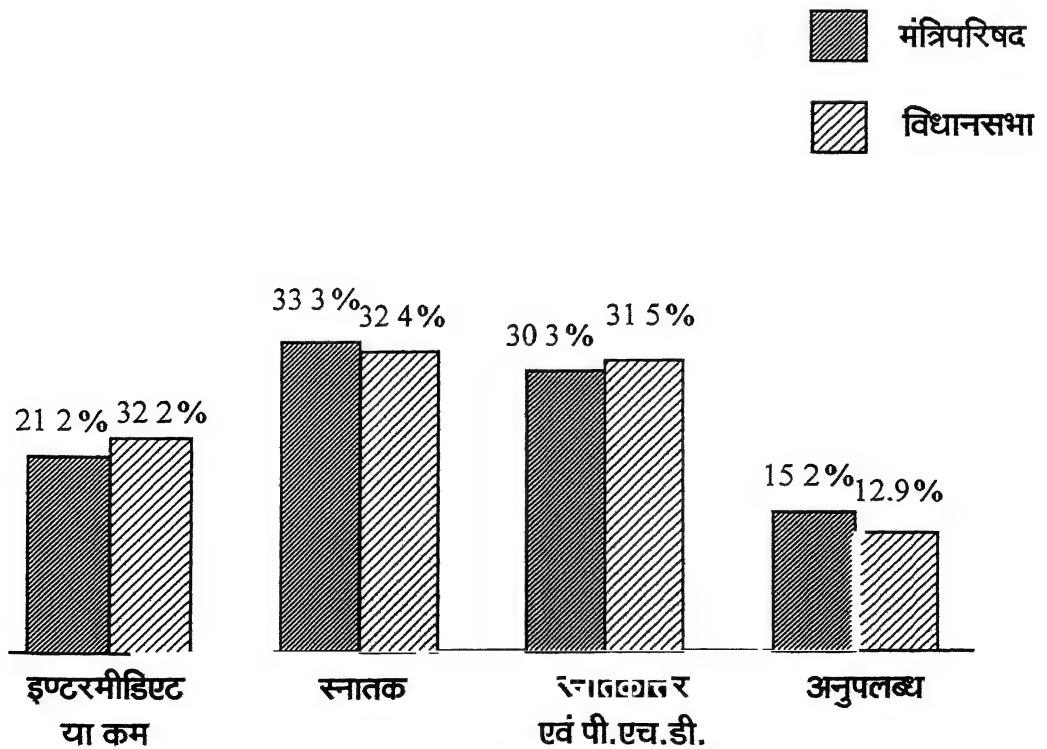
क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मन्त्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	99	23.2	7	21.2	7.1
2	स्नातक	138	32.4	11	33.3	8
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	134	31.5	10	30.3	7.5
4	अनुपलब्ध	55	12.9	5	15.2	9.1
	योग	426	100	33	100	7.7 (प्रतिशत)

रेखा चित्र संख्या-5.1.3 (अ)



सन 1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद में शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.3.(ब)



सन 1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

सारिणी सख्या 5 1 3 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 3-6-95 के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित तथा दिनांक 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे कुल 33 सदस्य सम्मिलित थे जिसमे 7 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे निम्न स्तरीय रही है 11 सदस्यो की स्नातक स्तरीय रही जबकि 10 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर या पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है, शेष 5 सदस्य ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। जबकि इस काल मे विधान सभा के कुल 426 सदस्यो मे 99 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय रही, 138 सदस्यो की स्नातक स्तरीय रही है तथा 134 सदस्यो की स्नातकोत्तर एव पी 0 एच डी0 स्तरीय रही है, शेष 55 सदस्यो ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोक से यह स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 23 2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 21 2 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को 2 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 32 4 रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 33 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद मे लगभग समान प्राप्त हुआ। वही स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का विधान सभा मे प्रतिनिधित्व 31 5 प्रतिशत और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 30 5 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को भी विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद मे लगभग समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5 1 3 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित मन्त्रिपरिषद मे सवार्धिक प्रतिनिधित्व स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ। तथा इस काल मे विधानसभा

मे भी सवार्धिक प्रतिनिधित्व स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को ही प्राप्त हुआ। जबकि इस काल मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद मे न्यूनतम रहा। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा के सदस्यो के आधार पर मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दर (प्रतिशत)स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे उच्च तथा इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे न्यून रहा है, जबकि स्नातकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का इन दोनो के मध्य रहा है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इन दोनो के मध्य विधान सभा मे भिन्न-भिन्न शैक्षिक स्तर प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त प्रतिनिधित्व के पैटर्न का अनुसरण मायावती के मन्त्रिपरिषद मे किया गया है। तथा लगभग उसी अनुपात मे विभिन्न शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जिस अनुपात मे उनका प्रतिनिधित्व विधान सभा मे था। मायावती की प्रथम मन्त्रिपरिषद मे सदस्यो के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 3 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स० 5 1 3 (ब) मे प्रदर्शित किया गया है।

सितम्बर -अक्टूबर मे त्रयोदश विधान सभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित तथा दिनांक 21-9-97 कार्यरत बहुजन समाज पार्टी की सयुक्त मन्त्रिपरिषद के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति को सारिणी सख्या 5 1 4 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 1 4 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहै कि दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित तथा दिनांक 21-9-97 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे कुल 45 सदस्य थे। जिसमे 7 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे कम स्तरीय रही, 23 सदस्यो की स्नातक स्तरीय तथा 10 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर या पी० एच० डी० स्तरीय रही है तथा शेष 5 सदस्य ऐसे रहे जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इसी काल मे विधान सभा के कुल 426 सदस्यो मे 85

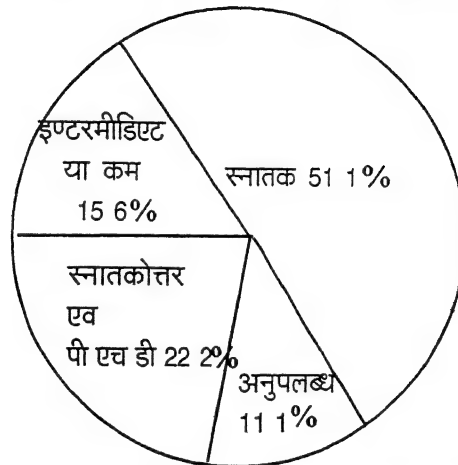
सारिणी सख्या - 5 1 4

सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मन्त्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	85	20	7	15 6	8 2
2	स्नातक	138	32 4	9	32 1	6 5
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	134	31 5	11	39 3	8 2
4	अनुपलब्ध	55	12 9	4	14 3	7 3
	योग	426	100	28	100	6 6 (प्रतिशत)

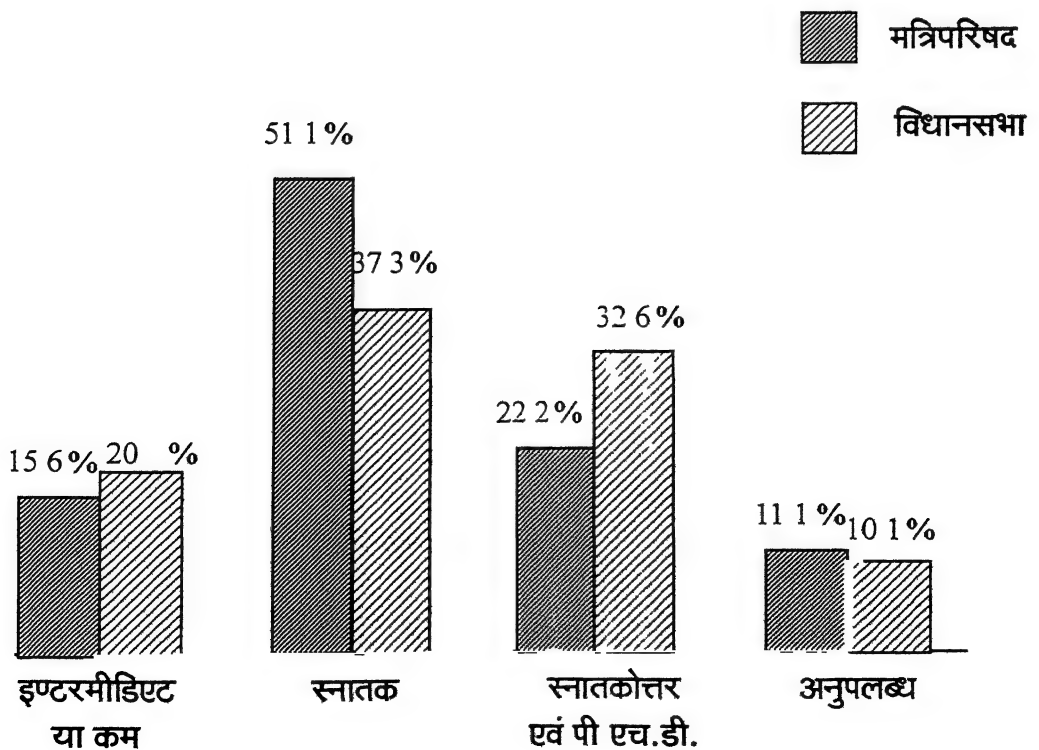
सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय, 159 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय तथा 139 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर या पी० एच० डी० स्तरीय रही है शेष 43 सदस्य ऐसे रहे है कि जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोक से यह स्पष्ट होता है कि विधान सभा मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हे 15 6 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को लगभग 5 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 37 3 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 51 1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद के प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधान सभा मे 32 6 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 22 2 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातकोत्तर एव पी० एच०

रेखा चित्र संख्या-5.1.4 (अ)



सन 1997 मे मायावती के मंत्रिपरिषद मे शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.4.(ब)



डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे लगभग 10 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5 1 4 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मन्त्रिपरिषद मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ तथा इस काल मे विधान सभा मे भी सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को ही प्राप्त हुआ, जबकि इस काल मे इण्टरमीडिएट तथा कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद मे न्यूनतम रहा इसके आधार पर मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दर(प्रतिशत) स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे उच्च तथा स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे उच्च तथा स्नातकोत्तर या पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का न्यूनतम रहा जबकि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का इन दोनो के मध्य रहा है। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा मे भिन्न-भिन्न शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त प्रतिनिधि के पैटर्न का अनुसरण मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे किया गया है। किन्तु यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि मन्त्रिपरिषद मे विधान सभा के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण नहीं किया गया है। मायावती की द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे सदस्यो के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 4 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 4 (ब) मे प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणामस्वरूप छ महीने की अवधि के अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमन्त्री मायावती द्वारा दिये गये त्याग पत्र के उपरान्त दिनांक 21-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे 31 दिसम्बर 1997 तक सम्मिलित सदस्यो की शैक्षिणित सारिणी सख्या 5 1 5 मे प्रदर्शित है।

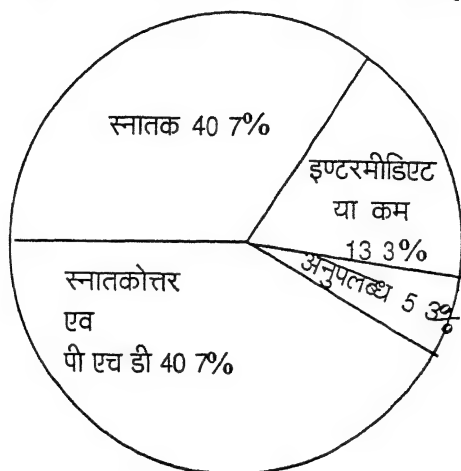
सारिणी सख्या 5 1 5

सन् 1997 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यों के आधार पर मन्त्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	85	20	15	13 3	17 6
2	स्नातक	159	37 3	46	40 7	28 3
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	139	32 6	46	40 7	33 1
4	अनुपलब्ध	43	10 1	6	5 3	14
योग		426	100	113	100	26 5 (प्रतिशत)

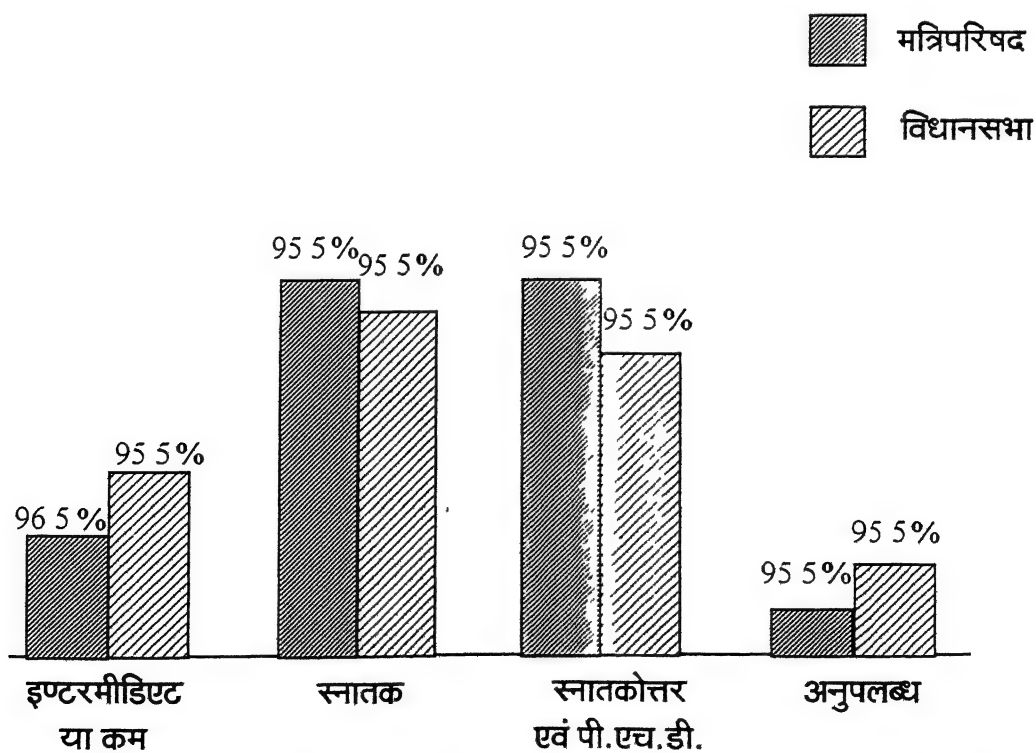
सारिणी सख्या 5 1 5 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है दिनांक 21-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व मे द्वितीयवार गठित मन्त्रिपरिषद मे 31 दिसम्बर 1997 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए। जिसमे 15 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे कम स्तरीय रही, 46 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय एव पी० एच० डी० स्तरीय रही। शेष 6 सदस्य ऐसे रहे हैं जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इसी काल मे विधान सभा के कुल 426 सदस्यों मे 85 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय, 159 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय या पी० एच० डी० स्तरीय रही है शेष 43 सदस्य ऐसे रहे हैं जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विधान सभा मे इण्टर मीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत

रेखा चित्र संख्या-5.1.5 (अ)



सन 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद में शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.5(ब)



सन 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

रहा और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 13 3 स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में इण्टर मीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को लगभग 7 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा में स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में लगभग 3 प्रतिशत अधिक स्थान प्राप्त हुआ। वही स्नातकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व विधान सभा में 32 6 प्रतिशत रहा है और मन्त्रिपरिषद में उन्हें 40 7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद में स्नातकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को लगभग 8 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5 1 5 के समस्त आकड़ों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो रहा है कि कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद में सर्वाधिक समान रूप से प्रतिनिधित्व स्नातक और स्नातकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को प्राप्त हुआ। तथा इस काल में विधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को प्राप्त हुआ। जबकि इस काल में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का सबसे उच्च तथा इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का न्यूनतम रहा जबकि स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का इन दोनों के मध्य रहा। मन्त्रिपरिषद में उच्च शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को विधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व अनुपात ।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व देने में विधान सभा के उच्च शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों पर वरीयता दी गई है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विधान सभा में भिन्न-भिन्न शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के अनुपात का अनुसरण मन्त्रिपरिषद में नहीं किया गया है। कल्याण सिंह की द्वितीय मन्त्रिपरिषद में सदस्यों के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या

5 1 5 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 5 (ब) में प्रदर्शित किया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों के सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति को सारिणी सख्या 5 1 6 में दर्शाया गया है

सारिणी सख्या 5 1 6 के अन्तिर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रत्येक में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व सबसे न्यून रहा है। यदि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व को इस काल में गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में देखे तो इन्हें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 21 2 प्रतिशत सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद में प्राप्त हुआ तदपश्चात् 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद में 15 6 प्रतिशत, 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमवार गठित मन्त्रिपरिषद व 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद में समान रूप से 14 3 प्रतिशत और न्यूनतम 13 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व उच्च रहा है अपेक्षा कृत इस काल में गठित अन्य मन्त्रिपरिषदों के। यदि इस काल में गठित पाँचों मन्त्रिपरिषदों में समग्र रूप से इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल में कुल 275 सदस्यों को मंत्री पद प्राप्त हुए जिसमें 41 सदस्य जिनका प्रतिशत 14 9 रहा इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले रहे। जिसके सापेक्ष मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में इस स्तर के शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व उच्च रहा वही इस काल में गठित अन्य मन्त्रिपरिषदों का न्यून रहा।

इस प्रकार सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद में

सारणी संख्या 5.1.6

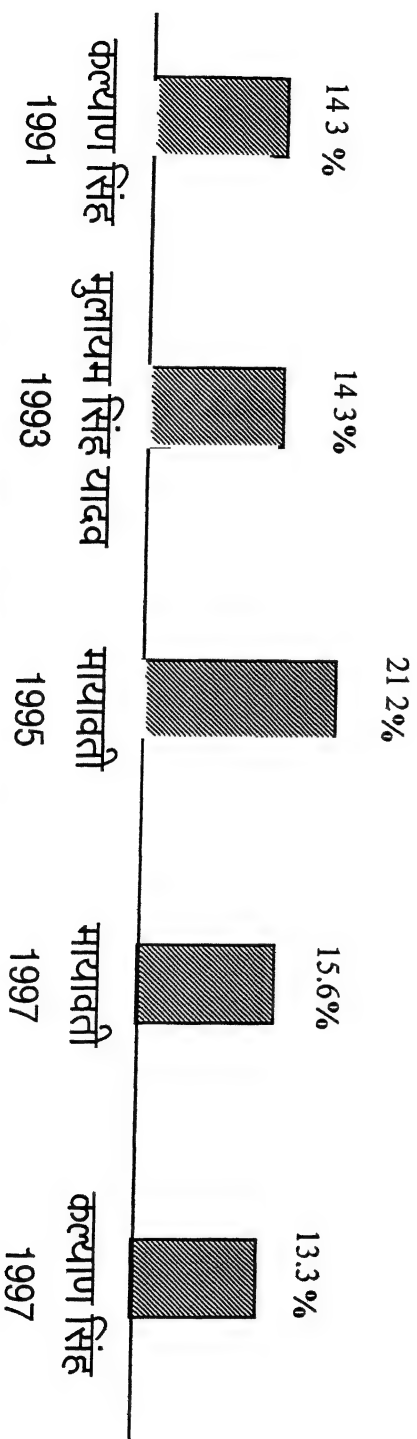
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : शैक्षिक प्रस्थिति

क्र० स०	शैक्षिक स्तर	मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व											
		कल्याण सिंह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिंह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिंह द्वितीय 21-09-97 से -----तक		समय 1991 से 1997 तक	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	इण्टरमीडिएट या कम	8	14 3	4	14 3	7	21 2	7	15 6	15	13 3	41	14 9
2	स्नातक	28	50	9	32 1	11	33 3	23	51 1	46	40 7	171	42 5
3	स्नातकोत्तर एव भी एच डी	18	32 1	11	39 3	10	30 3	10	22 2	46	40 7	95	34 6
4	अनुपलब्ध	2	3 3	4	14 3	5	15 2	5	11 1	6	5 3	22	8
योग		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

इनका प्रतिनिधित्व घटता बढ़ता रहा है तथा इस काल में विभिन्न समयों में यह 32.1 प्रतिशत से 51.1 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुआ। स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को इस काल में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 51.1, सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद् में 50 प्रतिशत सन् 1997 में कल्याण सिंह के ही नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद् में 40.7 प्रतिशत, 1995 में मायावती के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद् में 33.3 प्रतिशत और 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में न्यूनतम 32.1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्नातकीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ 1997 में गठित मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में व 1997 में कल्याण सिंह मन्त्रिपरिषद् में स्नातकीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और यह लगभग मन्त्रिपरिषद् के कुल प्रतिनिधित्व का आधा या आधे से अधिक रहा। यदि इस काल में गठित पाँचों मन्त्रिपरिषदों में समग्र रूप से स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो इस काल में कुल 275 सदस्य मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित हुए जिसमें 117 सदस्य जिनका प्रतिशत 42.5 रहा स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले रहे। जिसके सापेक्ष मायावती के द्वितीय तथा कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद् में इस स्तर के शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व उच्च रहा वहीं इस काल में गठित अन्य मन्त्रिपरिषदों में न्यून रहा।

इसी प्रकार सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद् में इनका प्रतिनिधित्व घटता बढ़ता रहा है तथा इस काल में भिन्न-भिन्न मन्त्रिपरिषदों में यह 22.2 प्रतिशत से 40.7 प्रतिशत के मध्य रहा स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को इस काल में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 40.7 प्रतिशत सन् 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद् में रहा है। तदपश्चात् सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में 39.3 सन् 1991 में

रेखा चित्र संख्या-5.1.6(अ)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक
प्रस्थिति के सदस्य

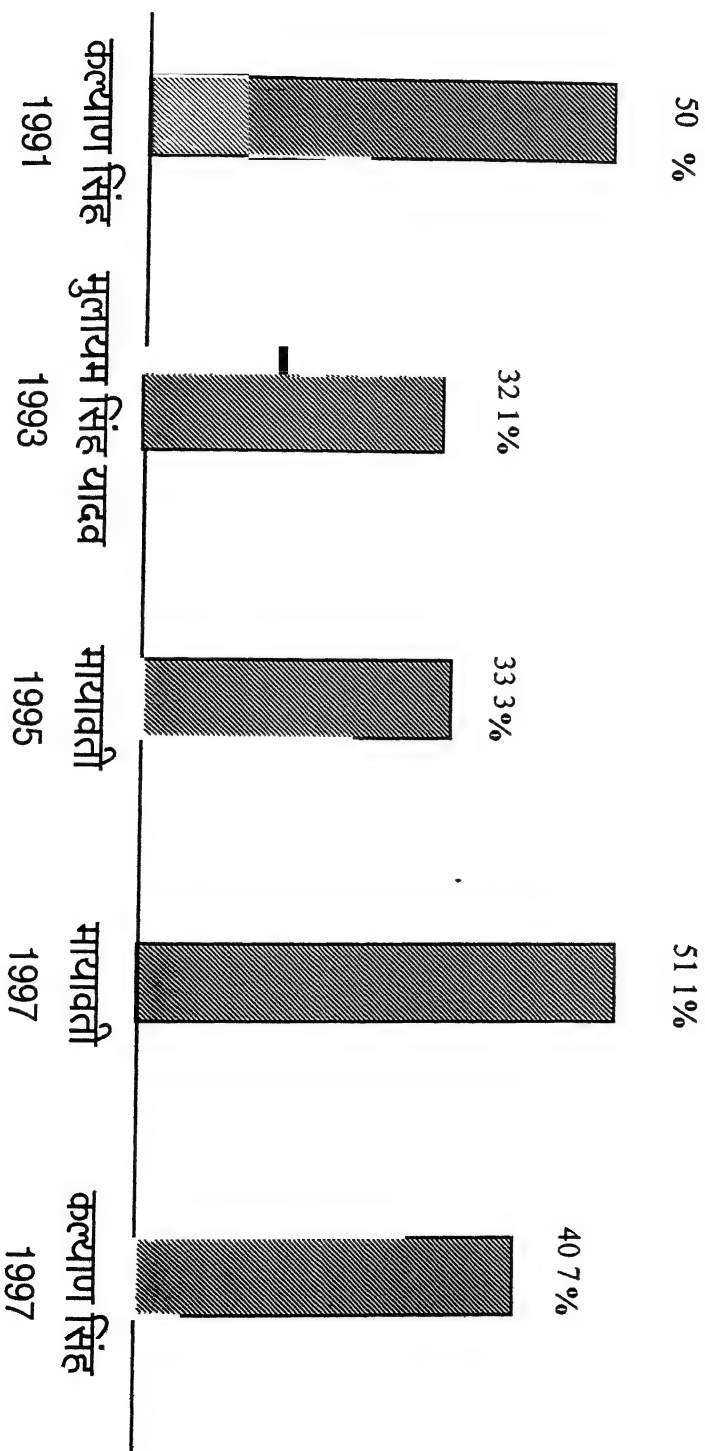
कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में 32 1, सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मंत्रिपरिषद् में 30 3 प्रतिशत तथा 1997 में मायावती के ही नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मंत्रिपरिषद् में सबसे कम 22 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्नातकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों को प्राप्त हुआ है। यदि इस काल में गठित पांचों मंत्रिपरिषदों में समग्र रूप से स्नातकोत्तर एव पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल में कुल 275 सदस्यों मंत्रिपरिषदों में सम्मिलित हुए जिसमें 95 सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति इस स्तर की रही है। जिसका प्रतिशत 34 6 रहा जिसके सापेक्ष 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय बार व सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में इस स्तर के शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व उच्च रहा वहीं इस काल में गठित अन्य मंत्रिपरिषदों में न्यून रहा है।

इसके अतिरिक्त 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में शेष 3 6 प्रतिशत, 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में शेष 14 3, मायावती की प्रथम मंत्रिपरिषद् में शेष 15 2 प्रतिशत, मायावती की ही द्वितीय मंत्रिपरिषद् में शेष 11 1 प्रतिशत और 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मंत्रिपरिषद् में शेष 5 3 प्रतिशत सदस्य रहे जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही।

विभिन्न मंत्रिपरिषदों में इण्टरमीडिएट कम स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 5 1 6 (अ) में, तथा स्नातक स्तरीय स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 5 1 6 (ब) एव स्नातकोत्तर पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र 5 1 6 (स) में प्रदर्शित किया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद् व विधान सभा के सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति सारणी सख्या 5 1 7 में दर्शाया गया है।

रेखा चित्र संख्या-5.1.6(ब)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में स्नातक शैक्षिक प्रस्थिति के

सदस्य

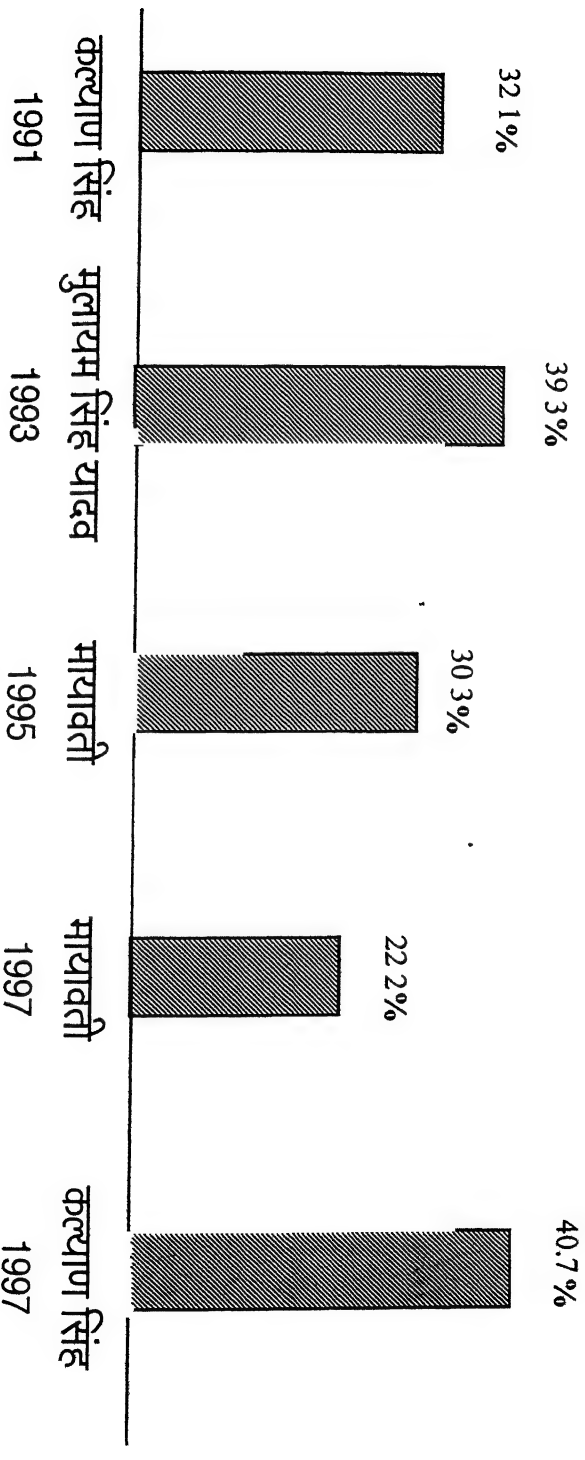
सारिणी संख्या 5.1.7

शैक्षिक प्रस्थिति विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद्

	मन्त्रिपरिषद्	इण्टरमीडिएट या कम		स्नातकोत्तर एव पी एच डी		स्नातक		अनुपलब्ध	
		विधानसभा (% मे)	मन्त्रिपरिषद् (% मे)	विधानसभा (% मे)	मन्त्रिपरिषद् (% मे)	विधानसभा (% मे)	मन्त्रिपरिषद् (% मे)	विधानसभा (% मे)	मन्त्रिपरिषद् (% मे)
1	कल्याण सिंह (प्रथम)	26.8	14.3	30.4	50	27.3	32.1	15.5	3.3
2	मुलायम सिंह यादव	23.2	14.3	32.4	32.1	31.5	39.3	12.9	14.3
3	मायावती (प्रथम)	स	21.2	स	33.3	स	30.3	स	15.2
3	मायावती (द्वितीय)	त्र यो द 20	15.6	त्र यो द 37.3	51.1	त्र यो द 32.6	22.2	त्र यो द 10.1	11.1
4	कल्याण सिंह (द्वितीय)	स	13.3	स	40.7	स	40.7	स	5.3

सारिणी संख्या 5.1.7 के अन्तर्विष्ट आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विधानसभा के सदस्यों की शैक्षिक प्रस्थिति में लगातार विधान सभा दर विधानसभा बढ़ोत्तरी हो रही है। यदि इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि विधान सभाओं में इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है। जहाँ 1991 में गठित एकादश विधान सभा में ऐसे सदस्यों का प्रतिनिधित्व 26.8 प्रतिशत हो गया तथा त्रयोदश विधान सभा में और कम होकर 20 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। जबकि इस काल मन्त्रिपरिषद् में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व अस्थिर रहा और यह 13.3 प्रतिशत

रेखा चित्र संख्या-5.1.6(स)



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. शैक्षिक प्रस्थिति के सदस्य

से 21.2 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न मन्त्रिपरिषदों में रहा है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व हमेशा विधान सभा के अपेक्षा मन्त्रिपरिषदों में कम रहा है।

यदि स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों के विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि विधानसभा में इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है जहाँ 1991 में गठित एकादश विधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व 34.4 प्रतिशत रहा वहीं 1993 में गठित द्वादश विधान सभा में इसका प्रतिनिधित्व बढ़कर 32.4 प्रतिशत रहा और त्रयोदश विधान सभा में यह और बढ़कर 37.3 प्रतिशत हो गया जबकि इस काल में (1991 से 1997) के मध्य स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों की मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा है और यह 51.1 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न मन्त्रिपरिषदों में रहा, यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि 1993 में गठित मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिमण्डल के मन्त्रिमण्डल को छोड़ दें तो इस काल में गठित अन्य मन्त्रिपरिषदों में स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व हमेशा विधान सभा में इनके प्रतिनिधित्व से उच्च रहा है।

यदि स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि विधान सभा में इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। जहाँ 1991 में गठित एकादश विधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व 27.3 रहा वहीं 1993 में गठित द्वादश विधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व बढ़कर 31.5 प्रतिशत रहा है और त्रयोदश विधान सभा में यह और बढ़कर 32.6 प्रतिशत हो गया। जबकि इस काल (1991 से 1997) के मध्य स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों की मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व घटता बढ़ता रहा है और यह 40.7 प्रतिशत से 22.2 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न मन्त्रिपरिषदों में रहा है। और यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि मायावती के नेतृत्व में गठित

दोनो मंत्रिपरिषदो को छोड़ दे तो इस काल में गठित अन्य मंत्रिपरिषदो में स्नातकोत्तर एवं पी० एच० डी० स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व हमेशा विधानसभा में इनके प्रतिनिधित्व से उच्च रहा है।

यहां यह तथ्य भी स्मरणीय है कि एकादश विधानसभा में 15.5 प्रतिशत द्वादश विधानसभा में 12.9 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधानसभा में 10.1 प्रतिशत सदस्य ऐसे रहे जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदो के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति सम्बन्धी सम्पूर्ण आकड़ो के अध्ययन से जो प्रमुख तथ्य उजागर हो रहा है वह यह है कि इस काल में मंत्रिपरिषदो में स्नातक या स्नातक से उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्यो का ही वर्चस्व रहा है। और मंत्रिपरिषद की लगभग 80 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इन्ही को प्राप्त थी, उनको ही प्राप्त थी, जब की इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत के आस पास ही रही अतः स्पष्ट है कि इस काल में मंत्रिपरिषदो के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति काफी उच्च रही है और अधिकांशतः प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्यो की भी। साथ ही इस काल में विधान सभा में भी उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्यो का प्रतिनिधित्व काफी ऊंचा रहा।

यदि इस काल में गठित तीनो विधान सभाओ के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति का अवलोकन करें तो विधान सभा दर विधान सभा इनकी शैक्षिक प्रस्थिति ऊंची हुई है। किंतु मंत्रिपरिषदो के सदस्यो के शैक्षिक स्तर में अनुपात में घट बढ़ होती रही है। सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में व 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में जहां इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो की संख्या 14.3 प्रतिशत रही है वही मायावती के दोनो मंत्रिपरिषदो में यह बढ़कर प्रथम मंत्रिपरिषद में 21.2 व द्वितीय मंत्रिपरिषद में 12.6 प्रतिशत रही है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मायावती की द्वितीय मंत्रिपरिषद भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त मंत्रिपरिषद रही है और दोनो दलो से लगभग बराबर-बराबर सदस्य मंत्रिपरिषद में सम्मिलित

किये गये। जबकि 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मंत्रिपरिषद में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व इस काल में गठित अन्य मंत्रिपरिषदों की तुलना में न्यूनतम 13.3 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक कम शैक्षिक स्तर वाला मंत्रिपरिषद मायावती की 1995 में प्रथम बार गठित मंत्रिपरिषद रही है। तत्पश्चात् सबसे कम शैक्षिक प्रस्थिति वाली मंत्रिपरिषद मायावती के नेतृत्व में 1997 में गठित बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मंत्रिपरिषद रही है। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि 1993 के विधान सभा चुनाव तक बहुजन समाज पार्टी किसी भी उच्च जाति के सदस्य को अपने दल का उम्मीदवार नहीं बनाया, दूसरे शब्दों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी दलित एवं पिछड़ों को ही केन्द्र में रख कर अपनी राजनैतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया। शासन प्रशासन में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित कराना बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यदि दलित एवं पिछड़ी जाति के साक्षरता स्तर को देखें तो मायावती के मंत्रिपरिषद के कम शैक्षिक स्तर को समझा जा सकता है।

लेकिन यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मायावती के मंत्रिपरिषद में भी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का ही वर्चस्व रहा है। इस आधार पर यह प्रतीत होता है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनता का शैक्षिक स्तर काफी कम रहा है और पिछड़ों तथा दलितों की स्थिति और भी दयनीय रही है किन्तु यह अपने विधान सभा या मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उच्च शैक्षिक स्तर वाले प्रतिनिधियों के रूप में ही देखना पसन्द करते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि चूँकि मंत्रिपरिषद एवं विधान सभा में आने वाले सदस्यों का शैक्षिक स्तर काफी ऊँचा रहा है। अतः राजनीतिक सफलता और शैक्षिक स्तर के बीच सह सम्बन्ध के रूप में देखा जा सकता है आज भी उच्च शैक्षिक तथा कम शिक्षित लोगों का राजनैतिक चेतना का स्तर अपेक्षाकृत अशिक्षित तथा कम शिक्षित लोगों के स्तर से ऊँचा रहा है और यह तथ्य सभी वर्ग-धर्म जाति के लोगों पर लागू होती है क्योंकि प्रत्येक

समुदाय का राजनैतिक नेतृत्व प्रायः शिक्षित सभ्रान्त लोगो के रूप में उभर कर सामने आ रहा है।

5.2 व्यवसायिक स्थिति

राजनीतिक समाज शास्त्र की यह बहुत प्रचलित मान्यता है कि नीति निर्माताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का उनके दृष्टिकोण एवं नीतियों पर प्रभाव अवश्यम्भावी है।¹ बचपन में माता-पिता, अध्यापक, मित्र मण्डली के द्वारा जो विचार उनके मन में घर कर दिये गये हैं, चेतन अथवा अवचेतन रूप में उनका प्रभाव उसके परवर्ती आचरण पर निश्चित पड़ता है² यही कारण है कि समाजशास्त्री विधायकों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। उनकी मान्यता है कि विधायकों को साधारणतया अपने समाज का प्रतिबिम्ब होना चाहिए अर्थात् समाज में जिस अनुपात में विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व है उसी अनुपात में विधान मण्डल में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए³; यदि किसी विधान मण्डल की स्थिति ऐसी प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है तो वहाँ सामाजिक तनाव आसन्न है।

समाज में लोगों की ये आम धारणा है कि उनके व्यवसाय वर्ग का व्यक्ति जब शासन की प्रतिनिधित्व सभाओं में पहुँचेगा तो उनकी समस्याओं एवं कठिनाइयों को भली

1 पैरी जी - पॉलिटीकल इलीट, एलेन और यूनविन (1963) पृष्ठ संख्या 97

2 वही

3 पैरी जी - वही पृष्ठ 102

प्रकार समझ कर उनके हितों में कार्य करेगा। इस सन्दर्भ में समाजवाद की एक शाखा श्रेणी समाजवाद की यह मान्यता है कि विधान मण्डल का गठन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए। उनका मानना है कि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व कभी नहीं किया जा सकता, प्रतिनिधित्व केवल किसी समूह के सामान्य हितों का किया जा सकता है जैसे- वकील, वकील होने के नाते वकील का, डाक्टर, डाक्टर होने के नाते डाक्टर के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

व्यवसाय या वृत्ति की पृष्ठभूमि से सदस्यों के मस्तिष्क के झुकाव का बोध होता है और भिन्न-भिन्न समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय का मंत्रिपरिषद् एवं विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व यह तथ्य भी प्रदर्शित करता है कि भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों की राजनीति के प्रति अभिरुचि कैसी है या किसी व्यवसाय वर्ग के लोगों में राजनीतिक चेतना तथा राजनीतिक सहभागिता का स्तर क्या है ?

अतीत में दृष्टि डाले तो, कांग्रेस की स्थापना के समय जिसे राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना का उषाकाल माना जा सकता है, राजनीति में पत्रकारिता तथा वकालत से जुड़े लोगों की भागीदारी सर्वाधिक थी। स्वतंत्रता के पश्चात् लोकसभा के सदस्यों पर किए गये अध्ययन से पता चलता है कि वकीलों की संख्या घट रही है उसका स्थान कृषक एवं जमींदार वर्ग के लोग ले रहे हैं।⁴ कृषक वर्ग में बड़े जमींदारों से लेकर छोटे जमींदार व कृषक वर्ग सभी हैं लेकिन वे शहरी पेशेवर वर्ग के मुकाबले जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया था और स्वतंत्रता के बाद सरकार का भी, देहाती जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।⁵

4 रत्नादत्त, 'द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव इन फोर्थ लोकसभा इक एंड पोली, वीकली, 4 संख्या 1 व 2 जनवरी 1966 उद्धृत कोठारी रजनी - भारत में राजनीति' नई दिल्ली, ओरिएन्टलॉग मैन् लिमिटेड, पृष्ठ 43 से ।

भारत में दलों के नेता एवं पदाधिकारियों के व्यवसायिक पृष्ठ भूमि से यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ ऐसे दल हैं जिसमें कुछ निश्चित व्यवसायिक पृष्ठ भूमि के लोग ही आते हैं, जैसे स्वतंत्र दल में बड़े जमींदार और भूमिपतियों का जमघट, जबकि मध्यम दर्जे के किसान कांग्रेस, जनसंघ, बांम दलों में अधिक हैं, इसी तरह जनसंघ में व्यापार और उद्योग के लोग हैं, जो अधिकतर दुकानदार हैं, किन्तु स्वतंत्र पार्टी में बड़े व्यवसायिक और उद्योगपति हैं।⁶ दूसरी और कम्युनिष्ट पार्टी में अधिकांश ट्रेड यूनियन और पेशेवर राजनीतिक पत्रकार आदि हैं।⁷

उपर्युक्त सन्दर्भों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध के इस अध्याय में 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की व्यवसायिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन किया गया है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यवसाय को दस वर्गों में विभक्त किया गया है यथा कृषि, सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीति एवं सामाजिक कार्य, वकालत व्यापार एवं उद्योग अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता, चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा विविध।

5 कोठारी रजनी - 'भारत में राजनीति' नई दिल्ली, ओरिएण्ट लॉग मैन लिमिटेड, पृष्ठ 143 से

6 रत्नादत्त वही से दृष्ट।

7 कोठारी रजनी, वही

मई-जून 1991 में एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 24 06 1991 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमबार गठित तथा दिनांक 06 12 1992 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का व्यवसाय सारिणी सख्या 5.2 1 में प्रदर्शित है—

सारिणी सख्या-5 2 1

सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

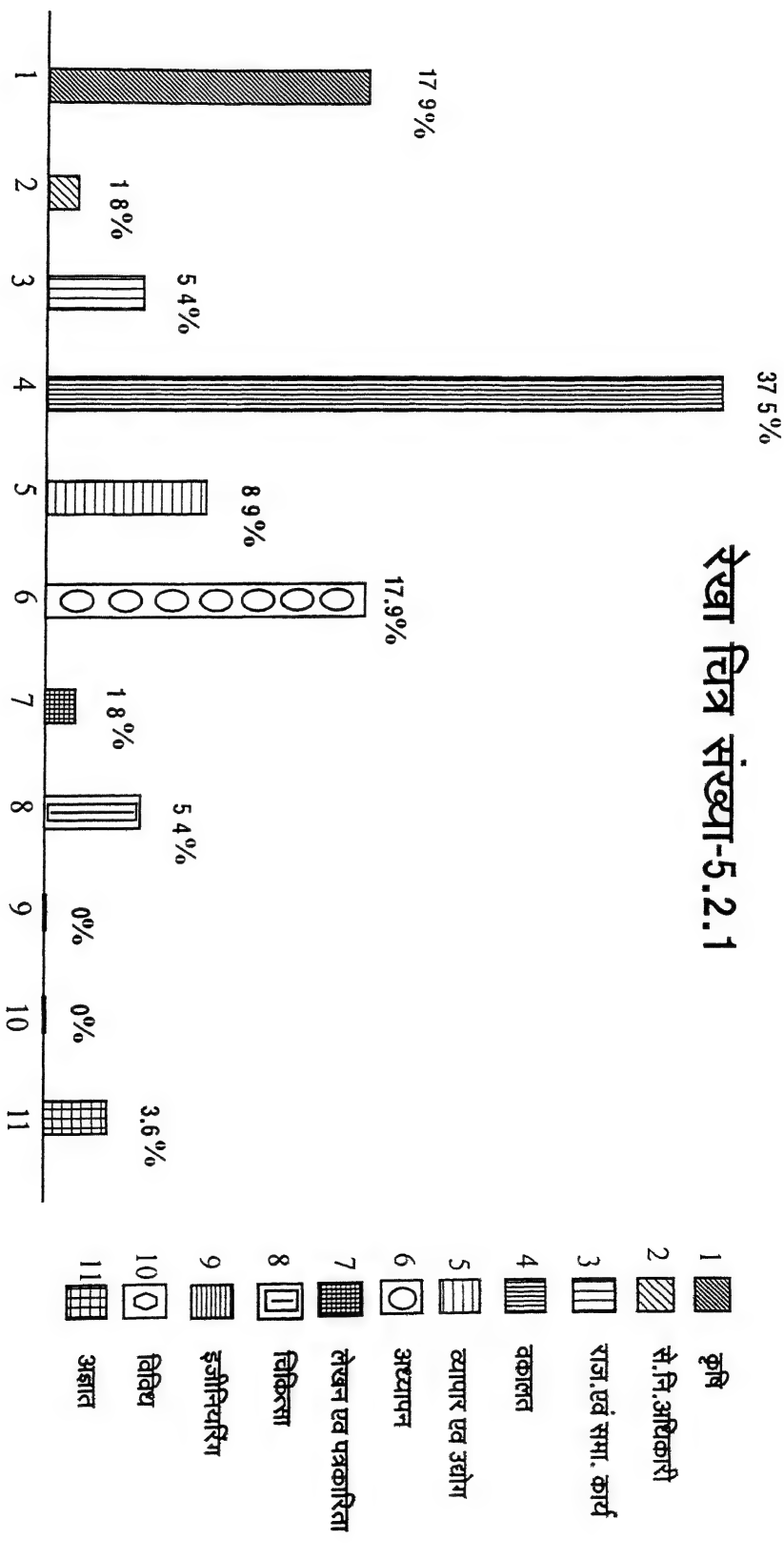
क्र. सं.	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मन्त्री- परिषद के मध्य) 1मन्त्री विधानसभा सदस्य
		(अ)	(ब)	(अ)	(ब)	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	237	56.7	10	17.9	23.7
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0.7	1	1.8	3
3	राजनीति एवं सामाजिक कार्य	03	0.7	03	5.4	1
4	वकालत	44	10.5	21	37.5	2.1
5	व्यापार एवं उद्योग	20	4.8	05	8.9	4
6.	अध्यापन	26	6.2	10	17.9	2.6
7	लेखन एवं पत्रकारिता	04	1	01	1.8	4
8	चिकित्सा	07	1.7	03	5.4	2.3
9	इंजीनियरिंग	02	0.5	-	-	-
10	विविध	08	1.9	-	-	-
11	अज्ञात	64	15.3	2	3.6	32
	योग—	418	100	56	100	7.5 (अनुपात)

सारिणी सख्या 5 2 1 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कल्याण सिंह (24 06 1991 से 06 12 1992 तक) के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद् में वकालत व्यवसाय से सर्वाधिक 21 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 37 5 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त कृषि व अध्यापन से 10-10 सदस्यों को, व्यापार व उद्योग से 5 सदस्यों को, राजनीति व सामाजिक कार्य तथा चिकित्सा से 3-3 सदस्यों को, सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग तथा लेखन व पत्रकारिता से 1-1 सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः कृषि तथा अध्यापन 17 9 फीसदी, व्यापार एवं उद्योग 8 9 फीसदी, राजनीति व सामाजिक कार्य तथा चिकित्सा 5 4 फीसदी और सेवा निवृत्त अधिकारी एवं लेखन व पत्रकारिता के व्यवसाय में लिप्त सदस्यों का 1 8 फीसदी रहा।

यदि विधान सभा सदस्यों की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि विधान सभा में कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 237 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 56 7 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमशः वकालत से 44, अध्यापन से 26, व्यापार एवं उद्योग से 20, चिकित्सा से 7, सेवा निवृत्त अधिकारी व राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य से 03-03 इन्जीनियरिंग से 02 तथा विविध I से 08 सदस्यों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमशः वकालत—10 5, अध्यापन 6 2, व्यापार एवं उद्योग 4 8, चिकित्सा 1 7, सेवा निवृत्त अधिकारी व राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य 0 7-0 7, इन्जीनियरिंग 0 5 तथा विविध 1 9 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5 2 1 के कालम-7 में अन्तर्विष्ट आकड़ों के आधार पर यदि विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के अनुपात पर दृष्टि डालें तो कृषि से 23 7, सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग से 3, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य से 1, वकालत से 2 1, व्यापार एवं उद्योग से 4, अध्यापन से 2 6, 4, चिकित्सा से 2 3, विधानसभा सदस्यों

रेखा चित्र संख्या-5.2.1



सन् 1991 में कल्याण सिंह के द्वारा गठित मंत्रिपरिषद् की व्यवसायिक प्रस्थिति

पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य करने वाले विधान सभा सदस्यों का मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वहीं कृषि कार्य करने वालों का अनुपात सबसे निम्न रहा है।

यदि उपर्युक्त अनुपातों की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद व विधान सभा के अनुपात से करे तो स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 7.5 है अर्थात् विधान सभा के 7.5 सदस्यों पर (चाहे वह किसी व्यवसाय का हो) मन्त्रिपरिषद में एक सदस्य को स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य, वकालत चिकित्सा, अध्यापन, सेवानिवृत्त अधिकारी, लेखन एवं पत्रकारिता तथा उद्योग एवं व्यापार को उच्च अनुपात प्रदान किया गया, वहीं केवल कृषि को निम्न अनुपात प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद के सदस्यों के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5.2.1 में दर्शाया गया है।

नवम्बर 1993 में विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् के दिनांक-04.12.1993 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक-03.06.1995 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का व्यवसाय सारिणी सख्या 5.2.2 में प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5.2.2 में अन्तर्विष्ट ऑकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव (04.12.1993 से 03.06.1995 तक) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में कृषि व्यवसाय के सर्वाधिक 10 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 16.1 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त राजनीति व सामाजिक कार्य व वकालत से 4-4 सदस्यों को, अध्यापन से 3 सदस्यों को, सेवा निवृत्त अधिकारी, व्यापार एवं उद्योग, लेखन एवं पत्रकारिता व चिकित्सा से 1-1 सदस्यों को मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः राजनीतिक कार्य तथा वकालत 14.3 फीसदी, अध्यापन 10.7 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी, व्यापार एवं

उद्योग, लेखन एवं पत्रकारिता व चिकित्सा से 36 फीसदी रहा।

यदि विधान सभा सदस्यों की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधान सभा में कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 161 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 37.8 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमशः

सारिणी सख्या-522

1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों का व्यवसाय

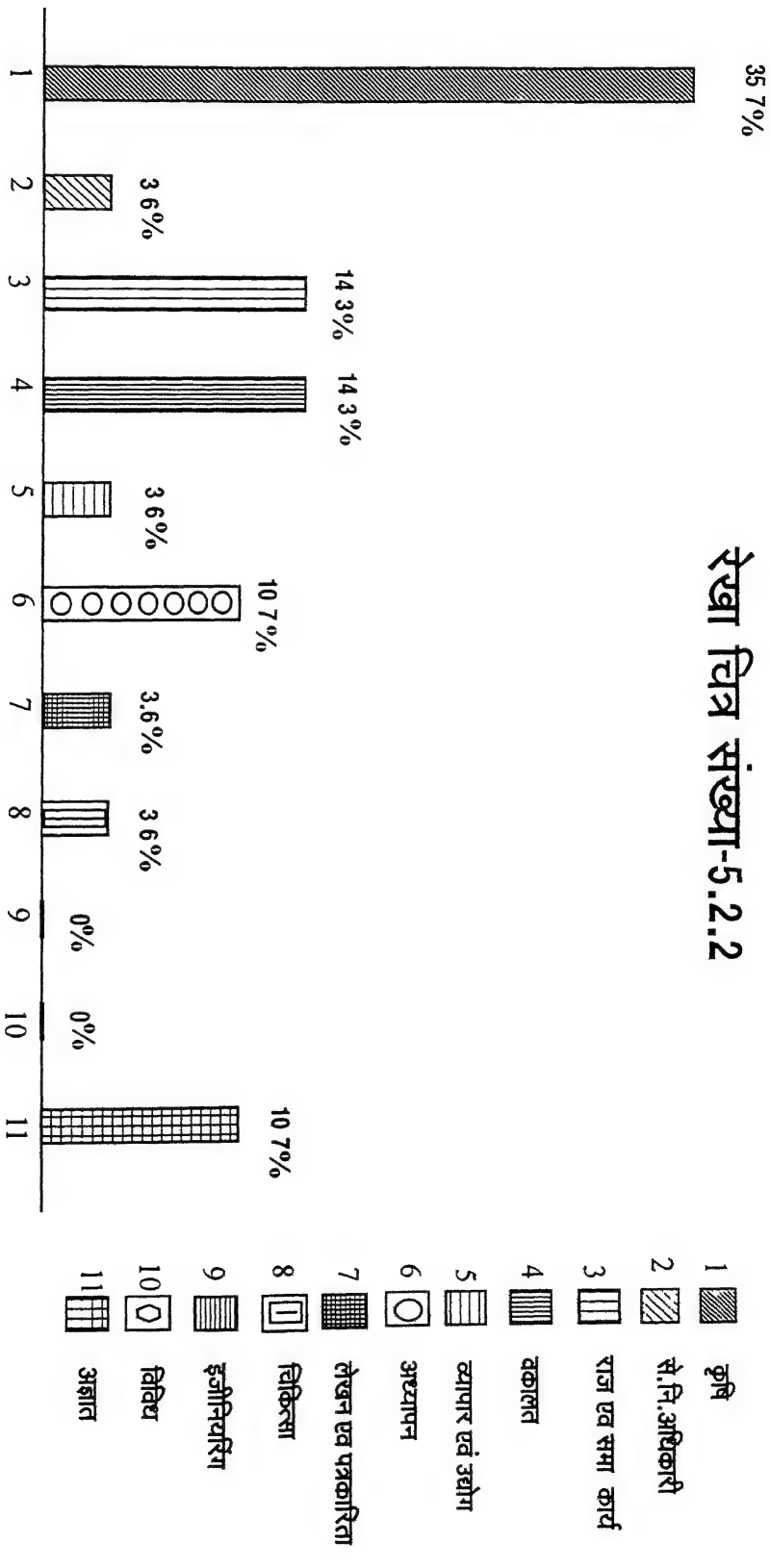
क्र. स.	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्		अनुपात (विधानसभा व मन्त्री- परिषद् के मध्य) 1 मन्त्री विधानसभा सदस्य
		(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि	161	37.8	10	35.7	16.1
2.	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0.7	1	3.6	3
3	राजनीति एवं सामाजिक कार्य	10	2.4	4	14.3	2.5
4	वकालत	64	15	4	14.3	16
5	व्यापार एवं उद्योग	60	14.1	1	3.6	60
6	अध्यापन	47	11	3	10.7	15.7
7	लेखन एवं पत्रकारिता	11	2.6	1	3.6	11
8	चिकित्सा	7	1.6	1	3.6	7
9	इंजीनियरिंग	02	0.5	-	-	-
10.	विविध	06	1.4	-	-	-
11	अज्ञात	55	12.9	3	10.7	18.3
	योग-	426	100	28	100	15.2 (अनुपात)

वकालत से 64, व्यापार एव उद्योग से 60, अध्यापन से 47, लेखन एव पत्रकारिता से 11, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 10, चिकित्सा से 07, सेवा निवृत्त अधिकारी से 03, इंजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमशः वकालत से 15 फीसदी, व्यापार एव उद्योग से 14.1 फीसदी, अध्यापन से 11 फीसदी, लेखन एव पत्रकारिता से 2.6, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2.4 फीसदी, चिकित्सा से 1.6 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी से 0.7 फीसदी, इंजीनियरिंग से 0.5 फीसदी तथा विविध से 1.4 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5.2.2 के कालम-7 में अन्तर्विष्ट आकड़ों के आधार पर यदि विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के अनुपात पर दृष्टि डाले तो कृषि से 16.1, सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग से 3, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2.5, वकालत से 16, व्यापार एव उद्योग से 60, अध्यापन से 15.7, लेखन एव पत्रकारिता से 11, चिकित्सा से 7 विधान सभा सदस्यों पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ राजनीति एव सामाजिक कार्य करने वाले विधानसभा सदस्यों का मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वही कृषि कार्य करने वालों का अनुपात सबसे निम्न रहा है।

यदि विभिन्न व्यवसाय के सन्दर्भ प्राप्त अनुपातों की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् व विधान सभा के अनुपात से करे तो, स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 15.2 है अर्थात् 15.2 विधानसभा सदस्यों (चाहे वह किसी व्यवसाय से सम्बन्धित हों) पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष जहाँ राजनीतिक एव सामाजिक कार्य, सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग, लेखन एव पत्रकारिता तथा चिकित्सा को उच्च अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वही कृषि, वकालत, व्यापार एव उद्योगों को निम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5.2.2 में दर्शाया गया है।

रेखा चित्र संख्या-5.2.2



सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के द्वारा गठित मंत्रिपरिषद् की व्यवसायिक प्रस्थिति

मुलायम सिंह यादव के मन्त्रि-परिषद के पतन के पश्चात् दिनांक-03 06 1995 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक-18 10.1995 तक कार्यरत मन्त्रि-परिषद के सदस्यों का व्यवसाय सारिणी सख्या-5 2 3 में प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 2 3 अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती (03 06.1995 से 08 10 1995 तक) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 12 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 36.4 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त वकालत से 08 सदस्यों को, व्यापार एवं उद्योग से 05 सदस्यों को, राजनीति व सामाजिक कार्य से 02 सदस्यों को तथा अध्यापन व लेखन एवं पत्रकारिता से 1-1 सदस्यों को मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः वकालत 24 2 फीसदी, व्यापार एवं उद्योग 15 2 फीसदी, राजनीति व सामाजिक कार्य 6 1 फीसदी तथा अध्यापन व लेखन एवं पत्रकारिता से 03 0 फीसदी रहा।

यदि विधान सभा सदस्यों की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि विधान सभा में कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 161 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 37 8 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमशः वकालत से 64, व्यापार एवं उद्योग से 60, अध्यापन से 47, लेखन एवं पत्रकारिता से 11, राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 10, चिकित्सा से 07, सेवा निवृत्त अधिकारी से 03, इंजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमशः वकालत से 15 फीसदी, व्यापार एवं उद्योग से 2 6 फीसदी, राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 2 4 फीसदी, चिकित्सा से 1 6 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी से 0 7 फीसदी, इंजीनियरिंग से 0 5 फीसदी तथा विविध से 1 4 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5.2.3 के कालम-7 में अन्तर्विष्ट आकड़ों के आधार पर यदि विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद के सदस्यों के अनुपात पर दृष्टि डालें तो कृषि से 13.4,

राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 5, वकलात से 8, व्यापार एवं उद्योग से 12, अध्यापन से 47, लेखन एवं पत्रकारिता से 11 विधान सभा सदस्यों पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ राजनीति एवं सामाजिक कार्य करने वाले विधान सभा सदस्यों का मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है, वहीं अध्यापन कार्य करने वालों का अनुपात सबसे निम्न रहा है।

सारिणी सख्या-5 2.3

1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रि-परिषद के सदस्यों का व्यवसाय

क्र. स.	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मन्त्री-परिषद के मध्य) 1 मन्त्री विधानसभा सदस्य
		(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	161	37.8	12	36.4	13.4
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0.7	-	-	-
3	राजनीति एवं सामाजिक कार्य	10	2.4	2	6.1	5
4.	वकालत	64	15	8	24.2	8
5.	व्यापार एवं उद्योग	60	14.1	5	15.2	12
6.	अध्यापन	47	11	1	3.1	47
7.	लेखन एवं पत्रकारिता	11	2.6	1	3	11
8.	चिकित्सा	7	1.6	-	-	-
9.	इंजीनियरिंग	02	0.5	-	-	-
10	विविध	06	1.4	-	-	-
11	अज्ञात	55	12.9	4	12.1	13.8
	योग-	426	100	33	100	12.9 (अनुपात)

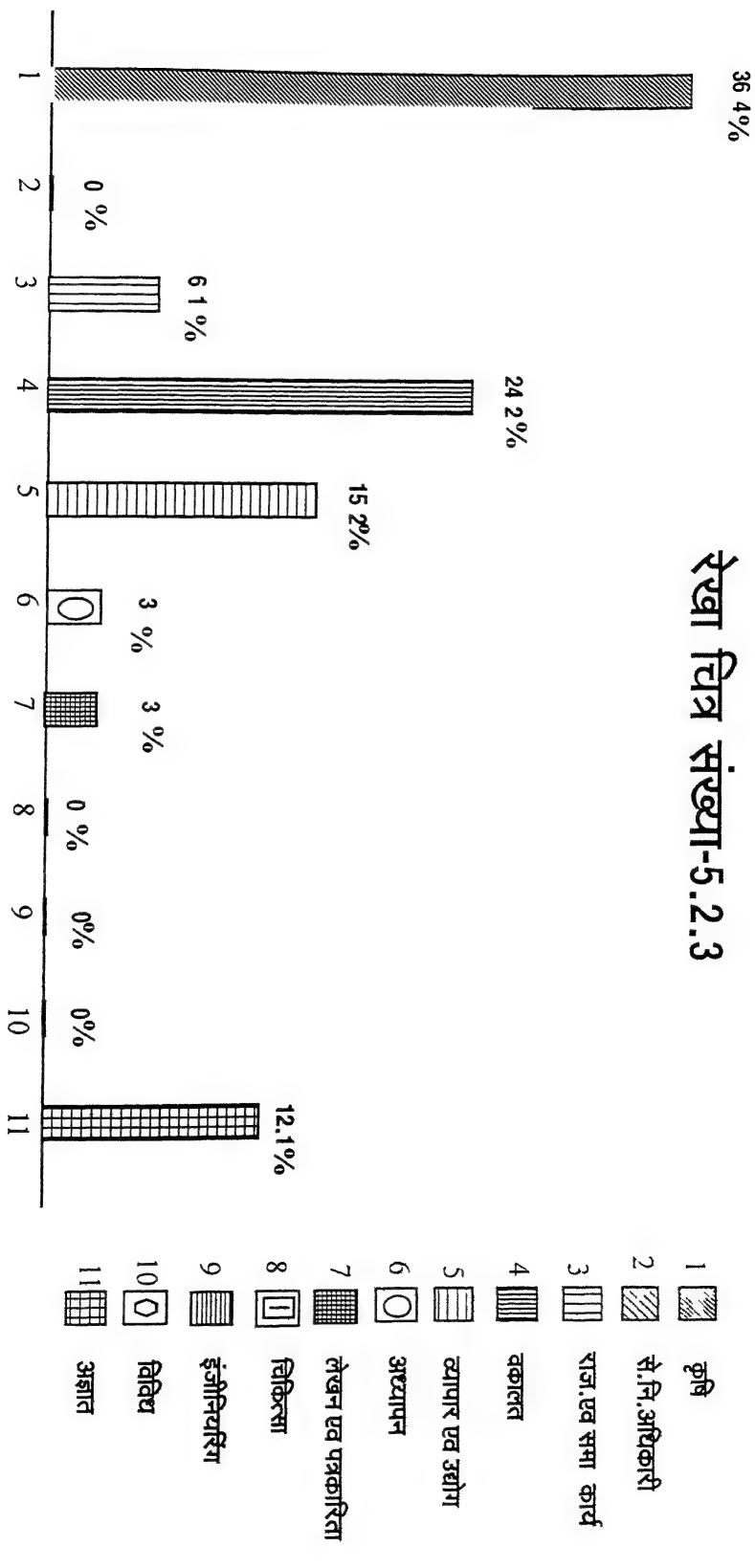
यदि विभिन्न व्यवसाय के सन्दर्भ में प्राप्त अनुपातों की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् व विधान सभा के अनुपात से करे तो, स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 12.9 है अर्थात् 12.9 विधानसभा सदस्यों (चाहे वह किसी व्यवसाय से सम्बन्धित हो) पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष जहाँ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य, वकालत तथा लेखन एवं पत्रकारिता तथा चिकित्सा को उच्च अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वही अध्यापन, कृषि तथा व्यापार एवं उद्योग को निम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5.2.3 में दर्शाया गया है।

सितम्बर-अक्टूबर 1998 में त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 21.3.97 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 21.9.97 तक कार्यरत, भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों का व्यवसाय सारिणी सख्या 5.2.4 में प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5.2.4 के अन्तर्विष्ट ऑकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती (21.3.97 से 21.9.97 तक) के नेतृत्व में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में कृषि व वकालत व्यवसाय से सर्वाधिक 13-13 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 28.9 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त राजनीति एवं सामाजिक कार्य व अध्यापन से 05-05 सदस्यों को, व्यापार एवं उद्योग से 03 सदस्य को, सेवा निवृत्त अधिकारी से 02 सदस्य, तथा लेखन एवं पत्रकारिता से 01 सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः राजनीति एवं सामाजिक कार्य व अध्यापन 11.1 फीसदी, व्यापार एवं उद्योग 6.7 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी 4.4 फीसदी तथा लेखन एवं पत्रकारिता 2.2 फीसदी रहा।

यदि विधानसभा सदस्यों की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधानसभा में कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 170 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ

रेखा चित्र संख्या-5.2.3



सन् 1995 में मायावती के द्वारा गठित मंत्रिपरिषदों की व्यवसायिक प्रस्थिति

1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय

क्र० स०	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मन्त्रिपरिषद के मध्य) 1 मन्त्री विधानसभा सदस्य
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	170	39.9	13	28.9	13.1
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0.7	02	4.4	1.5
3	राजनीति एव सामाजिक कार्य	11	2.6	05	11.1	2.2
4	वकालत	74	17.4	13	28.9	5.9
5	व्यापार एव उद्योग	63	14.8	03	6.7	2.1
6	अध्यापन	34	8	05	11.1	6.8
7	लेखन एव पत्रकारिता	10	2.4	01	2.2	1.0
8	चिकित्सा	10	2.4	-	-	-
9	इजीनियरिंग	02	0.5	-	-	-
10	विविध	06	1.4	-	-	-
11	अज्ञात	41	9.6	03	6.7	13.7
	योग	426	100	45	100	9.5

जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 39.9 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमशः वकालत से 74, व्यापार एव उद्योग से 63, अध्यापन से 34, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 11, लेखन एव पत्रकारिता व चिकित्सा से 10-10, सेवा निवृत्त अधिकारी से 03, इजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमशः

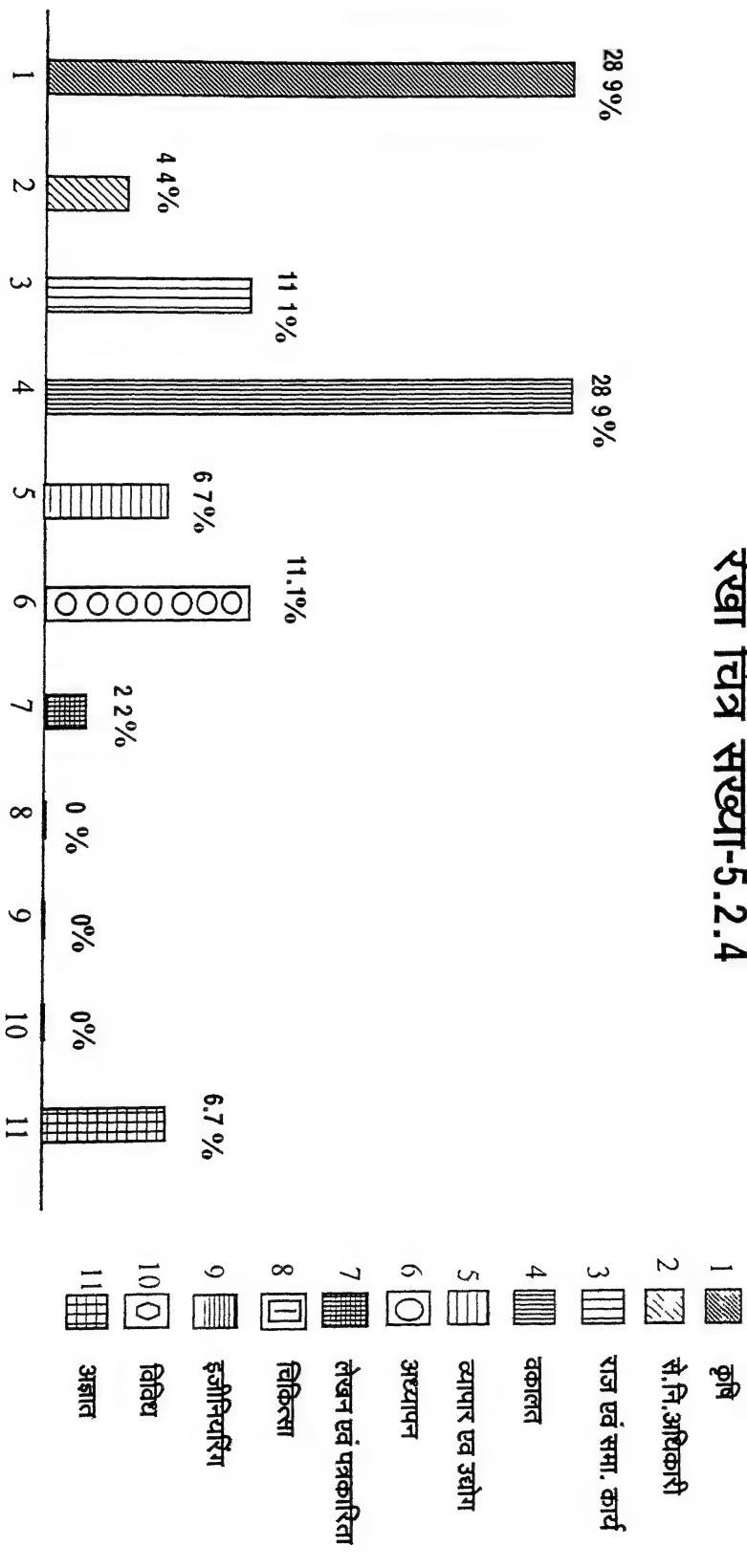
राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 26 फीसदी, लेखन एवं पत्रकारिता व चिकित्सा से 24 फीसदी, सेवानिवृत्त अधिकारी से 07 फीसदी, इंजीनियरिंग से 05 फीसदी तथा विविध से 14 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5.2.4 के कालम (V) में अन्तर्विष्ट ऑकड़ों के आधार पर यदि विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के अनुपात पर दृष्टि डाले तो कृषि से 13.1, सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग से 1.5 राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 2.2, वकालत से 5.9, व्यापार एवं उद्योग से 21, अध्यापन से 6.8 लेखन एवं पत्रकारिता से 10, विधानसभा सदस्यों एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग को विधानसभा सदस्यों का मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वही कृषि कार्य करने वालों का अनुपात सबसे निम्न रहा।

यदि विभिन्न व्यवसायों के अनुपात की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् व विधानसभा के अनुपात से करे तो स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 9.5 है अर्थात् विधानसभा के 9.5 सदस्यों पर (चाहे वह किसी भी व्यवसाय से सम्बन्धित) मन्त्रिपरिषद् में एक सदस्य को स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीति एवं सामाजिक कार्य, वकालत व अध्यापन को उच्च अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया वहीं कृषि, व्यापार एवं उद्योग तथा लेखन एवं पत्रकारिता को निम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5.2.5 में दर्शाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणाम स्वरूप छ महीने की अवधि की सामाप्ति के पश्चात् मुख्यमंत्री मायावती द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनांक 21.9.97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में 31 दिसम्बर 1997 तक विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 8.5 में प्रदर्शित किया गया है।

रेखा चित्र संख्या-5.2.4



सन् 1997 में मायावती के द्वारा गठित मंत्रिपरिषद् की व्यावसायिक प्रस्थिति

सारिणी सख्या-5.2.5

1997 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय

क्र० सं०	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मन्त्रिपरिषद के मध्य) 1 मन्त्री विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	कृषि	170	39.9	48	42.5	3.5
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0.7	03	2.6	1
3	राजनीति एव सामाजिक कार्य	11	2.6	06	5.3	1.8
4.	वकालत	74	17.4	27	23.9	2.7
5	व्यापार एव उद्योग	63	14.8	12	10.6	5.3
6	अध्यापन	34	8	09	8	3.8
7	लेखन एव पत्रकारिता	10	2.4	3	2.6	3.3
8	चिकित्सा	10	2.4	1	9	10
9.	इजीनियरिंग	02	0.5	-	-	-
10.	विविध	06	1.4	1	9	6
11.	अज्ञात	41	9.6	03	2.7	13.7
		426	100	113	100	3.8 अनुपात

सारिणी सख्या 5.2.5 के अन्तर्विष्ट आँकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती (21.3.97 से 21.9.97 तक) के नेतृत्व में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद में कृषि व वकालत व्यवसाय से सर्वाधिक 13-13 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 42.5 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त वकालत से 9 सदस्य को राजनीति एव सामाजिक कार्य से 06 सदस्यों को, सेवानिवृत्त अधिकारी व लेखन एव पत्रकारिता से 03-03

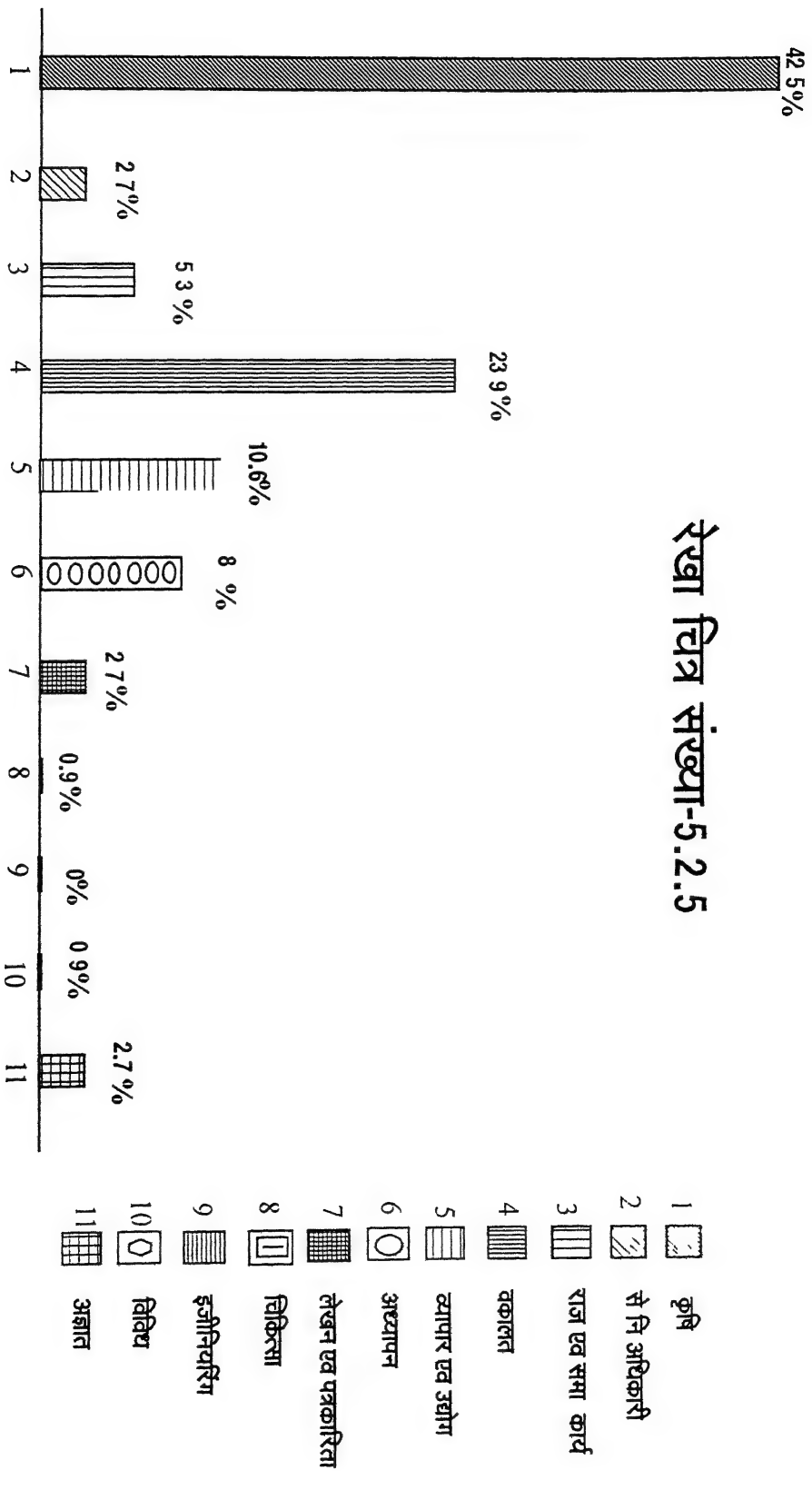
सदस्यो को , तथा चिकित्सा तथा विविध से 1-1 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः वकालत 23.9 फीसदी, व्यापार एवं उद्योग 10.6 फीसदी अध्यापन 8 फीसदी, राजनीति एवं सामाजिक कार्य 5.3 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी व लेखन एवं पत्रकारिता 2.6 फीसदी, चिकित्सा तथा विविध 9 फीसदी रहा।

यदि विधानसभा सदस्यो की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधानसभा मे कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 170 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 39.9 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमशः वकालत से 74, व्यापार एवं उद्योग से 63, अध्यापन से 34, राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 11, लेखन एवं पत्रकारिता व चिकित्सा से 10-10, सेवा निवृत्त अधिकारी से 03, इंजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यो को विधान सभा मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमशः वकालत से 17.4 फीसदी, व्यापार एवं उद्योग से 14.8 फीसदी, अध्यापन से 8 फीसदी, राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 2.6 फीसदी, लेखन एवं पत्रकारिता व चिकित्सा से 2.4 फीसदी, सेवानिवृत्त अधिकारी से 0.7 फीसदी, इंजीनियरिंग से 0.5 फीसदी तथा विविध से 1.4 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5.2.5 के कालम (v) मे अन्तर्विष्ट ऑकड़ो के आधार पर यदि विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद के सदस्यो के अनुपात पर दृष्टि डाले तो कृषि से 13.5, सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग से 1 राजनीति एवं सामाजिक कार्य से 1.8, वकालत से 2.7, व्यापार एवं उद्योग से 5.3, अध्यापन से 3.8 लेखन एवं पत्रकारिता से 3.3, चिकित्सा से 10 एवं विविध से 6, विधानसभा सदस्यो पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग को विधानसभा सदस्यो का मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वहीं कृषि कार्य करने वालो का अनुपात सबसे निम्न रहा।

यदि विभिन्न व्यवसायो के अनुपात की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद व विधानसभा के अनुपात से करे तो स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 3.8 है अर्थात् विधानसभा के 3.8 सदस्यो पर

रेखा चित्र संख्या-5.2.5



सन् 1997 में कल्याण सिंह के द्वारा गठित मंत्रिपरिषद् की व्यावसायिक प्रस्थिति

(चाहे वह किसी भी व्यवसाय से सम्बन्धित) मन्त्रिपरिषद् में एक सदस्य को स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीति एवं सामाजिक कार्य, वकालत व अध्यापन को उच्च अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया वहीं कृषि, व्यापार एवं उद्योग तथा लेखन एवं पत्रकारिता को निम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5 2.5 में दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्यगठित विभिन्न मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों में प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 5 2 6 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 5 2 6 के अन्तर्गत ऑकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित पाँचों मन्त्रिपरिषदों में प्रत्येक में सर्वाधिक सदस्य कृषि व्यवसाय से आये जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 42.5 फीसदी 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद् का रहा। तदपश्चात् मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद् में 36.4 प्रतिशत, मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद् में 35.7 प्रतिशत, मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में 28.9 प्रतिशत तथा कल्याण सिंह की सन् 1991 में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद् में 17.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व कृषि व्यवसाय करने वाले सदस्यों को प्राप्त हुआ।

यदि सारिणी सख्या 5.2 6 के माध्यम से सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग का विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि इस वर्ग के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 4.4 प्रतिशत मायावती के 1997 में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में प्राप्त हुआ, तदपश्चात् मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद् में 3.6 प्रतिशत, कल्याण सिंह ने द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में 2.7 प्रतिशत और कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद् में 1.8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इस वर्ग के सदस्यों को प्राप्त हुआ, यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद् में सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

यदि राजनीति एवं सामाजिक कार्य करने वाले सदस्यों के प्रतिनिधित्व की स्थिति विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में क्या है? का अवलोकन करें तो सारिणी सख्या 5.2.6 में स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 14.3 प्रतिशत मुलायम सिंह यादव के

सारिणी संख्या- 5.2.6

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : व्यवसाय

मन्त्रिपरिषद												
क्र० सं०	व्यवसाय	कल्याण सिंह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिंह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिंह द्वितीय 21-09-97 से -----तक		समग्र 1991 से 1997
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	कृषि सेवा निवृत्त अधिकारी राजनिती एवं सामाजिक कार्य वकालत व्यापार एवं उद्योग अध्यापन लेखन एवं पत्रकारिता चिकित्सा इजीनियरिंग विविध अज्ञात	10	17.9	10	35.7	12	36.4	13	28.9	48	42.5	93
2		1	1.8	1	3.6	-	-	2	4.4	3	2.7	7
3		3	5.4	4	14.3	2	6.1	5	11.1	6	5.3	20
4		21	37.5	4	14.3	8	24.2	13	38.9	27	23.9	73
5		5	8.9	1	3.6	5	15.2	3	6.7	12	10.6	26
6		10	17.9	3	10.7	1	3	5	11.1	9	8	28
7		1	1.8	1	3.6	1	3	1	2.4	3	2.7	7
8		3	5.4	1	3.6	-	-	-	-	1	0.9	6
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.9	1
11		2	3.6	3	10.7	4	12.1	3	6.7	3	2.7	15
योग		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275

मन्त्रिपरिषद में प्राप्त में हुआ है, तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मन्त्री-परिषद में 11.1 प्रतिशत मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 6.1 प्रतिशत कल्याण सिंह के प्रथम एवं द्वितीय मन्त्रिपरिषद में क्रमशः 5.4 प्रतिशत व 5.3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

यदि सारिणी सख्या 5.2.6 के माध्यम से वकालत पेशे से आयी सदस्यों का विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 5.3 प्रतिशत कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में प्राप्त हुआ, तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मन्त्री परिषद में 24.2 प्रतिशत कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 23.9 प्रतिशत तथा मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में 14.3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 1991 से 1997 के मध्य गठित होने वाले पाँचों मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व कृषि के बाद सर्वाधिक इसी पेशे से आने वाले सदस्यों का है।

यदि सारिणी 5.2.6 के माध्यम से व्यापार एवं उद्योग वर्ग से आने वाले सदस्यों का विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि इस वर्ग के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 15.2 फीसदी मायावती की प्रथम मन्त्रिपरिषद में प्राप्त हुआ। तदपश्चात् कल्याण सिंह की द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 10.6 प्रतिशत, कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 8.9 प्रतिशत, मायावती की द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 6.7 प्रतिशत तथा मुलायम सिंह यादव की मन्त्रिपरिषद में 3.6 प्रतिशत स्थान व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को प्राप्त हुआ।

यदि सारिणी सख्या 5.2.6 के माध्यम से अध्यापन कार्य करने वाले सदस्यों का विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि इस वर्ग के सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 17.9 प्रतिशत कल्याण सिंह की प्रथम मन्त्रिपरिषद में प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 11.1 प्रतिशत, कल्याण सिंह

के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 8 प्रतिशत तथा मुलायम सिंह यादव एवं मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 3-3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को प्राप्त हुआ है।

यदि सारिणी सख्या 5 2 6 के माध्यम से लेखन एवं पत्रकारिता से सम्बन्धित सदस्यों का विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को सर्वाधिक 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में प्राप्त हुआ। तदपश्चात् मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 3 प्रतिशत, कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 2 7 प्रतिशत, मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 2 2 प्रतिशत तथा कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 1 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को प्राप्त हुआ।

यदि सारिणी सख्या 5 2 6 के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों का विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि इन व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को सर्वाधिक 5.4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद में प्राप्त था। तदपश्चात् मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में 3.6 प्रतिशत, कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 0 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों को प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के प्रथम एवं द्वितीय मन्त्रिपरिषद में इस व्यवसाय वर्ग के किसी सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका।

यदि सारिणी सख्या 5 2.6 के माध्यम से इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों के विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के किसी भी सदस्य को किसी भी मन्त्रिपरिषद में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया।

यदि सारिणी सख्या 5 2.6 के माध्यम से विविध (फोटोग्राफी, जीवन बीमा

एजेन्ट, ट्रासपोर्टेशन एव सन्यास दीक्षा आदि) क्षेत्रों में कार्यरत सदस्यों का विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि केवल कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 0.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इन क्षेत्रों में कार्यरत सदस्यों को प्राप्त हुआ, जबकि अन्य मन्त्रिपरिषदों में इस वर्ग के सदस्यों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका।

इसके अतिरिक्त कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद में 3.6 प्रतिशत, मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में 10.7 प्रतिशत मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषदों में 12.1 प्रतिशत एव मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 6.7 प्रतिशत तथा कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद में 2.7 प्रतिशत सदस्यों के व्यवसाय के विषय में कोई जानकारी शोधार्थिनी को प्राप्त नहीं हो पायी। इन तथ्यों को रेखाचित्र संख्या 8.6 में दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों की प्रस्थिति का अवलोकन करने के पश्चात् जो तथ्य उजागर हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मन्त्रिपरिषद में विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों की प्रतिनिधित्व का कोई निश्चित अनुपात नहीं रहा है, अर्थात् विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा है। लेकिन प्रत्येक मन्त्रिपरिषदों में एक तथ्य सामान्य है कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जो इस काल में गठित सभी मन्त्रिपरिषदों में (कल्याण सिंह के प्रथम मन्त्रिपरिषद को छोड़कर) 17.9 प्रतिशत से 42.5 प्रतिशत के बीच ठहरता है यदि इसकी तुलना प्रदेश की जनसंख्या में कृषि कार्य में रत व्यक्तियों के प्रतिशत से करें तो यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद में इस व्यवसाय वर्ग को यद्यपि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान हो रहा है तथापि प्रदेश की जनसंख्या के कृषि कार्य करने वाले भाग का हूँ बहू प्रतिनिधित्व नहीं करते, अर्थात् इसे प्रदेश की जनसंख्या में कृषि कार्य में रत व्यक्तियों के प्रतिशत से निम्न प्रतिशत में मन्त्रिपरिषदों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उजागर हो रहा है कि मन्त्रिपरिषदों में कृषि के अलावा सर्वाधिक वकालत, अध्यापन तथा व्यापार एवं उद्योग, व्यवसाय वर्ग से आने वाले सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक मन्त्रिपरिषद में लगभग दो तिहाई या उससे अधिक इन्हीं व्यवसाय वर्ग से आने वाले सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभाओं में भी इन्हीं अर्थात् कृषि, वकालत, व्यापार एवं उद्योग तथा अध्यापन क्षेत्र से आने वाले सदस्यों की प्रमुखता रही है तथा विधान सभा में लगभग दो तिहाई प्रतिनिधित्व इन्हीं व्यवसाय वर्ग के लोगों का रहा है।

अध्ययन के माध्यम से यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि मन्त्रिपरिषदों में तकनीकी क्षेत्र से अर्थात् चिकित्सा, इंजीनियरिंग क्षेत्रों के कार्यरत सदस्यों को मन्त्रिपरिषदों में अत्यन्त अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है तथा कई मन्त्रिपरिषदों में इन्हें कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका है। लेकिन अध्ययन में यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है कि तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत सदस्यों का निर्वाचित होकर विधान सभा में आने का प्रतिशत अत्यन्त अल्प रहा है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की प्रदेश की सक्रिय राजनीति में सहभागिता के प्रति रुचि का अभाव रहा है। यहाँ यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जो सदस्य इस व्यवसाय से चुन कर विधान सभा में आये हैं, उनका मन्त्रिपरिषद में सम्मिलित होने की अनुपात की दर काफी उच्च रही है, अध्ययन के माध्यम से यह तथ्य भी प्रकाश में आ रहा है कि सेवा निवृत्त अधिकारी, राजनीतिक एवम् सामाजिक कार्य तथा लेखन एवं पत्रकारिता में सलग्न व्यक्तियों में जो विधान सभा के लिए निर्वाचित होते हैं उनमें मन्त्रिपरिषद में सम्मिलित होने की सम्भावना सर्वाधिक होती है।

अध्ययन के आधार पर यह तथ्य भी सामने आता है कि 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वह इसी दौरान कार्यरत विधानसभा में विभिन्न व्यवसाय वर्ग

के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से भिन्न है अर्थात् विधान सभा में व्यवसाय वर्ग के प्रतिनिधित्व का समान चित्र कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद में प्रस्तुत नहीं किया गया। किन्तु इसके पश्चात् मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि उस समय विधान सभा में विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को जिस अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है लगभग उसी अनुपात का अनुसरण मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद में करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार का प्रयास 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद में भी किया गया। किन्तु मायावती के इस मन्त्रिपरिषद के विषय में यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग के साथ तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों को कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया।

इसी क्रम 1997 में मायावती के नेतृत्व में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद के विषय में अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के अनुपात का अनुसरण मायावती के मन्त्रिपरिषद में नहीं किया गया। साथ ही इस मन्त्रिपरिषद में तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट उजागर हो रहा है कि मायावती अर्थात् बसपा के नेतृत्व में जब-जब मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों की अवहेलना की गयी। 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के विषय में यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यों को विधान सभा में जिस अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लगभग उसी का अनुसरण मन्त्रिपरिषद में करने का प्रयास किया गया है या प्रदान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस काल में मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का शैक्षिक पृष्ठ भूमि अत्यन्त उत्साहवर्धक है। अतः यह लोकतंत्र को सशक्त सम्बन्ध प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा का जेतना उन्नत स्तर मन्त्रियों का है सदन में उनके आचरण और सम्भाषण में भी वही

षष्ठम् अध्याय

मंत्रिपरिषद् में स्त्री-पुरुष का प्रतिनिधित्व

मंत्रिपरिषद् में स्त्री - पुरुष का प्रतिनिधित्व)

स्वतंत्र भारत में सविधान निर्माताओं ने जब पुरुष और नारी को समान अधिकार प्रदान किए तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए ¹ सविधान में समुचित व्यवस्था ² की तो उनका यह कदम क्रान्तिकारी माना गया।³ यह क्रान्तिकारी इसलिए था कि प्रथम तो, इसने भारतवर्ष को न केवल अन्य विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा किया वरन् कुछ दिशाओं में विकसित राष्ट्रों को भी पीछे ढकेल दिया तथा दूसरे, यह प्रचलित भारतीय परम्पराओं, जितने नारी की स्थिति पुरुष की अपेक्षा अत्यन्त हीन मानी गयी है, से सर्वथा भिन्न था।

जहां तक अन्य राष्ट्रों का सम्बन्ध है ब्रिटेन, फ्रान्स तथा स्विटजरलैण्ड विश्व के उन कुछ गिने चुने राष्ट्रों में से हैं-जिनकी राजनीतिक व्यवस्था अत्यन्त विकसित तथा प्रगतिशील मानी जाती है किन्तु फिर भी ब्रिटेन में सन् 1958 से पूर्व महिलाओं को लार्ड सभा की सदस्यता से वंचित रखा गया था, फ्रान्स में चतुर्थ गणतन्त्र से पूर्व महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था स्विटजरलैण्ड में सन् 1971 से पूर्व महिलाओं को राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस दृष्टि से भारतीय सविधान सभा का निर्णय निश्चित ही प्रगतिशील एवं क्रान्तिकारी कहा जाना चाहिए।

जहां तक भारतीय परम्पराओं का सम्बन्ध है यह सत्य है कि स्वतन्त्रता से पूर्व महिलाओं

1 भारतीय सविधान, अनुच्छेद 14, 15, 16

2 वही, अनुच्छेद 32 एवं 226

3 स्टेट्स ऑफ वूमेन इन इण्डिया (सिनोपासिस आफ द रिपोर्ट द नेशनल कमेटी आन द स्टेट्स आफ ओमन (1971-74) इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल साइंस एण्ड रिसर्च ,

की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त दुर्बल थी। प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं को कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन दिनों तो पुरुषों को भी आज की भाँति स्वतन्त्र राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, अतः स्त्रियों की स्वतन्त्र राजनीतिक स्थिति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन दिनों राजनैतिक अधिकार केवल शासकों को प्राप्त थे और शासक अधिकांशमें पुरुष ही होते थे। महिला शासकों का दृष्टान्त केवल दो प्रदेशों, कश्मीर एवं लका में मिलते हैं। कश्मीर की सुगन्धा एवं दिद्धा तथा लका की लालवती ऐसी विधवा रानिया थी जो अपने पतियों के निधन के उपरान्त सत्तारूढ़ हुई। तत्कालीन अज्ञान राजनीतिक स्थिति के ही कारण शासन-कार्य का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ। महावंश में तीन और रानियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने लका में शासन किया था और उनके नाम हैं-अनुला, शिवाली और कल्याणवती। कश्मीर के शासक अनन्त की पत्नी सूर्यमती का भी उल्लेख मिलता है जिसने अपने पति के साथ संयुक्त रूप से कश्मीर का शासन किया था।⁴

मध्य काल में दिल्ली की रजिया सुल्ताना, बीजापुर की चादबीबी और आधुनिक काल में भावणकोर की गौरी लक्ष्मी बाई तथा गौरी पार्वती बाई का भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में शासन-कार्य सम्पादित किया।⁵

भोपाल तो लगभग एक शताब्दी तक महिला-शासकों द्वारा शासित होता रहा। भोपाल की प्रमुख शासिका थी- नवाब कुदसिया बेगम, नवाब सुल्ताना जहा बेगम, नवाब सिकन्दर तथा नवाब शाहजहाँ बेगम।⁶

जहाँ तक साधारण महिलाओं का सम्बन्ध है उनके राजनैतिक उत्थान का आरम्भ होता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, जिसने अपने प्रारम्भिक काल से ही महिलाओं को कांग्रेस संगठन के चुनावों में मतदान करने, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में **प्रत्याशि** (डेलीगेट्स)

4 इन्दिरा - 'द स्टेट्स आफ ओमन', लाहौर 1904 पृ० 174-175

5 सेनगुप्ता, पद्मिनी 'द स्टोरी आफ ओमन आफ इण्डिया', नई दिल्ली, पृ० 132, 133, 134, 173, 175

6 वही, पृ० 177

बनने तथा कांग्रेस मंच से भाषण करने का अधिकार प्रदान किया और 1917 में एक महिला को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया।⁷

शासकीय सगठनों में सन् 1914-15 में भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी की नगरपालिकाओं के चुनावों में मतदान का अधिकार दिया गया, किन्तु यह इतनी कम महिलाओं को प्राप्त हुआ कि इसका महिलाओं की चेतना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और जब कुछ ही समय बाद इसे समाप्त कर दिया गया तो इसके विरुद्ध कोई आवाज भी नहीं उठायी गई।

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में एक नये मोड़ का आरम्भ होता है सन् 1917 से जब श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने तत्कालीन भारत-मन्त्री माण्टेग्यु के समक्ष एक स्मृति-पत्र रखा⁸ जिसमें अन्य बातों के साथ यह माग भी रखी गयी कि महिलाओं के साथ, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाय और उन्हें वे समस्त अधिकार प्रदान किये जायें जो पुरुषों को प्राप्त हों।⁹ किन्तु माण्टेग्यु ने इस माग को अस्वीकर कर दिया और सन् 1918 में मताधिकार से सम्बन्धित सिफारिशें देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त (साउथ वरो) समिति ने भी माण्टेग्यु के इस विचार से सहमति व्यक्त की थी।¹⁰ परिणामस्वरूप सन् 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका किन्तु माण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि नव निर्वाचित विधानमण्डल चाहे तो महिलाओं को मताधिकार दे सकते हैं। इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम मद्रास ने 1921 में प्रान्तीय विधान परिषद के निर्वाचन में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया।¹¹ कालांतर में अन्य प्रांतों में एक के

7 मेनन एल एन पालिटिकल राइट आफ ओमन इन इण्डिया में से उद्धृत अप्पादोरई ८० (सम्पा०)

द स्टेटस आफ ओमन इन साउथ एशिया, कलकत्ता, 1954 पृ० 86

8 वेग टी० ए० (सम्पा०) - ओमन आफ इण्डिया, दिल्ली 1956 पृ० 35

9 मेनन एल० एन०, वही से उद्धृत पृ० 86

10 कृष्णस्वामी बी सोशल चेंज इन इण्डिया. दिल्ली (1972) पृ० 192

11 मेनन एल० एन०, वही से उद्धृत पृ० 86

बाद एक, मताधिकार दिया जाने लगा। सन् 1926 तक भारत के सभी प्रान्तों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया।¹² किन्तु मताधिकार सम्बन्धित शर्तें (सम्पत्ति तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएँ) इतनी कड़ी थीं कि सन् 1921 से 1933 के बीच जहाँ एक ओर 6,80,00,000 पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, वहीं दूसरी ओर इस अवधि में केवल 3,15,651 महिलाओं को ही मताधिकार प्राप्त था।¹³ जब सन् 1932 में मताधिकार से सम्बन्धित लोथियन कमेटी भारत आई तो भारतीय महिलाएँ इतनी सगठित हो चुकी थीं कि उनकी मांगों की सर्वथा उद्देक्षा सम्भव नहीं थी। परिणामस्वरूप महिलाओं के मताधिकार से सम्बन्धित व्यवस्था में कुछ ढिलाई की गई। अब महिलाओं को पत्नीत्व के आधार पर मताधिकार प्राप्त हो गया तथा उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता में भी कमी कर दी गयी।¹⁴

इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय प्रान्तों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 60,00,000 हो गई किन्तु फिर भी स्त्री और पुरुष मतदाताओं का अनुपात 1:5 का बना रहा।¹⁵

जहाँ तक ईम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली एवं कौंसिल आफ स्टेट का सम्बन्ध है उन प्रान्तों को जिनमें महिलाओं को मताधिकार प्रदान कर दिया गया, अनुमति दे दी गई कि वे उक्त दोनों सदनों के निर्वाचन के लिए महिलाओं को मताधिकार प्रदान कर सकते हैं। सर्वप्रथम सन् 1923 में महिलाओं ने इससे लाभ उठाया।¹⁶

सन् 1923 में भारत सरकार ने एक प्रगतिशील कदम और उठाया। उसने महिलाओं को प्रान्तीय विधान परिषदों की सदस्यता की अनुमति दे दी।¹⁷

12 मेनन एल0 एन0, वही से उद्धृत पृ0 86

13 मेनन एल0 एन0, वही से उद्धृत पृ0 86

14 मेनन एल0 एन0, वही से उद्धृत पृ0 86

15 कोवेकर एस वी द रोल आफ ओमन इन द जनरल इलेक्शन इन इण्डिया (1951-52) इन अप्पादोरई

ए0 (संपा0) द स्टेटस आफ ओमन इन साउथ एशिया, कलकत्ता, 1954, पृ0 104

16 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0 577

17 वेग टी0 ए0 (संपा0) वही से उद्धृत पृ0 92

मद्रास पहला प्रान्त था जिसकी विधान परिषद में महिलाएँ सर्वप्रथम प्रवेश पा सकी।¹⁸ महिलाएँ विधानमण्डल में एक निश्चित अनुपात में निर्वाचित हो सके इसके लिए कालान्तर में विधानमण्डलो में उनके लिए कुछ सीटें भी सुरक्षित रख दी गयीं।¹⁹ परणामस्वरूप सन् 1933 से 1936 के बीच तीन प्रान्तो-मध्य प्रान्त, सयुक्त प्रान्त तथा मद्रास की विधान परिषदों में, प्रत्येक में, एक-एक महिला को सदस्यता का अवसर प्राप्त हुआ।²⁰

सन् 1937 के निर्वाचन में 8 महिलाएं साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से एवं 42 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से विभिन्न प्रान्तीय विधान सभाओं में निर्वाचित हुयीं। 5 महिलाओं को विधान मण्डल के द्वितीय सदन में नामांकित भी किया गया।²¹ दो महिलाएं-श्रीमती अनुसूया बाई काले तथा श्रीमती सिफाई मलानी क्रमशः मध्य प्रान्त एवं सिन्ध विधानसभाओं की उपाध्यक्ष भी चुनी गयीं।²² श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति एवं श्रीमती ज्योति वेकटाचलम् मद्रास में,²³ श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित सयुक्त प्रान्त में²⁴ मन्त्रीपद पर भी नियुक्त की गयीं। श्रीमती जहाआरा शाहनवाज पंजाब में पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी नियुक्त हुई।²⁵

जहाँ तक केन्द्रीय विधान मण्डल का सम्बन्ध है, सन् 1936 से 42 के बीच 1 और 1943 में 2 महिलाएं केन्द्रीय विधान सभा की सदस्याएँ रही।²⁶

18 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0 577

19 मेनन एल0 एन0, वहीं से उद्धृत प0 86

20 मित्रा द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वॉल्यूम 1 आफ 1933, 1935 और 1936

21 मेनन एल0 एन0, वहीं से उद्धृत पृ0 86-87

22 वेग टी0 ए0 (सपा0) वहीं से उद्धृत पृ0 98

23 वेग टी0 ए0 (सपा0) वहीं से उद्धृत पृ0 92

24 मित्रा द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वॉल्यूम 1 आफ 1938, पृ0 178

25 मित्रा द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वॉल्यूम 1 आफ 1938, पृ0 234

26 मित्रा द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वॉल्यूम 1 आफ 1939, पृ0 40-41 और 42

भारत की विभिन्न देशी रियासतों में भावणकोर पहली रियासत थी जिसने सन् 1920 के अन्तिम चरण में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया और इसके तत्काल बाद झालावाड़ ने भी इसका अनुगमन किया।²⁷ इतना ही नहीं, सन् 1926 तक भारत की तीन रियासतों भावणकोर, कोचीन एवं राजकोट में लिंग के आधार पर भेदभाव को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। वहाँ न केवल महिलाओं को विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, वरन् दो महिलाएँ राजकोट की नवगठित प्रतिनिधि परिषद् की सदस्यएँ निर्वाचित हुईं। एक महिला श्रीमती पूनम लुखोज तो सन् 1925 में कोचीन रियासत में स्वास्थ्य मन्त्री पद पर नियुक्त भी हुईं।²⁸

जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है सन् 1923 में संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद ने सर्वानुमति से यह प्रस्ताव पास किया कि महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाय।²⁹ सन् 1926 से 1936 के बीच संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद् में सदैव 1 महिला सदस्यएँ बनीं रहीं।³⁰ सन् 1937 के निर्वाचन में 11 महिलाएँ विधानसभा के लिये निर्वाचित हुईं तथा 3 महिलाएँ विधानपरिषद् की सदस्यएँ बनीं।³¹

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भूमिका बनी रही है। केवल मताधिकार एवं निर्वाचन में ही महिलाओं ने भाग नहीं लिया। वरन् विभिन्न राजनीतिक एवं शासन के पदों पर भी महिलाओं ने आसीन होकर सक्रिय योगदान दिया है। श्रीमती गांधी भारत की वह प्रतिभाशाली महिला थी जो लगभग 16 वर्षों तक प्रधान मन्त्री पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू के रूप में प्रदेश को एक प्रतिभाशाली मुख्यमन्त्री मिला।

रंग, जाति, धर्म भाषा के समान ही लिंग के भेद-भाव को अस्वीकार कर महिलाओं को

27 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0576

28 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0577

29 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0576

30 वेद इण्डियन इयर बुक और इण्डियन एनुअल रजिस्टर फार दीज इयर

31 मित्रा: द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वॉल्यूम 1 आफ 1938, पृ0 177-180

पुरुषों के समान अवसर की समानता का अधिकार उपलब्ध है। यद्यपि स्त्रियों के पुरुषों के समान अधिकार, अवसर की समानता तथा सैद्धान्तिक रूप में स्त्री-पुरुष समानता है तथापि यह सत्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय समाज व्यवहार में पुरुष प्रधान समाज है। सामाजिक रीतियाँ, परम्पराएँ, धर्म, निर्धनता एवं अशिक्षा आदि महिलाओं के शोषण एवं महिलाओं पर पुरुषों की प्रधानता स्थापित करने में सहायक हुई है तथा कानून द्वारा उपलब्ध समानता ही यदा-कदा महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने में सहायक रही है। अधिकशत केवल अभिजन वर्ग की महिलाओं को ही पुरुषों के समान स्वतन्त्रता को भोगने के अवसर मिले हैं।

प्रदेश में विद्यमान वर्तमान राजनीतिक परिवेश में सामान्य महिलाओं की पुरुषों के समकक्ष भागीदारी की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। दिन-प्रतिदिन मूल्यविहीन राजनीति के प्रसार में महिलाओं का पुरुषों के समान सक्रिय होकर पुरुषों के बराबर भागीदारी प्राप्त कर पाना अभी प्रश्नचिन्हित ही है।

मई-जून 1991 में एकादश विधान सभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 24-6-91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथमवार गठित तथा दिनांक 6-12-92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद् में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 1 में दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-6 1

सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्

क्र० सं०	लिंग	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
१	पुरुष	408	97.6	54	96.4	13.2
२	स्त्री	10	2.4	2*	3.6	20
योग		418	100	56	100	13.4

* कल्याण सिंह के इस मन्त्रिपरिषद् में दो महिला सदस्य श्रीमती प्रेमलता कटियार कैबिनेट मंत्री तथा श्रीमती शारदा चौहान राज्य मंत्री थीं।

सारिणी सख्या 6 1 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 24-6-91 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित तथा 6-12-92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद् में कुल 56 सदस्य थे, जिसमें 54 पुरुष तथा 2 स्त्री सदस्य थी, इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् में उनका प्रतिनिधि प्रतिशत क्रमशः पुरुषों का 96.47 प्रतिशत तथा स्त्रियों का 3.6 प्रतिशत रहा। जबकि विधानसभा में 418 सदस्यों में 408 पुरुष तथा 10 स्त्री सदस्य थीं। इनका प्रतिशत क्रमशः पुरुष 97.6 प्रतिशत तथा स्त्री 2.4 प्रतिशत रहा।

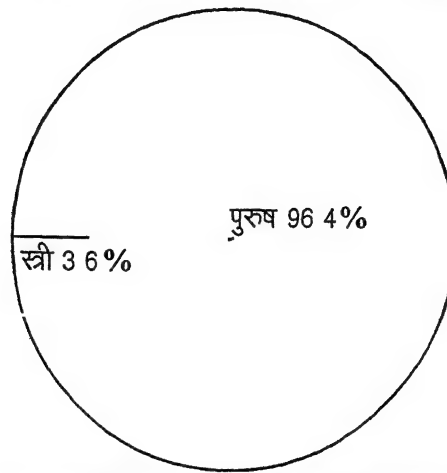
यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा की कुल 10 महिला सदस्यों में से 2 को मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित किया गया जो विधान सभा में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर 20 प्रतिशत रहा। इस प्रकार यह विधान सभा के पुरुष सदस्यों के मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के प्रतिशत 13.2 से उच्च रहा।

इस प्रकार सारिणी सख्या 6 1 के सम्पूर्ण तथ्यों के प्रकाश में यहां कहा जा सकता है कि इस काल में यद्यपि मन्त्रिपरिषद् एवम् विधान सभा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा है तथापि विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों को थोड़ा अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, किन्तु यह अन्तर भी नाम मात्र का है। यहाँ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि विधानसभा में से मन्त्रिपरिषद् में आने की सम्भावना पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिक है। कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित इस मन्त्रिपरिषद् में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 6 1 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र सं० 6 1 (ब) में दर्शाया गया है।

नवम्बर 1993 में द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनावों के परिणामस्वरूप दिनांक 4-12-93 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद् में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 2 में दर्शाया गया है।

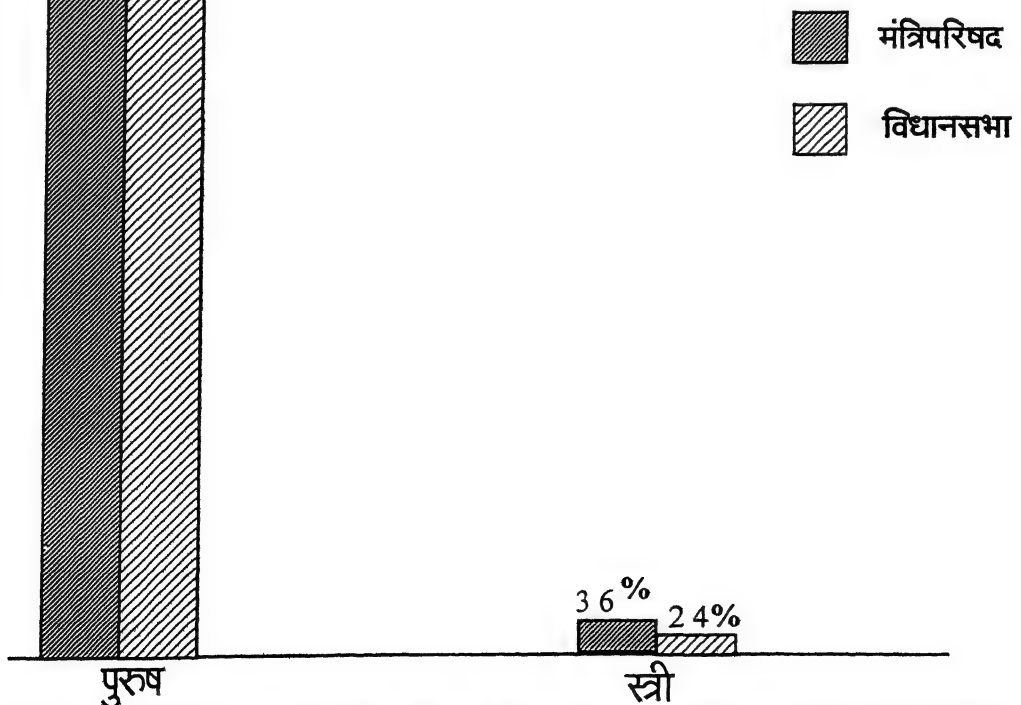
सारिणी सख्या 6 2 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 4-12-93 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित तथा 3-6-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद् में कुल

रेखा चित्र संख्या-6.1 (अ)



96.4% 96.4% सन 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या-6.1.(ब)



सन 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या-6.2

सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद्

क्र० सं०	लिंग	विधानसभा		मंत्रिपरिषद्		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मंत्रिपरिषद् प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	पुरुष	412	96.7	28	100	6.8
2	स्त्री	14	3.3	0	0	-----
योग		426	100	28	100	10.6

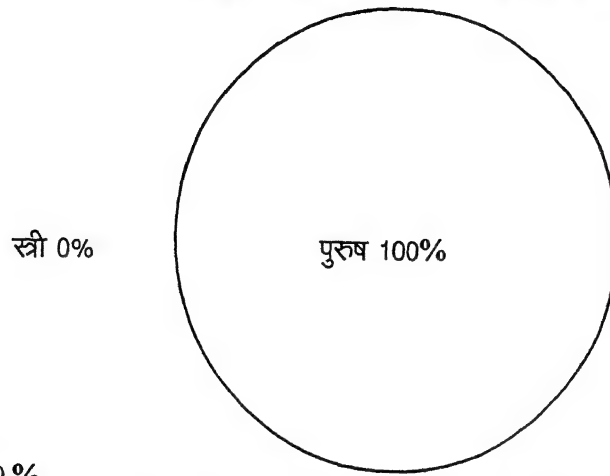
28 सदस्य थे जो सभी पुरुष थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुलायम सिंह यादव के इस मंत्रिपरिषद् में किसी स्त्री सदस्या को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया जबकि विधान सभा के 426 सदस्यों में से 412 पुरुष तथा 14 स्त्रियाँ थी, इस प्रकार विधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः पुरुष 96.7 प्रतिशत तथा स्त्री 3.3 प्रतिशत रहा।

सारिणी सख्या 6.2 के सम्पूर्ण तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि इस काल में जहाँ विधान सभा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा वहीं मंत्रिपरिषद् में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। मुलायम सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सं 6.2 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र सं 6.2 (ब) दर्शाये गया है।

मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद् के पतन के पश्चात् दिनांक 3-6-1995 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 18-10-95 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद् में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6.3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 6.3 के अन्तर्विष्ट आकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 3-6-95 को

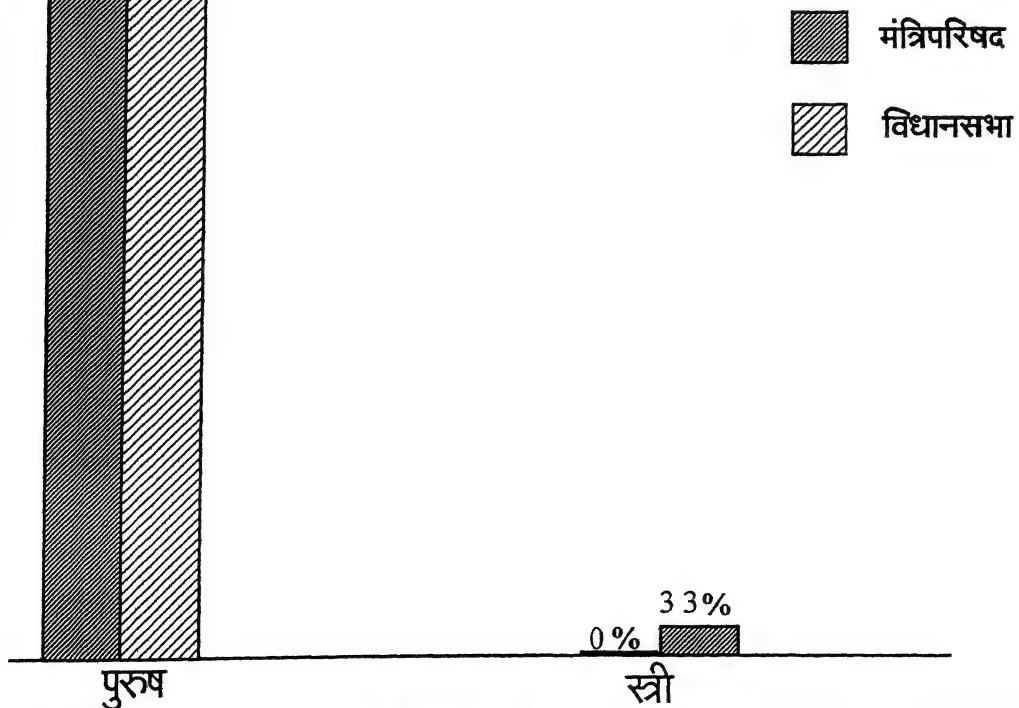
रेखा चित्र संख्या -6.2 (अ)



100 %

96.7 % सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या-6.2.(ब)



सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

मायावती के नेतृत्व में गठित तथा 8-10-95 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद् में कुल 33 सदस्य थे, जिसमें 31 पुरुष तथा 2 स्त्री सदस्या थी, इस प्रकार मंत्रिपरिषद् में इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः पुरुष का 93.9 प्रतिशत था स्त्रियों का 6.1 प्रतिशत रहा। जबकि इस काल में विधान सभा के 426 सदस्या

सारिणी सख्या - 6.3

सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद्

क्र.सं.	लिंग	विधानसभा		मंत्रिपरिषद्		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मंत्रिपरिषद् प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
पुरुष	पुरुष	412	96.7	31	93.9	7.5
स्त्री	स्त्री	14	3.3	2 ^{*1}	6.1	14.3
कुल		426 ^{*2}	100	33	100	7.7

*¹ मंत्रिपरिषद् में स्त्री सदस्या मुख्यमंत्री मायावती व सुशीला सरोज चौहान राज्यमंत्री रहीं।

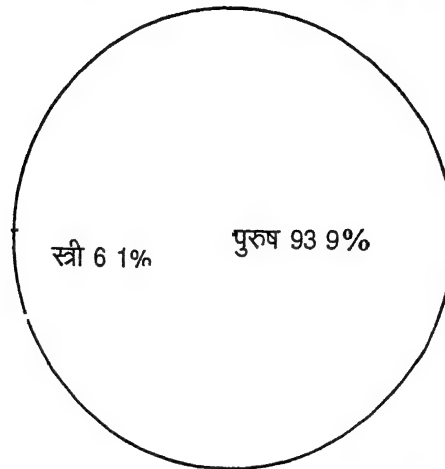
*² विधानसभा में 426 सदस्यों का आकड़ा है इसमें मृत सदस्य के साथ उपचुनाव में विजयी सदस्य को शामिल किया गया है जिससे यह विधान सभा के कुल सदस्य सख्या 425 से अधिक हो गया है।

में 412 पुरुष तथा 14 स्त्रियां थी, इनका प्रतिशत क्रमशः पुरुष 96.7 प्रतिशत तथा स्त्री 3.3 प्रतिशत रहा।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा की कुल 14 महिला सदस्यों में से 2 को मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित किया गया, जो विधान सभा में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर 14.3 रहा, इस प्रकार यह विधान सभा के पुरुष सदस्यों के मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के प्रतिशत 7.5 से लगभग दुगना रहा।

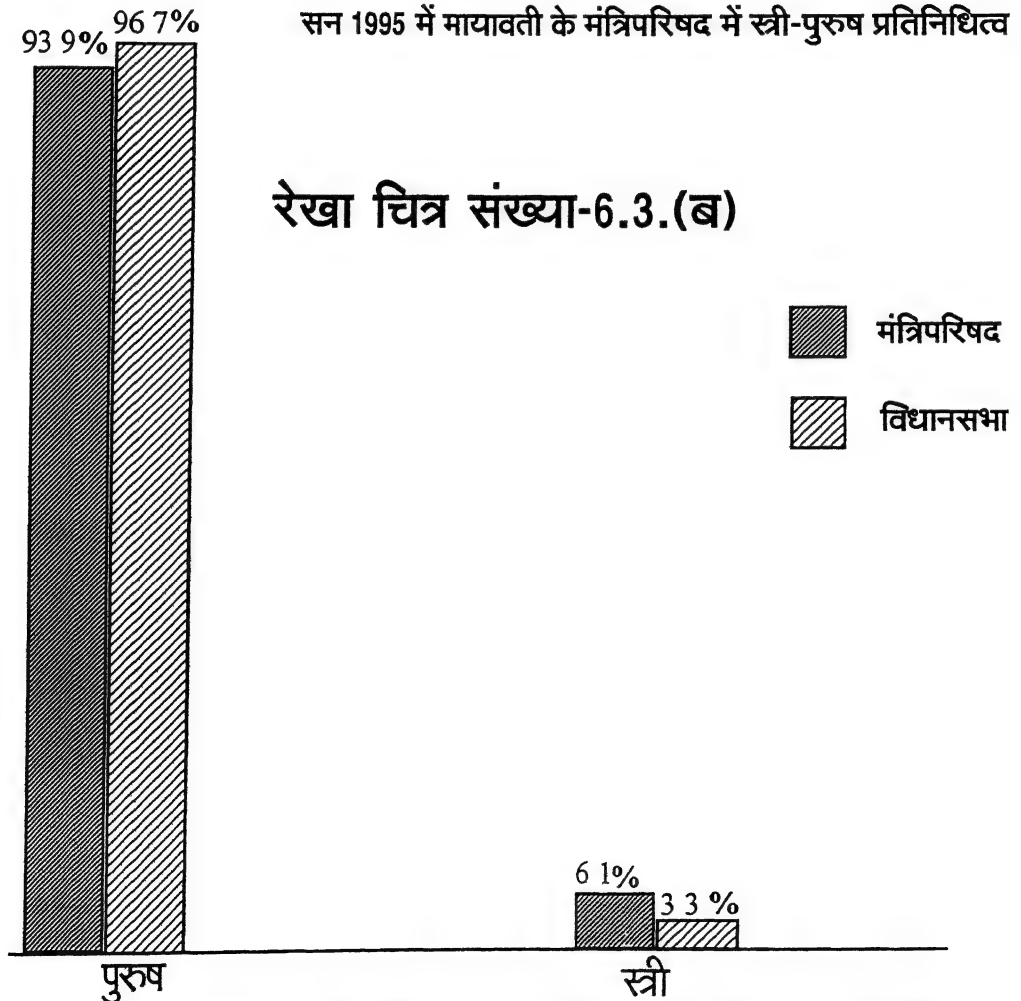
इस प्रकार सारिणी सख्या 6.3 के सम्पूर्ण तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि

रेखा चित्र संख्या -6.3 (अ)



सन 1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या-6.3.(ब)



सन 1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

इस काल में मंत्रिपरिषद् एवं विधान सभा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा, किन्तु विधान सभा की तुलना में मंत्रिपरिषद् में स्त्रियों को लगभग दो गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, फिर भी यह मात्र 6.1 प्रतिशत ही रहा, यहाँ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि विधान सभा से मंत्रिपरिषद् में आने की सम्भावना पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिक रही। मायावती के इस मंत्रिपरिषद् में स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स० 6.3 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र स० 6.3 (ब) में दर्शाया गया है।

सितम्बर-अक्टूबर 1996 में त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा दिनांक 21-9-97 तक कार्यरत भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मंत्रिपरिषद् में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6.4 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 6.4

सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद्

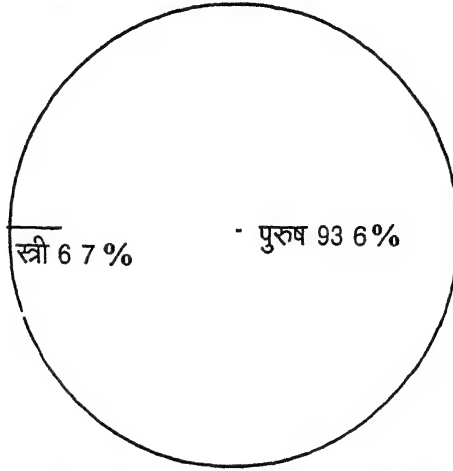
क्र० सं०	लिंग	विधानसभा		मंत्रिपरिषद्		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मंत्रिपरिषद् प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	पुरुष	407	95.5	42	93.3	10.3
2	स्त्री	19	4.5	3* ¹	6.7	15.8
योग		426* ²	100	45	100	10.6

*¹ मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री मायावती, प्रभा द्विवेदी कैबिनेट मंत्री तथा राजराय सिंह राज्य मंत्री के रूप में स्त्री सदस्य थी।

*² विधानसभा में 426 सदस्यों का आकड़ा है इसमें मृत सदस्य के साथ उपचुनाव में विजयी सदस्य को शामिल

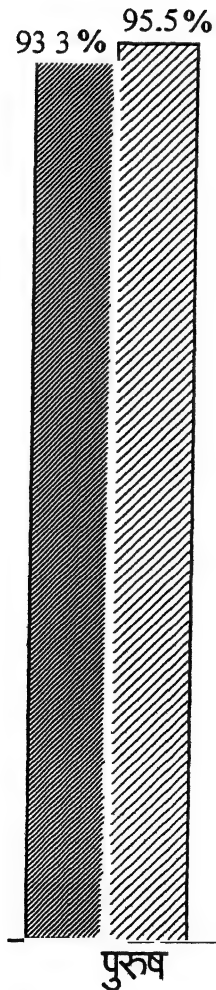
किया गया है जिससे यह विधान सभा के कुल सदस्य सख्या 425 से अधिक हो गया है।

रेखा चित्र संख्या -6.4 (अ)



सन 1997 में मायावती के मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या -6.4.(ब)



मंत्रिपरिषद



विधानसभा

सन 1997 में मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या 6 4 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व में गठित तथा 21-9-97 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद् में कुल 45 सदस्य थे, जिनमें 42 पुरुष तथा 3 स्त्री सदस्य थीं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद् इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः पुरुषों का 93.3 प्रतिशत तथा स्त्रियों का 6.7 प्रतिशत रहा। जबकि इस कार्यरत विधान सभा के 426 सदस्यों में 407 पुरुष तथा 19 स्त्री सदस्य थीं, इनका प्रतिशत क्रमशः पुरुष 95.5 प्रतिशत तथा स्त्री 4.5 प्रतिशत रहा।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा की 19 महिला सदस्यों में से 3 को मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित किया गया, जो विधान सभा में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर 15.8 प्रतिशत रहा, इस प्रकार यह विधान सभा के पुरुष सदस्यों के मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के प्रतिशत 10।3 से उच्च रहा।

इस प्रकार सारिणी सख्या 6 4 के सन्दर्भ तथ्यों के प्रकार ने यह कहा जा सकता है कि इस काल में मंत्रिपरिषद् एवं विधान सभा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा, किन्तु विधान सभा की तुलना में मंत्रिपरिषद् में स्त्रियों को थोड़ा अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, फिर भी यह आंकड़ा 6.7 प्रतिशत ही तक पहुँच पाया यहाँ यह तथ्य ध्यान योग्य है कि विधान सभा से मंत्रिपरिषद् में आने की सम्भावना पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिक है। मायावती के (1997) इस मंत्रिपरिषद् में स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सं० 6 4 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र सं० 6 4 (ब) में दर्शाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के संविदा के परिणाम स्वरूप छ महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री मायावती द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनांक 21-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् ने 31 दिसम्बर 1997 तक स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 5 में दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 6 5 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 29-9-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में दिनांक 31-12-97 तक कुल 113 सदस्यों को सम्मिलित

सारिणी संख्या -6.5

सन् 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद्

क्र० सं०	लिंग	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद्		विधानसभा में सदस्यों के आधार पर मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	पुरुष	407	95.5	109	96.5	26.8
2	स्त्री	19	4.5	4* ¹	3.5	21
योग		426* ²	100	113	100	26.5

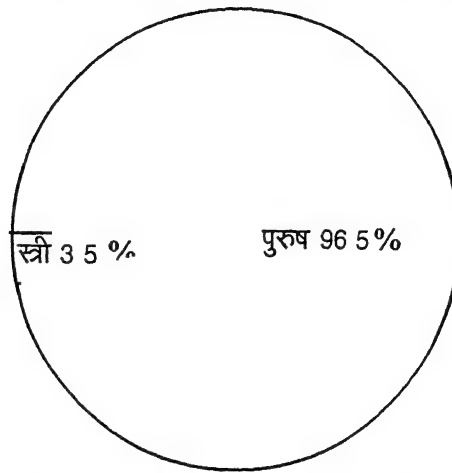
*¹ मन्त्रिपरिषद् में चार महिला सदस्य-प्रेमलता कटियार, व प्रभा द्विवेदी कैबिनेट मंत्री तथा मुल्क देवे व राजराय सिंह राज्य मंत्री थीं।

*² विधानसभा में 426 सदस्यों का आँकड़ा है इसमें मृत सदस्य के साथ उपचुनाव में विजयी सदस्य को शामिल किया गया है जिससे यह विधान सभा के कुल सदस्य संख्या 425 से अधिक हो गया है।

किया गया (कल्याण सिंह सहित) जिसमें 109 पुरुष तथा 4 स्त्री सदस्य थीं, इस मन्त्रिपरिषद् में इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः पुरुषों का 96.5 प्रतिशत तथा स्त्रियों का 3.5 प्रतिशत रहा। जबकि इस समय कार्यरत विधान सभा के 426 सदस्यों में 407 पुरुष तथा 19 स्त्री सदस्य थीं, इनका प्रतिशत क्रमशः पुरुष 95.5 प्रतिशत तथा स्त्री 4.5 प्रतिशत रहा।

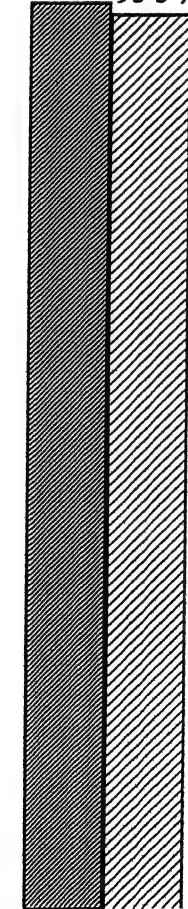
इसके साथ ही विधान सभा की 19 महिला सदस्यों में से 4 को मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित किया गया जो विधान सभा में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर 21 प्रतिशत रहा, जबकि विधान सभा के 407 पुरुष सदस्यों में 109 को मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित किया गया जो विधान सभा के पुरुष सदस्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर 26.8 प्रतिशत रहा। इस प्रकार शोधकाल खण्ड 1991 में सन् 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद् में यह ही एक ऐसी मन्त्रिपरिषद् थी जिसमें विधान सभा

रेखा चित्र संख्या-6.5 (अ)



सन 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

96.5% 95.5%



पुरुष

स्त्री

रेखा चित्र संख्या-6.5.(ब)



मंत्रिपरिषद



विधानसभा

सन 1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

से मन्त्रिपरिषद् में आने की सम्भावना स्त्री की तुलना में पुरुष की अधिक रही।

इस प्रकार सारिणी सख्या 6 5 के सम्पूर्ण तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद् एवं विधान सभा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा और इनकी स्थिति विधान सभा की तुलना में मन्त्रिपरिषद् में और दयनीय हो जाती है। कल्याण सिंह के इस मन्त्रिपरिषद् में स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स0 6 5 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र स0 6 5 (ब) में दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में स्त्री-पुरुष अनुपात के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 6 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 6 6 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। स्त्रियों की सर्वाधिक भागीदारी सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीयवार गठित मन्त्रिपरिषद् में 6 7 प्रतिशत रही। जबकि पुरुषों का प्रभुत्व इस काल के सभी मन्त्रिपरिषद् में बना रहा तथा मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में तो सभी सदस्य पुरुष ही थे।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व पर एक-एक कर दृष्टि डाले तो सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में कुल 56 सदस्यों में 54 पुरुष तथा 2 स्त्रियाँ थीं। इस प्रकार इनका प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुरुष 96 4 प्रतिशत तथा स्त्री 3 6 प्रतिशत रहा। तदुपश्चात् सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में कुल 28 सदस्य थे और सभी पुरुष थे इस प्रकार इस मन्त्रिपरिषद् में पुरुषों को 100 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि स्त्रियों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका। तदुपरान्त सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में कुल 33 सदस्य थे जिसमें 31 पुरुष तथा 2 स्त्रियाँ थीं। इस प्रकार इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत पुरुष 93 9 प्रतिशत तथा स्त्री 6 1 प्रतिशत रहा। मायावती के सन् 1995 के मन्त्रिपरिषद् के बाद सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीयवार गठित मन्त्रिपरिषद् में कुल 45 सदस्यों में 42 पुरुष तथा 3 स्त्रियाँ थीं। इस प्रकार इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत

सारिणी संख्या-6.6

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्री परिषद : स्त्री - पुरुष

मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व													
क्र० स०	लिंग	कल्याण सिंह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिंह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिंह द्वितीय 21-09-97 से -----तक		समग्र 1991 से 1997 तक	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	54	94.4	28	100	31	93.9	42	93.3	109	96.5	246	96
2	स्त्री	2	3.6	0	0	2	6.1	3	6.7	4	3.5	11	4
योग		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

पुरुष 93 प्रतिशत तथा स्त्री 67 प्रतिशत रहा। अन्ततः 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीयवार गठित मन्त्रिपरिषद् में 31 दिसम्बर 1997 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए जिसमें 109 पुरुष तथा 4 स्त्रियाँ थी। संख्या की दृष्टि से अन्य मन्त्रिपरिषदों की तुलना में इस मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। किन्तु मन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या 113 के सापेक्ष देखे तो स्त्रियों का यह प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प था। यदि कल्याण सिंह की द्वितीय मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्रतिशत पर दृष्टि डाले तो पुरुषों की 96.5 प्रतिशत की तुलना में स्त्रियों को 3.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व ही प्राप्त हो सका।

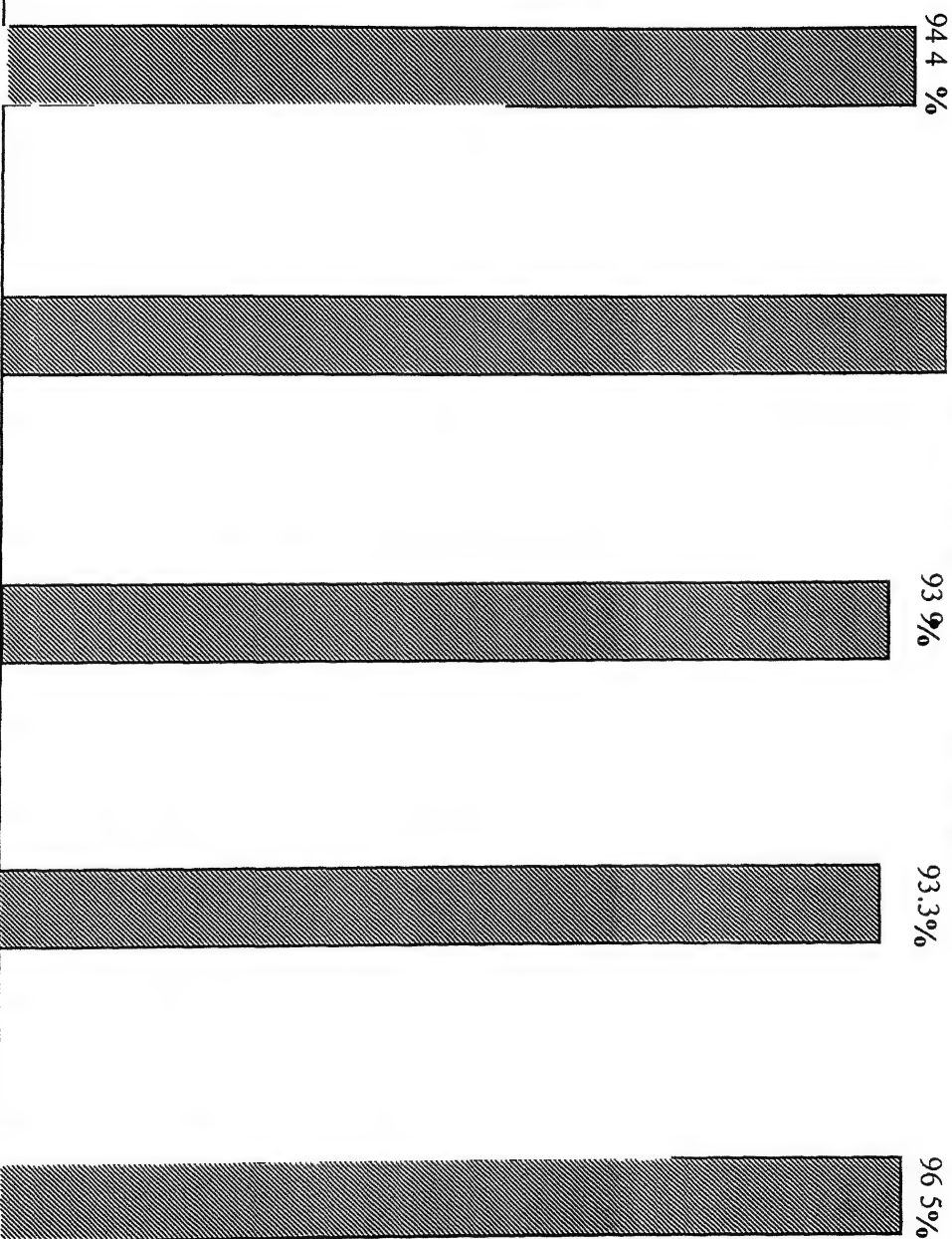
अतः सारिणी संख्या 6.6 के सम्पूर्ण आँकड़ों के प्रकाश में जो तथ्य उजागर हो रहा, उसमें प्रथम तो यह है कि इस काल में मन्त्रिपरिषदों में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व में काफी विषमता रही तथा समाज की लगभग 50 फीसदी भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्रियाँ मन्त्रिपरिषद् में कमी की 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर पायीं। इस काल में मन्त्रिपरिषदों में स्त्रियों की सबसे अधिक भागेदारी मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में प्राप्त हुई। फिर भी यह 6 से 7 प्रतिशत के बीच ही रहा।

यदि शोध काल खण्ड 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदों में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व पर समग्र रूप से दृष्टि डाले तो इस काल में 275 सदस्य मन्त्रिपरिषदों में सम्मिलित हुए जिसमें 264 पुरुष तथा 11 स्त्रियाँ थी। इस प्रकार इनका प्रतिशत क्रमशः पुरुष 96 प्रतिशत तथा स्त्री 4 प्रतिशत रहा। इस काल खण्ड में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स० 6.6 (अ) तथा पुरुषों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स० 6.6 (ब) में दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य विधान सभा व मन्त्रिपरिषदों में स्त्री-पुरुष अनुपात का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। यह सारिणी संख्या 6.7 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 6.7 के अन्तर्विष्ट आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस काल में विधान सभाओं में लगातार स्त्रियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, जबकि इस काल में गठित मन्त्रिपरिषदों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा है और यह 3.5 से 6.7 के मध्य भिन्न-भिन्न मन्त्रिपरिषदों में प्राप्त हुआ।

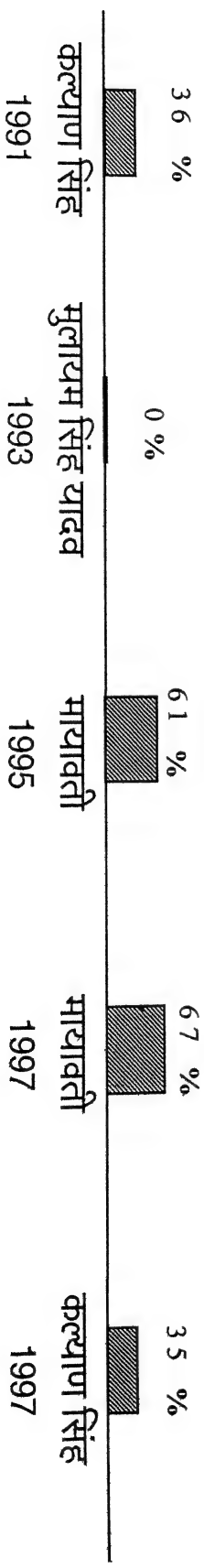
रेखा चित्र संख्या- 6.6(अ)



कल्याण सिंह 1991 मुलायम सिंह यादव 1993 मायावती 1995 मायावती 1997 कल्याण सिंह 1997

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद्‌ों में पुरुषों का प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या- 6.6(ब)



न् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या 6.7

1991 से 1997 के मध्य मंत्रिपरिषद् व विधान सभा स्त्री पुरुष अनुपात

क्रम	मन्त्रि परिषद	पुरुष		स्त्री	
		विधानसभा	मन्त्रिपरिषद	विधानसभा	मन्त्रिपरिषद
1	कल्याण सिंह (प्रथम)	97 6	94 4	2 4	3 6
2	मुलायम सिंह यादव	द्वा वा द 96 7	0	द्वा वा द 3 3	0
3	मायावती (प्रथम)		93 9		6 1
4	मायावती (द्वितीय)	त्र यो द 95 5	93 3	त्र यो द 4 5	6.7
5	कल्याण सिंह (द्वितीय)		96 5		3 5

1991 में गठित एकादश विधान सभा में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व 2 4 प्रतिशत रहा है 1993 में द्वादश विधान सभा में यह बढ़कर 3 3 प्रतिशत हो गया तथा त्रयोदश विधान सभा में यह और बढ़कर 4 5 प्रतिशत हो गया जबकि मन्त्रिपरिषदों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को देखें तो 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व 3 6 प्रतिशत है, जबकि 1993 में गठित मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद् में किसी स्त्री सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया। किन्तु मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषदों में स्त्रियों को इस काल में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जहाँ 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में 6 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्त्रियों को प्रदान किया गया वहीं इन्हीं की 1997 के मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों को 6 7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जबकि 1997 के कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद् में मात्र 3.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्त्रियों को प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ विधान सभा की तुलना में कल्याण

सिंह की प्रथम मन्त्रिपरिषद् तथा मायावती की दोनों मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, वहीं कल्याण सिंह की 1997 के मन्त्रिपरिषद् में कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

यद्यपि शोध कालखण्ड में मंत्री रही स्त्रियों की संख्या 11 थी लेकिन यदि अन्य दृष्टि से देखें तो केवल 7 स्त्रियाँ थी जिन्हें मंत्री पद प्राप्त हुआ क्योंकि इनमें कई ने एक बार से अधिक मंत्रीपद को सुशोभित किया अतः उनकी कुल संख्या 11 तक पहुँच जाती है।

इनमें प्रेमलता कटियार, कल्याण सिंह की दोनों मन्त्रिपरिषदों तथा प्रभा द्विवेदी तथा राज राय सिंह मायावती तथा कल्याण सिंह के 1997 में गठित मन्त्रिपरिषद् में सदस्य थी। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती स्वयं में दो बार 1995 व 1997 में मन्त्रिपरिषद् में रही। इसके अतिरिक्त वे स्त्रियाँ जो मन्त्रिपरिषद् में केवल सम्मिलित हुईं सुशीला सरोज, शारदा चौहान, और गुलाब देवी रहीं।

सन् 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित महिलाओं की दलीय स्थिति सारिणी संख्या 6.8.1 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 6.8.1

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद् में स्त्री प्रतिनिधित्व दल

क्र०सं०	दल	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		संख्या	प्रतिशत
1	भारतीय जनता पार्टी	5	71.4
2	बहुजन समाज पार्टी	1	14.3
3	समाजवादी पार्टी	1	14.3
4	अन्य		
योग		7	100

सारिणी संख्या 6.8.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991 से 1997 के मध्य 7 स्त्रियाँ मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित हुईं जिसमें सर्वाधिक 5 भारतीय जनता पार्टी, 1 बहुजन समाज पार्टी, तथा 1 समाजवादी पार्टी से आयी थी। इनका प्रतिशत क्रमशः भारतीय जनता पार्टी की स्त्री सदस्यों का

71 4 प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी की स्त्री सदस्याओं का 14 3 प्रतिशत और समाजवादी पार्टी की स्त्री सदस्याओं का भी 14 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा है। अन्य दल की किसी स्त्री सदस्या को मंत्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में सम्मिलित स्त्रियों की धार्मिक प्रस्थिति सारणी सख्या 6 8 2 में दर्शायी गया है।

सारिणी संख्या 6.8.2

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद् में स्त्री प्रतिनिधित्व: धार्मिक प्रस्थिति

क्र०स०	धर्म	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	6	85.7
2	मुस्लिम		
3	अन्य	1	14.3
योग		7	100

सारिणी सख्या 6 8 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य जो सात स्त्रियाँ मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित हुईं उनमें से 6 हिन्दू जिनका प्रतिशत 85.7 रहा जबकि 1 सदस्या अन्य धर्म से सम्बन्धित रही जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 14.3 प्रतिशत रहा। यहाँ उल्लेखनीय है कि किसी भी मुस्लिम सदस्या को इस काल में मंत्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में सम्मिलित स्त्रियों की जातीय स्थिति को सारिणी सख्या 6 8 3 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 6 8 3 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस काल में 7 स्त्री सदस्यों को मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित किया गया। उनमें 2 उच्च जाति, 2 मध्यम जाति तथा 3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित थी। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमशः उच्च जाति का 28.6 प्रतिशत मध्यम जाति का 28.6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति का 42.8 प्रतिशत रहा।

सारिणी सख्या 6.8 3

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद् मे स्त्री प्रतिनिधित्व जाति

क्र०स०	जाति	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	उच्च	2	28.6
2	मध्यम	2	28.6
3	अनु जाति व ज जा	3	42.8
4	अनुपलब्ध		
योग		7	100

यहाँ यह तथ्य का उल्लेखनीय है कि मन्त्रिपरिषद् मे सम्मिलित अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला सदस्या आरक्षित सीटो से चुन कर आयी थीं।

सन् 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रिपरिषदो मे सम्मिलित स्त्री सदस्याओ का शैक्षिक स्तर सारिणी सख्या 6.8.4 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 6.8.4

सन् 1991से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद मे स्त्री प्रतिनिधित्व शैक्षिक स्तर

क्र०स०	शैक्षिक स्तर	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	इण्टरमीडिएट या कम		.
2	स्नातक	4	57.1
3	स्नातकोत्तर एवं पी० एच० डी०	3	42.9
4	अनुपलब्ध		.
योग		7	100

सारिणी सख्या 6 8 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्राप्त स्त्री सदस्यो मे 4 प्रतिशत स्नातक स्तरीय रहा तथा 3 का स्नातकोत्तर एवं पी0 एच0 डी0 स्तरीय रहा है। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाली महिला सदस्यो का प्रतिनिधित्व 57 1 प्रतिशत रहा तथा स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाली महिला सदस्यो का प्रतिनिधित्व 42 9 प्रतिशत रहा।

सन् 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रि परिषदो मे सम्मिलित स्त्री सदस्यो का व्यवसाय सारिणी सख्या 6.8 5 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 6.8.5

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद् मे स्त्री प्रतिनिधित्व: व्यवसाय

क्रम सं०	व्यवसाय	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	कृषि	1	14 3
2	सेवा निवृत्त अधिकारी	1	14 3
3	राजनीति एवं सामाजिक कार्य	1	14 3
4	वकालत	1	14 3
5	व्यपार एवं उद्योग	1	14 3
6	अध्यापन	1	14 3
7	लेखन एवं पत्रकारिता	.	
8	चिकित्सा	..	.
9	ईन्जीनियरिंग		
10	विविध	1	14 3
11	अज्ञात	.	.
योग		7	100

सारिणी संख्या 6.8 5 के अन्तर्विष्ट आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रिपरिषद् में कृषि सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य, वकालत उद्योग

एव व्यापार, अध्यापन तथा विविध व्यवसाय वर्ग से एक एक सदस्या को मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

सम्पूर्ण आकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यद्यपि भारतीय संविधान तथा विधि में लिंग भेद स्वीकार नहीं किया गया है तथा स्त्री व पुरुष को समान दर्जा प्रदान है, फिर भी इस काल में (1991 से 1997 तक) उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद् में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त ही अल्प और अपर्याप्त रहा है। विधान सभा की स्थिति इससे भिन्न नहीं थी। वस्तुतः मन्त्रिपरिषद् में पुरुषों के वर्चस्व का जो चित्र उपस्थित हो रहा है वह विधान सभा, प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व के चित्र का ही प्रतिबिम्ब है। उल्लेखनीय है कि लोकतन्त्र में विधान सभा तथा मन्त्रिपरिषद् वास्तव में उसी समाज का रूप प्रदर्शित करती है जिसके अन्तर्गत वह क्रियाशील होती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के मन्त्रिपरिषद् एवं विधानसभाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में खोजा जा सकता है। सम्भवतः स्त्रियों का आर्थिक रूप से पुरुषों पर अवलम्बित होना, साक्षरता की कमी, घरेलू स्वभाव, परम्परागत रीति-रिवाज एवं मान्यताएँ जिसके तहत सार्वजनिक क्रियाकलापों में स्त्रियों की भागीदारी को अच्छा न माना जाना, महिलाओं को अपने पति की आज्ञाओं एवं विचारों के अनुरूप कार्य करने का संस्कार आदि में देखा जा सकता है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही स्त्री को द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आज का समाज भी इसका अपवाद नहीं है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य स्त्रियों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषद् में प्राप्त हुआ किन्तु यह मात्र 6.1 प्रतिशत तथा 6.7 प्रतिशत ही था जबकि कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद् में यह अपेक्षाकृत कम रहा। जहाँ सन् 1991 के कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद् में मात्र 3.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्त्रियों को प्राप्त हुआ वहीं इन्हीं के 1997 के मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों को मात्र 3.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जबकि मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद् में किसी भी स्त्री सदस्य को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया है।

इस काल में यदि विधान सभा में स्त्री प्रतिनिधित्व के सापेक्ष मन्त्रिपरिषद् में स्त्री प्रतिनिधित्व

को देखे तो जहा कल्याण सिंह की प्रथम मंत्रिपरिषद् तथा मायावती के दोनो मंत्रिपरिषदो मे तत्कालीन विधान सभा मे स्त्रियो के प्रतिनिधित्व से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वही कल्याण सिंह के द्वितीय मंत्रिपरिषद् मे कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इस काल मे यद्यपि मंत्रिपरिषद् मे स्त्रियो की प्रतिनिधित्व मे स्थिरता नही थी और उनका अनुपात घटबढ़ रहा था किन्तु विधान सभा मे स्त्रियो के प्रतिनिधित्व मे विधान सभा दर विधान सभा बढोत्तरी देखी गयी। यदि इस काल मे मंत्रिपरिषद् मे जो स्त्रियँ चुनकर आयीं, उनसे सम्बन्धित आकडो पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि यह समाज के श्रेष्ठ एव विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हे स्त्री समाज का हूबहू प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था। इन स्त्रियो मे अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी से रहीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी से मात्र एक-एक सदस्य मन्त्री पद प्राप्त कर सकी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल मे अन्य दलो की तुलना मे भारतीय जनता पार्टी ने स्त्री प्रतिनिधित्व को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया।

जाति की दृष्टि से इस काल मे मन्त्री पद प्राप्त करने वाली स्त्रियो मे सर्वाधिक 42.8 प्रतिशत स्त्रियाँ अनुसूचित जाति एव जनजाति से थी किन्तु यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यह सभी केवल उन्ही सीटो से चुनकर विधान सभा तक पहुची थीं जो अनुसूचित जाति एव जनजाति के लिए आरक्षित थी। इसके अतिरिक्त 28.6 प्रतिशत स्त्रियाँ उच्च जाति से और इतनी ही मध्यम जाति से सम्बन्धित थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक जाति वर्ग के स्त्री को मंत्रिपरिषद् मे समय-समय पर स्थान मिलता रहा है। उदाहरण के लिए यदि 1997 के कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद् को लें तो इसमें सम्मिलित 4 स्त्री सदस्यो मे एक उच्च सामान्य, एक मध्यम, एक अनुसूचित जाति एव जनजाति तथा एक अल्पसंख्यक वर्ग से थी। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि महिलाओ मे राजनैतिक चेतना का विकास बहुत ही कम हुआ है किन्तु जो हुआ है उसका विस्तार जाति के आधार पर नही बांधा जा सकता।

धार्मिक दृष्टि से इस काल मे मन्त्री पद प्राप्त करने वाली स्त्रियो में 85.7 प्रतिशत स्त्रिया हिन्दू धर्म से थीं तथा 14.3 प्रतिशत के साथ एक स्त्री अन्य धर्म से सम्बन्धित थी। जबकि मुस्लिम धर्म से किसी भी स्त्री सदस्या को मंत्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय

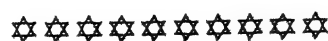
है कि मुस्लिम समाज में स्त्रियों की दशा अपेक्षाकृत अधिक चिन्तनीय है।

जहाँ तक शैक्षिक स्तर का प्रश्न है तो इस काल में वही स्त्री सदस्य मन्त्री पद प्राप्त कर पायी जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति उच्च रही है। जैसा कि स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद् की सभी सदस्या स्नातक या स्नातक से उच्च शिक्षा प्राप्त थीं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक चेतना का कोई न कोई सम्बन्ध शिक्षा से होता है।

इस काल में जो स्त्री सदस्य मन्त्री पद प्राप्त थी वह किसी न किसी व्यवसाय में रत थी तथा इनमें अधिकांशतः नगरीय तथा कस्बाई क्षेत्रों में निवास करती थी। इसका कारण शायद यह रहा हो कि नगरीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता व आधुनिक विचारधारा का प्रभाव ज्यादा पड़ा हो जबकि ग्रामीण स्त्रियों के सम्भवतः परम्परागत स्वभाव व सामाजिक रुढ़िवादिता से ग्रस्त होने के कारण उनकी राजनीतिक अभिरुचि कम रही हो। यदि यह तथ्य सही हो तो स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को औद्योगिक विकास, नगरीकरण, तथा आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिए।

सदस्यों की राजनीतिक पृष्ठभूमि की विवेचना से यह तथ्य भी उजागर हो रहा है कि अधिकांश सदस्य ऐसी थी जिन्हें किसी प्रकार का विधायी अनुभव प्राप्त नहीं था तथा विधान सभा में प्रथम प्रवेश पर ही उन्हें मन्त्री पद प्रदान किया गया। यही नहीं इनमें अधिकांश ने राजनीतिक प्रशिक्षण स्थानीय शासन में प्राप्त नहीं किया था और सीधे राज्य स्तरीय राजनीति में प्रवेश किया।

इस काल में यद्यपि स्त्रियों का प्रतिनिधित्व विधान सभाओं तथा मन्त्रिपरिषदों में अत्यन्त अल्प रहा है किन्तु स्त्रियों की बढ़ती साक्षरता दर तथा इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण तथा प्रत्येक आर्थिक गतिविधियों में महिला पुरुष समानता को प्रोत्साहन, यह ऐसे कदम हैं जो निश्चय ही स्त्रियों को आर्थिक स्वावलम्बन की तरफ ले जायेंगे। जिसके प्रभाव से उनमें स्वतन्त्र निर्णयन की क्षमता में वृद्धि होगी तथा यह सार्वजनिक गतिविधियों में अपने को अधिक मुक्त पा सकेंगी।



सप्तम् अध्याय

मंत्रिपरिषद् एवं विधानसभा, विधान परिषद्

मन्त्रिपरिषद् एवं विधानसभा, विधान परिषद्

आधुनिक युग में विधान मंडल का स्वरूप प्रायः द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधान मंडल मुख्यतः दो कारणों से अपरिहार्य समझा जाता है। सघीय व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त के रूप में तथा सविधान के लोकप्रिय सिद्धान्तों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए¹। प्रथम कारण के आधार पर सघीय शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन की उपस्थिति को समझा जा सकता है किन्तु वर्तमान विश्व अधिकांश गैर सघीय एकात्मक शासन व्यवस्था में इसकी उपस्थिति को द्वितीय कारण के आधार पर समझा जा सकता है। वस्तुतः द्वितीय सदन की आवश्यकता केवल सघीय राज्यों में इकाइयों के प्रतिनिधित्व के लिए न होकर मुख्यतः प्रथम सदन की निरकुश लोकप्रियता के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने के लिए है, जिसके शीघ्रता से बनाये गये, स्वार्थमूलक अथवा बिना सोचे-विचारे गये कानूनों पर यदि स्थायी न सही तो कम से कम सामयिक रोक लगाकर लोकमत को संगठित होने का अवसर दिया जा सके। इसी कारण एकात्मक सरकारों में भी द्वितीय सदन को वाछनीय समझा गया²। किन्तु सभी विद्वानों का यह मत नहीं 'ऐबेसिये' ने अनिवार्यता एवं उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा कि 'यदि दोनों सदन सहमत हैं तो द्विसदन आवश्यक है, और यदि उनमें मतभेद है तो यह भयावह है'³। लेकिन फाइनर ने 'ऐबेसिये' के इस भ्रम को दूर करते हुए कहा कि यदि

-
1. फाइनर एच 'थ्योरी एण्ड प्रैक्टिकल ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट', एडिशन 4, सूरजीत पब्लिशिंग, दिल्ली
 2. शुक्ल देवी प्रसाद व श्रीवास्तव वृजेन्द्र कुमार. आधुनिक सविधानों के सिद्धान्त और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1986 पृष्ठ 315
 3. फाइनर वही पृष्ठ 403

दोनों सदन सहमत है तो अति उत्तम है, क्योंकि इससे ज्ञान और विधि के न्याय के प्रति विश्वास बढ़ता है और यदि उनमें मतभेद है तो जनता को अवसर मिलता है कि वह अपने दृष्टिकोण पर पुन विचार करे।

एकात्मक शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन के पक्ष विपक्ष में दिये गये इन मतों के आधार पर 'प्रदेश' में द्विसदनीय विधान मंडल की आवश्यकता तथा अनावश्यकता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यद्यपि सविधान सभा में भी इस विषय पर काफी विवाद था कि राज्यों का विधानमंडल एकसदनीय हो या द्विसदनीय। एच० वी० कामथ का मानना था कि प्रान्तों में द्वितीय सदन का होना हानिकारक तथा दोषपूर्ण है।⁴ प्रो० के० टी० शाह का भी यही मत था, उन्होंने इसे 'व्यर्थ' एवं 'खतरनाक' बताया।⁵ असम के कुलदीप चलिया ने द्वितीय सदन को परम्परा की देन तथा प्रगतिशील विधान के मार्ग में बाधा के अतिरिक्त कुछ नहीं बताया।⁶ रेणुका राय का मानना है कि द्वितीय सदन का होना प्रतिगामी न भी माना जाय अनावश्यक तो माना ही जायेगा।⁷ किन्तु एल कृष्णा स्वामी भारतीय का मत इससे भिन्न है, उनका विचार है कि द्वितीय सदन का विरोध पूर्वाग्रह पर आधारित है। उनके अनुसार द्वितीय सदन बनाने के पीछे लक्ष्य जल्दबाजी में बनाये जाने वाले विधान पर रोक लगाना है। भीमराव अम्बेडकर ने सविधान सभा में हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा 'जहाँ तक मेरी बात है, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं द्वितीय सदन को बनाये जाने का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ। मेरे लिए यह एक 'क्यूरेट के अण्डे' के समान है जो केवल अशत उपयोगी है। इसे सविधान का एक अलंकारिक भाग बताया गया है तथा इसे एक प्रायोगिक दृष्टि से सविधान में रखने की सलाह दी गयी है।⁸

4 सी० ए० डी० वैल्यू० 9 पृ० 14-16

5 सी० ए० डी० वैल्यू० 10 पृ० 87-88

6 सी० ए० डी० वैल्यू० 7 पृ० 1310

7 वही० पृ० 1312

8 सी० ए० डी० वैल्यू० 8 पृ० 1317

उपर्युक्त कारणों से ही संविधान में राज्यों में द्वितीय सदन के सृजन और उत्पादन की अत्यधिक नमनीय व्यवस्था की गयी है, जो एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।⁹ अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि— कोई राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा विधान परिषद के सृजन और उत्पादन का एक संकल्प पारित करेगी, जिसके अनुसरण में संसद विधि बनायेगी।¹⁰

इसके साथ संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि किन प्रांतों में द्वितीय सदन रहे इसका निर्णय उस प्रान्त के संविधान सदस्यों पर छोड़ दिया जाय। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब छ प्रांतों की विधानसभाओं में द्विसदनीय व्यवस्था भारतीय संविधान के अनु० 168 के तहत किया गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् विधान परिषदों के सदस्य में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास पर दृष्टि डाली जाय तो यह अपने सृजन के आदेशों से कुछ भिन्न दिशा में बढ़ता प्रतीत हो रहा है। प्रदेश की राजनीति में ऐसी परिपाटी स्थापित हो रही है कि जो नेता विधानसभा के चुनाव में पराजित हो जाते हैं उन्हें विधान परिषद के लिए निर्वाचित कर लिया जाता है। इस प्रकार वे व्यक्ति द्वितीय सदन में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि मानने से इन्कार कर दिया है।¹¹ इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए जे० सी० जौहरी ने कहा

9. वसु डी० डी० 'भारत की संविधान एक परिचय' सातवां संस्करण, नई दिल्ली; प्रेषित हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, 98, पृ० 235

10. ए० ए० डी० वैल्यू 9 न० 1; पृ० 13

11. शुक्ल देवी प्रसाद व श्रीवास्तव बृजेन्द्र कुमार: 'आधुनिक संविधानों के सिद्धान्त और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1968, पृ० 319

सारिणी सख्या 71

1991 के कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मन्त्री 60)

1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यो की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा के मन्त्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व %मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यो की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद से मन्त्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	56	93.33	13.2	108	4	6.7	3.7

सारिणी सख्या 71 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा के 425 सदस्यो मे से कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद में 56 सदस्य लिये गये तथा विधानपरिषद के 108 सदस्यो मे से 4 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधानसभा का प्रतिशतवार प्रतिनिधित्व 13.2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिशतवार प्रतिनिधित्व 3.7 प्रतिशत रहा। कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद मे कुल 60 मन्त्री थे जिसमे विधानसभा का प्रतिनिधित्व 93.33 प्रतिशत रहा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व 6.7 प्रतिशत रहा।

कल्याण सिंह की मन्त्रिपरिषद के पतन एव विधानसभा भंग होने के पश्चात् नवम्बर 1993 मे उत्तर प्रदेश के द्वादश विधानसभा के लिए हुए मध्यमावधि चुनाव के परिणामस्वरूप मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व मे दिनांक 4/12/1993 को गठित तथा 3/6/1995 तक कार्यरत बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी की सम्मिलित मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा एव विधान परिषद के सदस्यो को प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी सख्या 72 के माध्यम से कर सकते हैं।

सारिणी सख्या 72

मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान
परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मन्त्री 28)

1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यो की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा के मन्त्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व %मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यो की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद से मन्त्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	28	85.7	5.7	108	4	14.3	3.7

सारिणी सख्या 72 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा के 425 सदस्यो मे से मुलायम सिंह यादव की मन्त्रिपरिषद मे 24 सदस्य लिये गये तथा विधान परिषद के 108 सदस्यो से 4 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित किया गया। इस प्रकार विधानसभा का प्रतिशत वार प्रतिनिधित्व 5.7 प्रतिशत तथा विधानपरिषद का प्रतिशतवार प्रतिनिधित्व 3.7 प्रतिशत रहा। मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद मे कुल 28 मन्त्री थे जिसमे विधानसभा का प्रतिनिधित्व 85.7 प्रतिशत तथा विधान परिषद 14.3 प्रतिशत रहा।

मुलायम सिंह यादव के मन्त्रिपरिषद के पतन के पश्चात् मायावती के नेतृत्व मे दिनांक 3/6/1995 को गठित तथा 18/10/1995 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा व विधानपरिषद के सदस्यो का प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी संख्या 73 के माध्यम से किया जा सकता है।

सारिणी सख्या 73

1995 के मायावती मंत्रिपरिषद में विधानसभा तथा विधान परिषद
का प्रतिनिधित्व

(कुल मंत्री 33)

1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा में सदस्यों की संख्या	मंत्रिपरिषद में विधानसभा के मंत्री	मंत्रिपरिषद में विधानसभा का प्रतिनिधित्व % में	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या	मंत्रिपरिषद में विधानपरिषद से मंत्री	मंत्रिपरिषद में विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % में	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	22*	66.7	5.2	108	2	6.1	1.9

* इसमें विधान सभा के उन सदस्यों को भी शामिल किया गया है जिन पर सपा से अलग होने के कारण दल-बदल अधिनियम के आधार पर कार्यवाही की गयी।

सारिणी सख्या 73 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा के 425 सदस्यों में से मायावती के 1995 के मंत्रिपरिषद में 22 सदस्य तथा विधान परिषद के 108 सदस्यों में से 2 सदस्य मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधान सभा का प्रतिशतवार प्रतिनिधित्व 5.2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का 1.9 प्रतिशत रहा। मायावती के मंत्रिपरिषद में कुल 33 मंत्री थे जिसमें विधान सभा का प्रतिनिधित्व 6.1 प्रतिशत रहा। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि मायावती के इस मंत्रिपरिषद में स्वयं मुख्यमंत्री मायावती किसी भी सदन (हाउस) की सदस्या नहीं थी तथा इसके अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य भी विधान मंडल के किसी भी सदन (हाउस) के सदस्य नहीं थे।

मायावती की 3/6/1995 को गठित तथा 18/10/1995 तक कार्यरत 'प्रथम' मंत्रिपरिषद के पतन के पश्चात् हुए मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप

प्रदेश को एक बार पुन साझा सरकार का अनुभव प्राप्त हुआ। इस बार पुन मायावती के नेतृत्व मे दिनांक 21/3/1997 को बसपा तथा भाजपा का सम्मिलित मन्त्रिपरिषद का गठन हुआ, जो दिनांक 18/10/1997 तक कार्यरत था। इस मन्त्रिपरिषद मे विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी सख्या 74 के माध्यम से किया जा सकता है।

सारिणी सख्या 74

1997 के मायावती मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद

का प्रतिनिधित्व

(कुल मन्त्री 45)

7 1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यों की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा के मन्त्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व % मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यों की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद से मन्त्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	38	82.2	8.7	108	7	15.6	6.5

सारिणी सख्या 74 के अवलोकन से स्पष्ट है होता है कि विधान सभा के 425 सदस्यों मे से मायावती के 1997 के मन्त्रिपरिषद मे 37 सदस्य तथा विधान परिषद के 108 सदस्यों मे से 7 सदस्य मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधान सभा का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 8.7 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 6.5 प्रतिशत रहा। मायावती के इस मन्त्रिपरिषद मे कुल 45 मन्त्री थे, जिसमे विधान सभा का प्रतिनिधित्व 82.2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व 15.6 प्रतिशत रहा। यहां यह तथ्य स्मरणीय है कि बरखू राम वर्मा विधान मडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।

भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के मध्य सरकार

बनाने के लिए हुए समझौते के परिणाम स्वरूप मायावती ने 21/9/1997 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। परिणामस्वरूप मायावती के मंत्रिपरिषद का विघटन हो गया। तदपश्चात् कल्याण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 21/9/1997 को गठित तथा शोधकाल खण्ड 1997 के समापन के आगे तक कार्यरत मंत्रिपरिषद में विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी सख्या 75 के माध्यम से किया जा सकता है।

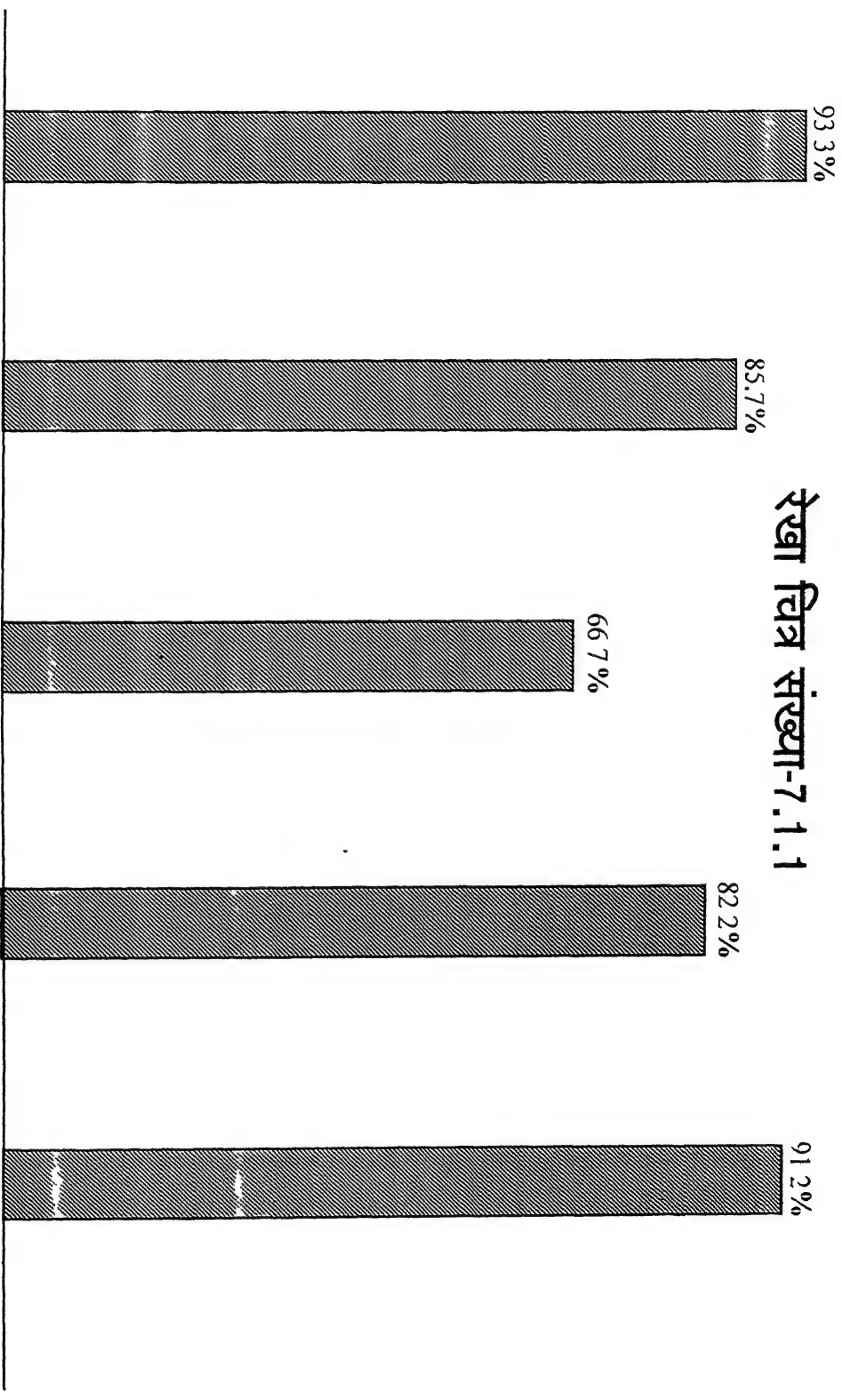
सारिणी सख्या 75

1997 के कल्याण सिंह मंत्रिपरिषद में विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मंत्री 45)							
1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा में सदस्यों की सख्या	मंत्रिपरिषद में विधानसभा के मंत्री	मंत्रिपरिषद में विधानसभा का प्रतिनिधित्व % में	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यों की सख्या	मंत्रिपरिषद में विधानपरिषद से मंत्री	मंत्रिपरिषद में विधानपरिषद का प्रतिनिधित्व % में	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	103	91.2	24.2	108	9	7.9	8.3

सारिणी सख्या 75 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा के 425 सदस्यों में से कल्याण सिंह के 1997 के मंत्रिपरिषद में 103 सदस्य तथा विधान परिषद के 108 सदस्यों में से 9 सदस्य मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधान सभा का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 24.2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 8.3 प्रतिशत रहा। कल्याण सिंह के इस मंत्रिपरिषद में कुल 113 मंत्री थे, जिसमें विधान सभा का प्रतिनिधित्व 91.2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व 7.9 प्रतिशत रहा।

रेखा चित्र संख्या-7.1.1



सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद्‌ों में विधान सभा से लिए गये सदस्य

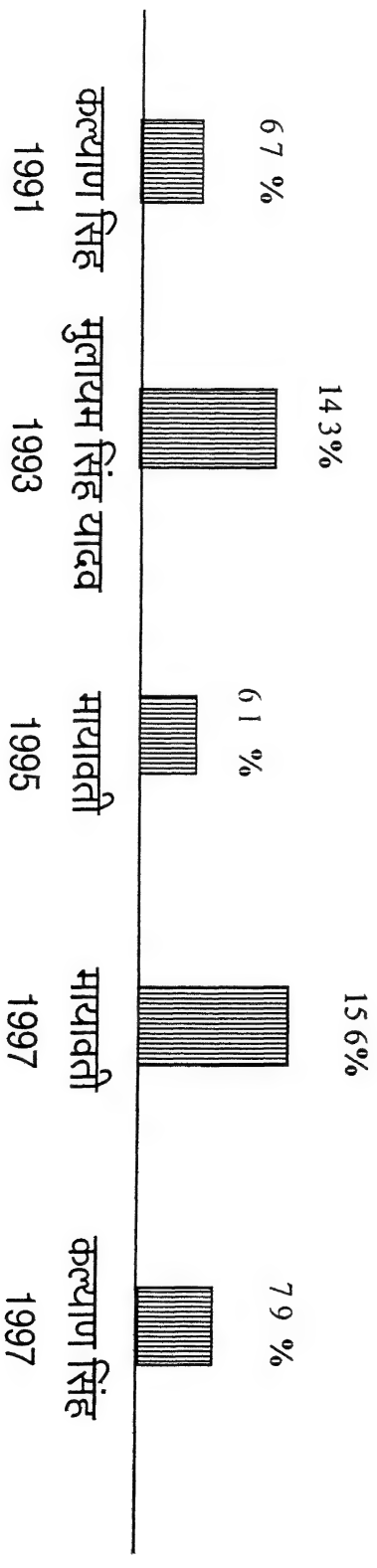
पूर्ववर्ती सभी तालिकाओं के अध्ययन – अवलोकन से विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रतिनिधित्व एवं मन्त्रिपरिषद में उनके प्रतिनिधित्व प्रतिशत की स्थिति स्पष्ट होती है।

मन्त्रिपरिषद	विधान सभा का प्रतिनिधित्व	मन्त्रिपरिषद में प्रतिशत
कल्याण सिंह (24/6/91 से 6/12/92)	132	93.3
मुलायम सिंह यादव (4/12/93 से 3/6/95)	57	85.7
मायावती (3/6/95 से 18/10/95)	52	66.7
मायावती (21/3/97 से 21/9/99)	87	82.2
कल्याण सिंह* (21/9/97 से 12/11/99)	242	91.2

* कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित (21/9/97 से 12/9/97 तक) द्वितीय मन्त्रिपरिषद का विधानसभा एवं विधान परिषद में मन्त्रिपरिषद के प्रतिशत को 31 दिस 1997 तक दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के बीच विभिन्न कालों में गठित मन्त्रिपरिषदों में विधान सभा के प्रतिनिधित्व की स्थिति रेखाचित्र संख्या 7.1.1 में दर्शायी गयी है। इसी प्रकार विभिन्न कालों में गठित मन्त्रिपरिषदों में विधान परिषद के प्रतिनिधित्व की स्थिति रेखाचित्र संख्या 7.1.2 में प्रदर्शित की गयी है एवं विधान सभा एवं विधान परिषद दोनों की मन्त्रिपरिषद में स्थिति को सम्मिलित रूप से रेखाचित्र संख्या 7.1.3 में प्रदर्शित किया गया है तथा मन्त्रिपरिषद में विधान सभा तथा विधान परिषद

रेखा चित्र संख्या-7.1.2



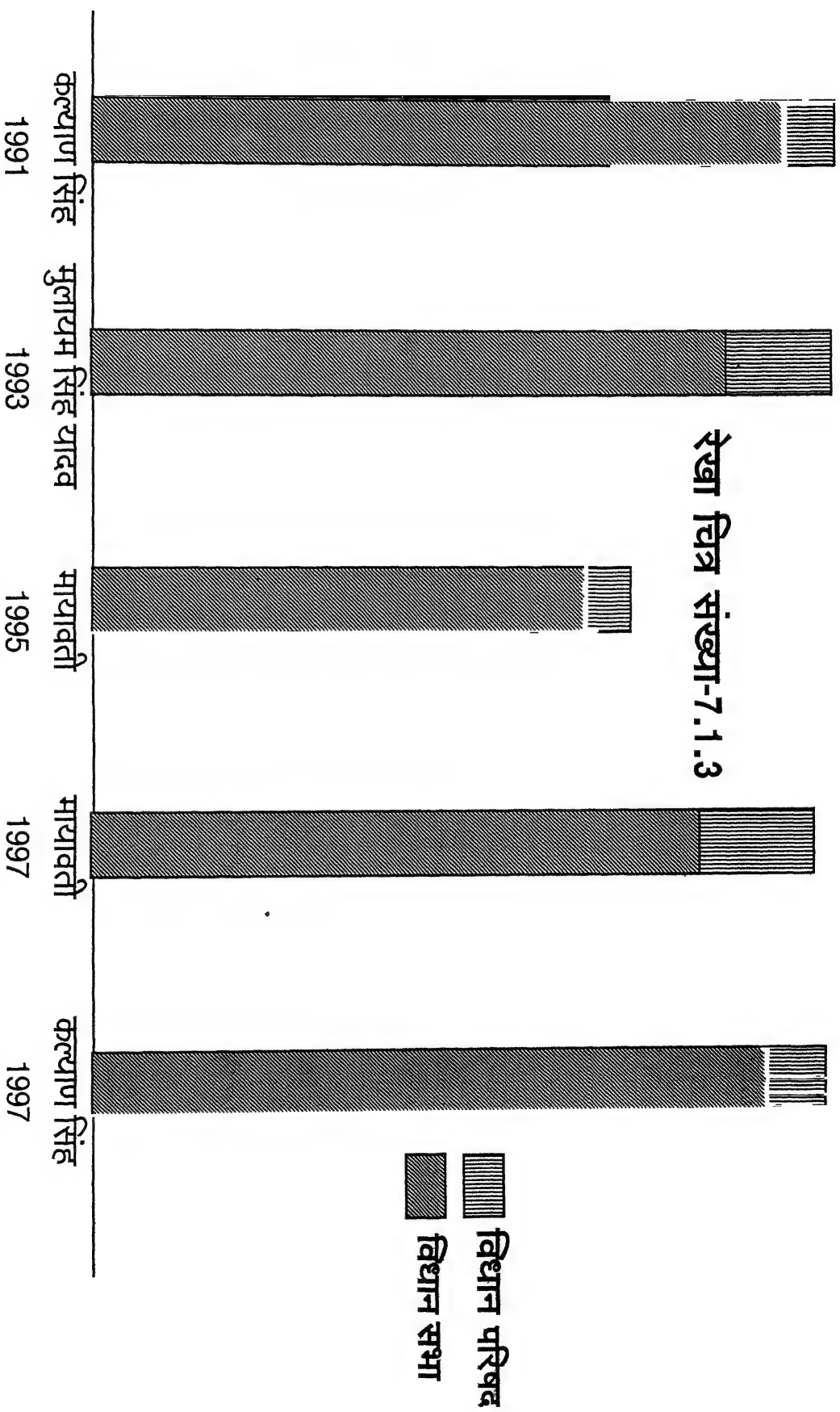
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद् में विधान परिषद से लिए गये सदस्य

सदस्यों के प्रतिनिधित्व के उतार-चढ़ाव को रेखा चित्र सख्या 714 में दर्शाया गया है।

मन्त्रिपरिषद	विधान परिषद का प्रतिनिधित्व	मन्त्रिपरिषद में प्रतिशत
कल्याण सिंह (24/6/91 से 6/12/92)	37	67
मुलायम सिंह यादव (4/12/93 से 3/6/95)	37	143
मायावती (3/6/95 से 18/10/95)	19	61
मायावती (21/9/97 से 2/11/97)	65	156
कल्याण सिंह ' (21/9/97 से 12/11/99)	83	79
औसत	48	101

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का अवलोकन करने के पश्चात् जो तथ्य उजागर हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन्त्रिपरिषद में विधान सभा एवं विधान परिषद की भागेदारी का कोई निश्चित अनुपात नहीं रहा। इस काल में गठित मन्त्रिपरिषदों में विधान परिषद का न्यूनतम प्रतिनिधित्व 61 फीसदी तथा अधिकतम प्रतिनिधित्व 156 फीसदी रहा है। यदि विधान सभा का मन्त्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो यह न्यूनतम 66.7 फीसदी तथा अधिकतम 93.3 फीसदी रहा है। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद में विधान सभा व विधान परिषद अनुपात 66.7/15.6 से लेकर 93.3/6.7 फीसदी के मध्य रहा है।

रेखा चित्र संख्या-7.1.3

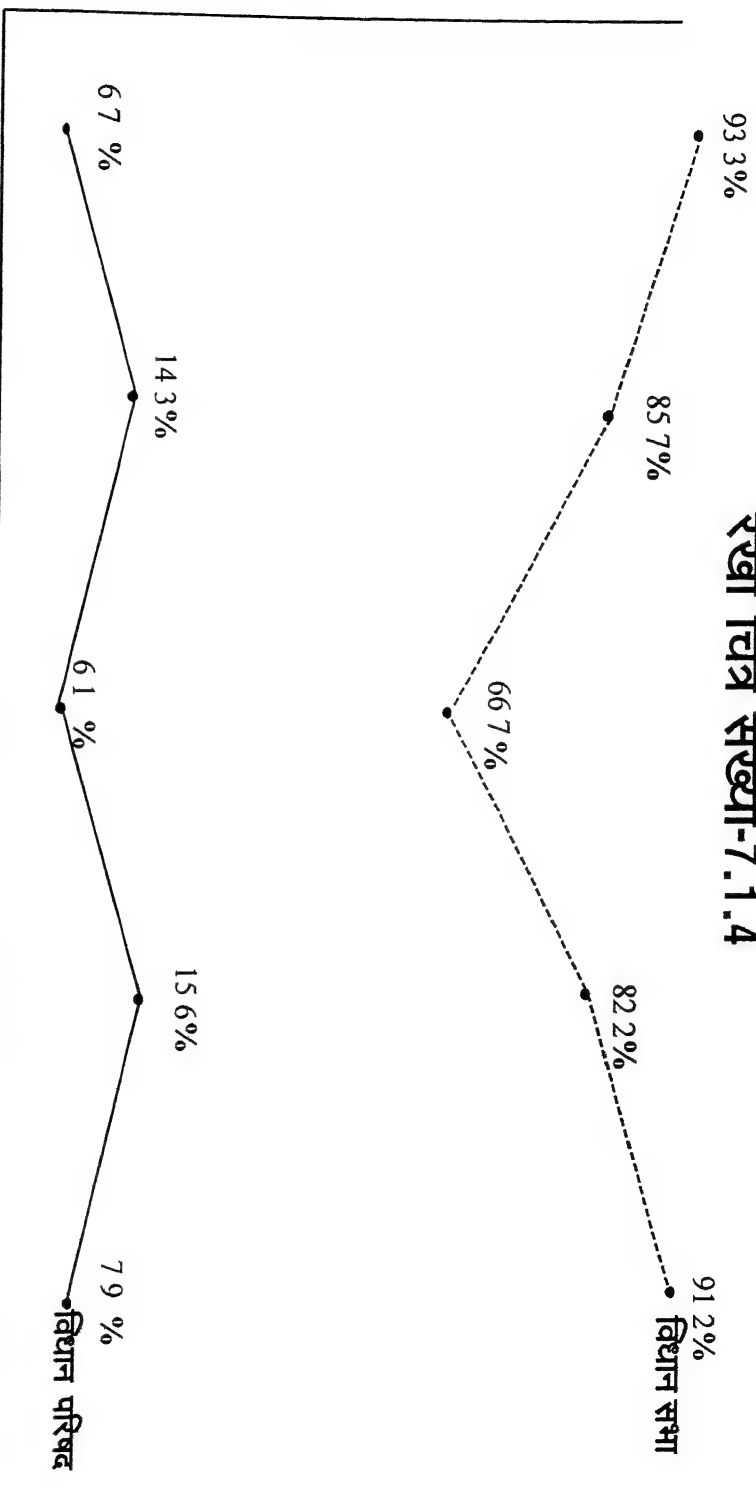


सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में विधान सभा एवं विधान परिषद से लिए गये सदा

कल्याण सिंह के दोनो मंत्रिपरिषदो मे अर्थात् 1991 ई० मे तथा 1997 ई० मे गठित मंत्रिपरिषद मे कुल सदस्यो के 90 फीसदी से ऊपर प्रतिनिधित्व विधान सभा के सदस्यो को दिया गया जो सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मंत्रिपरिषदो मे विधान सभा का सबसे उच्च प्रतिनिधित्व रहा। यह क्रमश 24/6/1991 से 6/12/1992 तक कार्यरत प्रथम मंत्रिपरिषद मे 93.3 फीसदी एव 21/9/1997 से 12/11/1999 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद में 31 दिसम्बर 1997 के अत तक 91.2 फीसदी रहा। इस प्रकार यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद मे विधान परिषद के सदस्यो का प्रतिनिधित्व अत्यंत निम्न रहा है किन्तु विधान परिषद के सदस्यो को न्यूनतम प्रतिनिधित्व दिनांक 3/6/1995 को मायावती के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित तथा दिनांक 18/10/1995 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ। इसमे मात्र 6.1 फीसदी प्रतिनिधित्व ही विधान परिषद के सदस्यो को प्राप्त हो सका है जबकि इसके पश्चात् विधान परिषद के सदस्यो का सबसे निम्न प्रतिनिधित्व 6.7 फीसदी दिनांक 24/6/1991 को कल्याण सिंह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मंत्रिपरिषद मे प्राप्त रहा है।

कल्याण सिंह के प्रथम मंत्रिपरिषद के पश्चात् मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व मे दिनांक 4/12/1993 को गठित समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त मंत्रिपरिषद में विधान परिषद के सदस्यो को 14.3 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जो कल्याण सिंह के दोनो मंत्रिपरिषदो मे विधान परिषद के सदस्यो को प्रदान किये गये प्रतिनिधित्व अनुपात से उच्च था जबकि विधान सभा के सदस्यो को 85.7 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद मे विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपात 14.3: 85.7 शोधकाल खण्ड सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मंत्रिपरिषदो के विधान सभा व विधान परिषद सदस्यों के औसत (सम्पूर्ण) प्रतिनिधित्व अनुपात 10:1 है। 83.8 के सबसे अधिक निकट है।

रेखा चित्र संख्या-7.1.4



कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव मायावती मायावती कल्याण सिंह
1991 1993 1995 1997 1997

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

मुलायम सिंह यादव के पश्चात् मायावती के नेतृत्व में दिनांक 3/6/1995 को प्रथम बार गठित मंत्रिपरिषद में विधान सभा के सदस्यों को 61 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जो सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मंत्रिपरिषदों में सबसे निम्न था। मायावती के 33 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 2 मंत्री विधान परिषद से तथा 22 मंत्री विधान सभा से लिये गये थे। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के इस मंत्रिपरिषद में 4 सदस्य ऐसे थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत स्वयं मायावती भी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त विधान सभा के सदस्य के रूप में दिखाये गये सारणी संख्या 3 के सदस्यों में 4 सदस्य ऐसे थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा के लिए निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् पार्टी से अलग होकर मायावती के मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होने के कारण दल-बदल अधिनियम के तहत उन पर कार्यवाही की गयी। यहाँ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि मायावती के दल बहुजन समाज पार्टी को विधान सभा में मात्र 67 स्थान प्राप्त थे।

मायावती की प्रथम मंत्रिपरिषद चूँकि विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर आधारित थी। अतः भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद उसका पतन हो गया तथा प्रदेश को फिर से एकबार मध्यरात्रि चुनाव झेलना पड़ा। जिसमें किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो सका। अतः एक बार पुनः मायावती के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था तथा इस बार भारतीय जनता पार्टी मंत्रिपरिषद में सम्मिलित भी थी। इस मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रिपरिषदों की तुलना में विधान परिषद के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मायावती की इस 45 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 7 मंत्री विधान परिषद से लिये गये, मंत्रिपरिषद में इनका प्रतिनिधित्व 15.6 फीसदी रहा। इस प्रकार यहाँ यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मंत्रिपरिषदों में भी विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व अनुपात में काफी

भिन्नता है।

अतः सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद् में विधान परिषद् के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपात सदैव अनिश्चित रहा है। विधान परिषद् के सदस्यों को मन्त्रिपरिषद् में न्यूनतम अथवा अधिकतम कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाये इस सदर्भ में किसी भी परम्परा का विकास नहीं हो सका है। यहाँ तक कि एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में भी विधान परिषद् के प्रतिनिधित्व के विषय में कोई निश्चित दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं हो सका।

वस्तुतः मन्त्रिपरिषद् में विधान परिषद् के सदस्य के रूप में सम्मिलित होना राजनेताओं के पीछे के द्वार से सरकार में आने का प्रयास प्रतीत होता है। सामान्यतः विधान सभा के चुनावों में असफलता के कारण मन्त्रिपरिषद् में स्थान प्राप्त करने के लिए राजनेता विधान परिषद् की सदस्यता का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन के दौरान ऐसे भी मंत्री पाये गये हैं जो कभी भी विधान सभा चुनावों में हिस्सा नहीं लेते हैं या सफल नहीं होते हैं, किन्तु अपने दलों में शक्तिशाली स्थिति में होने के कारण उन्हें मन्त्रिपरिषद् में स्थान प्रदान किया जाता है जिसके लिए वह संवैधानिक योग्यता की पूर्ति विधान परिषद् की सदस्यता प्राप्त करके करते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि विधान परिषद् ने संविधान संस्थापकों की आशा के विपरीत सत्ताधारी दलों के शक्तिशाली लोगों के लिए आरामघर का अभाग ध्येय ही पूरा किया है।

अष्टम् अध्याय

मंत्रिपरिव. में सम्मिलित दलों की स्थिति

मन्त्रिपरिषद् मे सम्मिलित दलो की स्थिति)

यह एक स्वतः सिद्ध नियम है कि जनतान्त्रिक शासन प्रणाली के कार्यकरण मे दल एक अपरिहार्य अंग बन गया है।¹ बिना राजनीतिक दलो के न तो सिद्धान्तो की सगठित अभिव्यक्ति हो सकती है, न नीतियो का व्यवस्थित विकास, न ससदीय निर्वाचन के सविधानिक साधन का अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त ऐसी सस्था का नियमित प्रयोग जिसके द्वारा दल सत्ता प्राप्त करते है और उसे बनाये रखते है।² विभिन्न देशो मे दल प्रणाली का स्वरुप सम्बन्धित देश के राजनीतिक इतिहास और सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियो की देन होती है।³ यही कारण है कि ससार मे विभिन्न शासन व्यवस्थाओ मे दल प्रणाली का स्वरुप और उसका कार्य भार भिन्न-भिन्न दिखायी देता है। भारत मे पश्चिम ढंग की सुसगठित तथा प्रभावशाली लोकतान्त्रिक दल प्रणाली का विकास नही हुआ है।⁴

भारत मे दल प्रणाली का उद्भव काग्रेस की स्थापना से माना जाता है⁵ तथा स्वतन्त्रता बाद भी लम्बे समय तक इसी दल का प्रभुत्व बना रहा जिसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मे एकदलीय प्रभुत्व काल के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः काग्रेस ने लम्बे समय तक भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया, जिसमे उसे विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म तथा आदर्श को मानने वालो का सहयोग प्राप्त हुआ क्योकि इनमे सबका एक ही लक्ष्य था स्वतन्त्रता प्राप्ति। इस कारण काग्रेस का उदय एक छत्र सगठन के रूप मे हुआ जिसका अर्थ है इसने सभी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय हितो तथा सिद्धान्तो को मानने वालो को अपने में सम्मो लिया।⁶

-
- 1- पोलम्बरा लाओ जोओ - 'पैलिटिकल पार्टी एण्ड पैलिटिकल डेवलपमेन्ट' न्यूजर्सी, प्रिन्स्टन यूओ प्रेस 1966, पृ० 03
 - 2- मैक आइवर आरओ एमओ - 'दि माईन स्टेट', ओओ यूओ पीओ आक्सफोर्ड, 1928 पृ० 316
 - 3- सर्ईद एसओ एमओ - भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लखनऊ, सुलभप्रकाशन (1996), पृ० 205
 - 4- पायर डीओ नार्मन - 'दि इण्डियन पैलिटिकल सिस्टम', लन्दन, जार्ज ऐलन एण्ड एनविन, पृ० 182
 - 5- सर्ईद एस एम - वही पृ० 205
 - 6- पामर डीओ नार्मन वही पृ० 187

इसी विशेषता को ध्यान में रखकर अम्बेडकर ने इसकी तुलना धर्मशाला से की है।⁷

इसी आधार पर सदाशिव का कहना है कि कांग्रेस की वैज्ञानिक रूप से कोई सरचित विचार धारा नहीं है। वस्तुतः दल की सामाजिक स्थिति और स्वरूप, सत्ता में बने रहने के लिए विभिन्न स्वार्थों के बीच समझौता और इसके नेताओं का सैद्धान्तिक बहुलवाद किसी स्पष्ट विचारधारा के मार्ग में बाधाएँ बनी हैं।⁸ अन्य दलों की प्रकृति भी कमोबेश इसी प्रकार की हैं क्योंकि अधिकतर विरोधी दलों के सदस्य पहले कांग्रेस में रह चुके थे तथा जिनकी सामाजिक-बौद्धिक पृष्ठभूमि एक सी थी।⁹ इनका विरोध सामाजिक या संघर्ष का परिणाम नहीं था बल्कि राजनैतिक फूट व संघर्ष का परिणाम था।¹⁰

इस प्रकार भारत में सत्ताधारी तथा विरोधी दोनों दलों में वैचारिक स्पष्टता एवं एकता का अभाव नजर आता है।¹¹ विरोधी दल सत्तारूढ़ दल के सिद्धान्तों या लक्ष्यों का विरोध नहीं करते बल्कि वह कहते हैं कि सत्ताधारी दल उस पर अमल नहीं कर रहा है।¹² इस प्रकार विरोधी तत्वों का उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था को उलटना नहीं उस पर कब्जा करना है।¹³ इस कारण विचारधारा और नीति जैसे भिन्न तत्व भी आपस में मिलते हैं और अवसरवादिता का परिचय देते हैं।¹⁴

- 7- अम्बेडकर के कथन से उद्धृत सईद एस0 एम0 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लखनऊ, सुलभ प्रकाशन पृ0 214
- 8- सदाशिवन एस0 एन0 - 'पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया', नई दिल्ली, टाटा मैक्ग्रा हिल पब्लिशर 1977 पृ0 252
- 9- कोठारी रजनी भारत में राजनीति, 'नई दिल्ली, ओरिएण्ट लांगमैन पृ0 115
- 10- वही पृ0 115
- 11- वही पृ0 116
- 12- वही पृ0 117
- 13- वही पृ0 117
- 14- वही पृ0 118

स्वतन्त्रता के पश्चात प्रदेश की राजनीति व्यवस्था के इतिहास में गठित सविदा सरकारों में इन तथ्यों की बहुलता देखी जा सकती है। यथा चरण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 3-4-67 में गठित सरकार पर दृष्टि डाले तो इस सरकार में ससोपा, प्रसोप जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, जनकाग्रेस, रिपब्लिक पार्टी, साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी तथा निर्दलीय भी थे।¹⁵ इस प्रकार चरण का यह मंत्रिपरिषद् विभिन्न विचारधाराओं तथा सिद्धान्तों को मानने वाले दलों का एक अवसरवादी गठबंधन था। पुनः चरणसिंह ने कांग्रेस (आर) के साथ मिलकर दिनांक 18-10-70 को मन्त्रिपरिषद् का गठन किया। वह भी अवसरवादी गठबंधन ही था जिसका पतन भी शीघ्र हो गया। इसी क्रम में यदि शोध काल खण्ड सन् 1991 से 1997 के मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह समय स्थिर राजनीति का समय था। इस दौरान गठित कोई भी सरकार अपने कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर सकी। तुष्टीकरण, सत्तालोलुपता, आदर्श हीनता का जो परिचय प्रदेश के राजनीतिज्ञों द्वारा इस दौरान प्रदर्शित किया गया वह प्रदेश को स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति की तरफ ले जाती प्रतीत नहीं हो रहा था। बेताहाशा दलबद्धता, गैर सैद्धान्तिक गठबंधन, विस्तृत मन्त्रिपरिषद् तथा सदन में होने वाले हंगामा तथा सवाद का गिरता स्तर प्रदेश राजनीति की शोचनीय स्थिति प्रदर्शित करता रहा है।

इस काल में प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति पर दृष्टि डालें तो राजनेताओं का केवल एक ही लक्ष्य दृष्टिगोचर हो रहा है- सत्ता पर काबिज होना। इसके लिए वह अनेक नैतिक-अनैतिक साधन प्रयोग में लाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विभिन्न दलों का विघटन नये- नये समीकरण प्रदेश की राजनीति में दिन- प्रतिदिन देखे जा सकते हैं। मन्त्रिपरिषद् का निर्माण योग्यता, अनुभव एवं दक्षता के आधार पर न होकर केवल सत्ता में काबिज रहने के समीकरणों के द्वारा निर्धारित होते प्रतीत हो रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध के इस अध्याय में विभिन्न मन्त्रिपरिषदों की दलीय स्थिति का अवलोक

किया जा रहा है ताकि सविदा सरकार की मजबूरियों तथा वर्तमान राजनीतिक संस्कृति की दिशा को जाना जा सके। मई जून में 1991 में एकादश विधानसभा के लिए हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 221 स्थान प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत अर्जित किया। जिसके परिणामस्वरूप कल्याण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 24-6-91 को गठित तथा 6-12-92 तक कार्यरत भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिपरिषद में दलीय स्थिति को सारिणी सख्या 8-1 में दर्शाया गया।

सारिणी सख्या 8-1

सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में सत्तारूढ दल

क्र० स०	सत्तारूढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	भारतीय जनता पार्टी	221	22	100	56	100	4
योग		221	22	100	56	100	4

सारिणी 8-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद में भारतीय जनता दल के ही 56 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें से 22 सदस्य मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री हैं। यदि विधान सभा में इस दल की स्थिति पर दृष्टि डालें तो इसे विधानसभा में 221 स्थान प्राप्त है। इस प्रकार विधानसभा व मन्त्रिपरिषद अनुपात 4 है अर्थात् 4 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद में एक सदस्य को सम्मिलित किया गया।

कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद की बर्खास्तगी के पश्चात नवम्बर 1993 में द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न चुनावों में बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी ने साथ मिल कर चुनाव लड़ने का फैसला किया था वामदलों के साथ इनका चुनावी समझौता था। किन्तु फिर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 107 स्थान तथा बहुजन समाज पार्टी को 67 स्थान ही प्राप्त हो सका। इस प्रकार यह दोनों दल अब भी बहुमत से दूर थे। भारतीय जनता पार्टी 176 स्थान प्राप्त कर एक बार पुनः प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी किन्तु वह भी पूर्ण बहुमत प्राप्त न कर सकी। तदपश्चात कांग्रेस, जनता दल तथा वामदलों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिये लिखित आश्वासन दिया।¹ परिणामस्वरूप दिनांक 4-1-93 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी को साझा मन्त्रिपरिषद का गठन हुआ जो दिनांक 3-6-95 तक कार्यरत थी। इस मन्त्रिपरिषद में विभिन्न दलों की स्थिति को सारिणी संख्या 8-2 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 8-2

सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में सत्तारूढ दल

क्र० सं०	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	समाजवादी पार्टी	107	9	60	16	57.1	6.7
2	बहुजन समाज पार्टी	67	6	40	12	42.9	5.6
योग		174	15	100	28	100	6.2

सारिणी सख्या 8-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिमण्डल में समाजवादी दल के सदस्यों के साथ बहुजन समाजवादी दल के सदस्यों के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। मन्त्रिपरिषद में इनकी सख्या क्रमशः 16 तथा 12 है तथा प्रतिशत 57.1 फीसदी व 42.9 रहा है। यदि मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व को देखे तो समाजवादी दल के 9 सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के 6 सदस्य को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जिनका प्रतिशत क्रमशः 60 व 40 रहा।

यदि विधानसभा में इन दलों की स्थिति को देखे तो समाजवादी पार्टी को 107 व बहुजन समाज पार्टी को 67 स्थान प्राप्त हुए हैं। यदि विधानसभा व मन्त्रिपरिषद के अनुपात पर दृष्टि डालें तो जहाँ समाजवादी पार्टी का प्रतिशत 67.1 रहा, वहीं बहुजन समाज पार्टी का 56.1 रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी को उच्च प्रतिनिधित्व अनुपात प्राप्त हुआ।

प्रदेश के बदलते हुए घटनाक्रम में मायावती द्वारा बहुजन समाज पार्टी का मुलायम सिंह के सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय, तद्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त समर्थन देने के फैसले के परिणामस्वरूप दिनांक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में विभिन्न दलों की दलीय स्थिति को सारिणी सख्या 8-3 में दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 8-3

1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में सम्मिलित दल

क्र० सं०	सत्तारूढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	बहुजन समाज पार्टी	67	12	100	33	100	2

सारिणी सख्या 8-3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद के सभी 33 सदस्य बहुजन समाज पार्टी से ही लिये गये जिसमें 12 सदस्य मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री हैं। इस दल की विधानसभा में मात्र 67 सीटें थीं। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का अनुपात 2:1 ठहरता है अर्थात् इस दल के दो विधानसभा सदस्यों पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद में सम्मिलित किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के नेतृत्व में गठित इस मन्त्रिपरिषद में 9 ऐसे सदस्य थे जिन्हें विधानमण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं थी। स्वयं मुख्यमंत्री मायावती भी किसी सदन की सदस्य नहीं थीं।

मायावती की अल्पावधि सरकार का पतन, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने के परिणामस्वरूप दिनांक 18/10/95 को हुआ। तद्पश्चात् एक लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन में रहने के पश्चात् सितम्बर-अक्टूबर 1996 में सम्पन्न त्रयोदश विधानसभा चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। अतः राजनीतिक विवशताओं के परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी ने मिल कर प्रदेश में सरकार बनाने का फैसला किया। जिसके लिए हुए समझौते में यह प्रावधान किया गया कि सरकार का नेतृत्व अर्थात् मुख्यमंत्री पद छ महीने के लिए दोनों दलों से बारी बारी लिया जाएगा। इसी क्रम में दिनांक 3/6/95 को मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के साझा मन्त्रिपरिषद का गठन किया गया। जिसमें विभिन्न दलों की स्थिति को सारिणी सख्या 8-4 में दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 8-4 के अन्तर्वर्णित आकड़ों का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में बहुजन समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मन्त्रिपरिषद में इनकी सख्या क्रमशः 23 व 23 थी अर्थात् दोनों दलों को मन्त्रिपरिषद में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। जबकि मन्त्रिमण्डल में इन दोनों दलों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो बहुजन समाज पार्टी के 11 तथा भारतीय जनता पार्टी के 10 सदस्य को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित किया गया था।

सारिणी संख्या 8-4

सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित दल

क्र० सं०	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे संख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	बहुजन समाज पार्टी	67	11	52.4	23	50	2.9
2	भारतीय जनता पार्टी	174	10	47.6	23	50	7.6
योग		241	21	100	46	100	5.2

यदि विधान सभा मे इन दोनो दलो की स्थिति को देखे तो बहुजन समाज पार्टी को 67 व भारतीय जनता पार्टी को 107 स्थान प्राप्त हुए हैं और यदि विधानसभा व मन्त्रिपरिषद अनुपात पर दृष्टि डाले तो जहाँ बहुजन समाज पार्टी का अनुपात 2.9 1 रहा वही भारतीय जनता पार्टी का 7.6 1। इस प्रकार स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी को उच्च प्रतिनिधित्व अनुपात प्राप्त हुआ।

मायावती के मन्त्रिपरिषद की छ महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के मध्य हुए समझौते के परिणामस्वरूप दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त कल्याण सिंह के नेतृत्व मे दिनांक 21-3-97 को भाजपा तथा बसपा की संयुक्त मन्त्रिपरिषद का गठन हुआ। किन्तु जल्द ही बहुजन समाज दल ने इस सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी तथा उसके दल के सभी मन्त्रियों ने मन्त्रिपरिषद से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। तदपश्चात विभिन्न दलों टूट कर आये विधायकों के समर्थन से संचालित मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न दलों की स्थिति को सारिणी संख्या 8.5 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 8.5

1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में सत्तारुढ़ दल⁽¹⁾

क्र० सं०	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	भारती जनता पार्टी	174	22	57.9	52	55.9	3.4
2	जन बसपा	13	4	10.5	13	14	1
3	लो० कांग्रेस	22	9	23.7	22	23.7	1
4	समता पार्टी	02	1	2.6	1	1.1	2
5	जनता दल (पाण्डेय)	03	1	2.6	3	3.2	1
6	निर्दल	02	1	2.6	2	2.2	1
योग		216	38	99.9	93	100.1	2.3 (अनुपात)

सारिणी सख्या 8-5 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद् में अनेक दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जिनमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के 52 सदस्य, तदपश्चात् लोकतान्त्रिक कांग्रेस के 23 सदस्य, जनवादी बहुजन समाज पार्टी के 13 सदस्य, जनता दल (पाण्डेय) से 3 सदस्य, समता पार्टी से 1 सदस्य व निर्दल 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इनका प्रतिशत क्रमशः भारतीय जनता पार्टी 55.9, लोकतान्त्रिक कांग्रेस 23.7, जनवादी बहुजन समाज पार्टी 14, जनता दल (पाण्डेय) 3.2, समता पार्टी 1.1 तथा निर्दल 2.2 फीसदी रहा।

⁽¹⁾ इस सारिणी में कल्याणसिंह की मन्त्रिपरिषद् से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद निर्मित मन्त्रिपरिषद् की दलीय स्थिति को दर्शाया गया है।

यदि मन्त्रिमण्डल में इनके प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो भारतीय जनता पार्टी के 22 सदस्य, लोकतान्त्रिक कांग्रेस के 9 सदस्य जनवादी बहुजन समाज पार्टी के 4 सदस्य, जनता दल (पाण्डेय) समता पार्टी तथा निर्दल के एक-एक सदस्य को मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

यदि विधानसभा में इन सत्तारूढ़ दलों की स्थिति का अवलोकन करें तो भारतीय जनता पार्टी को 174 लोकतान्त्रिक कांग्रेस को 22, जनवादी बहुजन समाज पार्टी को 13, जनता दल (पाण्डेय) को 03, समता पार्टी को 02 तथा निर्दल को 02 स्थान प्राप्त हैं।

यदि मन्त्रिपरिषद् विधानसभा अनुपात पर दृष्टि डाले तो समग्र अनुपात 1 2 3 है अर्थात् 2 3 विधानसभा सदस्यों पर मन्त्रिपरिषद् में एक सदस्य को सम्मिलित किया गया। जिसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी को निम्न अनुपातित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वहीं अन्य दलों को उच्च अनुपातित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यह अनुपात क्रमशः भारतीय जनता पार्टी 1 3 4, समता 1 2, जन बसपा, लोकतान्त्रिक कांग्रेस, जनता दल (पाण्डेय) व निर्दल का 1 1 रहा।

सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में दलीय स्थिति के अवलोकन से जो प्रमुख तथ्य उजागर हो रहा है वह यह है कि यह काल साझा सरकारों का काल रहा है। इस काल में गठित पाँच सरकारों में चार साझा सरकारें थीं। केवल कल्याण सिंह के नेतृत्व में सन् 1991 में प्रथमबार गठित मन्त्रिपरिषद् ही एक स्वावलम्बी मन्त्रिपरिषद् थी अर्थात् यह बिना किसी दल के सहयोग पर निर्मित थी। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य कांग्रेस को छोड़कर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण दल ने यथा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, समय-समय पर सत्ता पर काबिज हुई।

सन् 1991 से 1997 के मध्य तीन विधान सभा चुनावों का सामना प्रदेश को करना

पड़ा जिसमें प्रथम अर्थात् एकादश विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव मई-जून 1991 में सम्पन्न कराये गये, जिसमें 221 स्थान प्राप्त भारतीय जनता पार्टी ने केवल सबसे बड़े दल के रूप में उभरी वरन् उसे पूर्णतः बहुमत भी प्राप्त हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 24-6-97 को कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। इस काल में (सन् 1991 से 1997 के मध्य) यही एक ऐसी सरकार थी जो बिना किसी दल के सहयोग से निर्मित थी। कल्याण सिंह के इस मन्त्रिपरिषद में कुल 56 मन्त्रियों को शामिल किया गया जो सभी भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित थे। इनमें 22 को कैबिनेट स्तर का मन्त्री पद प्रदान किया गया जिसका विधान सभा मन्त्रिपरिषद अनुपात 1:4 था। किन्तु दिनांक 6-12-92 को कल्याण की सरकार को अयोध्या में विवादित ढाँचे की रक्षा न कर पाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। तदपश्चात् प्रदेश को सन् 1997 तक दो मध्यावधि चुनावों का सामना करना पड़ा जिसमें नवम्बर 1993 में द्वादश विधानसभा के लिए तथा सितम्बर-अक्टूबर सन् 1996 में त्रयोदश विधानसभा के लिए कराये गये चुनाव सम्मिलित थे। इन दोनों विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और यह पूरा काल साझा सरकारों तथा अस्थिर राजनीति का रहा। यह तथ्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस काल में गठित किसी भी मन्त्रिपरिषद ने अपना कार्य काल पूर्ण नहीं किया।

द्वादश विधानसभा चुनाव के पश्चात् मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के साझे मन्त्रिपरिषद पर नजर डाले तो इसमें सम्मिलित 28 सदस्यों में से 16 समाजवादी पार्टी तथा 12 बहुजन समाज पार्टी से सम्बन्धित थे, जबकि विधान सभा में इनकी स्थिति पर नजर डाले तो समाजवादी पार्टी को 107 तथा बहुजन समाज पार्टी को 67 स्थान प्राप्त थे। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी की अपेक्षा अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

मुलायम सिंह यादव के पश्चात्

मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद

पर दृष्टि डाले तो यह सरकार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बिना शर्त समर्थन पर आधारित थी। किन्तु वह (भारतीय जनता पार्टी) सरकार में सम्मिलित नहीं हुई। इस प्रकार मायावती ने अपने दल के सदस्यों में से ही मन्त्रिपरिषद् का गठन किया। जबकि दल को विधानसभा में मात्र 67 सीटें ही प्राप्त थीं। इस मन्त्रिपरिषद् में कुल 33 मन्त्री शामिल किये गये जिसमें 12 सदस्यों को कैबिनेट स्तर का मन्त्रिपद प्रदान किया गया। इस प्रकार विधान सभा व मन्त्रिपरिषद् का अनुपात इस दौरान गठित सभी मन्त्रिपरिषदों में सबसे उच्च था तथा विधान सभा में दो सदस्यों पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में शामिल किया गया था।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मायावती की यह मन्त्रिपरिषद् उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर आधारित थी जिसके विषय में बहुजन समाज पार्टी का मानना रहा है कि यह मनुवादी पार्टी है जो उच्च वर्ग के लोगों को व्यवस्था में अधिक लाभ पहुँचाने के लिए कार्य करती है तथा इसी व्यवस्था के परिवर्तन के सकल्प के साथ मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावों के दौरान एक साम्प्रदायिक दल बताया था तथा इसे सत्ता से दूर रखने का भी सकल्प लिया था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता प्राप्ति की अभिलाषा ने बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेने को विवश कर दिया। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विचारधारों तथा सिद्धान्तों का एक अवसरवादी गठबन्धन अस्तित्व में आया, किन्तु जैसी उम्मीद थी, यह सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लम्बे समय तक नहीं चल सकी और 136 दिन के पश्चात् ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में अपने को एक धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में प्रस्तुत किया। उसके पार्टी प्रमुख काशीराम ने एक समय मुसलमानों को देश का गद्दार कहा था।¹

मायावती की सरकार के पतन के पश्चात एक लम्बे समय तक राज्य को राष्ट्रपति शासन में रहना पड़ा किन्तु अन्त में जब राज्यपाल को यह प्रतीत हुआ कि किसी भी सरकार का गठन अब प्रदेश में सम्भव नहीं है तो उन्होंने द्वादश विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की सस्ती कर दी। जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में हुए त्रयोदश विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और बहुत दिनों की कवायद के बाद एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी ने मिल कर सरकार के निर्माण हेतु सविदा कर लिया। इस सविदा में यह प्रावधान था कि प्रत्येक दल का मुख्यमंत्री छ-छ महीने के लिए प्रदेश की सरकार की बागडोर सम्भालेगा। इस प्रकार सिद्धान्तहीन ही नहीं बल्कि सत्ता लोलुपता की जिस राजनीति का चित्र प्रदेश राजनैतिक दलों ने प्रस्तुत किया उसका दूसरा उदाहरण दूढ़ना एक कठिन कार्य प्रतीत होता है।

मायावती के नेतृत्व में द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद में दलीय स्थिति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि यह एक समझौते की विवशता का परिणाम था क्योंकि मन्त्रिपरिषद में बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जबकि विधानसभा में इन दलों की स्थिति में काफी भिन्नता थी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 176 स्थान प्राप्त हुए थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी को मात्र 67 स्थान ही विधानसभा में प्राप्त थे।

बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के मध्य सम्पन्न समझौते के परिणामस्वरूप मायावती के मन्त्रिपरिषद के छ महीने के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात मायावती ने त्यागपत्र दे दिया, तदोपरान्त कल्याण सिंह के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल का गठन किया गया। किन्तु जल्द ही बहुजन समाज पार्टी ने इससे अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद प्रदेश में जो राजनैतिक घटना चक्र चला वह सत्तालोलुपता और सिद्धान्तहीन राजनीति का ऐसा प्रदर्शन था जिसकी कल्पना भी असम्भव प्रतीत होती है जबकि विभिन्न दलों से टूट कर आये विधायकों ने कल्याण सिंह की सरकार को समर्थन प्रदान किया तथा

इसके ऐवज में उन्हें मन्त्रिपरिषद् में स्थान प्रदान किया गया। जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्रदान करने वाले सभी विधायकों को मन्त्रिपरिषद् में स्थान प्रदान किया गया।

इस प्रकार सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषद् में दलीय स्थिति के अवलोकन से प्रदेश की राजनीति में साझा सरकार की मजबूरियाँ, सत्ता लोलुपता, सिद्धान्तहीन तथा विचारहीन राजनीति का मिला जुला चित्र प्रस्तुत हो रहा है। अतः यह कहना उचित प्रतीत हो रहा है कि भारतीय राजनीति दलों में किसी निश्चित सिद्धान्त तथा वैचारिकता का अभाव है।



यसंहार

उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (1991 - 1997 ई०) के सरचनात्मक—सख्यात्मक दृष्टिकोण, शीर्षक से सम्पन्न प्रस्तुत शोध—प्रबन्ध में विवेचित विभिन्न परिवर्त्यों के आधार पर निर्गत निष्कर्षों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। शोधकर्त्ता ने अनुभव किया है कि राजनीतिक—व्यवस्था पर पृष्ठभूमि सम्बन्धी परिवर्त्यों का प्रभाव इतना सघन और आपस में मिलाजुला होता है कि यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि कौन—कौन से परिवर्त्य किस—किस समय कितना प्रभाव अनुकूल या प्रतिकूल रूप में डाल रहे हैं। यह भी देखने में आया है कि एक ही परिवर्त्य एक ही समय में अलग—अलग प्रभाव डालता है तथा एक परिवर्त्य दूसरे परिवर्त्य के प्रभाव को या तो ज्यादा प्रभावशाली बना देता है या प्रभावशून्य। कहीं—कहीं परिवर्त्य आपस में एक—दूसरे के सम्पूरक के रूप में या विरोधी रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन सब विसंगतियों एवं परिवर्त्यों की विचलन की स्थिति में सटीक निष्कर्ष पर पहुँचना अत्यन्त कठिन होता है, जबकि वैज्ञानिक शोध—विधि से यही अपेक्षा की जाती है कि निष्कर्ष या उपलब्धियाँ सटीक हो और उनके आधार पर निश्चित रूप में कोई भविष्यवाणी भी की जा सके। शोधकर्त्ता का विश्वास है कि चूँकि सामाजिक विज्ञान की विषय—वस्तु व्यक्ति है जो देश, काल, परिस्थिति से नित्य प्रभावित होता रहता है, अतः उससे सम्बन्धी निर्णय भी परिवर्तनीय होते रहते हैं। पुनरपि, शोध की पूर्णता या औपचारिकता के निर्वहन के रूप में उपसंहार इस प्रकार है—

मन्त्रिपरिषद् की जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर विवेचन में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि बसपा (1995) की सरकार में मात्र एक मन्त्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित) सवर्ण था, शेष मध्यम तथा अनुसूचित जातियों के थे, जबकि भाजपा के समर्थन से यह सरकार बनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक सवर्ण मन्त्री का उक्त सरकार में चयन कोई न कोई विवशता ही रही होगी।

1991 में श्री कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषद् में उच्च वर्ग को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व (48 प्रतिशत लगभग) प्रदान किया गया था। 1993 में श्री मुलायम सिंह की बसपा

समर्थित सयुक्त सरकार में मध्यम जातिवर्ग को सर्वाधिक (53.5 प्रतिशत लगभग) प्रतिनिधित्व दिया गया।

सन् 1997 में भाजपा समर्थित सुश्री मायावती की सरकार में मध्यम वर्ग को लगभग 42.2 प्रतिशत स्थान दिया गया, जबकि श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में पहले बसपा के समर्थन और उसके बाद में अन्य छोटे-छोटे दलों तथा निर्दलियों के समर्थन से बनी सरकार में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 54.5 प्रतिशत उच्च जातियों को प्राप्त हुआ। उक्त तथ्य विभिन्न सरकारों में सर्वाधिक मात्रा में जाति स्तर पर चयनित मन्त्रियों की संख्या को इंगित करता है। इसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा में उच्च जाति, सपा में मध्यम जाति और बसपा में अनुसूचित जाति को सर्वाधिक वरीयता दी गई है। अपवाद स्वरूप दलों के आपसी समझौते एवं सहमति से बनी सरकारों में ही अन्य जातियों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो दल की जातीय दृष्टि का नहीं अपितु सरकार बनाने के लिए हुए समझौते का परिचायक है। इससे दलों के जातीय दृष्टिकोण का स्पष्ट पता चलता है। कोई भी दल किसी जाति-विशेष पर केन्द्रित होकर यदि कोई ऐसी राजनीति करता है और सरकार बनाता है तो यह लोकतन्त्र की आत्मा (जनता की सरकार) की पूर्णतया अवहेलना एवं उपेक्षा है। ऐसी स्थिति प्रदेश और देश के लिए घातक है। जातीयता के पाश में आबद्ध राजनीति का विशाक्त परिणाम हमारे लोकतन्त्र को क्षतिग्रस्त कर रहा है। अपेक्षा यह है कि जातीय सकीर्णता से ऊपर उठकर राजनीतिक दल अपनी मनोवृत्ति को व्यापक बनाएं। वर्तमान सरकार विधानसभा के लिए जो निर्वाचन (चतुर्दश विधानसभा) सम्पन्न हुआ था उसमें अन्य दलों की अपेक्षा बसपा को अधिक सीटें प्राप्त हुई थी, जिसका स्पष्ट कारण यह रहा कि इस दल ने अपने को जातीय सकीर्णता से थोड़ा उदार बनाते हुए अन्य जातियों के सदस्यों (मध्यम या उच्च जाति) को अपना प्रत्याशी बनाया, जो विजयी भी हुए, जनाधार बढ़ा। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जातीय व्यवस्था को यदि सम्भव हो सके तो राजनीति का आधार बनाया ही न जाय अथवा अत्यन्त न्यून कर दिया जाए।

मन्त्रिपरिषद् में धार्मिक पृष्ठभूमि के आँकड़ों के आधार पर यह तथ्य निर्गत हुआ

है कि अल्पसंख्यकों (मुस्लिम) को उनकी प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर न निर्वाचनों में दलों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व बनाया गया और न जनसंख्या के आधार पर मंत्री बनाया गया। इतना अवश्य है कि सदन में जीत कर आए हुए मुस्लिम विधायकों की संख्या की तुलना में उनका मंत्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व अधिक है। वस्तुतः यह भी एक रहस्यात्मक तथ्य ही है जो देखने में आकर्षक है परन्तु निहितार्थ यह है कि उनको सदन में पहुँचने के लिए दलों द्वारा अपेक्षित मात्रा में टिकट न देकर प्रथम द्वारा ही रोक लगा दी जाती है। जबकि दूसरे धर्म (हिन्दु) के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व अधिक है।

भाजपा के कल्याण सिंह की प्रथम सरकार में तो एक ही मुस्लिम मंत्री बनाया गया था। सपा में इनकी संख्या 10.7 प्रतिशत (कुल तीन सदस्य) और बसपा में 12.1 प्रतिशत प्रथम सरकार में (इसमें भाजपा अन्दर से सम्मिलित नहीं थी) और द्वितीय सरकार में 8.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व (इसमें भाजपा सम्मिलित थी) दिया गया। भाजपा की द्वितीय सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 4.4 प्रतिशत रहा। समवेत रूप से इस तथ्य के आधार पर जो रुझान स्पष्ट होता है, वह मुस्लिमों के प्रति भाजपा की सर्वाधिक कम और सपा की सबसे अधिक। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, विशेषतः मन्दिर-मस्जिद विवाद के कारण, धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। एक ओर मण्डल-कमीशन ने जातिवाद को बढ़ावा दिया तो मन्दिर-मस्जिद विवाद ने हिन्दु-मुस्लिम धर्म को आवश्यकता से अधिक विवादस्पद बना दिया। राजनीति को धार्मिक आधार ही प्रदान नहीं किया गया, प्रत्युत सम्पूर्ण धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया। यही नहीं, धर्म का विकृत स्वरूप सम्प्रदायवाद के रूप में उभर कर सामने आया। जातीय एवं धार्मिक हिंसा में वृद्धि हुई। धर्मानिरपेक्षता का छद्म स्वरूप ही वस्तुतः दिखायी पड़ता है। राजनीतिक दलों की धार्मिक प्रतिबद्धता उनके द्वारा टिकट-वितरण के समय स्वतः स्पष्ट हो जाती है। शोधकर्त्ता का सुझाव है कि धर्मानिरपेक्ष आचरण को व्यावहारिकता प्रदान की जाय। टिकट-वितरण से लेकर मन्त्रिपद प्रदान करने तक धर्म को आधार न बनाया जाय। धर्माधारित राजनीति भी प्रदेश, देश और मानव-समाज के लिए अवांछनीय है। गुजरात के वर्तमान (दिसम्बर 2002) चुनाव में भाजपा की विजय को हिन्दूवाद की विजय

कहना भी धर्मोन्माद भडकाना ही है। सूचना तन्त्रो, राजनेताओ और समीक्षको को इस प्रकार के विश्लेषणो से अपने को दूर रखते हुए स्वस्थ वातावरण के सृजन मे सहयोग करना होगा। सत्ता के लिए धर्म की महत्ता को स्वीकार नही किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय आधार पर प्रदेश को उत्तराचल, पश्चिमाचल, मध्याचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वाचल के रूप मे पाँच भागो के विभक्त किया गया है। इसमे उत्तराचल को भाजपा ने, पश्चिमाचल को मायावती की द्वितीय सरकार(भाजपा समर्थित), मध्याचल को कल्याण सिंह की प्रथम सरकार मे, बुन्देलखण्ड को मायावती की प्रथम सरकार मे पूर्वाचल को भी मायावती की प्रथम सरकार मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर महत्व दिया गया है। मायावती की प्रथम और मुलायम सिंह की सरकार मे उत्तराचल का एक भी मन्त्री नही बनाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा ने उत्तराचल को, बसपा ने बुन्देलखण्ड और पूर्वाचल को विशेष महत्व दिया है, जबकि सपा ने किसी क्षेत्र विशेष को अत्यधिक महत्व नही दिया है। ऐसी स्थिति मे कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रो मे दलो की स्थिति अत्यधिक मजबूत थी या जो क्षेत्र किसी दल विशेष के गढ़ या वोट-बैंक थे, उन्हे मन्त्रिपरिषद् मे अधिक स्थान दिया गया है। क्षेत्र को वरीयता मतों के प्रतिशत, दल की स्थिति, विजय का अन्तर आदि के आधार पर दिया गया है। क्षेत्रीयता के सन्दर्भ मे दलो का दृष्टिकोण या तो अपने क्षेत्रीय वर्चस्व को बनाए रखने के लिए या दल की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। मन्त्री बनने से क्षेत्रीय विकास निश्चित रूप से प्रभावित होता है। यदि क्षेत्रीय असन्तुलन मन्त्रिपरिषद् मे रहेगा तो उसी के आधार पर क्षेत्रीय विकास मे भी असन्तुलन उत्पन्न होगा। सम्पूर्ण प्रदेश को अपना क्षेत्र मानते हुए उनके हितो को ध्यान मे रखना दलो के लिए आवश्यक है। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन मे भी इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए।

समूचा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसका उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद् मे स्पष्ट झलक मिलती है, क्योंकि कृषि-क्षेत्र से आने वाले विधायको को अधिक मन्त्री बनाया गया है, उसके बाद वकालत, अध्यापक, व्यापार-उद्योग वर्ग से मन्त्री बनाए जाते है। इन्ही से दो-तिहाई सख्या की पूर्ति हो रही है। चिकित्सा एवं अभियांत्रिक क्षेत्र से

बनने वाले मन्त्रियों की संख्या लगभग शून्य ही है। सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य तथा लेखन पत्रकारिता में सलग्न सदस्य आसानी से मन्त्रिपद प्राप्त कर लेते हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक चेतना की दृष्टि से कृषको की संख्या सबसे अधिक है। इनकी राजनीतिक चेतना का आधार वैचारिक ही न होकर राजनीतिक सहभागिता एवं राजनीतिक प्रक्रिया से अधिक है। पढ़े-लिखे विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर वैचारिक अधिक है, व्यवहारिक कम और जिनमें व्यवहार या क्रियाशीलता के स्तर पर राजनीतिक जागरूकता, सहभागिता के रूप में अधिक है, उनका प्रतिनिधित्व भी अधिक है। स्पष्ट है कि मन्त्री का पद व्यवसाय से सीधे न जुड़कर व्यावसायिक राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा है। स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती थी कि स्वातंत्र्य संग्राम में पहले राजा महाराजा, उसके बाद पढ़े-लिखे खास तौर से वकील वर्ग में राजनीतिक चेतना अधिक थी और वे ही स्वतन्त्रता-संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लेते रहे, लेकिन पूर्णरूपेण सफलता तभी मिली जब जनसामान्य में स्वतंत्रता की चेतना आ गयी। इसी प्रकार, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् चुनावों में पहले राजा, महाराजा व पढ़े-लिखे आभिजात्य वर्ग के लोगों की रुझान बढ़ी, सामान्य वर्ग में यह चेतना धीरे-धीरे विकसित हुई और अन्ततः वर्तमान में देखा जा सकता है कि जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बसपा और सपा ने ग्रामीण क्षेत्रों कृषि कार्य में लगे हुए लोगों में राजनीतिक अभिरुचि और चेतना उत्पन्न कर उनकी सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिसका स्पष्ट प्रभाव मतदान के प्रतिशत से लेकर सदन में पहुँचने वाले सदस्यों एवं मन्त्रियों के रूप में देखा जा सकता है।

मन्त्रिपरिषद् की शैक्षिक पृष्ठभूमि अत्यन्त उत्साहवर्धक है क्योंकि लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मन्त्री स्नातक स्तर से अधिक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। बसपा सरकार के मन्त्रियों का शिक्षा-स्तर अन्य दलों के सरकारों के मन्त्रियों से स्नातक स्तर या उससे ऊपर के स्तर पर बहुत कम मात्रा में न्यून है। अतः कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद् की शैक्षिक पृष्ठभूमि लोकतन्त्र को सशक्त सम्बल प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा का जितना उन्नत स्तर मन्त्रियों का है, सदन में उनके आचरण

और सम्भाषण में भी वही परिलक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षा — स्तर के आँकड़े औपचारिक शिक्षा (संस्थात्मक शिक्षा) से सम्बद्ध है। शिक्षा के माध्यम से व्यवहार, संस्कार, विचारधारा आदि का भी उन्नयन अपेक्षित है।

मन्त्रिपरिषद् में स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व के अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि इस काल में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद् में अत्यन्त ही अल्प रहा है। (सर्वाधिक 6.7 प्रतिशत रहा)। मुलायम सिंह के मन्त्रिपरिषद् में तो कोई भी स्त्री सदस्य को शामिल नहीं किया गया, मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व अन्य मन्त्रिपरिषद् की तुलना में उच्च था, किन्तु यह अन्तर नाम मात्र का था।

इससे स्पष्ट है कि यद्यपि संविधान में लिंग भेद स्वीकार नहीं किया गया है तथा स्त्री व पुरुष को समान दर्जा प्रदान है फिर भी इस काल में मन्त्रिपरिषद् में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प है और पुरुषों का बर्चस्व बना हुआ है जो किसी भी समाज के लिए एक स्वस्थ लक्षण नहीं है। जो स्त्रियाँ मन्त्रिपरिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकीं उनका शिक्षा स्तर उच्च रहा तथा वह प्रत्येक जाति वर्ग से आयी थी। जहाँ तक उनकी धार्मिक प्रस्थिति का प्रश्न है तो एक सिक्ख धर्म से तथा अन्य सभी हिन्दू धर्म से थीं।

उत्तर प्रदेश की महिलाओं का मन्त्रिपरिषद् तथा विधानसभाओं में कम प्रतिनिधित्व का कारण प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में खोजा जा सकता है। स्त्रियों का आर्थिक रूप से पुरुषों पर अवलम्बित होना, साक्षरता की कमी, घरेलू स्वभाव, परम्परागत रीति-रिवाज एवं मान्यताएँ जिसके तहत सार्वजनिक क्रियाकलापों में स्त्रियों की भागीदारी को अच्छा न माना जाना आदि कारण प्रतीत होता है।

स्त्रियों के लिए व्यापक साक्षरता कार्यक्रम सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण तथा प्रत्येक आर्थिक गतिविधियों में महिला पुरुष समानता को प्रोत्साहन, यह ऐसे कदम हैं जो निश्चय ही स्त्रियों को आर्थिक स्वावलम्बन की तरफ ले जायेंगे। जिसके प्रभाव से उनमें स्वतंत्र निर्णय की क्षमता में वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक गतिविधियों में अपने को मुक्त पा सकेंगी। जिसमें राजनीतिक गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं।

मन्त्रिपरिषद् में विधानसभा और विधान परिषद् से सम्बन्धित सदस्यों की संख्या के अन्तर्गत यह परिलक्षित हुआ है कि सर्वाधिक संख्या निम्न सदन के सदस्यों की ही रही है। उच्च सदन के सदस्य 15.6 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत के अन्तर्गत ही मंत्री बनाए गए। मायावती (1995 ई०) की मन्त्रिपरिषद् के अधिकांश ऐसे सदस्य थे, जो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और चूंकि छ महीने के अन्दर ही वह सरकार गिर गयी। अतः सदस्यता का प्रश्न महत्वहीन हो गया। विधानपरिषद् से मंत्री बनने वाले अधिकांश सदस्य ऐसे रहे हैं जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित न हो सकने की दशा में मन्त्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में सत्ता में पिछले दरवाजे से प्रविष्ट किए।

जहाँ तक मन्त्रिपरिषद् की दलीय स्थिति का प्रश्न है, इसमें सविद सरकार होने के कारण दल की भागेदारी समझौते के आधार पर सुनिश्चित होती रही है, जैसे बसपा-भाजपा गठबन्धन 1997 में मन्त्रिपरिषद् में दोनों दलों के बराबर मंत्री बने परन्तु कल्याण सिंह ने बसपा के समर्थन वापसी के बाद जब विभिन्न छोटे-छोटे दलों के सहयोग से सरकार बनायी तो सभी सहयोगी दलों के सदस्य ही मंत्री नहीं बनाए गए, अपितु प्रत्येक निर्दलीय सहयोगियों को भी मंत्री बना दिया गया। जबकि सपा-बसपा सरकार कि सरकार में मन्त्रिपरिषद् के प्रतिनिधित्व का निर्धारण विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर की गयी। भाजपा (1991) की सरकार बिना किसी दल के सहयोग से बनी थी, अतः उसकी सरकार में भाजपा के ही सदस्य मंत्री बनाए गए। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद् में दलीय स्थिति बहुमत या गठबन्धन के आधार पर निर्धारित शर्तों के आधार पर घटती बढ़ती रही है।

मन्त्रियों का संचरण और विभागों में परिवर्तन की प्रवृत्ति भी बहुधा दलीय नेतृत्व के निर्णयों के अनुसार ही हुआ है। यद्यपि कि यह कार्य नितान्त मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री के स्वविवेक के आधार पर सम्पन्न होता है, किन्तु गठबन्धन या बाहर से दलों के समर्थन के कारण यह कार्य बाहर के निर्देशन पर होता रहा है। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री बहुत ही कम मात्रा में स्वतन्त्र हो पाया है। प्रायः मन्त्रीगणों का संचरण दलों के निर्धारित कोटे द्वारा निश्चित किया जाता है। सरकार चलाने का वास्तविक कार्य संचालक समिति

(स्टीयरिंग कमेटी) द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त सक्षिप्त उपसहारात्मक विश्लेषण के पश्चात् सुझाव के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे कि लोकतन्त्र सुदृढ़ हो सके तथा साथ ही राजनीतिक एवं संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए स्वस्थ राजनीतिक क्रियाकलापों का सम्पादन हो सके—

- 1 राजनीतिक दलों को अपनी निर्धारित विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए। विचारधाराविहीन व्यक्ति या दल किसी भी दशा में राष्ट्र या जनहित में नहीं हो सकता है।
- 2 सत्ता हेतु परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दलों द्वारा किए गए समझौतों का जनता द्वारा विरोध किया जाना चाहिए एवं निर्वाचनों में ऐसे दलों को नहीं चुनना चाहिए।
- 3 जाति, धर्म, क्षेत्र आदि की सकीर्णता से ऊपर उठकर मन्त्रियों का चयन हो और इस आधार पर की जाने वाली राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए।
- 4 स्पष्ट बहुमत का अभाव इन दिनों सामान्य बात हो गयी है। केन्द्र और उत्तर प्रदेश में यह तथ्य स्पष्टरूप से दिखायी पड़ता है। अतः आवश्यकता यह है कि चुनाव पूर्व गठबन्धन को महत्व दिया जाय, चुनाव के पश्चात् केवल सरकार बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले गठबन्धनों को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- 5 मन्त्रियों के चयन में क्षेत्र, जाति, धर्म आदि के आधार पर अन्तर न करते हुए योग्यता और आवश्यकता पर बल देना चाहिए। इससे राजनीति की स्वस्थ परम्परा को बल मिलेगा।
- 6 अल्प सख्यकों और स्त्रियों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि उन्हें उनकी सख्या के आधार पर दलों द्वारा प्रत्याशी न बनाया जाए और उसी अनुपात में उन्हें मन्त्रीपद प्रदान किया जाय।
- 7 धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता सौहार्द के लिए आवश्यक है कि इन तत्वों को महत्व न दिया जाय। धर्म को राजनीति का विषय न बनाया जाय।

- 8 मन्त्रिपरिषद् की संख्या को भी नियन्त्रित करना आवश्यक है। सहयोग करने वाले प्रत्येक सदस्य को मंत्री बनाना हास्यास्पद है तथा आर्थिक दृष्टि से प्रदेश या देश की स्थिति के अनुकूल नहीं है।
- 9 मन्त्रियों का संचरण दलीय निर्देश, बाहर के दबाव या व्यक्तिगत विद्वेष के आधार पर न करके कार्य एवं परिणाम के आधार पर होना चाहिए। मूल्य परक राजनीति की स्थापना तभी सम्भव होगी जब मन्त्रिपरिषद् की संरचना स्वस्थ मानसिकता का परिणाम हो।
10. विधान सभाओं में महिलाओं के लिए निश्चित संख्या में स्थानों को आरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वह विधान मण्डल तक पहुँच सके एवं मान्यताएँ जिसके तहत सार्वजनिक क्रिया कलापों में स्त्रियों की भागीदारी को अच्छा न माना जाना आदि कारण प्रतीत होता है।

स्त्रियों के लिए व्यापक साक्षरता कार्यक्रम सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण तथा प्रत्येक आर्थिक गतिविधियों में महिला-पुरुष समानता को प्रोत्साहन, यह ऐसे कदम हैं जो निश्चय ही स्त्रियों को आर्थिक स्वावलम्बन की तरफ ले जायेंगे। जिसके प्रधान से उनमें स्वतन्त्र निर्णय की क्षमता में वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक गतिविधियों में अपने को मुक्त पा सकेंगी। जिसमें राजनीतिक गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं।



परिशिष्ट

परिशिष्ट सख्या-एक

उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद (1991-1997)के विभागों / संस्थाओं का स्वरूप इस प्रकार रहा-

1. लोक निर्माण
2. पर्यटन
3. सिंचाई
4. समाज कल्याण
5. ऊर्जा
6. कृषि
7. उच्च शिक्षा
8. ग्राम्य विकास
9. परिवहन
10. लघु सिंचाई
11. वन
12. माध्यमिक शिक्षा
13. बेसिक शिक्षा
14. उद्योगकारो
15. महिला कल्याण
16. सकारेता
17. श्रम
18. वस्त्र उद्योग
19. संस्थागत वित्त
20. लघु उद्योग
21. खाद्य एवं रसद
22. पर्यावरण
23. अतिरिक्त ऊर्जा
24. कारागार
25. राजस्व
26. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
27. क्षेत्रिय विकास

28. परती भूमि विकास
29. राष्ट्रीय एकीकरण
30. उत्तरांचल विकास
31. उद्यान
32. खेलकूद
33. युवा कल्याण
34. पंजीयन
35. ंर कर
36. स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क
37. चिकित्स शिक्षा
38. होमगार्ड्स
39. राजनैतिक पेंशन
40. संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
41. खादी एवं ग्रामीण उद्योग
42. कार्यक्रम ंगलन
43. वित्त
44. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
45. आवास सहायता एवं पुर्नवास
46. नगर विकास
47. दुग्ध विकास
48. पशुधन
49. नियोजन
50. पंचायती राज
51. बाढ नियंत्रण
52. परिवार कल्याण
53. अम्बेडकर ग्राम्य विकास
54. से
55. अल्प संख्यक कल्याण
56. मुस्लिम वक्फ एवं हज
57. नियुक्ति
58. कार्मिक
59. प्रशासनिक सुधार
60. गोपन
61. सतर्कता

62. निर्वाह
63. नागरिक उड्डयन
64. सूचना
65. प्रोटोकाल
66. अभिसूचना
67. गृह
68. अपराध अनुसंधान
69. राज्य संपत्ति
70. भारी उद्योग
71. बिक्री कर
72. संसदीय कार्य
73. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो
74. अर्थ एवं संख्या
75. प्रावधिक शिक्षा
76. जल सम्पूर्ति
77. मद्य निषेध
78. गन्ना विकास चीनी मिलें
79. न्याय एवं विधायी कार्य
80. प्रौढ शिक्षा
81. नागरिक सुरक्षा
82. मत्स्य
83. इलेक्ट्रानिक

श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल

24-6-91 से 6-12-92

क्रम संख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री	नियुक्ति, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, गोपन, सतर्कता, निर्वाचन, नागरिक उड्डयन, सूचना, प्रोटोकाल, अभिसूचना, गृह, अपराध अनुसंधान, राज्य सम्पत्ति, आवास, भारी उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक 15-10-91 से 16-8-92 तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा परिवार कल्याण भी रहा	24-6-91 से 6-12-92

मंत्री

1.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	वित्त, संस्थागत वित्त, बिक्रीकर, मनोरंजन कर, पजीयन, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, नियोजन, अर्थ एवं संख्या कार्यक्रम क्रियान्वयन	24-6-91 से 6-12-92
2.	श्री लालजी टण्डन	ऊर्जा 16-8-92 से नगर विकास एवं आवास	24-6-91 से 6-12-92
3.	श्री गंगा बक्श सिंह	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	24-6-91 से 6-12-92
4.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिचाई, बाढ़ नियंत्रण, न्याय विधाई कार्य 16-8-92 से ग्राम विकास बढ़ा	19-7-91 से 6-12-92
5.	श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी	राजस्व, आवास सहायता एवं पुर्नवास 16-8-92 से ऊर्जा	24-6-91 से 6-12-92

6	श्री दिनेश जौहरी	स्वास्थ्य, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण	24-6-91 से 14-10-91
7.	श्री राजनाथ सिंह	माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक 16-8-92 से माध्यमिक शिक्षा एवं वैमिक शिक्षा	19-7-91 से 6-12-92
8	श्रीमती प्रेमलता कटियार	नगर विकास, जल सम्पूर्ति नगरभूमि 16-8-92 से समाज कल्याण एवं महिला कल्याण	24-6-91 से 6-12-92
9	श्री सत्य प्रकाश विकल	आवकारी, मदयनिषेध, परिवहन, पूर्त धर्मस्व राष्ट्रीय एकीकरण 16-8-92 से परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व	19-7-91 से 6-12-92
10.	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, श्रम सेवायोजन 16-8-92 से उच्च शिक्षा	19-7-91 से 6-12-92
11	डा० मरजीत सिंह डग	लोक निर्माण 16-8-92 में वन तथा पर्यावरण	19-7-91 से 6-12-92
12.	श्री हनुमन्त सिंह	गन्ना विकास चीनी मिले	19-7-91 से 6-12-92
13	श्री रमापति शात्री	हरिजन एवं समाज कल्याण महिला कल्याण 16-8-92 में राजस्व अभाव सहायता एवं पुर्नवास	24-6-91 से 6-12-92
14.	श्री ऐजाज रिजवी	खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण मुस्लिम वक्फ 16-8-92 से कारागार एवं राजनैतिक पेन्शन एवं मुस्लिम वक्फ	24-6-91 से 6-12-92
15	श्री सुधीर कुमार वालियान	सहकारिता	24-6-91 से 6-12-92
16	श्री केदार सिंह फोनिया	पर्यटन सांस्कृतिक कार्य युवाकल्याण एवं खेलकूद	24-6-91 से 6-12-92
17	श्री गिरीश नारायण पाण्डेय	न्याय तथा विधायी कार्य	16-8-92 से 6-12-92
18.	श्री दौलत राम	प्राँद शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	16-8-92 से 6-12-92

19.	श्री सूर्य प्रताप शाही	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा परिवार कल्याण	16-8-92 से 6-12-92
20.	श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण	16-8-92 से 6-12-92
21	श्री बाल चन्द्र मिश्र	खाद्य एवं रसद तथा श्रम	16-8-92 से 6-12-92

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1.	श्री उमानाथ सिंह	कारागार, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन 16-8-92 से पशुधन दुग्ध विकास तथा मत्स्य	24-6-91 से 6-12-92
2.	श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	पचायती राज, प्रान्तीय विकास दल, क्षेत्रीय विकास	24-6-91 से 6-12-92
3.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य	19-7-91 से 16-8-92
4.	श्री शिव प्रताप शुल्क	बेसिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा 16-8-92 से उड्यान युवा कल्याण एवं खेलकूद	24-6-91 से 6-12-92
5.	श्री पूरन चन्द्र शर्मा	उत्तरांचल विकास	19-7-91 से 6-12-92

राज्य मंत्री

1.	श्री सूर्य प्रताप शाही	गृह	24-6-91 से 16-8-92
2.	श्री धनराज यादव	खाद्य प्रसस्करण एवं उद्यान 16-8-92 से वन एवं पर्यावरण	24-6-91 से 6-12-92
3.	श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण	24-6-91 से 16-8-92
4.	श्री मस्तराम	नागरिक आपूर्ति	24-6-91 से 16-8-92
5.	श्री अमरनाथ यादव	माध्यमिक शिक्षा	19-7-91 से 6-12-92
6.	श्री मयकर सिंह	लघु उद्योग	19-7-91 से 6-12-92
7.	श्री रविकांत गर्ग	ऊर्जा 16-8-92 से सस्थागत वित्त	19-7-91 से 6-12-92
8.	श्री हरिद्वार दुबे	संस्थागत वित्त	24-6-91 से 16-8-92
9.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति	19-7-91 से 6-12-92
10.	श्री बाल चन्द्र मिश्र	श्रम तथा सेवायोजन	19-7-91 से 16-8-92

11	श्री शिव बहादुर	गन्ना विकास 16-8-92 से	19-7-91 से 6-12-92
		कारागार एव होमगार्ड	
12	श्री हरवश कपूर	ग्राम विकास 16-8-92 से श्रम	19-7-91 से 6-12-92
		एव सेवायोजन	
13.	श्री बाबू राम एम0 काम	खाद्य 16-8-92 से आवकारी एव	19-7-91 से 6-12-92
		मद्य निषेध स्वतंत्र प्रभार	
14.	श्री ब्रजेश कुमार शर्मा	परिवहन 16-8-92 से नियोजन	19-7-91 से 6-12-92
15.	श्री सूरज सिंह शाक्य	सहकारिता 16-8-92 से समाज	19-7-91 से 6-12-92
		कल्याण	
16.	श्री बालेश्वर त्यागी	राजस्व 16-8-92 से गृह	19-7-91 से 6-12-92
17.	श्रीमती शारदा चौहान	नियोजन 16-8-92 से परिवहन	19-7-91 से 6-12-92
18.	डा0 अमर सिंह	चिकित्सा परिवार कल्याण	19-7-91 से 6-12-92
19.	श्री अनिल कुमार तिवारी	हरिजन एव समाज कल्याण	19-7-91 से 6-12-92
20.	श्री महाबीर सिंह	कृषि शिक्षा	19-7-91 से 16-8-92
21.	श्री हरक सिंह रावत	पर्यटन	19-7-91 से 6-12-92
22.	श्री पृथ्वी सिंह	सिंचाई	19-7-91 से 6-12-92
23.	श्री रवीन्द्र शुक्ल	कृषि, कृषि शिक्षा	16-8-92 से 6-12-92
24.	श्री वासुदेव सिंह	ग्राम्य विकास	16-8-92 से 6-12-92
25.	श्री मन्नू लाल कुरील	लोक निर्माण	16-8-92 से 6-12-92
26.	श्री भगवती प्रसाद शुक्ल	सहकारिता	16-8-92 से 6-12-92
27.	श्री अम्बिका सिंह	गन्ना विकास, चीनी मिलें	16-8-92 से 6-12-92

उप मंत्री

1.	श्री राम सरन वर्मा	दुग्ध विकास	19-7-91 से 6-12-92
2.	श्री पतिराज	पचायती राज	19-7-91 से 6-12-92
3.	श्री मन्नू लाल कुरील	कारागार, होमगार्ड्स	19-7-91 से 16-8-92
4.	श्री बैजनाथ रावत	ऊर्जा	17-8-91 से 6-12-92
5.	श्री बच्ची सिंह रावत	राजस्व	17-8-91 से 6-12-92
6.	श्री राजेन्द्र सिंह	सांस्कृतिक कार्य	17-8-91 से 6-12-92

श्री मुलायम सिंह यादव गेटिंग्स

4-12-93 से 3-6-95 अपरान्ह तक

क्रम संख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री	शेष सभी विभाग जो आवंटित नहीं हैं	4-12-93 से 3-6-95

मंत्री

1.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	लोक निर्माण तथा ससदीय कार्य	4-12-93 से 3-6-95
2.	मो० आजम खॉ	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ	4-12-93 से 3-6-95
3.	श्री राज बहादुर	समाज कल्याण	4-12-93 से 1-6-95
4.	श्री रामलखन वर्मा	पचायती राज	4-12-93 से 1-6-95
5.	श्री रमा शंकर कौशिक	नगर विकास	4-12-93 से 3-6-95
6.	श्री भगवती सिंह	वन	4-12-93 से 3-6-95
7.	श्री बलराम यादव	स्वास्थ्य चिकित्सा तथा	4-12-93 से 3-6-95
8.	श्री बाबूराम यादव	राजस्व	4-12-93 से 3-6-95
9.	श्री मनोहर लाल	पशुधन तथा मत्स्य	4-12-93 से 29-9-94
10.	श्री अवधेश प्रसाद	कारागार होमगार्ड्स	4-12-93 से 3-6-95
11.	श्री आर० के० चौधरी	परिवहन	4-12-93 से 1-6-95
12.	डा० मसूद अहमद	माध्यमिक शिक्षा तथा वेसिक शिक्षा	4-12-93 से 20-6-94
13.	श्री शाकिर अली	माध्यमिक शिक्षा तथा वेसिक शिक्षा	21-6-94 से 1-6-95
14.	श्री श्रीराम यादव	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास	4-12-93 से 1-6-95

राज्य मंत्री

1.	श्री शारदा नन्द अचल	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा 10-8-94 से मत्स्य पशुधन	4-12-93 से 3-6-95
2.	श्री राम धनी	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास 10-8-94 से सहकारिता	4-12-93 से 3-6-95
3.	श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा	परिवहन 10-8-94 से कारागार होमगार्डस	4-12-93 से 3-6-95
4.	श्री दीनानाथ भाष्कर	स्वास्थ्य चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा 10-8-94 से क्षेत्रीय विकास	4-12-93 से 1-6-95
5	श्री राम पाल	मत्स्य तथा पशुधन 10-8-94 से समाज कल्याण	4-12-93 से 1-6-95
6.	श्री सुन्दर सिंह बघेल	समाज कल्याण 10-8-94 से वन	4-12-93 से 3-6-95
7.	श्री सन्त बख्श रावत	नगर विकास	4-12-93 से 3-6-95
8.	श्री सुखराम सिंह यादव	लोक निर्माण तथा ससदीय कार्य	4-12-93 से 3-6-95
9.	श्री अशोक कुमार सिंह बेबी	पंचायती राज 10-8-94 से स्वास्थ्य	4-12-93 से 3-6-95
10.	श्री सुखदेव राजभर	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ	4-12-93 से 1-6-95
11.	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	राजस्व	4-12-93 से 1-6-95

उप. मंत्री

1.	श्री राम किशोर विन्द	कारागार होमगार्डस तथा राजनैतिक पेंशन 10-8-94 से परिवहन	4-12-93 से 1-6-95
2.	श्री लाल जी चौहान	वन 10-8-94 से पंचायती राज	4-12-93 से 1-6-95

सुश्री मायावती मंत्रमण्डल

3-6-95 से 18-10-95 तक

क्रम सख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	सुश्री मायावती	सभी शेष विभाग जो आवटित नही है	3-6-95 से 18-10-95

मंत्री

1.	श्री रामलखन वर्मा	वन जन्तु उद्यान लघुउद्योग खादी एव ग्रामीण उद्योग हथकरघा 16-6-95 से 26-6-95 तक संसदीय कार्य भी रहा	3-6-95 से 18-10-95
2	श्री आर० के० चौधरी	स्वास्थ्य चिकित्सा, परिवार कल्याण, मातृ एव शिशु कल्याण विज्ञान एव प्रौद्योगिकी	26-6-95 से 18-10-95
3	श्री राजेन्द्र कुमार	राजस्व अभाव सहायता एव पुनर्वास	26-6-95 से 18-10-95
4.	श्री अकबर अली	कारागार, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेशन	26-6-95 से 18-10-95
5.	श्री हृदय नारायण दीक्षित	पचायती राज, संसदीय कार्य	26-6-95 से 18-10-95
6.	श्री अवधपाल सिंह	दुग्ध विकास	26-6-95 से 18-10-95
7.	चौधरी जगवीर सिंह गूजर	सहकारिता	26-6-95 से 18-10-95
8.	श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एव जनजाति कल्याण, पिछडा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण	26-6-95 से 18-10-95
9.	श्री सुखदेव राजभर	माध्यमिक शिक्षा, वेसिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा	26-6-95 से 18-10-95

- | | | | |
|-----|--------------------|--|---------------------|
| 10. | श्री नन्द लाल पटेल | परिवहन | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 11. | श्री चैनसुख भारती | ग्राम्य विकास, अम्बेदकर ग्राम्य योजना, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिचाई, क्षेत्रीय विकास प्रान्तीय विकास दल | 26-6-95 से 18-10-95 |

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

- | | | | |
|----|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | श्री श्याम लाल यादव | श्रम सेवायोजन | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 2. | श्री वशीरुद्दीन | अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ हज | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 3. | श्री रामकिशोर विन्द | नगर विकास, जल सम्पूर्ति | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 4. | श्री विशम्भर प्रसाद निषाद | पशुधन मत्स्य | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 5. | श्री फौजदार प्रसाद | उद्यान, खाद्य प्रसस्करण | 26-6-95 से 18-10-95 |

राज्य मंत्री

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|---------------------|
| 1. | श्री इशितयाक अन्सारी | वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 2. | श्री अंगद यादव | वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 3. | श्री लाल जी चौहान | वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 4. | श्री नजमउद्दीन | राजस्व | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 5. | श्री हीरामनि पटेल | कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 6. | श्री राम विलास वाल्मिकी | कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 7. | श्री भागवत पाल | दुग्ध विकास | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 8. | श्री राम अचल राजभर | परिवहन | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 9. | श्री जयराम कुशवाहा | माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 10. | श्री भगवती प्रसाद सागर | माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 11. | श्री धूराम चौधरी | पचायती राज एवं ससदीय कार्य | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 12. | श्री चौधरी तेजपाल सिंह | ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 13. | श्री राम दवर | ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 14. | श्री धूरा राम | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 15. | श्री प्रवीण सिंह ऐरन | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 26-6-95 से 18-10-95 |
| 16. | श्रीमती सुशीला सरोज | समाज कल्याण | 26-6-95 से 18-10-95 |

सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल

21-3-97 से 21-9-97 तक

क्रम सख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	सुश्री मायावती मुख्य मंत्री	सभी शेष विभाग जो किसी को आवटित नहीं है	21-3-97 से 21-9-97

मंत्री

1.	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण एवं पर्यटन	21-3-97 से 21-9-97
2.	श्री आर० के० चौधरी	सहकारिता, 16-8-97 से बढ़ा लघुउद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन, 13-9-97 तक रहा पुनः वन व जन्तु बढ़ा	21-3-97 से 21-9-97
3.	श्री लालजी टण्डन	आवास एवं नगर विकास	21-3-97 से 21-9-97
4.	श्री बरखू राम वर्मा	संसदीय कार्य एवं पर्यावरण	21-3-97 से 21-9-97
5.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिचाई एवं गन्ना विकास बाढ़ नियंत्रण, चीनी मिले	21-3-97 से 21-9-97
6.	श्री सुखदेव राजभर	ग्राम्य विकास, 16-8-97 से बढ़ा अम्बेडकर ग्राम विकास तथा प्रान्तीय विकास दल	21-3-97 से 21-9-97
7.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार	27-3-97 से 21-9-97
8.	डा० नरेन्द्र कुमार गौर	उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा	27-3-97 से 21-9-97
9.	श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	27-3-97 से 21-9-97
10.	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	27-3-97 से 21-9-97
11.	श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन	कारागार एवं राजनैतिक पेन्शन, 13-9-97 से बढ़ा होमगार्ड्स	27-3-97 से 21-9-97
12.	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा	27-3-97 से 21-9-97
13.	श्री मारकण्डे चन्द	संस्कृति एवं खेलकूद	27-3-97 से 21-9-97
14.	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम	27-3-97 से 21-9-97

- 15 श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी कृषि, 16-8-97 से चिकित्सा 27-3-97 से 21-9-97
शिक्षा तथा लघु सिचाई वढा,
13-9-97 से आवकारी और
औद्योगिक भी बढा
- 16 श्री ऐजाज रिजवी खाद्य एव रसद, नागरिक 27-3-97 से 21-9-97
आपूर्ति, किराया नियत्रण
17. श्री राधेश्याम गुप्ता सस्थागत वित्त, व्यापार कर, 27-3-97 से 21-9-97
मनोरजन कर, पजीयन, स्टाम्प
तथा न्यायालय शुल्क
18. श्री रामवीर उपाध्याय परिवहन, 13-9-97 से ऊर्जा 27-3-97 से 21-9-97
बढा
19. श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही राजस्व, अभाव, सहायता एवं 27-3-97 से 21-9-97
पुनर्वासन
20. श्री स्वामी प्रसाद मौर्य खादी एव ग्रामीण उद्योग 27-3-97 से 21-9-97
13-9-97 से पिछडा वर्ग
कल्याण तथा विकलाग बढा

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

1. श्री बाबू लाल कुक्षमहा हथकरघा एवं रेशम उद्योग 27-3-97 से 21-9-97
2. श्री बालेश्वर त्यागी पंचायती राज 27-3-97 से 21-9-97
3. श्री सुन्दर सिंह बघेल दुग्ध विकास एव पशुधन 27-3-97 से 21-9-97
4. श्री भोला शंकर मौर्य विज्ञान एव प्रौद्योगिकी 27-3-97 से 21-9-97
5. श्री रवीन्द्र शुक्ला बेसिक शिक्षा 27-3-97 से 21-9-97
6. श्री भगवती प्रसाद सागर वैकल्पिक ऊर्जा, 16-8-97 से 27-3-97 से 21-9-97
उद्यान तथा खाद्य प्रसस्करण बढा
7. श्री बुनियाद हुसेन अन्सारी अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम 27-3-97 से 21-9-97
वक्फ, हज
8. श्री राम प्रसाद चौधरी क्षेत्रीय विकास 27-3-97 से 21-9-97
9. श्री विभूती प्रसाद निषाद इलेक्ट्रानिक्स 27-3-97 से 21-9-97
10. श्री शिव चरण प्रजापति पिछडा वर्ग कल्याण 13-9-97 से 27-3-97 से 21-9-97
हटा और लघु सिचाई मिला
विकलाग कल्याण
11. श्री राम अचल राजभर कृषि शिक्षा, कृषि अनुसधान 27-3-97 से 21-9-97

12.	श्री लाल मणि प्रसाद	होमगार्डस 13-9-97 से हटा और लघु उद्योग एवनिर्यात प्रोत्साहन मिला नागरिक सुरक्षा	27-3-97 से 21-9-97
13.	श्री गंगा प्रसाद पुष्कर	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	27-3-97 से 21-9-97
14.	श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तराखण्ड विकास	27-3-97 से 21-9-97
15.	श्री राधेश्याम कोरी	राष्ट्रीय एकीकरण एव क्रियान्वयन	27-3-97 से 21-9-97

राज्य मंत्री

1.	श्री रमा शकर पाल	सहकारिता	27-3-97 से 21-9-97
2.	श्री गोरख प्रसाद निषाद	श्रम, सेवायोजन	27-3-97 से 21-9-97
3.	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	आवास एवं नगर विकास, नगर भूमि, जलसम्पूर्ति	27-3-97 से 21-9-97
4.	श्री धर्मपाल सिंह	लोक निर्माण एवं पर्यटन	27-3-97 से 21-9-97
5.	श्री जयपाल सिंह	सिंचाई एव गन्ना विकास, बाढ़ नियंत्रण, चीनी मिले	27-3-97 से 21-9-97
6.	श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण	27-3-97 से 21-9-97
7.	श्री अशोक यादव	राजस्व, अभाव, सहायता और पुनर्वासन	27-3-97 से 21-9-97
8.	श्रीमती राज राय सिंह	संस्थानगत वित्त, व्यापार कर मनोरंजन कर, फंजीयन, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क	27-3-97 से 21-9-97
9.	श्री बशीधर भगत	खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण	27-3-97 से 21-9-97

श्री कल्याण सिंह मंत्रालय

21-9-97 से 12-11-99

क्रम संख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री	शेष सभी विभाग जो अन्य किसी को आवंटित नहीं हैं	21-9-97 से 12-11-99

मंत्री

1.	श्री आर० के० चौधरी	सहकारिता, पर्यावरण, अम्बेदकर ग्राम्य विकास	21-9-97 से 12-10-99
2.	श्री कलराज मिश्र	ढोकनिर्माण, पर्यटन	21-9-97 से 12-11-99
3.	श्री सुखदेव राजभर	ग्राम्य विकास लघु सिंचाई	21-9-97 से 19-10-97
4.	श्री लालजी टण्डन	आवास नगर भूमि, नगर विकास, जल सम्पूर्ति नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	21-9-97 से 12-11-99
5.	डा० नसीमुद्दीन सिद्दीकी	कृषि, कृषि विदेश व्यापार, औद्योगिक, मध्य निषेध, चिकित्सा शिक्षा	21-9-97 से 19-10-97
6.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास चीनी मिलें कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति 9-10-98 से बाढ़ नियंत्रण	21-9-97 से 12-11-99
7.	श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग विकलांग कल्याण	21-9-97 से 19-10-97
8.	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग कल्याण, सैनिक कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
9.	श्री रामवीर उपाध्याय	परिवहन, ऊर्जा	21-10-97 से 19-10-97
10.	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
11.	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि, कृषि विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान	27-10-97 से 12-11-99

12.	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा	21-9-97 से 12-11-99
13.	चौधरी नरेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास	27-10-97 से 12-11-99
14.	श्री जगदम्बिका पाल	परिवाहन	27-10-97 से 7-2-98
15.	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	21-9-97 से 12-11-99
16.	श्री मारकण्डे चन्द्र	लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण	21-9-97 से 19-10-97 21-10-97 से 12-11-99
17.	श्री रघुवर दयाल वर्मा	वन जन्तु उद्यान	21-10-97 से 12-11-99
18.	डा० नेपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा भाषा	21-9-97 से 12-11-99
19.	श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन	वन जन्तु उद्यान	21-9-97 से 19-10-97
20.	श्री हरी किशन	संस्कृति खेलकूद युवा कल्याण	21-9-97 से 24-9-97
21.	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	21-9-97 से 19-10-97
22.	श्री राम प्रसाद चौधरी	वस्त्र उद्योग हथकरघा रेशम उद्योग	21-9-97 से 19-10-97
23.	श्री उमेश चन्द्र	संस्कृति खेलकूद युवा कल्याण	25-9-97 से 19-10-97
24.	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी मदननिषेध	27-10-97 से 12-11-99
25.	श्री राम कुमार वर्मा	सहकारिता	27-10-97 से 12-11-99
26.	श्रीमती प्रेमलता कटियार	महिला कल्याण बालविकास एवं पुष्टाहार	27-10-97 से 12-11-99
27.	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम	21-9-97 से 12-11-99
28.	श्री सरदार सिंह	वस्त्र उद्योग हथकरघा रेशम उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
29.	श्री राधेश्याम गुप्ता	संस्थागत वित्त व्यापार कर 9-10-98 को हटा पशुधन एवं मत्स्य मिला	21-9-97 से 12-11-99
30.	श्री बाबू राम एम० काम	लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन	27-10-97 से 12-11-99
31.	श्री हुकुम सिंह	पजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प 15-1-98 से संसदीय भी 14-9-98 से खाद्य तथा रसद भी मिला	27-10-97 से 12-11-99
32.	श्री ऐजाज रिजवी	खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण	21-9-97 से 11-9-98
33.	श्री शिव प्रताप शुक्ला	कारागार	27-10-97 से 12-11-99
34.	श्री वच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
35.	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरौही	राजस्व	21-9-97 से 12-11-99
36.	श्री हरिशंकर तिवारी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	27-10-97 से 12-11-99

37.	श्री मण्डलेश्वर सिंह	क्षेत्रीय विकास, परती भूमि विकास	27-10-97 से 12-11-99
38.	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	राष्ट्रीय एकीकरण इलेक्ट्रानिक्स	27-10-97 से 12-11-99
39.	डा० रमेश पोखरियाल निशंक	उत्तराचल विकास	27-10-97 से 12-11-99
40.	चौ० लक्ष्मी नारायण	उद्यान खाद्य प्रसस्करण	27-10-97 से 12-11-99
41.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	खेलकूद युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल	27-10-97 से 12-11-99
42.	श्री शिवाकान्त ओझा	चिकित्सा शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
43.	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा	27-10-97 से 12-11-99
44.	श्री फागू चौहान	संस्कृति पूर्वधर्मस्व	27-10-97 से 12-11-99
45.	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
46.	राजा रघुराज प्रताप सिंह	कार्यक्रम कार्यान्वयन	27-10-97 से 12-11-99
47.	श्री जय नारायण तिवारी	सार्वजनिक उद्यम	10-3-98 से 12-11-99

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) / राज्यमंत्री

1.	श्री सुन्दर सिंह बघेल स्वतंत्र प्रभार	दुग्ध विकास	21-9-97 से 9-10-98
2.	श्री रवीन्द्र शुक्ला स्वतंत्र प्रभार	बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा	21-9-97 से 4-12-98
3.	श्री गोरख प्रसाद निषाद स्वतंत्र प्रभार	पशुधन, मत्स्य	21-9-97 से 9-10-98
4.	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे स्वतंत्र प्रभार	नियोजन अर्थ एवं संख्या	21-9-97 से 12-11-99
5.	श्री धर्म पाल सिंह स्वतंत्र प्रभार	पंचायती राज	21-9-97 से 12-11-99
6.	श्री जयपाल सिंह स्वतंत्र प्रभार	बाढ नियंत्रण 9-10-98 को हटा और दुग्ध विकास मिला	21-9-97 से 12-11-99
7.	श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह स्वतंत्र प्रभार	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण	21-9-97 से 31-3-99

8.	श्री अशोक यादव स्वतंत्र प्रभार	अभाव सहायता एवं पुनर्वास	21-9-97 से 12-11-99
9.	श्री राधेश्याम कोरी स्वतंत्र प्रभार	अम्बेडकर ग्राम विकास	21-9-97 से 19-10-97 तक पुनः 27-10-97 से 12-11-99
10.	राजा गजनपर अली स्वतंत्र प्रभार	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ हज	27-10-97 से 12-11-99
11.	श्री बाबू लाल कुशवाहा स्वतंत्र प्रभार	क्षेत्रीय विकास	21-9-97 से 19-10-97
12.	श्री भगवती प्रसाद सागर स्वतंत्र प्रभार	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्ठाहार	21-9-97 से 19-10-97
13.	श्री विभूति प्रसाद निषाद स्वतंत्र प्रभार	इलेक्ट्रानिक्स	21-9-97 से 19-10-97
14.	श्री लाल जी वर्मा स्वतंत्र प्रभार	कारागार	23-9-97 से 19-10-97
15.	श्री लालमणि प्रसाद स्वतंत्र प्रभार	लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन	21-9-97 से 19-10-97
15.	श्री शिव चरण प्रजापति स्वतंत्र प्रभार	कृषि अनुसंधान	21-9-97 से 19-10-97
16.	श्री गंगा प्रसाद पुष्कर स्वतंत्र प्रभार	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	21-9-97 से 19-10-97
17.	श्री राम अचल राजभर स्वतंत्र प्रभार	वैकल्पिक ऊर्जा	21-9-97 से 19-10-97
18.	श्री भोला शंकर मौर्य स्वतंत्र प्रभार	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	21-9-97 से 19-10-97
19.	श्री बुनियाद हुसेन अन्सारी स्वतंत्र प्रभार	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ हज	21-9-97 से 19-10-97
20.	श्री राम शंकर पाल स्वतंत्र प्रभार	उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण	21-9-97 से 19-10-97

राज्य मंत्री

1.	श्री बालेश्वर त्यागी	वित्त 9-10-98 बढ़ा कर एवं संस्थागत वित्त 7-12-98 से हटा एवं मिला बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा स्वतंत्र प्रभार	21-9-97 से 12-11-99
2.	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास	27-10-97 से 12-11-99
3.	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण	27-10-97 से 12-11-99
4.	श्री लल्लू सिंह चौहान	पर्यटन 14-9-98 को हटा मिला ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
5.	श्री सुरेश खन्ना	आवास	27-10-97 से 12-11-99
6.	श्री सतीश महाना	नगर विकास	27-10-97 से 12-11-99
7.	श्री धनराज यादव	सिंचाई	27-10-97 से 12-11-99
8.	श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें	27-10-97 से 12-11-99
9.	श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें	27-10-97 से 12-11-99
10.	श्री राम आसरे कुशवाहा	अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
11.	श्री रंगनाथ मिश्र	ऊर्जा 14-9-98 से हटा मिला वन 3-6-99 से परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
12.	श्री भगवान सिंह शाक्य	कृषि	27-10-97 से 12-11-99
13.	श्री वीरेन्द्र सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान	27-10-97 से 12-11-99
14.	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
15.	श्री यशवन्त सिंह	प्राविधिक शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
16.	श्री शिवेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास	27-10-97 से 12-11-99
17.	श्री बश नारायण सिंह	ग्राम्य विकास	27-10-97 से 12-11-99
18.	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन	27-10-97 से 12-11-99
19.	डा० अरिवन्द कुमार जैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	27-10-97 से 12-11-99
20.	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई	27-10-97 से 12-11-99
21.	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
22.	श्री विक्रमाजीत मौर्य	आबकारी	27-10-97 से 12-11-99
23.	श्री राम चन्द्र वाल्मीकि	सहकारिता	27-10-97 से 12-11-99
24.	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
25.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	वस्त्रोद्योग	27-10-97 से 12-11-99
26.	श्री बहोरन लाल मौर्य	संस्थागत वित्त 9-10-98 से राजस्व बढ़ा	27-10-97 से 12-11-99

27.	श्री बिहारी लाल आर्य	लघु उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
28.	श्री राकेश त्यागी	पजीयन	27-10-97 से 12-11-99
29.	श्रीमती राजराय सिंह	सेवायोजन हटा 19-10-97 से 2-11-97 से मिला खाद्य एवं रसद	21-9-97 से 27-2-98
30.	श्री हरि नारायण राजभर	कारागार	27-10-97 से 12-11-99
31.	श्री विवेक कुमार सिंह	पर्यावरण	27-10-97 से 12-11-99
32.	श्री रामपाल राजवशी	वैकल्पिक ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
33.	श्री शिवशकर सिंह	राजस्व 9-10-98 को हटा मिला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	27-10-97 से 12-11-99
34.	श्री सतीश शर्मा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 9-10-98 को हटा मिला वित्त	27-10-97 से 12-11-99
35.	श्री सग्राम सिंह	क्षेत्रीय विकास 3-6-99 को मिला कृषि	27-10-97 से 12-11-99
36.	श्री श्रीराम सोनकर	राष्ट्रीय एकीकरण	27-10-97 से 12-11-99
37.	श्री मातबर सिंह कंडारी	उत्तरांचल विकास स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री	21-9-97 से 19-10-97 20-10-97 से 12-11-99
38.	श्री बंशीधर भगत	सार्वजनिक उद्यम स्वतंत्र प्रभार 19-10-97 को हटा मिला उत्तरांचल विकास राज्यमंत्री	21-9-97 से 19-10-97 20-10-97 से 12-11-99
39.	श्री नारायण मजवाला	उत्तरांचल विकास	27-10-97 से 12-11-99
40.	श्री पूरन सिंह बुन्देला	उद्यान	27-10-97 से 27-2-98
41.	श्री दलबीर सिंह	खेलकूद 14-7-98 को हटा मिला पर्यटन	27-10-97 से 12-11-99
42.	श्री अमर मणि त्रिपाठी	युवा कल्याण 9-10-98 को हटा मिला पशुधन एवं मत्स्य	27-10-97 से 12-11-99
43.	श्री गंगा बख्श सिंह	चिकित्सा शिक्षा 3-6-99 को हटा मिला वन	27-10-97 से 12-11-99
44.	श्री विनय पाण्डेय	होमगार्ड्स	27-10-97 से 12-11-99
45.	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	संस्कृति	27-10-97 से 12-11-99
46.	श्री राम लखन पासी	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
47.	श्री मुन्ना लाल मौर्य	उद्यान	10-3-98 से 12-11-99
48.	श्री वेद प्रकाश	श्रम	10-3-98 से 12-11-99
49.	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	10-3-98 से 12-11-99
50.	श्री शिव गणेश लोधी	खाद्य एवं रसद	10-3-98 से 9-10-98

उत्तर प्रदेश के मन्त्रिपरिषद (1991-97) के सदस्यों के सामाजिक
पृष्ठभूमि से संबन्धित व्यक्तिगत आंकड़ा---

प्रश्नावली संख्या -

दिनांक -

स्थान -

निर्देश - (आवश्यकतानुसार उत्तर के सामने सही (✓) का निशान लगाये/हों/ना लिखे अथवा विवरण दे।) प्रस्तुत विवरण गोपनीय रखा जाएगा।

1 नाम

2 मुल निवास

(क) ग्राम/कसबा/शहर

(ख) तहसील

(ग) जिला

3 विधान मंडल के किस सदन से आप सम्बन्धित हैं।

(क) विधानसभा सदस्य ()

(ख) विधान परिषद सदस्य ()

(ग) किसी भी सदन से सम्बन्धित नहीं ()

4 आपकी किस विधानसभा के सदस्य रहे हैं।

(क) एकादश ()

(ख) द्वादश ()

(ग) त्रयोदश ()

(घ) उपर्युक्त में से किन्हीं दो में ()

(ङ) उपर्युक्त सभी में ()

- 5 विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल। उल्लेख करें
- 6 आप किस धर्म से सम्बन्धित हैं।
- (क) हिन्दू ()
- (ख) मुस्लिम ()
- (ग) अन्य (उल्लेख करें)
- 7 आप किस जाति से सम्बन्धित हैं।
- (क) उच्च वर्गीय ()
- (ख) मध्य वर्गीय ()
- (ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति ()
- (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं तो उल्लेख करें
- 8 आप किस लिंग से सम्बन्ध रखते हैं।
- (क) स्त्री ()
- (ख) पुरुष ()
- 9 आप किस दल से सम्बन्धित हैं।
- (क) भारतीय जनता पार्टी ()
- (ख) समाजवादी पार्टी ()
- (ग) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ()
- (घ) बहुजन समाज पार्टी ()
- (ङ) जनता दल ()
- (च) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सी पी आई (माक्सवादी) ()
- (छ) उपर्युक्त के अतिरिक्त (कृपया दल का नाम लिखें)
- (ज) निर्दल ()

- 10 आपका शैक्षिक स्तर
- (क) जूनियर हाई स्कूल या उससे कम ()
- (ख) हाईस्कूल/समकक्ष ()
- (ग) इण्टरमीडिएट तथा सीनियर कैम्ब्रिज या समकक्ष ()
- (घ) स्नातक एव विधि स्नातक ()
- (ङ) स्नातकोत्तर ()
- (च) पी0 एच0 डी0 अथवा अन्य उच्च शैक्षिक अर्हता ()
- (छ) डिप्लोमा ()
- (ज) तकनीकी शिक्षा (चिकित्सा/इजीनियरिंग) ()
- (झ) अशिक्षित ()
- 11 आपका व्यवसायिक पृष्ठ भूमि
- (क) कृषि ()
- (ख) सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी ()
- (ग) राजनीति एवं सामाजिक कार्य ()
- (घ) वकालत ()
- (ङ) व्यापार एवं उद्योग ()
- (च) अध्यापन ()
- (छ) लेखन/पत्रकारिता ()
- (ज) चिकित्सा/इजीनियरिंग ()
- (झ) विविध (उल्लेख करें)
- 12 आप किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये हैं।
- (क) निर्वाचन क्षेत्र
- (ख) जिला

- 13 क्या यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित है।
(क) हाँ ()
(ख) नहीं ()
- 14 यदि इस अवधि में दल परिवर्तन किये हो तो इसका उल्लेख करें।
- 15 क्या आप उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति से सतुष्ट हैं।
(क) हाँ ()
(ख) नहीं ()
- 16 मन्त्रिपरिषद् तथा राज्य की राजनैतिक स्थिति के सदर्थ में सुझाव दें।



संदर्भ ग्रन्थ सूची

- आमण्ड एण्ड कोलमैन - 'द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट', एरिपाटन, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1960।
- एस0 जे0 डब्लू - 'द नेचर ऑफ लीडरशीप: ए पोलिटिकल अप्रोच', बम्बे, लालवानी, 1968।
- अवस्थी डॉ0 विशम्बर दयाल - 'वैदिक सस्कृति और दर्शन', सरस्वती प्रकाश, इलाहाबाद, 1978।
- अस्थाना पुष्पा - 'पार्टी सिस्टम इन इण्डिया', डेवलपमेंट, आर डिके, क्राइटेरियन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1988।
- एलन जार्ज एण्ड अमकिन - 'पॉलिटिक्स एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया'।
- अस्टिन ग्रैनविल - 'इन्डियन कान्स्टीट्यूशन: कार्नेस स्टोन ऑफ ए नेशन्स', लन्दन, कलेरन्डन।
- ऐण्टर डेविड - 'पोलिटिकल पार्टीज'
- आहूजा राम - 'भारतीय समाज' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एव नई दिल्ली, 2000।

- बसु दुर्गादास - 'कामेट्री ऑफ दी कान्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया,' द्वितीय सस्करण, 1952।
- ब्राउन बर्नार्ड इ - 'न्यू डायरेक्शन्स इन कम्पैरेटिव पालिटिक्स' बाम्बे, एशिया पब्लिकेशन्स, 1962।
- भाम्भारी, सी० पी० - 'पैटर्न ऑफ कैबिनेट, मेकिंग इन इण्डियन स्टेट पोलिटिकल साइन्स,' रिव्यू खण्ड-2, 1963।
- बसु दुर्गादास - 'कमेन्टरी ऑफ द कान्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया', एस० सी० सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता, 1965।
- भास्करन० आर - 'सोशियोलोजी ऑफ पालिटिक्स, एशिया पब्लिकेशन्स,' बम्बई, 1967
- ब्लोण्डेल० जीन - 'एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्पैरेटिव पालिटिक्स बीडेनफील्ड एण्ड निकोल्स, लन्दन, 1969।
- भाम्भारी, सी. पी - 'व्यूरोक्रेसी एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया' विकास पब्लिकेशन्स, दिल्ली 1971।
- बोस, निमाई साधन - 'इण्डिया इन द एट्रिज, न्यू पर्सपेक्टिव, 1982।
- भाम्भारी० सी० पी० - 'फोर्थ जनरल इलेक्शन एण्ड पोलिटिकल, कॉम्पटिशन इन इण्डिया, (1947-1991) विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1991।

- बॉल एलन - 'मार्डन पालिटिक्स एण्ड गर्वनमेण्ट,'
लन्दन मैकमिलन, 27।
- बाइस जेम्स - 'मार्डन डेमोक्रेसी '
- बख्सी उपेन्द्र एण्ड भीखू पोरख - 'क्राइसिस एण्ड चेन्ज इन इन्डिपेन्डेंस'।
- बसु दुर्गा दास - 'भारत का संविधान एक परिचय,' प्रेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया
प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998।
- चन्द्र बिपिन - 'भारत का स्वतंत्रता संघर्ष,'
हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, 1998।
- चन्द्र बिपिन - 'आजादी के बाद का भारत,'
हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, 2002।
- दास श्यामसुन्दर - 'हिन्दी शब्द सागर,' पहला भाग,
काशी नागरी प्रचारणी सभा, 1916।
- दत्त एम के - 'आरिजन एण्ड ग्रोथ ऑफ करेन्ट इन इण्डिया,'
मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1968।

डहल आर० ए०	:	‘पोलियार्की पार्टिसिपेशन एण्ड अपोजिशन,’ येल यूनिवर्सिटी, प्रेस न्यू हैवेन, 1971।
दीक्षित प्रभा	:	‘साम्प्रदायिका का ऐतिहासिक, सन्दर्भ,’ मेकमिलन, 1980।
इल्डर्सवेल्ड एस जे एण्ड वशीरउद्दीन अहमद	:	‘सिटीजन एण्ड पॉलिटिक्स - मास पोलिटिकल विहेवियर इन इण्डिया।
फाइनर एच	-	‘द थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ मार्टन,’ 1932।
फिलीप सी० एच०	:	‘सलेक्ट डाकोमेन्ट्स आनन्द हिस्ट्री आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान’ आक्स फोर्ड, लन्दन, 1962।
फिलीप सी० एच०	-	‘पालिटिक्स एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया’ लन्दन, जार्जी एलन एण्ड अनविन, 1963।
फडिया बी० एल०	=	‘भारतीय शासन और राजनीति।
फाइनर एस ई	:	‘कम्पैरिटिव गवर्नमेन्ट एलन लेन,’ द पेम्बिन प्रेस, लन्दन, 1970।
गाडगिल एन० सी०	-	‘गवर्नमेन्ट फ्राम इनसाइड,’ मीनाक्षी प्रकाश, मेरट, 1968।
गगल एस० सी०	-	‘प्राइम मिनिस्टर एण्ड द कैबिनेट इन इण्डिया,’ नव चेतना प्रकाशन, दिल्ली, 1972।

- गोयल ओ० पी० - 'कम्पेरिटिव गवर्मेन्ट्स,' ऋतु पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
- गजेन्द्र गडकर पी० बी० - 'द कान्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया; इट्स फिलासफी एण्ड बेसिक पोस्ट लेट्स,' आक्सफोर्ड, 1972।
- गुप्ता डी० सी० : 'इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पोलिटिक्स,' विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०, दिल्ली, 1972।
- गुप्ता आर दास एण्ड मॉरिस जोन्स - 'पैटर्न्स एण्ड ट्रेन्ड्स इन इण्डियन पालिटिक्स।'
- ग्रेवर वी० : 'पोलिटिकल सिस्टम इन इण्डिया।'
- ग्रेवर वी० एण्ड रजना अरोरा - 'इण्डिया 50 ईयर्स आफ इनडिपेन्डेन्स।'
- गुप्ता वि० दास - 'पैटर्न्स एण्ड ट्रेन्ड्स इन इण्डियन पॉलिटिक्स।'
- गुप्ता अश्वनी सेन - 'इण्डिया प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेन्स।'
- गिलक्राइस्ट : 'प्रिन्सिपल्स ऑफ पोलिटिकल साइंस।'
- ग्रानविल : 'दि इण्डियन कान्सटिट्यूशन; कार्नर स्टीन आफ ए नेशन,' बाम्बे, 1972
- गाबा ओम प्रकाश - 'राजनीतिक विचार शब्दकोश,' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- हैन्सन ए० एच० एण्ड जैनेट डगलस - 'इण्डियन डेमोक्रेसी,' विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1972

हलम्पा	- 'डाइलमाज ऑफ डेमोक्रेटिक पालिटिक्स इन इण्डिया'
हन्ना डब्ल्यू ए०	- 'एट नेशनमेकर्स साउथ ईस्ट एशियाज कैरियरमैटिक स्टेट मेटरन', अमेरिका, यूनिवर्सिटीज, फील्ड स्टाफ, 1964।
जोन्स सक्लू एस मॉरिस	- 'पार्लियामेन्ट इन इण्डिया', लागमेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी, 1957।
जैन एच० एम०	- 'द यूनियन एक्जीक्यूटिव', चैतन्य पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 1969।
जोन्स डब्ल्यू० एच० मॉरिस	- 'द गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स आफ इण्डिया', हचिन्सन यूनिवर्सिटी, लन्दन, 1971।
जौहरी जे० सी०	- 'रिफ्लेक्श ऑफ इण्डियन पॉलिटिक्स', नई दिल्ली, 1974।
जौहरी जे० सी०	- 'भारतीय शासन और राजनीति', विशाल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1976।
जैन एव फडिया	- 'भारतीय शासन एव राजनीति', साहित्य भवन आगरा, 1986।
जोन्स डब्ल्यू० एच० मॉरिस	- 'डामिनेन्स एण्ड डिसेन्ट देयर इण्टर रिलेशन इन द इण्डियन पार्टी सिस्टम', ओरियन्ट लॉगमैन, मद्रास, 1978।
जोन्स डब्ल्यू० एच० मॉरिस	- 'पार्लियामेन्ट एण्ड डामिनेन्ट पार्टी द इण्डियन एक्सपीरियन्स', ओरियन्ट लॉगमैन, मद्रास 1978।

मैनर जेम्स	- 'इन्दिरा एण्ड ऑपटर', यूरोप एण्ड थर्ड वर्ल्ड' 1977।
	- 'पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टम'।
मैन हार्ट हॉट	- 'पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया', मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1982।
मलिक (डा०) सरला	- 'प्राइमिनिस्टर ऑफ इण्डिया या पार्वस एण्ड फन्क्शसन्स' प्रथम संस्करण, चिन्ता प्रकाशन, पिलानी, राजस्थान, 1984।
मोहम्मद खालिद	- 'इण्डियन पोलिटिकल सीन 1989 मेन कन्टेडर्स फार पावर (साउथ एशियन स्टडीज-2) इन्स्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज पैनाग्राफिक्स लिमिटेड इस्लामाबाद 1989।
मानेकर डी० आर०	- लाल बहादुर शास्त्री, पापुलर प्रकाशन, बम्बई।
मजूमदार बिमल विदासी	- 'इण्डियन पोलिटिकल एसोसियेशन एण्ड रिफार्मस ऑफ लेजिलेशन'।
मर्कल पीटर एच	- 'मॉडर्न कम्पैरिटिव पॉलिटिक्स'।
महेश्वरी एस० आर०	- 'तुलनात्मक राजनीति'।
मित्रा एस० के० एण्ड सिंह बी० बी०	- 'डेमोक्रेसी एण्ड सोशल चेन्ज इन इण्डिया ए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ऑफ द नेशनल इलेक्टोरेट'।

- राव वी० शिवा - 'द फ्रेमिंग ऑफ इण्डिया कान्सटीट्यूशन,' इण्डिया इन्सटीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली; 1968।
- राय अमल - 'टेशन एरिया इन इण्डियाज फेडरल सिस्टम' वर्ल्ड प्रेस कलकत्ता, 1970।
- राव के० आर० - 'कांग्रेस स्थिति' लालबानी पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 19
- राव वी० शिवा - 'द फ्रेमिंग ऑफ इण्डियन कांसटीट्यूशन' खण्ड-2 दिल्ली, 19
- राव शा० भाले - 'विधान मंडल में द्वितीय सदन का स्थान' राज्यसभा सचिवालय दिल्ली; 1977।
- राजकिशोर - 'जाति का जहर,' वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1998।
- राम रामाश्रय एण्ड पॉल वालेस - 'इण्डियन पॉलिटिक्स एण्ड द 1998 इलेक्शन्स रीजनल हिन्दुत्व स्टेट पॉलिटिक्स।
- राजपूत सरला - 'सोल ऑफ सी० एम० इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक के स्टडी ऑफ एम० पी० मोपाल, 1982।
- राय एम० एन० - 'पॉलिटिक्स पावर एण्ड पार्टीज डेमोक्रेसी एण्ड पार्टी कम्पलैक्स
- राव के० वी० - 'पालियमेट्री डेमोक्रेसी इन इण्डिया।

जोन्स डब्ल्यू० एच० मॉरिस	-	‘फ्राम मोनोपाली टु कम्पीटीशन इन इण्डियाज पोलिटिक्स’
जोन्स डब्ल्यू० एच० मॉरिस	-	‘पार्लियामेन्ट इन इण्डिया’
जोसी राम एण्ड आर० के० हेस्तर	-	‘कांग्रेस इन इण्डियन पॉलिटिक्स’, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1987।
जैन पुखराज	-	‘भारतीय प्रधानमन्त्री’, साहित्य भवन, आगरा, 1981
जैन पुखराज	-	‘राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त’, साहित्य भवन, आगरा, 1992।
जौहरी जे० सी०	-	‘भारतीय राजनीति,’ ‘विशाल पब्लिकेशन्स’ जालन्धर, 1995।
कोर्टनी सर इल्बर्ट	-	‘द गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया’, आक्सफोर्ड, 1922।
कुमार बी० आर०	-	‘इज पार्टी सिस्टम सुटेबिल फॉर इण्डिया,’ ‘स्वराज्य मद्रास’, 1961।
कोटारी रजनी	-	‘पॉलिटिक्स इन इण्डिया स्टेट अगेन्स्ट डेमोक्रेसी’, ओ लागमैन, नई दिल्ली, 1970।
कोचानेक स्टैनली ए.	-	‘द कांग्रेस पार्टी ऑफ इण्डिया, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968।
कश्यप (डॉ०) सुभाष	-	‘राजनीतिक शब्द कोष’ राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1971।

कोटरी रजनी	-	‘भारत मे राजनीति,’ ओरियन्ट लागमैन लि०, दिल्ली, 1972।
कीथ ए बी	-	‘ए कान्सटीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया,’ सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1973।
कोचानेक स्टैनली ए०	∴	‘मिसेज गांधी पिरैमिड द न्यू कांग्रेस इन गांधीज इण्डिया,’ वेस्ट व्यू, 1976।
कुल सद्गुरु दयाल एव माटे सुरेश चन्द्र	-	‘सामाजिक नियंत्रण एव परिवर्तन,’ स्टुडेंट्स फ्रेंड्स एण्ड कम्पनी, वाराणसी, 1971।
केरास मेरी सी	∴	‘इन्दिरा गांधी,’ जयको पब्लिशिंग, दिल्ली, 1980।
कोटारी रजनी	-	‘पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज।
कोटारी रजनी	-	‘द कन्टेक्ट ऑफ इलेक्टोरल चेंज इन इण्डिया।
कौशिक सुशीला	-	‘भारतीय शासन एव राजनीति,’ हिन्दी क्रियान्वयन निदेशालय , दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990।
कटियार भगवान् स्वरूप	∴	‘उत्तर प्रदेश 99,’ सूचना एव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश 1999।
कोटारी रजनी	-	‘भारत मे राजनीति,’ ओरिएण्ट लागमैन लिमिटेड, नयी दिल्ली।
कोहली अतुल	∴	‘इण्डियाज डेमोक्रेसी एण्ड एनासिसिस ऑफ चेन्जिंग स्टेट सोसायटी रिलेशन।

लायड आई रुडोलफ	- 'दि माडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन,' ओरियेन्ट लागमेन लिमिटेड, दिल्ली-1969।
लासवेल हैराल्ड	- 'फैक्शन्स इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइसेज'।
लीनग्रीन्स	- 'हैन्ड बुक ऑफ पोलिटिकल साइंस'।
मिल जे0 एस0	- 'कन्सीडरेशन ऑफ रिप्रेजेटेटिव गवर्नमेन्ट,' पारकेन्स एण्ड बोर्न लन्दन, 1861।
मुन्शी के0 एम0	- 'पार्वस एण्ड फन्क्शन्स ऑफ प्रेसीडेन्ट,' दि हिन्दुस्तान टाइम्स (गणतंत्र दिवस परिशिष्ट), 26 जनवरी 1956।
मुन्शी के0 एम0	- 'द प्रेसीडेन्ट अन्डर द इण्डियन कान्स्टीट्यूशन,' प्रथम संस्करण 'भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 1963।
मुन्शी के0 एम0	- 'इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल डक्मेन्ट्स; द फ्रीडम 1902-1950,' भारतीय विद्या भवन, खण्ड-एक/द्वितीय, 1967।
मालेराव आर0 सी0	- 'पोलिटिकल इलीट इन अनडेवलपड सोसायटी, ए केस ऑफ यू0 पी0 1969।
मोरिस जोन्स	- 'द गवर्नमेन्ट एण्ड पालिटिक्स ऑफ इण्डिया,' हिन्दी अनुवाद सुरजीत सिंह, दिल्ली, 1970।
मुखर्जी पी0 बी0	- 'प्री एलीमेन्टल प्रॉब्लम्स ऑफ दी इण्डियन कान्स्टीट्यूशन' नेशनल, दिल्ली, 1972।

नेहरु जे0 एल0	-	‘द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया,’ ओरियण्ट लांगमैन, कलकत्ता 1946।
नारायण जय प्रकाश	-	‘ए प्ली फार रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अण्डियन पॉलिटिक्स,’ काशी, 1959।
न्यूमैन सिगमण्ड	-	‘मार्डन पोलिटिकल पार्टीज सिस्टम ए फ्रेमवर्क फार एनालिसिस’ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1965।
निले वाल्टर सी0	-	‘इण्डिया द सर्च ऑफ युनिटी डेमोक्रेसी एण्ड प्रोग्रेस,’ प्रिन्सटन, डी0 वैन नैसटैड कम्पनी, 1965।
नारायण इकबाल	∴	‘स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया’ भीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1967।
नूरानी ए0 जी0	-	‘इण्डियाज कान्सटीट्यूशन एण्ड पालिटिक्स,’ जयको पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1970।
नैखार कुलदीप	-	‘इण्डिया द क्रिटिकल इयर्स,’ विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1971।
नारायण इकबाल	∴	‘भारतीय सरकार एव राजनीतिक’ हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान, 1974।
नारायण श्रीमन	-	‘ए प्ली फॉर आइडियोलॉजिकल,’ क्लैरिटी।

- पालोम्बरा जोसेफ एव बीनर माइनर - 'पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल डेबल-पमेट,'
'प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966।
- डॉ० पाण्डेय दुर्गादत्त - 'धर्मदर्शन सिद्धान्त और समीक्षा प्रकाशन,
सस्थान, शाहदरा, दिल्ली, 1979।
- पालकीवाला एन० ए० - 'वी द पीपुल, स्टैन्डर्ड बुक स्टाल, बम्बई, 1984।
- पालोम्बरा जोसेफ लॉ - 'पालिटिक्स एमंग नेशन्स।
- पूरी जी० एस० : 'भारतीय राजनीति व्यवस्था।
- पार्क एण्ड टिंकर : 'लीडरशीप एण्ड पालिटिकल इन्स्टीट्यूशन इन इण्डिया।
- राय बी० पी० सिंह - 'पार्लियामेन्टरी गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, कलकत्ता, 1945।
- राव वी० वेकटा - 'द प्राइमर मिनिस्टर, बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स,
बम्बई, 1954।
- राव बी० एन० : - 'इण्डियन कान्स्टीट्यूशन इन द मेकिंग
एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1960।
- राव के० बी० - 'पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी आफ इण्डिया,'
'वर्ल्ड प्रेस, कलकत्ता, 1965।
- रूडाल्फ एण्ड रूडाल्फ : 'द माडर्निटी ऑफ ट्रेडिसन पोलिटिकल
टेवलपमेन्ट इन इण्डिया,' यूनिवर्सिटी प्रेस,
शिकागो, 1967।

- स्थिम डोनाल्डई - 'नेहरू एण्ड डेमोक्रेसी द पालिटिकल थॉट आफ एन एशियन डेमोक्रेट' बम्बई, आरियन्स लागमैस, 1958।
- शर्मा पी० के० - 'पालिटिकल एस्पेक्ट्स आफ स्टेट्स आर्गनाइजेशन इन इण्डिया', 1958।
- सन्थानम के० - 'यूनियन स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया,' एशियन पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1960।
- शरण (डा०) परमात्मा - 'द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल ऑफ इण्डिया' एस० चन्द एण्ड कम्पनी, 1961।
- स्मिथ डोनाल्ड ई० - 'इण्डिया एज सेक्युलर स्टेट' न्यू जर्सी प्रिंटन, यूनिवर्सिटी प्रेस, 1963।
- स्ट्रेलिंगमैन ई० एच आर० - 'इन्साइक्लोपीडिया ऑफ द सोशलसाइंसेज' मैकमिलन, न्यूयार्क 1967।
- साटौंसी - 'पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टम ए फेडरल फार एनालिसिस' कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी. प्रेस, 1967।
- शर्माराम - 'पार्लियामेन्टरी गवर्मेन्ट इन इण्डिया' जर्नल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1969 ।
- सेट डी० एल० - 'सिटीजन्स एण्ड पार्टी एस्पेक्ट्स ऑफ कम्पिटिटिव पालिटिक्स इन इण्डिया,' एलाइड, बाम्बे, 1975।
- शर्मा एल० एन० - 'द इण्डियन प्राइम मिनिस्टर आफिस एण्ड पावर' नई दिल्ली, मैकमिलन, 1976।
- शर्मा रामशरण - 'प्राचीन भारत, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली, 1977।

सदाशिव एस0 एन0	-	‘पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया’ टाटा मैकग्राहिल, दिल्ली; 1977
शुक्ला (डॉ0) विमला	-	‘भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका,’ राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, 1978।
शुक्ल देवी प्रसाद एवं श्रीवास्तव वृजेन्द्र कुमार	-	‘आधुनिक संविधानों के सिद्धान्त और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन’ मध्य प्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1986।
सईद एस0 एम0	∴	‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था’ सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 1978।
सुद ज्योति प्रसाद	∴	‘आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास’ के0 नाथ एण्ड कम्पनी पुस्तक प्रकाशन, मेरठ, 1998।
सिंह जे0 पी0	-	‘सामाजिक परिवर्तन स्वरूप एवं सिद्धान्त,’ प्रेंटिस हल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली; 1999।
सूद ज्योति प्रसाद	-	‘पाश्चात्य राजनीतिक विचार का इतिहास,’ के0 नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ।
सिंह कीरेन्द्र प्रताप एवं सिंह श्यामधर	∴	‘सामाजिक परिवर्तन, दूरदर्शी शिक्षा अनुभाग, दूरदर्शी शिक्षा अनुभाग काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
श्रीनिवास एम0 एस0	-	‘आधुनिक भारत में जाति,’ राजकमल प्रकाशन प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली; 2001।
तिवारी उमाकान्त	-	‘द मेकिंग ऑफ द इण्डियन कान्स्टीट्यूशन,’ कर्नल बुक डिपो इलाहाबाद, 1974।
ठाकुर जनार्दन	∴	‘आल दि पी0 एम् स0 मेन’ दिल्ली, 1977

- जे० आर० वेकटेश्वरन - 'कैबिनेट गर्वनमेण्ट इन इण्डिया,' लन्दन 1967।
- वीनर माइनर - 'स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया' न्यू जर्सी, 1968।
- वर्मा एस० पी० - 'भारतीय संविधान एवं शासन,' एन० सी० ई० आर० टी० दिल्ली-1978।
- वर्मा एम० एस० - 'यूनियन कैबिनेट इन इण्डिया,' आलेख पब्लिशर्स, जयपुर 1980।
- विद्यालकार सत्यकेतु : 'राजनीतिशास्त्र राज्य और शासन,' सरस्वती सदन, दिल्ली, 1985।
- वर्मा एस० पी० - 'इण्डियन पार्लियामेन्ट एन्स',
उपाल पब्लिकेशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1986।
- वुड जान आर० - 'स्टेट पॉलिटिक्स इन कन्टेम्पोरेरी इण्डिया,' क्राइसिस आर
कान्टीन्यूटी बुल्डर वेस्टर व्यू, 1984।



एशियन सर्वे

एशियन रिकार्डर

एबुअल रिसर्च रजिस्टर

(पुस्तकालय जी० वी० पन्त इन्स्टीट्यूट,
झूसी, इलाहाबाद)

इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली

इन्साइक्लोपीडिया ऑफ नेशन्स - एटी नेशन्स

इण्डियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल साइंस

जर्नल ऑफ कान्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्टरी कन्ट्री स्टडीज

जर्नल ऑफ एशियन अफ्रीकन स्टडीज, दिल्ली
सेमिनार, मेन्सट्रीम, इण्डिया टुडे, आउटलुक,
पॉलिटिक्स इण्डिया, फ्रन्टलाइन
गार्जियन (मानचेस्टर)
डेली टेलीग्राफ (लन्दन)
इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया (बाम्बे)
हिन्दुस्तान टाइम्स, द पैट्रियेट
टाइम्स ऑफ इण्डिया, स्टेटसमैन
द हिन्दू, इण्डियन एक्सप्रेस, डेकन हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड,
नव भारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा।

